राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 79

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 28 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

फेडरर से लड़कर हारे झज्जर के सुमित नागल

>> 14

पाक की कई चौकियां तबाह, तीन सैनिक भी ढेर

जागरण संवाददाता, पुंछ

- पाकिस्तान ने पुंछ और उड़ी में की गोलाबारी, भारतीय सेना ने दिया माकूल जवाब
- सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश नाकाम, उल्टे पांव भागे आतंकी

सीमा पर तैनात सुरक्षाकर्मी। फाइल फोटो

पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए मंगलवार को नियंत्रण रेखा पर फिर भारी गोलाबारी की, लेकिन उसको इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। पाकिस्तानी सेना ने पहले कश्मीर के उड़ी सेक्टर और फिर जम्मू के पुंछ में सैन्य चौकियां और रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। भारत की जवाबी कार्रवाई में उड़ी के सामने सीमा पार नीलम घाटी में भारी तबाही हुई है। सूचना है कि भारतीय कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां पूरी तरह तबाह हो गई हैं। वहीं, तीन पाक सैनिक भी मारे गए हैं।

पाक सेना ने सबसे पहले आतंकियों के दल की घुसपैठ करवाने के लिए सोमवार रात पुंछ सेक्टर में गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की इस साजिश से पहले से सतर्क भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। इसके बाद आतंकी उल्टे पांव वापस भाग गए। इससे बौखलाई पाक सेना ने भारत की अग्रिम चौकियों और रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर मोर्टार दागना शुरू कर दिए। भारतीय सेना ने भी पाक सेना को कड़ा जवाब दिया।

पाक सेना ने मंगलवार दिन में भी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में बंदूकों के मुंह खोल दिए। पहले भारतीय सेना ने संयम बरता, लेकिन जब गोलाबारी की तीव्रता बढ़ने लगी और पाकिस्तान ने ग्रामीण क्षेत्रों को निशाना बनाना शुरू किया तो भारतीय सेना ने पाक को माकूल जवाब दिया। इसमें पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह होने के बाद सीमा पार पाक सेना में खामोशी छा गई, लेकिन उसने शाम सात बजे फिर पुंछ के खड़ी करमाड़ा में भारी गोलाबारी शुरू कर दी। यहां भी भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। गोलाबारी से सीमा पर तनाव बना हुआ है।

पाकिस्तान को सताई गुलाम कश्मीर की चिंता, तैनात किए कमांडो

नई दिल्ली : कश्मीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ हर ओर से मिली हार ने पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ा दी है। इसी खिसियाहट में वह भारत से जंग शुरू करने का माहौल बना रहा है। गुलाम कश्मीर को लेकर भी उसकी चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तानी सेना ने गुलाम कश्मीर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। गुलाम कश्मीर में पाक ने 100 से ज्यादा एसएसजी कमांडो को तैनात किया है। (पेज-5)

भारत के साथ हवाई मार्ग पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहा इस्लामाबाद

इस्लामाबाद : पाकिस्तान भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई मार्ग पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही वह अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए भूमि मार्ग के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। मंगलवार को एक वरिष्ठ मंत्री ने इसके संकेत दिए हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने चीन सेना के वरिष्ठ जनरल के साथ कश्मीर में स्थिति पर बातचीत की। (पेज-5)

दुनिया जीतकर घर लौटीं सुपर सिंधू

भारत की पहली विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधू का स्वदेश लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। सिंधू ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत का गौरव बताया। मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट किया, 'भारत की गौरव, एक चैंपियन जो एक स्वर्ण और ढेर सारा सम्मान लेकर घर लौटीं, आपसे मिलकर खुशी हुई पीवी सिंधू। आपको बधाई और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।' (समाचार पेज-14 पर) प्रेट्र

सरोकार

सोनागाछी के 'अंधकार' को दूर करने में जुटीं महाश्वेता

कोलकाता : एशिया के सबसे बड़े रेडलाइट एरिया सोनागाछी (कोलकाता) की सैकड़ों सेक्स वर्कर्स के हक की लड़ाई लड़ रही हैं महाश्वेता मुखर्जी। 'दीदी' के रूप में जानी जाती हैं। तकदीर की मारी ये महिलाएं उनसे अपना दुख-दर्द साझा करती हैं। 20 साल के संघर्ष की प्रेरक कहानी। (पेज-11)

जागरण विशेष

मिंटी के युद्ध कौशल ने नारी शक्ति को दिया नया आयाम

अंबाला : बालाकोट एयर स्ट्राइक और अगले दिन पाकिस्तान के जवाबी हमले को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाने वाली वायुसेना की फाइटर कंट्रोलर मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने जा रही भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति पृष्ठ 3

न कभी बाबर अयोध्या गया न वहां मस्जिद बनवाई

नई दिल्ली : अयोध्या राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने मंगलवार को कहा कि न तो कभी बाबर अयोध्या आया था और न ही उसने वहां मस्जिद बनवाई थी। यहां तक कि मीर बाकी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था।

नेशनल न्यूज पृष्ठ 6

फिरोज शाह कोटला का नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम होगा

नई दिल्ली : दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने मंगलवार को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अपने पूर्व अध्यक्ष और देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया, जिनका पिछले सप्ताह निधन हो गया था। इस स्टेडियम को अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा।

बिजनेस पृष्ठ 12

भ्रामक विज्ञापनों के सेलिब्रिटी नहीं, कंपनी पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली : भ्रामक विज्ञापनों में शामिल होने के बावजूद नामी-गिरामी हस्तियों यानी सेलिब्रिटीज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। उनके खिलाफ अधिकतम केवल एक साल किसी प्रचार में हिस्सा लेने की पाबंदी लगाई जा सकती है। संसद से पारित उपभोक्ता संरक्षणअधिनियम की नियमावली बनाने के लिए बुलाई बैठक में केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने यह जानकारी दी।

अंतरराष्ट्रीय पृष्ठ 13

जॉनसन एंड जॉनसन पर 4100 करोड़ का जुर्माना

वाशिंगटन : अमेरिका के ओकलाहोमा राज्य के एक जज ने नशीली दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े ओपॉयड संकट मामले में दिग्गज अमेरिकी हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर 57.2 करोड़ डॉलर (करीब 4,100 करोड़ रुपये) का जुर्माना ठोका है। जज ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने जानबूझकर ओपॉयड के खतरे को नजरअंदाज किया।

सरप्लस फंड पर सियासी घमासान

टकराव ▸ राहुल ने बताया आरबीआइ खजाने की चोरी, वित्त मंत्री बोलीं-ऐसे आरोपों की परवाह नहीं

सीतारमण ने कहा, बोलने से पहले अपने पूर्व वित्त मंत्रियों से पूछ लेते राहुल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

हमला

प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को खुद पैदा की गई आर्थिक विपदा का समाधान कैसे निकाला जाए, इसका कोई अता-पता नहीं है। रिजर्व बैंक से चोरी इसमें कारगर नहीं होगी।

– राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

जवाब

चोरी के आरोप लगाने और किसी को भी चोर कहने में कांग्रेस एक्सपर्ट बन गई है। चुनावी हार के बावजूद उनकी यह आदत नहीं गई है। 'चोरी' जैसे शब्द कांग्रेस पर फिट बैठते हैं।

– निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के आपात कोष से सरकार को पौने दो लाख करोड़ रुपये देने के मामले पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के कदम को रिजर्व बैंक के खजाने से 'चोरी' करार देते हुए कहा कि इससे आर्थिक विपदा की हालत नहीं सुधरने वाली। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह ऐसे आरोपों की परवाह नहीं करतीं। राहुल को ऐसे आरोप लगाने से पहले अपने पूर्व वित्त मंत्रियों से बात कर लेनी चाहिए थी। भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने थोड़ा और आक्रामक होते हुए कहा कि 'चोरी' जैसे शब्द कांग्रेस पर फिट बैठते हैं, यही कारण है कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही थी।

एक दिन पहले ही आरबीआइ ने फैसला किया था कि वह सरकार के खजाने में पौने दो लाख करोड़ रुपये देगा। तभी से यह राजनीतिक विवाद का भी मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को खुद पैदा की गई आर्थिक विपदा का समाधान कैसे निकाला जाए इसका कोई अता-पता नहीं है। रिजर्व बैंक से चोरी इसमें कारगर नहीं होगी। यह कुछ ऐसा प्रयास है जैसे गोली लगे गहरे घाव पर डिस्पेंसरी से बैंडेड चुरा कर लगाना।'

सरकार पर राहुल के इस गंभीर वार का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुणे में जवाब देते हुए उन्हें कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्रियों से सलाह का सुझाव दिया। दरअसल, डेढ़ साल पहले भी जब यह मुद्दा उठा था और आरबीआइ के अंदर भी इसका विरोध हो रहा था तो यह याद दिलाया गया था कि पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का भी मानना था कि आरबीआइ की स्वायत्तता सरकार के दिशानिर्देश से परे नहीं हो सकती। कई वित्त मंत्रियों का यही मानना रहा है। निर्मला ने राहुल को याद दिलाया कि बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के बाद रिजर्व बैंक के फैसले पर सवाल करना सही नहीं है।

आनंद शर्मा की मांग, अर्थव्यवस्था की हालत पर श्वेत पत्र लाए सरकार : कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर राहुल गांधी के प्रहार को जारी रखते हुए उस पर देश को आर्थिक आपातकाल की ओर ले जाने का आरोप लगाया। साथ ही अर्थव्यवस्था की गंभीर स्थिति पर सरकार से तत्काल श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।

'5.5 फीसद पर पहुंचा आरबीआइ का रिजर्व कोष' : आनंद शर्मा ने कहा कि बिमल जालान समिति की चार-पांच साल में किस्तों में रकम देने की सिफारिश के उलट सरकार ने एक बार में ही पैसा लेकर रिजर्व बैंक को खतरे के निशान पर लाकर खड़ा कर दिया है। तमाम कमेटियों ने आरबीआइ का रिजर्व कोष 6.8 फीसद के स्तर पर रखने की राय दी थी। लेकिन पौने दो लाख करोड़ रुपये सरकार के खजाने में जाने से रिजर्व कोष 5.5 फीसद पर आ गया है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नरों रघुराम राजन, डी. सुब्बाराव आदि इसका विरोध कर चुके हैं और उर्जित पटेल ने तो इस्तीफा तक दे दिया। आनंद शर्मा ने अर्जेंटीना का हवाला देते हुए कहा कि उसने अपने केंद्रीय बैंक का आपात कोष घटाया तो वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई।

कांग्रेस ने कहा, सरकार ने आरबीआइ के पास कुछ नहीं छोड़ा : आनंद शर्मा ने कहा कि अभी दुनिया में 2008 जैसी वैश्विक आर्थिक मंदी नहीं है फिर भी सरकार ने आरबीआइ का कोष हासिल कर लिया और आपातस्थिति के लिए उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा।

'एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बन गया है रुपया' : अर्थव्यवस्था के अभूतपूर्व वित्तीय संकट के दौर में होने का दावा करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि जीडीपी निरंतर गिर रही है। औद्योगिक और मैनूफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन गिरकर 1.2 फीसद रह गया है। रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बन गया है और हाल में चार फीसद की गिरावट हुई है।

आरबीआइ से मिला फंड इकोनॉमी को देगा रफ्तार पेज>>12

दिल्ली में पहले बिजली मुफ्त अब पानी का बकाया माफ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- ई, एफ, जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों के 10.50 लाख उपभोक्ताओं का बिल पूरा माफ
- अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी बकाये बिल में छूट की घोषणा

बिजली मुफ्त की घोषणा करने के बाद दिल्ली सरकार ने मंगलवार को पानी के बकाये बिल पर बड़ी रियायत की घोषणा की है। इसके तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ई, एफ, जी व एच श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का बकाया बिल पूरा माफ करने की घोषणा की है। वहीं अन्य श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर 25 से 75 फीसद छूट के साथ सरचार्ज 100 फीसद माफ करने की घोषणा की है। साथ ही व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के बकाये बिल पर सरचार्ज माफ करने की बात कही गई है। इस तरह दिल्ली जल बोर्ड के करीब 13.5 लाख उपभोक्ताओं को इस योजना से राहत मिलेगी। जिसमें ई, एफ, जी व एच श्रेणी के 10.50 लाख उपभोक्ताओं का पूरा बिल माफ होगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, पहले दिल्ली में पानी का बिल आता था, पानी नहीं। अब दिल्ली में पानी आता है, बिल नहीं। अगले पांच साल में दिल्ली के घरों में 24 घंटे साफ पीने का पानी मिलेगा। पानी का बकाया बिल बहुत बढ़ गया है। इसका कारण बिलिंग सिस्टम में भी कुछ कमियां हैं। अनेक लोगों को महीनों तक बिल नहीं मिलता। कुछ लोग मीटर रीडिंग गलत होने की शिकायत करते हैं। कुछ मीटर रीडर भी ऐसे हो सकते हैं, जिनके कारण बिल गलत बने। नए बिलिंग सिस्टम से 5-7 साल पुराने बिल भी रीडिंग में आ रहे हैं। इसमें जल बोर्ड व जनता दोनों की गलती हो सकती है। इसलिए यह योजना लाई गई है। जिनके घर चालू मीटर हैं उनको लाभ मिलेगा। 30 नवंबर तक यह योजना लागू रहेगी। जिनके घर पानी का मीटर नहीं चलता यदि वे 30 नवंबर से पहले नया मीटर लग लें तो वे भी इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि बिल माफ करने की यह अंतिम योजना होगी।

बिलिंग सिस्टम में सुधार कर जल बोर्ड ने पिछले साल से नया बिलिंग सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत हर मीटर रीडर को टैब दे दिया गया है। वो टैब से मीटर की फोटो खींचने पर उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। जिससे यह पता चल जाता है कि वह मौके पर गया था या नहीं। इसलिए मीटर रीडर घर बैठकर आपका बिल नहीं बना सकता।

चार हजार करोड़ का है बकाया : जल बोर्ड के कुल 23 लाख 73 हजार उपभोक्ता हैं। इनमें से 13.5 लाख उपभोक्ताओं पर चार हजार करोड़ रुपये पानी का बिल बकाया है। इनमें से घरेलू उपभोक्ताओं पर 2500 करोड़ व व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 1500 करोड़ रुपये बकाया है। (पेज-2 भी देखें)

रेलवे शताब्दी समेत कई ट्रेनों के किराये पर देगा 25 फीसद छूट

- 50 फीसद से ज्यादा सीटें खाली रहने वाली ट्रेनों में लागू होगी योजना

नई दिल्ली, प्रेट्र : रोडवेज और कम किराये वाली एयरलाइंस की कड़ी टक्कर से निपटने के लिए रेलवे शताब्दी, तेजस व गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के किराये में 25 फीसद छूट देगा। रेलवे का उद्देश्य इन ट्रेनों की खाली सीटों को भरना और राजस्व में वृद्धि करना है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि रेलवे यह छूट इन एसी और एक्जक्यूटिव चेयरकार वाली ट्रेनों के मूल किराये पर देगा। जीएसटी, आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट टैरिफ और अन्य मदों की वसूली अलग से की जाएगी। हालांकि, छूट का प्रावधान उन्हीं ट्रेनों में लागू होगा, जिनमें पिछले साल 50 फीसद से ज्यादा सीटें खाली रही थीं। रेल मंत्रालय ने चिह्नित ट्रेनों के किराये में छूट लागू करने के लिए प्रधान वाणिज्यिक प्रबंधकों को अधिकृत करने का फैसला किया है।

छूट की योजना को लागू करने के लिए गाइडलाइन भी तय की गई हैं। इन ट्रेनों के किराये में छूट का प्रावधान पूरी यात्रा पर लागू होगा। शुरू से आखिरी स्टेशन ही नहीं, बल्कि शुरू से बीच और बीच से अंतिम स्टेशन तक यात्रा करने वाले लोगों को भी छूट का लाभ मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि यह छूट सालाना, छमाही, मौसमी या सप्ताहांत के दौरान दी जा सकती है। हालांकि, इस योजना के लागू होने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस में मिलने वाली श्रेणीबद्ध छूट या फ्लैक्सी फेयर जैसी योजनाएं प्रभावी नहीं होंगी। मंत्रालय ने जोनों को 30 सितंबर तक उन ट्रेनों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है, जिनकी सीटें 50 फीसद से ज्यादा खाली रह जाती हैं।

विमान से पचास फीसद कम होगा दो तेजस ट्रेनों में किराया पेज>>3

कुलदीप बिश्नोई का 150 करोड़ का बेनामी होटल जब्त

- आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति कानून के तहत की कार्रवाई
- 23 जुलाई को हरियाणा कांग्रेस नेता के 13 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी

साइबर सिटी के गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड स्थित होटल द ब्रिस्टल। जागरण

नई दिल्ली, प्रेट्र : आयकर विभाग से हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई को करारा झटका लगा है। विभाग ने कुलदीप बिश्नोई और उनके भाई चंद्रमोहन बिश्नोई के गुरुग्राम स्थित 150 करोड़ रुपये के बेनामी होटल को जब्त कर लिया है।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 स्थित 'द ब्रिस्टल होटल' को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धारा 24 (3) के तहत की गई है। यह संपत्ति ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदी गई थी। बिश्नोई के खिलाफ कर चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने 23 जुलाई को हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में उनसे जुड़े 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि जांच में पता चला था कि होटल कंपनी में 34 फीसद शेयर एक मुखौटा कंपनी के नाम से है, जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआइ) में पंजीकृत है और उसका संचालन संयुक्त अरब अमीरात से किया जाता है। सूत्रों ने बताया कि होटल और उसकी अन्य संपत्तियां कुलदीप बिश्नोई और उनके भाई चंद्रमोहन बिश्नोई की बेनामी संपत्तियां हैं। ये दोनों भाई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर सीट से कांग्रेस विधायक हैं और चंद्रमोहन राज्य के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं।

सूत्रों ने बताया कि बीवीआइ में पंजीकृत कंपनी के साझेदार बिश्नोई परिवार के विश्वासपात्र हैं। इनका यह भी कहना था कि होटल और उसकी अन्य संपत्तियों पर बिश्नोई परिवार की ही नियंत्रण है। इसकी खरीद के लिए भी बिश्नोई परिवार ने ही पैसे की व्यवस्था की थी।

छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने एक बयान जारी किया था। इसमें बताया गया था कि छापेमारी में करीब 200 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी संपत्ति का पता चला है और विभाग इसकी जांच कर रहा है। वर्ष 1988 में बने बेनामी निषेध कानून को मोदी सरकार द्वारा नवंबर, 2016 में लागू किया गया था। इसके तहत सात साल तक की कैद और और बेनामी संपत्ति के बाजार भाव के 25 फीसद तक जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है।

कुलदीप बिश्नोई के निजी सचिव की संदिग्ध हालत में मौत

जासं, नई दिल्ली : कुलदीप बिश्नोई के निजी सचिव सुकुमार पावरिया की मंगलवार को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुकुमार ने दिल्ली में रजोकरी स्थित घर में खुदकशी कर ली। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि सुकुमार भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के राडार पर थे। सुकुमार कुलदीप बिश्नोई के साथ 12 साल से काम कर रहे थे।

बदला माहौल

तत्काल तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद अकेले उत्तर प्रदेश में ही अब तक 216 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मुस्लिम महिलाओं का रुख बताता है कि उन्हें इस कानून से बल मिला है...

कानून का साथ मिला तो आगे आने लगीं मुस्लिम महिलाएं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए सबसे अधिक मामले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी 10 मुकदमे हुए दर्ज

तत्काल तीन तलाक पर कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में इसकी नई तस्वीर सामने आ रही है। मुस्लिम महिलाओं ने मिली इस नई ताकत का मुखर होकर प्रयोग भी करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में अब तक तत्काल तीन तलाक के 216 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। तीन तलाक के इन मामलों में सबसे अधिक एफआइआर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दर्ज कराई गई है। आंकड़े खुद गवाह हैं कि मुस्लिम महिलाएं घरेलू हिंसा व अत्याचार के खिलाफ मिली इस ताकत का भरपूर प्रयोग कर रही हैं। हालांकि, इन मामलों में अभी आरोपितों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की रफ्तार सुस्त है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार एक से 21 अगस्त के बीच प्रदेश में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम-2019) के तहत 216 एफआइआर दर्ज कराई गई है। इनमें सबसे अधिक शिकायतें दहेज प्रताड़ना, संपत्ति को लेकर प्रताड़ना व मारपीट के हैं। मेरठ में तत्काल तीन तलाक के सबसे अधिक 26 केस दर्ज हुए हैं, जबकि सहारनपुर में 17 व शामली में 10 एफआइआर दर्ज हुई है। गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये तीनों शहर मुस्लिम बहुल आबादी वाले हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 10 मुकदमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दर्ज कराए गए हैं। बताया गया है कि दो-तीन मुकदमों में ही पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी की है। डीजीपी मुख्यालय स्तर से इन मामलों में की जा रही कार्रवाई की मानीटरिंग भी कराई जा रही है। डीजीपी ओपी सिंह ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम-2019) के सभी प्रावधानों का पूरी तत्परता से अनुपालन कराने का कड़ा निर्देश दिया था। दो अगस्त को जारी निर्देश में डीजीपी ने कहा था कि सभी एडीजी, आइजी के अलावा जिलों के पुलिस अधिकारी संबंधित नए कानून का अध्ययन करें व अधीनस्थों को भी उसकी विस्तार से जानकारी दें। कार्यशालाओं का आयोजन कर भी अधिनियम पर विचार-विमर्श किया जाए और अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

19 सितंबर, 2018 से लागू किया गया है नया कानून

तत्काल तीन तलाक से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद तत्काल तीन तलाक कानून 19 सितंबर, 2018 से ही लागू माना गया है। इसके तहत एक साथ तीन तलाक बोलना यानी तलाक-ए-बिद्दत को आपराधिक माना गया है। ऐसा करने पर तीन साल तक जेल का प्रावधान है। इसके जरिये एकझटके में तलाक दे दिए जाने की कुप्रथा पर रोक लगाने की पहल की गई है।

छत्तीसगढ़ में 82 फीसद आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ में कैबिनेट ने 82 फीसद आरक्षण पर मुहर लगा दी है। सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के साथ ही जातिगत आरक्षण में किए गए बदलाव को भी मंजूरी दे दी गई। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकारी नौकरी में 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़कर 27 और एससी का 12 से बढ़कर 13 फीसद हो जाएगा। एसटी के 32 फीसद आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कैबिनेट ने लेमरू हाथी रिजर्व पर भी मुहर लगा दी।

मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि आर्थिक आरक्षण का लाभ केंद्र सरकार के नियमों के आधार पर मिलेगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय आठ लाख से कम है या पांच एकड़ से कम कृषि भूमि है या 1000 वर्ग फीट तक का फ्लैट है या ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज से कम भूखंड का स्वामी है, उसके परिवार को 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिल पाएगा।

कोटा के छात्र संघ चुनाव में वोट के लिए लड़कियों से करवाया डांस

राज्य ब्यूरो, जयपुर

- राजस्थान में एबीवीपी के जुड़े नेता ने कराया आयोजन
- सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, छात्र भी थिरकते दिखे

छात्र राजनीति में नैतिकता के पतन की पराकाष्ठा मंगलवार को राजस्थान में देखने को मिली। छात्रसंघ चुनाव में वोट पाने के लिए छात्र नेताओं ने जो किया, वह बताता है कि स्तर कितना गिर गया है। किसी भी हाल में जीत की होड़ में आगे निकले को कोटा में ऑर्केस्ट्रा पार्टी की लड़कियों का डांस कराया गया। लड़कियों के उत्तेजक हाव-भाव भरी प्रस्तुति के बीच छात्र भी झूमते नजर आए। सोशल मीडिया पर डांस का यह वीडियो वायरल हो रहा है। अलवर में भी इसी तरह के आयोजन होने की खबर है।

राजस्थान के 13 सरकारी विश्वविद्यालयों और 252 निजी व सरकारी कॉलेजों के छात्र संघों के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। इसमें वोट पाने के लिए कोटा के छात्र नेताओं ने सोमवार रात को तलवंडी क्षेत्र स्थित एक मैरिज गार्डन में ऑर्केस्ट्रा पार्टी की लड़कियों के डांस का आयोजन किया। बताया गया है कि यह आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े किसी नेता ने करवाया था। इस कार्यक्रम में लड़कियां फिल्मी गानों पर डांस करती रहीं। ऑर्केस्ट्रा पार्टी की कलाकार कोटा और आसपास के क्षेत्र की थीं। छात्रों को अपने पक्ष में रिझाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र भी पूरे समय फिल्मी गानों पर झूमते रहे। हालांकि, मामले को लेकर किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई है।

मंगलवार को छात्रसंघ चुनाव के लिए हुए मतदान के दौरान कोटा, झालावाड़, उदयपुर सहित कई स्थानों पर छात्रों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आईं। कोटा में दो छात्र गुटों की भिड़ंत के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदेश मे औसतन 50 से 55 फीसद वोट पड़े। मतगणना बुधवार को सुबह 11 बजे से सभी जगह एक साथ शुरू होगी।

50 फीसद तक जल बोर्ड के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है 20 हजार लीटर पानी प्रतिमाह मुफ्त देने के बावजूद। चार साल में जल बोर्ड का राजस्व 1219 करोड़ रुपये से बढ़कर 1819 करोड़ पहुंच चुका है। यह दावा दिल्ली सरकार ने किया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 28 अगस्त 2019

भ्रष्टाचार पर वार ▸ कार्यप्रणाली में सुधार के लिए उठाया गया बड़ा कदम

डीडीए में 10 अफसर जबरन सेवानिवृत्त

बी श्रेणी के इन सभी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हुए थे सिद्ध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कार्यप्रणाली में सुधार के मद्देनजर बड़ा निर्णय लेते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपने दस अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी है। बी श्रेणी के इन सभी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए थे। इनके खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं। जबरन सेवानिवृत्त किए गए इन अधिकारियों में सहायक निदेशक से लेकर सेक्शन अफसर के स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं।

अनावश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए डीडीए ने अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत एफ आर 56 (जे) / सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 48 के प्रावधानों के अंतर्गत दस राजपत्रित और गैर राजपत्रित अधिकारियों को डीडीए की सेवाओं से समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया है। इन अधिकारियों में एक सहायक निदेशक (लिपिक वर्गीय), एक सहायक लेखाधिकारी, दो सहायक अभियंता (सिविल), चार कनिष्ठ अभियंता (सिविल), एक सहायक अनुभाग अधिकारी तथा एक अनुभागीय अधिकारी (उद्यान) शामिल हैं। डीडीए के मुताबिक ये सभी अधिकारी कथित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। उनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें ये अधिकारी मुकदमे /जांच का सामना कर रहे हैं। नियुक्ति प्राधिकारी ने भी इन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। डीडीए में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए दो कमेटियां काम कर रही हैं। एक स्क्रीनिंग कमेटी एवं दूसरी है रिव्यू कमेटी। सभी श्रेणियों में शामिल ऐसे अधिकारियों की पहले स्क्रीनिंग कमेटी एक सूची तैयार करती है। इसके बाद इस सूची पर रिव्यू कमेटी विचार करती है। आखिर में डीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में उपराज्यपाल की सहमति से अंतिम निर्णय लिया जाता है। इन दस अधिकारियों के बाद अभी और भी बहुत से अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि डीडीए में दलाली का खेल पुराना है। इसमें नीचे से ऊपर तक के ज्यादातर अधिकारी संलिप्त रहते हैं। कई अधिकारी पहले से ही विभागीय कार्रवाई या जांच का सामना कर रहे हैं। इसलिए डीडीए को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान करने में समय लग रहा है। कार्मिक विभाग की मदद से काफी काम हो गया है, लेकिन अभी कुछ काम बचा भी हुआ है।

अफसरों पर कार्रवाई से बाकियों की चिंता बढ़ी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने विदाई तो अभी केवल 10 भ्रष्ट अधिकारियों की ही की है, लेकिन अब अगला किसका नंबर? इस चिंता ने बाकियों की भी नींद उड़ा दी है। आलम यह है कि इन दिनों डीडीए में न केवल अफरातफरी, बल्कि अफवाहों का बाजार भी गर्म है। कहीं से भी खबर उड़ जाती है कि जबरन सेवानिवृत्ति वाली सूची में फलां अधिकारी का भी नाम आ गया है और उस अधिकारी का खाना-पीना हराम हो जाता है। सरकारी सेवा के नियम संख्या 56 (जे) के अंतर्गत इन दिनों डीडीए में ऐसे अधिकारियों की पहचान की जा रही है, जो भ्रष्ट, नाकारा, अनुशासनहीन अथवा किसी न किसी मामले में आरोपित हैं या फिर पहले से भी कार्रवाई या जांच का सामना कर रहे हैं। इन दागी अधिकारियों को छांटने के लिए डीडीए की दो कमेटियां जुटी हुई हैं। इन्हीं कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों पर गाज गिरनी है।

150 दागियों की सूची तैयार : विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक करीब छह हजार अधिकारी-कर्मचारियों के लंबे-चौड़े कुनबे वाले डीडीए ने अभी तक ऐसे लगभग 150 दागियों की सूची तैयार कर ली है, जो विभिन्न प्रकार के आरोपों एवं जांच का सामना कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति उन्हीं को दी जाएगी, जिन पर आरोप सिद्ध हो गए हों और जिनके खिलाफ आपराधिक या कानूनी कार्यवाही भी शुरू हो चुकी हो। इनमें भी ए श्रेणी के अधिकारियों को हटाए जाने का निर्णय केंद्र सरकार के स्तर पर लिया जाना है। हालांकि इतना तय है कि आने वाले दिनों में दागियों की सूची और लंबी हो सकती है।

> भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों को चिह्नित कर बाहर का रास्ता दिखाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ शरारती तत्व अफवाहें फैलाकर डीडीए का माहौल खराब कर रहे हैं। जो भी किया जाएगा, वह नियमों के तहत किया जाएगा। डरना केवल उन्हें ही चाहिए जो गलत काम करते रहे हैं। ईमानदारी से काम करने वाले भयमुक्त रहें।
> **-तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए**

पहली बार दिल्ली को जनता के हित में सोचने वाला मुख्यमंत्री मिला है : आप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) ने बकाया पानी के बिल माफ किए जाने पर दिल्ली सरकार को धन्यवाद दिया है। आप ने कहा है कि दिल्लीवासियों को अरविंद केजरीवाल के रूप में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो जनता के हित के बारे में सोचता है।

आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली के 70 सालों के इतिहास में पहली बार दिल्ली की जनता को एक ईमानदार और जनता के हित में सोचने वाला मुख्यमंत्री मिला है। आज से पहले जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने केवल और केवल बड़े-बड़े पूंजीपतियों की जेब भरने का काम किया। दिल्ली की गरीब जनता के बारे में कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। 2015 से पहले लोगों के घरों में हर महीने पानी का बिल तो आता था, परंतु पानी नहीं आता था।

सौरभ भारद्वाज

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में बड़े-बड़े नेताओं के पानी के टैंकर चला करते थे। जानबूझकर वे लोग दिल्ली में पानी की समस्या पैदा करते थे और फिर टैंकरों के जरिये लोगों को भारी कीमतों पर पानी बेचा करते थे।

मुफ्त के नाम पर दिल्लीवासियों को गुमराह कर रहे केजरीवाल : भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पानी का बकाया बिल माफ करने को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। उसने इसे आम आदमी पार्टी (आप) का चुनावी घोषणा बताया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि चुनाव नजदीक देखकर मुख्यमंत्री मुफ्त घोषणाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास सिर्फ जल विभाग है जिसे चलाने में वह पूरी तरह से विफल हैं। पिछले साढ़े चार वर्षों में जल बोर्ड में अव्यवस्था फैल गई है। लोगों को कई महीने तक पानी के बिल नहीं दिए गए। बाद में मनमाने तरीके से भारी-भरकम बिल भेज दिए गए। लोगों की नाराजगी को देखते हुए मुख्यमंत्री चुनाव से पहले बकाया शुल्क माफ करने की घोषणा करके दिल्लीवासियों को गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में आठ जल शोधन संयंत्र से निकलने वाला पानी का 50 फीसद ही लोगों के घरों तक पहुंच पाता है। शेष पानी या तो बर्बाद हो जाता है या फिर चोरी। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली में भूजल स्तर बढ़ाने में पूरी तरह से विफल रही है।

राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने सरकार की इस घोषणा को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में चार माह बचे हैं और सीएम हताश हैं। अपनी हताशा व असफलता छिपाने के लिए इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। सरकार को यह बताना चाहिए कि जिन लोगों ने ईमानदारी से बिल चुका दिए हैं, क्या उनके पैसे वापस किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में दिल्ली सरकार से जुर्माना का भुगतान करने वालों के पैसे वापस करने की मांग की। उन्होंने दिल्ली सरकार की घोषणा को एरियर घोटाला करार देते हुए इस बारे में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में 50 फीसद आबादी के पास पानी का कनेक्शन नहीं है। आधी दिल्ली प्यासी है या फिर दूषित जल पीने के लिए मजबूर है। टैंकर माफिया पर रोक लगाने में भी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। लगभग दो हजार टैंकर माफिया सक्रिय हैं, जबकि पिछले साढ़े चार साल में मात्र दो टैंकर के खिलाफ कार्रवाई हुई है।

न्यूज गैलरी

लखानी वरदान ग्रुप के मालिक को एक साल की सजा

फरीदाबाद : चेक बाउंस के तीन मामलों में जूता कंपनी लखानी वरदान ग्रुप के मालिक पीडी लखानी व अधिकृत अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह को अलग-अलग एक-एक साल की सजा हुई है। यह मुकदमा श्री वेंकटेश पेपर कंपनी की तरफ से साल 2013 में दर्ज कराया गया था। श्री वेंकटेश पेपर कंपनी की तरफ से मुकदमे में बताया गया था कि साल 2013 में कच्चे माल की अदायगी के बदले उन्हें पीडी लखानी और पुष्पेंद्र सिंह ने 48-48 लाख रुपये के दो व 24 लाख का एक चेक दिया था। यह चेक बाउंस हो गए। इसके बाद अदालत में मुकदमा दायर किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआइसी) प्रदीप कुमार की अदालत ने मंगलवार को चेक की रकम का दोगुना भुगतान शिकायतकर्ता को करने के आदेश दिए। वहीं, तीनों मामलों में अलग-अलग एक-एक साल की सजा सुनाई। (जासं)

दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय में लगी आग

नई दिल्ली : आइटीओ इलाके के विकास भवन स्थित दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय में मंगलवार की शाम आग लग गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की सात गाड़ियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग से आयोग के कार्यालय में रखे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत एयर कंडीशनर से हुई थी। दमकल अधिकारियों के अनुसार मंगलवार शाम करीब सवा छह विभाग को दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर दमकल की गाड़ियों को रवाना कर दिया गया था। घटना के वक्त कार्यालय के ज्यादातर कर्मी घर के लिए रवाना हो गए चुके थे। आग से कोई हताहत नहीं हुआ। (जासं)

चचेरी बहन के प्रेमी को मारी गोली, जलाया शव

नई दिल्ली : द्वारका जिला पुलिस ने हरियाणा के झज्जर निवासी अंकित (25) की उत्तर प्रदेश स्थित बागपत में हुई हत्या के मामले को सुलझाते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। हत्या का कारण गिरफ्तार आरोपितों में से एक की चचेरी बहन व अंकित के बीच प्रेम प्रसंग था। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त एंटो अल्फोंस ने बताया कि चेकिंग के दौरान 26 अगस्त की दोपहर द्वारका सेक्टर एक से अवैध हथियारों समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में पता चला कि इनमें से एक की चचेरी बहन के साथ अंकित के प्रेम संबंध थे और दोनों शादी करना चाहते थे। परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। (जासं)

'राइट टू प्ले' को और मजबूत करने की जरूरत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को दिल्ली के मालवीय नगर में नगर निगम प्रतिभा विद्यालय में सेफ प्ले रूम का उद्घाटन किया। प्ले रूम में टॉय बैंक एनजीओ की ओर से खिलौने रखे गए हैं, जिनसे खाली समय में बच्चे खेल सकेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्कूलों में राइट टू प्ले को और मजबूत करने की जरूरत है। खेलों के माध्यम से हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को एक स्वस्थ व सुरक्षित बचपन का अनुभव हो सके।

उन्होंने कहा कि इस तरह के सेफ प्ले रूम के जरिये बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ ही उनके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए भी एक्टिविटी कराई जाएगी। इस रूम में खिलौने, कहानी की किताबें, पहेलियां, भाषा संबंधित खिलौने रखे गए हैं, जिनकी मदद से बच्चे स्वच्छता, पर्यावरण, अर्थजगत आदि में अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के बाद अब सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। इसके तहत हर स्कूल में इनोवेटिव खिलौने के लिए प्रतिवर्ष 20 हजार रुपये दिए जाते हैं ताकि बच्चों की सृजनात्मक क्षमता का विकास हो सके। टॉय बैंक की निदेशक विद्युन गोयल ने कहा कि इन सेफ प्ले रूम में जेंडर न्यूट्रल खिलौने रखे जाते हैं। साउथ जोन की उपनिदेशक शिक्षा मंजू खत्री, जोन कमेटी अध्यक्ष तुलसी जोशी आदि उपस्थित रहे।

मालवीय नगर स्थित निगम प्रतिभा विद्यालय में बच्चों के साथ कैरम खेलते केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर। साथ में टॉय बैंक की निदेशक विद्युन गोयल। विपिन शर्मा

लोक सेवकों की प्रवृति भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाली : कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दो लाख रुपये रिश्वत लेने के लिए एक पुलिसकर्मी को दोषी करार देते राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने चार साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को सजा सुनाते वक्त तल्ख टिप्पणी भी की। विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने कहा कि लोक सेवकों की प्रवृति भ्रष्टाचार में लिप्त होने की है और इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है।

विशेष अदालत ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सरूप सिंह को अदालत ने रिश्वत लेने का दोषी माना। सरूप को सीबीआइ ने 2016 में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सरूप जब केशव पुरम थाने में बतौर हेड कांस्टेबल तैनात था तो एक व्यक्ति से कैंटीन की मरम्मत करने देने की एवज में दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। कैंटीन संचालक ने सीबीआइ को शिकायत दी। इसके बाद सीबीआइ ने सरूप सिंह को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामले में सीबीआइ के आरोपपत्र को सही मानते हुए विशेष अदालत ने मंगलवार को सरूप सिंह को सजा दी।

जेवर एयरपोर्ट के पास बसने वाली आधुनिक सिटी का खाका तैयार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चारों ओर आधुनिक शहर के विकास का खाका तैयार हो गया है। यह क्षेत्र प्राधिकरण के पहले से विकसित हो रहे शहर का पूरक होगा। अर्नेस्ट एंड यंग ने सोमवार को यमुना प्राधिकरण में एयरपोर्ट सिटी पर प्रस्तुतीकरण दिया। एयरपोर्ट सिटी का खाका विश्व के कई देशों में एयरपोर्ट के आसपास बसे शहरों से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। यमुना प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में एयरपोर्ट सिटी का प्रस्ताव शामिल किया जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद इसे शासन के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर के नजदीक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। प्राधिकरण एयरपोर्ट के आसपास आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण शहर को बसाने की तैयारी कर रहा है। यह शहर एयरपोर्ट के चारों ओर करीब डेढ़ हजार से दो हजार हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया जाएगा। इसकी रूपरेखा सलाहकार एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग ने तैयार की है।

> एयरपोर्ट के आसपास आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण शहर विकसित करने की योजना है। इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। बोर्ड की मंजूरी के बाद इसे शासन के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
> **-डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण**

तीन जोन में होगा शहर : एयरपोर्ट सिटी तीन जोन में विकसित होगी। एयरपोर्ट के नजदीक तीन किमी के दायरे में यात्री व कार्गो से जुड़ी गतिविधियों के लिए ढांचा तैयार होगा। इसके आगे सात किमी के दायरे में राजस्व बढ़ाने से जुड़ी गतिविधियां होंगी। 12 किमी के दायरे में रिहायशी के साथ-साथ लोगों की जरूरत को पूरा करने वाली गतिविधियों का ढांचा तैयार होगा।

कई सुविधाएं होंगी एयरपोर्ट सिटी में : एयरपोर्ट सिटी में इंटीग्रेटिड टाउनशिप, लॉजिस्टिक, मेडिकल टूरिज्म, मंडी, रिक्रिएशनल, कंवेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, बायो डायवर्सिटी पार्क आदि होंगे।

इलाज में लापरवाही पर पांच डॉक्टरों को समन भेजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ **अदालत ने एमसीआइ को पांचों के नाम तीन महीने के लिए रजिस्टर से हटाने का दिया आदेश**

कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच डॉक्टरों को नवजात शिशु (19 माह) के इलाज में लापरवाही बरतने पर समन भेजा है। अदालत ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) को भी पांचों दोषियों के नाम तीन महीने के लिए उनके रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इस दौरान ये सभी डॉक्टर प्रेक्टिस नहीं कर सकेंगे और न ही मरीज का इलाज कर पाएंगे। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी अनुज अग्रवाल ने दो अलग-अलग निजी अस्पतालों के चार डॉक्टरों और एक चिकित्सा अधीक्षक को इलाज में लापरवाही बरतने के लिए दोषी ठहराया है।

शिकायतकर्ता रेणु त्यागी ने गांधी नगर के जैन धर्मार्थ ट्रस्ट अस्पताल के डॉ. ओम प्रकाश व राकेश त्यागी और प्रीत विहार के तनेजा अस्पताल के डॉ. राकेश कुमार जैन, शेफाली चौहान व चिकित्सा अधीक्षक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कोर्ट में यह भी दावा किया कि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उनसे मोटी रकम भी वसूली। इसके बावजूद ठीक से इलाज नहीं किया, जिससे उनके बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने भी अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। इसके लिए कोर्ट ने पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त को इस मामले में दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके बच्चे को 28 नवंबर 2012 को गांधी नगर स्थित जैन धर्मार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उचित इलाज न मिलने पर अस्पताल प्रशासन ने बच्चे को प्रीत विहार स्थित तनेजा अस्पताल स्थानांतरित करने की बात कही। अगले दिन बच्चे को तनेजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उपचार के दौरान बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। शिकायतकर्ता ने बताया कि अस्पताल ने उनसे साढ़े तीन लाख रुपये भी लिए। उन्होंने बताया कि जब वह बच्चे को आइसीयू में देखने गईं तो उनके बच्चे के चेहरे पर चीटियां घूम रही थीं। इस संबंध में जब उन्होंने डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा काम इलाज करना है न की चीटियों को निकालना। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने कई बार उन्हें पैसे जमा कराने को कहा, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। इस कारण उन्होंने बच्चे को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। वहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

कथित पत्रकार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : गाजियाबाद के एक व्यापारी ने सेक्टर बीटा दो कोतवाली में कथित पत्रकार चंदन राय के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। व्यापारी का आरोप है कि चंदन राय ने उसकी राजनीतिक पहुंच बढ़वाने और शस्त्र लाइसेंस बनाने का झांसा देकर छह लाख 25 हजार रुपये हड़प लिए। बीटा दो कोतवाली में ही चंदन राय समेत पांच कथित पत्रकारों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। सभी कथित पत्रकार पांच दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस इनके खाते खंगाल रही है।

बीटा दो कोतवाली में 23 अगस्त को कथित पत्रकार ग्रेटर नोएडा सेक्टर 37 निवासी सुशील पंडित, सूरजपुर मिगसन ग्रीन मेंशन निवासी उदित गोयल, बीटा एक निवासी रमन ठाकुर, गाजियाबाद के जयभारत एंक्लेव निवासी चंदन राय और लखनऊ के गोमतीनगर विवेक खंड निवासी नितिश पांडेय के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। पुलिस को पांच दिन का रिमांड मिल गया था। कथित पत्रकारों पर लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में पुलिस अफसरों से मिलीभगत करके लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। आरोप है कि आरोपित सोशल मीडिया पर पुलिस व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रामक और तथ्यहीन खबरें चला रहे थे।

कांग्रेस को जल्द मिल सकता है प्रदेश अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर विचार-विमर्श और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को जिलाध्यक्षों ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। प्रदेश प्रभारी पीसी चाको के नेतृत्व में मिले 14 में से दस जिलाध्यक्षों ने सोनिया को दिल्ली के सियासी हालात से भी अवगत कराया। साथ ही जल्द से जल्द दिल्ली को नया अध्यक्ष दिए जाने की मांग की।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली का अध्यक्ष चुने जाने से पूर्व चाको के लिखित सुझाव पर एक योजना तैयार की गई है। इसे तीन चरणों में बांटा गया है। इसके तहत जिलाध्यक्षों, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों व पूर्व मंत्रियों की सोनिया गांधी से मुलाकात कराई जाएगी। पहले चरण में मंगलवार को सोनिया ने जिलाध्यक्षों से मुलाकात की। यह बात अलग है कि दिल्ली के 14 में से 10 ही जिलाध्यक्ष पहुंचे। चार जिलाध्यक्ष नदारद रहे।

सूत्रों का कहना है कि करीब 30 मिनट की मुलाकात में इन जिलाध्यक्षों ने सोनिया गांधी को दिल्ली की सियासी परिस्थितियों से अवगत कराया। जिलाध्यक्षों ने इससे संबंधित तीन पृष्ठों का एक पत्र भी उन्हें सौंपा। जिलाध्यक्षों ने दिल्ली को जल्द से जल्द एक योग्य अध्यक्ष देने की भी मांग की। बताया जा रहा है कि जिलाध्यक्षों ने इस दौरान अध्यक्ष के लिए भले ही कोई नाम नहीं सुझाया, लेकिन इस बात के संकेत जरूर दे दिए कि दिल्ली में एक ही अध्यक्ष चाहिए एवं कार्यकारी अध्यक्ष नहीं चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जल्द नियुक्ति को लेकर सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे दिल्ली के जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी पीसी चाको। सौजन्य : कांग्रेस

▸ **सोनिया से मिले जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का किया अनुरोध**

जिलाध्यक्षों ने सोनिया को भरोसा दिलाया कि वे आगामी विधानसभा चुनावों में अच्छा नतीजा लाकर दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें जल्द से जल्द एक अच्छा अध्यक्ष चाहिए। इस दौरान जिलाध्यक्षों ने गत विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के दौरान हासिल किए वोटों का मत फीसद भी सोनिया को बताया। साथ ही कहा कि अगर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से विधानसभा चुनावों में समय रहते उतरती है तो परिणाम बेहतर निकल सकते हैं। सोनिया ने जिलाध्यक्षों को भरोसा दिलाया कि वह दिल्ली की सारी स्थिति से वाकिफ हैं और जल्द ही नए अध्यक्ष का फैसला किया जाएगा।

गौरतलब है कि शीला दीक्षित के निधन के बाद से यह पद खाली है। इस पद को लेकर दिल्ली में राजनीति भी खूब हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में जेपी अग्रवाल, सुभाष चोपड़ा, अरविंदर सिंह लवली और महाबल मिश्रा सहित शत्रुघ्न सिन्हा एवं नवजोत सिंह सिद्धू का का नाम भी चल रहा है।

छात्र राजनीति

जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए दाखिल किए नामांकन

केंद्रीय पैनल के चार मुख्य पदों-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव और स्कूलों के 43 काउंसलरों के लिए किया नामांकन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मंगलवार को जेएनयू छात्र संघ चुनावों में भागीदारी करने वाले छात्र संगठनों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। दामोदर छात्रावास के पास स्थित टैफलास कैफे के पास एक इमारत में चुनाव समिति की ओर से नामांकन दाखिल करने के लिए तीन काउंटर निर्धारित किए थे। इसके पास सभी छात्र संगठनों की तरफ से स्टॉल लगाए थे। इनमें नामांकन दाखिल करने के सिलसिले में प्रत्याशियों को सुझाव भी दे रहे थे। छात्र संघ चुनाव के तहत केंद्रीय पैनल के चार मुख्य पदों-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के लिए और स्कूलों के 43 काउंसलरों के लिए नामांकन दाखिल किए गए। सभी छात्र संगठनों के उम्मीदवारों की अंतिम सूची बुधवार को जारी की जाएगी। साथ ही कई उम्मीदवार बुधवार को नामांकन वापिस भी ले सकते हैं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के जेएनयू इकाई के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार ने बताया कि बीते रविवार को संगठन की तरफ से चार मुख्य पदों के लिए आठ उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इन सभी ने मंगलवार को चारों मुख्य पदों पर नामांकन भरा है। वहीं सभी स्कूलों के काउंसलरों के लिए करीब 50 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है।

छात्र संघ चुनाव के लिए चुनाव समिति की ओर से बनाए गए काउंटर पर नामंकन दर्ज कराते छात्र। जागरण

नए छात्रावास व पुस्तकालय की सुविधाओं पर वोट डालेंगे छात्र

राहुल मानव, नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव के लिए छात्र चार सितंबर को होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट को लेकर काफी उत्साहित हैं। बहस में अनुच्छेद 370 को हटाने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे मुद्दों पर छात्र संगठनों के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बहस कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र विश्वविद्यालय के कई मुद्दों को चुनाव में प्राथमिकता दे रहे हैं। नए छात्रावास के निर्माण की मांग छात्र संघ चुनाव का बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। इसके अलावा साफ-सफाई, खेल की गतिविधियों को बढ़ाने, स्वास्थ्य सुविधाएं, पुस्तकालय जैसे मुद्दों पर भी छात्र चुनाव में वोट डालेंगे। साथ ही छात्राओं के लिए सैनिटरी वेंडिंग मशीनों की सुविधाओं को बढ़ाने और उनके रखरखाव के लिए वोट डाले जाएंगे। जेएनयू में छह सितंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे।

जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंस के सेंटर फॉर पॉलिटिकल साइंस के पीएचडी के छात्र और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (डीएसएफ) के सदस्य शुभांशु सिंह कहते हैं कि जेएनयू के चुनाव में कैंपस के मुद्दों के साथ देश के भी मुद्दे छाए रहते हैं। इस बार के छात्र संघ चुनाव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी बहस होगी। हम चाहते हैं कि शिक्षा का निजीकरण बिल्कुल भी ना किया जाए।

एमए, पॉलिटिकल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस के छात्र शंकर सिंह भाटी कहते हैं कि जो भी प्रत्याशी जीतें, उन्हें नए छात्रावास के निर्माण का मुद्दा प्रशासन के सामने उठाना चाहिए। स्कूल ऑफ सोशल साइंस से पीएचडी कर रहे वेंकट चौबे का कहना है कि बीते कुछ समय में जेएनयू में नए स्कूल खुलने से अतिरिक्त 1500 छात्रों के दाखिले हुए हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए छात्र संगठनों को बढ़ चढ़कर प्रशासन से बात करनी होगी।

रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, एजेंसियां : तुगलकाबाद वन क्षेत्र में गुरु रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति देने के निर्देश की मांग संबंधी एक याचिका मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। इस क्षेत्र में मंदिर को हटाया गया था।

शीर्ष अदालत में यह याचिका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद अशोक तंवर और हरियाणा के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने दायर की है। याचिका में उन्होंने दलील दी है कि तुगलकाबाद से गुरु रविदास मंदिर हटाए जाने के कारण वे पूजा के अधिकार से वंचित हो गए हैं। खुद को गुरु रविदास का भक्त बताते हुए दोनों ने गुरु रविदास की प्रतिमा को पुनःस्थापित करने की मांग की है जिसे मंदिर स्थल से हटा दिया गया था। उन्होंने दावा किया है कि 1509 में सुल्तान सिकंदर लोधी ने यह जमीन मंदिर के लिए गुरु रविदास को दी थी। वह जमीन गुरु रविदास के सभी अनुयायियों के लिए बेहद ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की है।

404 किमी मिजोरम की म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ 318 किमी की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। इस सीमा पर कड़ी निगरानी के लिए भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों ने संयुक्त गश्त बढ़ाने और मिजोरम से लगती गैर बाड़ वाली सीमा पर और अधिक चेकपोस्ट स्थापित करने का फैसला किया है।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से बाहर रह गए लोगों को कानूनी मदद देगी असम सरकार

- कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी पात्र भारतीयों की मदद करने की घोषणा की
- 31 अगस्त को किया जाएगा अंतिम एनआरसी का प्रकाशन

गुवाहाटी, प्रेट्र : अंतिम एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) प्रकाशन के चार दिन शेष रह गए हैं। इसका प्रकाशन 31 अगस्त को किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को असम सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम इसमें शामिल नहीं होगा उनमें से जरूरतमंदों को वह मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराएगी। राज्य सरकार ने नागरिकता खोने के खतरे का सामना कर रहे पात्र भारतीयों को आश्वासन देने का प्रयास किया है। विपक्षी कांग्रेस के बाद सत्ताधारी भाजपा भी पात्र भारतीयों की सहायता करने के लिए आगे आई है। एनआरसी को नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच माना जा रहा है। ऐसे लोग हिरासत केंद्रों में कैद नहीं रहेंगे या उन्हें बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा।

असम सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह जिला विधि सेवा अधिकारियों (डीएलएसए) के माध्यम से ऐसे लोगों को कानूनी सहायता मुहैया कराने की जरूरी व्यवस्था करेगी। असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) कुमार संजय कृष्ण ने कहा कि एनआरसी से बाहर रह गए लोगों को जबतक विदेशी ट्रिब्यूनल विदेशी घोषित नहीं कर दे तबतक उन्हें किसी भी परिस्थिति में हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

बयान में कहा गया है कि विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों और विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश 1964 के तहत केवल विदेशी ट्रिब्यूनल को किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए एनआरसी में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि उसे (पुरुष या महिला) विदेशी घोषित कर दिया गया है।

अंतिम एनआरसी में जिनका नाम नहीं आया है उनके हित में नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान कार्ड) नियम 2003 की धारा 8 के तहत अपील की जा सकती है। केंद्र ने अपील दायर करने की समयसीमा को 60 से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है और विदेशी (ट्रिब्यूनल) संशोधन आदेश 2019 में आवश्यक संशोधन किए हैं।

दायर अपीलों की सुनवाई के लिए जल्दी ही 200 विदेशी ट्रिब्यूनल गठित किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा एनआरसी अपडेट किया जा रहा है। 1951 के बाद पहली बार असम में एनआरसी अपडेट किया जा रहा है। यह कदम वास्तविक निवासियों की पहचान और घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए उठाया जा रहा है।

कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक के 15 अयोग्य विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। बता दें कि मंगलवार को जस्टिस रमना की पीठ से बागी विधायकों के वकील वी गिरी ने जल्द सुनवाई की मांग की। दाखिल की गई याचिका में पूर्व जद(एस)-कांग्रेस गठबंधन सरकार के विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केआर रमेश कुमार के उस आदेश को रद करने की मांग की है, जिसमें उनके इस्तीफे अस्वीकार करते हुए उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। याचिका में विधायकों ने तत्कालीन स्पीकर के फैसले को पूरी तरह से अवैध और मनमाना बताया है। याचिका में अयोग्य विधायकों ने कहा कि उन लोगों ने छह जुलाई को न केवल अपना इस्तीफा दिया था, बल्कि 11 जुलाई को स्पीकर के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर शीर्ष अदालत के आदेशानुसार नए सिरे से इस्तीफा सौंपा था। याचिका में कोर्ट से विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता से संबंधित विधानसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड तलब करने का भी आग्रह किया है।

चिदंबरम ने मांगीं पहले हुई प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ की ट्रांस्क्रिप्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पी. चिदंबरम फाइल फोटो

भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी से मिला संरक्षण फिलहाल जारी है। चिदंबरम ने मंगलवार को मनी लांड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की। साथ ही एक और अर्जी दाखिल कर ईडी द्वारा पहले तीन बार की गई पूछताछ की ट्रांस्क्रिप्ट मुहैया कराने की मांग की। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह बारी आने पर हर बात का जवाब देंगे। वह चिदंबरम की पिछले साल 19 दिसंबर, इस साल एक जनवरी और 21 जनवरी की ईडी पूछताछ की ट्रांस्क्रिप्ट मांगने संबंधी याचिका पर बुधवार को जवाब देंगे।

मंगलवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस आर. भानुमति और एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष चिदंबरम को ईडी मामले में अग्रिम जमानत देने की मांग करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का याचिका खारिज करने का आदेश ठीक नहीं है। सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने गंभीर अपराध का विशेषण जोड़ा है। किसी अपराध की गंभीरता उसमें तय सजा से देखी जाती है। किसी मामले में जमानत मिलनी चाहिए या नहीं यह सिर्फ तीन चीजों से तय होता है। आरोपित साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करे, जांच में सहयोग दे और भागे नहीं। इस मामले में वह जांच में पूरा सहयोग दे रहे हैं। 11 साल पुराने केस में वह क्या छेड़छाड़ करेंगे। 2014 तक तो वह सत्ता में रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि चिदंबरम पिता-पुत्र पर एक ही लेनदेन के लिए समान आरोप लगाए गए हैं।

पूर्व वित्त मंत्री ने ईडी के आरोप नकारे, कहा-कर चुके हैं हर संपत्ति की घोषणा

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में ईडी के उन आरोपों को पूरी तरह नकार दिया कि उनके पास विदेश में कीमती संपत्तियां और 12 बैंक खाते हैं। चिदंबरम ने कहा कि वह अपनी हर संपत्ति की घोषणा कर चुके हैं। पीठ के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में चिदंबरम ने कहा है कि उनकी विदेश में न तो कोई संपत्ति है और न ही कोई खाता है। जबकि ईडी ने उनकी विदेश में 10 संपत्तियां और 17 बैंक खाते होने का आरोप लगाया है।

खनन कारोबारी रेड्डी को जमानत देने के लिए 40 करोड़ का मिला था प्रस्ताव

हैदराबाद, प्रेट्र : खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी से जुड़े चर्चित 'कैश फॉर बेल' मामले में गवाह के तौर पर पेश हुए सीबीआइ के पूर्व विशेष न्यायाधीश बी नागा मारुति सरमा ने बड़ा दावा किया है। सोमवार को एसीबी कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जस्टिस सरमा ने कहा कि 2012 में उन्हें रेड्डी को जमानत देने के लिए 40 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। बता दें कि पूर्व न्यायाधीश नगा मारुति सरमा 2012 में सीबीआइ मामलों के विशेष न्यायाधीश थे और रेड्डी से जुड़े कथित अवैध खनन से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे थे।

सरमा ने सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कोर्ट के सामने दावा किया कि रेड्डी को जमानत देने के लिए एक अन्य न्यायिक अधिकारी के माध्यम से रिश्वत की पेशकश की गई थी। यह मामला वर्तमान में शहर की एसीबी अदालत में चल रहा है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। इस मामले में 2012 से जेल में बंद रेड्डी ने सीबीआइ अदालत से जमानत मांगी थी। इससे पहले सरमा ने दावा किया था कि उन्होंने न्यायिक अधिकारी द्वारा की गई पेशकश को अस्वीकार कर दिया था। यह प्रस्ताव कथित तौर पर तब दिया गया था जब सरमा ने अपने से वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को फोन किया था और बाद में वह उनसे मिले थे। रेड्डी को एक दूसरे जज ने जमानत दे दी थी, जिसकी सीबीआइ ने एसीबी से शिकायत की थी। 2012 के इस सनसनीखेज मामले में दो जजों को निलंबित किया जा चुका है।

न कभी बाबर अयोध्या गया और न ही उसने वहां मस्जिद बनवाई

रखा पक्ष ▶ जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने कहा, मीर बाकी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ

मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश किए जा रहे तीनों शिलालेखों को संदिग्ध बताया

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने मंगलवार को कहा कि न तो कभी बाबर अयोध्या आया था और न ही उसने वहां मस्जिद बनवाई थी। यहां तक कि मीर बाकी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। जन्मस्थान पर मंदिर था और मंदिर है। इतना ही नहीं मुस्लिम पक्ष जिन शिलालेखों का सहारा लेकर वहां बाबर द्वारा मस्जिद बनाए जाने का दावा कर रहा है उन तीनों शिलालेखों में अंतर और विरोधाभास है। उनकी सत्यता पर संदेह है और इसीलिए हाई कोर्ट ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। बहस बुधवार को भी जारी रहेगी।

समिति की ओर से पेश वकील पीएन मिश्रा और उनकी सहयोगी रंजना अग्निहोत्री ने मुस्लिम पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुकदमे का विरोध करते हुए कहा कि जानकारी में आने से पहले से जन्मस्थान पर मंदिर था और वहां हिंदू पूजा करते थे। बाबर कभी अयोध्या नहीं आया न ही उसने वहां मस्जिद बनवाई। जब बाबर अयोध्या गया ही नहीं तो फिर वह मस्जिद बनवाकर उसे अल्लाह को कैसे समर्पित कर सकता था? बाबरनामा में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है।

इस दलील पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बाबरनामा में दो दिन के पेज नहीं हैं। मिश्रा ने यह भी कहा कि मीर बाकी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था (मुस्लिम पक्ष की दलील है कि बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बादशाह के आदेश पर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनवाई थी)। जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पक्ष के मुकदमे में प्रतिवादी है।

तीन गुंबद वाले विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं कहा जा सकता : मिश्रा ने कहा कि तीन गुंबद वाले विवादित ढांचे को

मस्जिद नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें मस्जिद की विशेषताएं नहीं थीं। मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद के दावे के पक्ष में दिए जा रहे तीनों शिलालेख फर्जी हैं और उनकी यह दलील हाई कोर्ट ने स्वीकार की है। हाई कोर्ट ने कहा था कि शिलालेखों में अंतर है इसलिए ये स्वीकार नहीं किए जा सकते।

इस पर जस्टिस एसए बोबडे ने पूछा कि ये शिलालेख कहां पाए गए। मिश्रा ने कहा कि एक भी शिलालेख दीवार में लगा नहीं पाया गया। तीनों किसी को किसी से मिले थे या किसी ने देखे थे और उन्हें उसके बारे में बताया। वास्तविक शिलालेख नहीं मिले हैं। इसके अलावा मस्जिद निर्माण की तिथि भी अलग-अलग बताई जा रही है। कुछ जगह तो तारीख बाबर के भारत आने के पहले की है। उन्होंने वक्फ बनाने और उसे अल्लाह को समर्पित करने की प्रक्रिया भी बताई।

मिश्रा ने राम जन्मभूमि का पुराना नक्शा पेश कर बहस की शुरुआत की। नक्शे में जन्मस्थान सहित सारा ब्योरा दिया गया है। उन्होंने फैजाबाद के कलेक्टर एडवर्ड के अयोध्या में किए गए शोध और तीर्थ विवेचनी सभा बनाए जाने का ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि 1902 में एडवर्ड ने पूरी अयोध्या में स्थानों को चिह्नित कर कुल 158 खंबे लगवाए थे। एक खंबा जन्मस्थान पर भी लगा हुआ है। मिश्रा ने कहा कि वह खंबा उसी जगह लगा है जिसे स्कंद पुराण में राम जन्मस्थान बताया गया है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का भी हवाला दिया। नीदरलैंड के शोधकर्ता हेन्स बेकर की किताब अयोध्या का भी जिक्र किया जिसमें अयोध्या का नक्शा दिया गया है। हालांकि नक्शे में दिशाओं को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कुछ आपत्तियां उठाईं तो कोर्ट ने कहा कि जब उनकी बारी आए तो वह इस पर स्थिति स्पष्ट करें।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज पोर्टलों को पीत पत्रकारिता पर किया आगाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- न्यूज पोर्टल द वायर ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका
- जय शाह के खिलाफ खबर को लेकर चलेगा मानहानि का मुकदमा

गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के खिलाफ आपत्तिजनक खबर जारी करने वाले न्यूज पोर्टल, द वायर के संपादक और पत्रकार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलेगा। मानहानि मामला निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका आरोपितों ने वापस ले ली है। खबर जारी करने के तरीके पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को 'पीत पत्रकारिता' से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मीडिया को स्वतंत्रता है लेकिन यह इकतरफा नहीं होना चाहिए।

लगभग डेढ़ साल तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने के बाद मानहानि के केस को निरस्त करने वाली याचिका को जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने वापस लेने की अनुमति तो दे दी, लेकिन तीखी नाराजगी जताने से नहीं चूकी। पीठ में जस्टिस बीआर शाह और जस्टिस एमआर गवई भी शामिल थे। जय शाह को स्पष्टीकरण के लिए केवल चार-पांच घंटे का समय देने और बिना स्पष्टीकरण के ही खबर जारी करने पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने पूछा कि यह किस तरह की पत्रकारिता है। न्यायपालिका के बारे में कुछ न्यूज पोर्टल पर जारी होने वाली खबरों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे हम भी पीड़ित रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। लेकिन अंततः याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी।

सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण के लिए केवल चार-पांच घंटे का समय दिए जाने पर बार-बार आपत्ति जताता रहा। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल और सालिसिटर जनरल के बीच तीखी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की पत्रकारिता संस्थाओं का बहुत ज्यादा नुकसान कर चुकी है।

गौरतलब है कि वायर ने 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले जय शाह की एक कंपनी में कई गुना ज्यादा लेन-देन की खबर प्रकाशित की थी। खबर को इस तरह पेश किया गया था कि जय शाह की कंपनी को अनुचित लाभ मिला हो। जय शाह ने खबर छापने वाले न्यूज पोर्टल, उसके संस्थापक संपादकों, प्रबंध संपादक, लोक संपादक, खबर लिखने वाली पत्रकार के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। शुरुआती सुनवाई में आरोपों को सही पाते हुए केस चलाने का फैसला लिया था। लेकिन इससे बचने के लिए आरोपितों ने हाई कोर्ट से केस को रद की गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट ने मानहानि के आरोपों को सही मानते हुए केस चलाने की इजाजत दे दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

गंगा से लगे सभी क्षेत्रों के लिए उचित पर्यटन नीति बने : एनजीटी

- एसटीपी तय समय में न लगाने पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल पर लग सकता है हर माह पांच लाख का जुर्माना
- जिन राज्यों में काम शुरू नहीं होगा, उन्हें हरेक एसटीपी के बदले एक जनवरी, 2021 से हर माह चुकाने होंगे दस लाख

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) का कहना है कि गंगा नदी से लगे हुए सभी क्षेत्रों के लिए एक उचित पर्यटन नीति विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि इन स्थानों पर यातायात नियमित हो सके। साथ ही ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण की जरूरत है।

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने मंगलवार को कहा कि तय समयसीमा में गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवरेज नेटवर्क में देरी पर हर महीने प्रत्येक एसटीपी पर राज्यों को दस लाख रुपये की लागत आएगी। एनजीटी के अनुसार तय समयसीमा में हालात में सुधार कर पाने में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल विफल रहे हैं। इसलिए अब इन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर महीने पांच लाख रुपये मुआवजा देना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क तय समयसीमा में स्थापित न कर पाने पर राज्यों पर प्रति माह हरेक एसटीपी और उसके संजाल के हिसाब से दस लाख रुपये वसूले जा सकते हैं। राज्यों को यह छूट होगी कि वह हर्जाने की यह रकम देरी करने वाले अधिकारी या ठेकेदार से वसूल करें। एनजीटी के अनुसार जिन सेक्टरों में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क का काम शुरू भी नहीं हुआ है, उन पर 31 दिसंबर, 2020 के बाद से 10 लाख रुपये प्रति माह का पर्यावरण मुआवजा वसूल किया जाएगा। स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय अभियान में भी विफलता पर 50 फीसद राशि चुकानी होगी।

एनजीटी फाइल फोटो

एनजीटी ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वह ई-मेल के जरिए 30 नवंबर तक तिमाही प्रगति रिपोर्ट सौंपें। नमामि गंगे के महानिदेशक को अगली तारीख तक ई-मेल से नमामि गंगे कार्यक्रम पर एक समग्र रिपोर्ट देनी होगी। आगामी एक नवंबर से नदी के जैविक उपचार समेत कई कदम उठाए जाएंगे।

कांग्रेस ने मोदी के प्रशंसक अपनों से किया जवाब-तलब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस ने सकारात्मक सियासत की पैरोकारी का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने वाले जयराम रमेश, शशि थरूर और अभिषेक मनु सिंघवी सरीखे अपने नेताओं को नसीहत दी है। कांग्रेस ने कहा कि सकारात्मक सियासत की बात करने वालों को इस पर भी गौर कर लेना चाहिए कि कैसे पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जैसी नेताओं की छवि खराब करने का भाजपा नेतृत्व की ओर से प्रयास हो रहा है।

पीएम मोदी की प्रशंसा करने की वजह से केरल कांग्रेस की ओर से शशि थरूर को नोटिस जारी किए जाने के सवाल का जवाब देने के क्रम में पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने अपने नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि केरल प्रदेश कांग्रेस को अपने नेताओं से पूछने और नोटिस देने का अधिकार है मगर इस पर कोई टिप्पणी प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक ही करेंगे। हालांकि सकारात्मक राजनीति की बात करने वालों से यह सवाल जरूर करेंगे कि जब प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष समेत उसका पूरा नेतृत्व पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी जैसे हमारे नेताओं पर लगातार आपत्तिजनक और घृणा पैदा करने वाली टिप्पणी करता रहता है तो क्या यह सकारात्मक सियासत है। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी ऐसे कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए यही सवाल दागे थे।

अगले दस साल में 50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि बनेगी उपजाऊ : जावडेकर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मरुस्थलीकरण पर दुनिया के जमावड़े से पहले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण वन एवं पर्यावरण मंत्री ने किया बड़ा एलान
- दो से 13 सितंबर के बीच होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगे 196 देशों के प्रतिनिधि

बढ़ते मरुस्थलीकरण को लेकर दिल्ली में दो सितंबर से होने वाले जमावड़े से पहले भारत ने बड़ा एलान किया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि अगले दस सालों में पचास लाख हेक्टेयर बेकार या बंजर पड़ी भूमि को उपजाऊ बनाया जाएगा। साथ ही मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में एक उत्कृष्ट सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। जो इससे जुड़े सभी उपायों को लेकर काम करेगा। साथ ही विशेषज्ञ और तकनीकी मदद भी देगा।

केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में मरुस्थीलकरण को लेकर 02 से 13 सितंबर तक होने वाले सम्मेलन की जानकारी दी। कॉप-14 के नाम से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के करीब 196 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें करीब 100 देशों के मंत्री भी शामिल होंगे। फिलहाल यह सभी नौ और दस सितंबर को मंत्रियों के सम्मेलन सत्र में हिस्सा लेंगे। इस सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। इस दौरान नौ सितंबर को एक घोषणा पत्र भी जारी होगा, जिसे दिल्ली घोषणा-पत्र के नाम से जाना जाएगा। यह सम्मेलन ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया गया है। बढ़ते मरुस्थलीकरण को लेकर दुनिया की यह चिंता 1992 में ब्राजील के रियो में जलवायु परिवर्तन को लेकर आयोजित सम्मेलन में सामने आयी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इससे निपटने के लिए एक संगठन का गठन किया। इसका भारत शुरू से ही सदस्य है। इस बार इस कार्यक्रम की मेजबानी भारत के पास है, जबकि इससे पहले इस सम्मेलन की मेजबानी चीन ने की थी।

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन की 14वीं बैठक में विचार रखते केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर। साथ में पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रीयो। जागरण

जमीन के उपजाऊ होने से पैदा होंगी 75 लाख नई नौकरियां

केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 50 लाख हेक्टेयर बेकार और बंजर भूमि के उपजाऊ बनने से देश में करीब 75 लाख नई नौकरियां भी पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि एक अध्ययन के मुताबिक एक हेक्टेयर बंजर जमीन के उपजाऊ बनाने से डेढ़ नई नौकरियां पैदा होती हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया मरुस्थलीकरण की इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में पूरी दुनिया में मौजूदा भूमि का करीब एक तिहाई हिस्सा मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। भारत में करीब 960 लाख हेक्टेयर भूमि इससे प्रभावित है। एक अन्य सवाल के जवाब में जावडेकर ने बताया कि भूमि के बंजर या बेकार होने के कई कारण हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन सहित ज्यादा खाद के इस्तेमाल व बाढ़ जैसी कई वजहें हैं।

एएसआइ संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण की मंजूरी लेना होगा आसान

नई दिल्ली, प्रेट्र : छह राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआइ) के संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में निर्माण की मंजूरी लेने की प्रक्रिया अब आसान होगी। ऐसा इन राज्यों के 517 स्थानीय निकायों द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से संभव हो सकेगा।

एक बयान में कहा गया है कि संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने मंगलवार को छह राज्यों में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के लिए एकीकृत एनओसी ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की शुरुआत की। बयान में कहा गया है कि संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में निर्माण-संबंधी कार्यों को स्वतः मंजूरी देने की प्रक्रिया के लिए एनएमए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनओओएस) नाम से एक वेब आधारित साफ्टवेयर एप्लिकेशन डिजाइन किया गया था और इसे सितंबर 2015 में लांच किया गया था। फिलहाल यह एप्लिकेशन दिल्ली के पांच शहरी स्थानीय निकायों और मुंबई के एक निकाय तक सीमित था। अब इसका दायरा बढ़ाकर छह राज्यों तक कर दिया गया है। इनमें मध्य प्रदेश (378), आंध्र प्रदेश (110), हरियाणा (15), झारखंड (3) और तेलंगाना (1) शामिल हैं।

पटेल ने कहा, 'यह प्रक्रिया स्मारकों को प्रभावित करती है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि संरक्षित स्मारकों के आसपास आवासीय वृद्धि को ठीक से विनियमित किया जाए। स्मारकों के संरक्षण और विकास की आवश्यकताओं को संतुलित करना आवश्यक है।' इस पोर्टल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के 'स्मारक' मोबाइल एप के साथ एकीकृत किया गया है। इससे लोगों को आसानी होगी।

कह के रहेंगे माधव जोशी

तैयारी

आइआरसीटीसी के नियंत्रण में संचालित होंगी दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल तेजस ट्रेन, दोनों ट्रेनें शताब्दी जैसी होंगी

विमान से 50 फीसद कम होगा दो तेजस ट्रेनों में किराया

नई दिल्ली, प्रेट्र : रेलवे की खानपान एवं पर्यटन इकाई आइआरसीटीसी के नियंत्रण में संचालित होने वाली दो तेजस ट्रेनों का किराया उसी मार्ग के विमान भाड़े से 50 फीसद कम होगा। आइआरसीटीसी को दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस का किराया तय करने में लचीला रवैया अपनाने को कहा गया है। खास बात यह है कि इन दोनों ट्रेनों में कोटा अथवा रियायत की कोई सुविधा नहीं होगी। हालांकि, यह पहली ऐसी ट्रेनें होंगी, जिनके यात्रियों को निजी कंपनी का 50 लाख रुपये का यात्रा बीमा का प्रस्ताव दिया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, भीड़भाड़ वाले मौसम में डायनेमिक प्राइसिंग यानी घटती सीटों के साथ बढ़ते किराये की व्यवस्था के बावजूद दोनों ट्रेनों का किराया विमान से कम होगा।' उन्होंने बताया कि दोनों ट्रेनें शताब्दी जैसी होंगी। हालांकि, इन ट्रेनों में कोटा या रियायत की कोई व्यवस्था नहीं होगी। रेलवे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग, बीमार और अवार्ड विजेताओं समेत 53 श्रेणी के लोगों को यात्रा किराये में रियायत देता है। इन ट्रेनों में पांच साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी पूरा किराया देना होगा।

उल्लेखनीय है कि सरकार के 100 दिनों के एजेंडे में रेलवे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की यात्री सेवा मुहैया कराने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों का कहना है कि दो तेजस ट्रेनों को आइआरसीटीसी को सौंपने की कवायद निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में पहला कदम है। इसके सफल रहने के बाद भविष्य में कई अन्य ट्रेनों में भी इस तरह का प्रयोग किया जाएगा।

- दिल्ली-लखनऊ व अहमदाबाद-मुंबई तेजस ट्रेनों में नहीं लागू होगा कोई कोटा, रियायत
- यह पहली ट्रेन होगी जिसके यात्रियों को निजी कंपनी का 50 लाख का यात्रा बीमा का प्रस्ताव मिलेगा

तेजस एक्सप्रेस फाइल फोटो

दिल्ली-लखनऊ तेजस ट्रेन अक्टूबर से, आइआरसीटीसी कर्मी करेंगे टिकट जांच

सूत्रों के अनुसार, रेलवे व आइआरसीटीसी के बीच अभी समझौते पर हस्ताक्षर होना बाकी है। इसके बाद रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। उम्मीद है कि दिल्ली-लखनऊ तेजस ट्रेन का परिचालन अक्टूबर तथा दूसरी ट्रेन का परिचालन नवंबर से शुरू होगा। इनमें एलईडी टीवी, कॉल बटन, स्वचालित दरवाजे व सीसीटीवी कैमरे आदि लगे होंगे। ये रेलवे की ऐसी पहली ट्रेनें होंगी, जिनमें टिकट की जांच रेलवे स्टाफ के बजाय आइआरसीटीसी के कर्मचारी करेंगे।

IAS GS World PCS
Committed To Excellence
You Deserve the Best
सामान्य अध्ययन
नया फाउंडेशन बैच प्रारंभ
निःशुल्क कार्यशाला
30th अगस्त 6:30 PM
011-27658013, 7042772062/63

27.66 फीसद की कमी दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में डकैती की वारदात में। वर्ष 2018 में जहां डकैती के 94 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2019 में 31 जुलाई तक इसके 68 मामले सामने आए।

शत्रुघ्न ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ

जेएनएन, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने को लेकर कांग्रेस में उथल-पुथल जारी है, लेकिन भाजपा से कांग्रेस में आए शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ही महीने में दूसरी बार मोदी की तारीफ की है। उन्होंने मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर ट्वीट किया, 'तेरा जादू चल गया।'

अभिनेता से नेता बने 73 वर्षीय शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को ट्वीट किया, 'फ्रांस में जी-7 में द्विपक्षीय बातचीत को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। हम सभी सांस रोक कर इस मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। आपका अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तालमेल और केमिस्ट्री बहुत बढ़िया थी। यह बात सभी को बहुत स्पष्ट हो गई।'

आपका करिश्मा और कूटनीति गजब कर गई : तीन दशक तक भाजपा में रह कर सालों में कभी मोदी की तारीफ न करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे ट्वीट किया, 'राष्ट्रपति ट्रंप के जादू के साथ आपका करिश्मा और कूटनीति गजब कर गई। इससे आगे भी दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। भले ही वह फिल्म न चली हो, लेकिन तेरा जादू चल गया। दीर्घायु हों भारत-अमेरिकी संबंध, दीर्घायु हों ट्रंप-मोदी।'

शत्रुघ्न सिन्हा फाइल

- ट्रंप-मोदी मुलाकात पर किया ट्वीट-तेरा जादू चल गया
- लिखा-अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया थी

नरेंद्र मोदी फाइल

15 अगस्त के भाषण की भी प्रशंसा की थी

इससे पहले, शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त के भाषण की प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया था, 'बेहद साहसी, अच्छा शोध और विचारोत्तेजक'। उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख समस्याओं को बेहतरीन तरीके से बताया है।

पहले निशाने पर रहते थे

भाजपा में रहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा मोदी के आलोचक रहे और समय-समय पर उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहते थे। उन्होंने भाजपा को वन मैन शो, टू मैन आर्मी करार दिया था। इसके बाद 'शॉटगन' इसी साल अप्रैल में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस साल आम चुनाव में वह कांग्रेस के टिकट पर अपनी परंपरागत सीट पटना साहिब से चुनाव लड़े और हार गए। उन्हें हराने वाले भाजपा में उनके पुराने साथी रविशंकर प्रसाद थे, लेकिन अब मोदी की तारीफों से शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस के रुख के खिलाफ जाने का काम किया है। चूंकि कांग्रेस लगातार मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध कर रही है।

मॉब लिंचिंग रोकने को विस में विधेयक लाएगी बंगाल सरकार

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल में मॉब लिंचिंग (उन्मादी भीड़ की हिंसा) की घटनाओं पर रोक लगाने को ममता सरकार विधानसभा के चालू सत्र में ही विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसे बुधवार या शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य कमजोर लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या की घटनाओं को रोकना है। इसमें अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रस्ताव किया गया है।

यह होगा विधेयक में : हमला कर घायल करने के लिए विधेयक में तीन साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान होगा। मौत के मामले में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कठोर आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट कर चुका है टिप्पणी : हाल में देश के विभिन्न इलाकों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। बंगाल भी इससे अछूता नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल राज्य सरकारों को ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा था।

झारखंड में भाजपा की झोली में गिर सकते हैं कुछ कांग्रेस विधायक

प्रदीप सिंह, रांची

- तीन विधायकों को लेकर कयास का दौर, जल्द हो सकता है उलटफेर
- विधानसभा चुनाव से पहले जोर पकड़ेगा दलबदल का सिलसिला

राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के प्रति बढ़े आकर्षण का असर स्वाभाविक तौर पर झारखंड में भी दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जहां विपक्षी दलों के हौसले पस्त हैं, वहीं मौका पाकर कुछ कांग्रेस विधायक बेहतर संभावनाओं के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम सकते हैं। राजनीतिक गलियारे में इस बाबत कयास का दौर चरम पर है। बताते हैं कि कांग्रेस के तीन विधायक सुखदेव भगत (लोहरदगा), मनोज कुमार यादव (बरही) और बादल (जरमुंडी) पाला बदल सकते हैं। ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस को झारखंड में जोर का झटका लगेगा।

सुखदेव भगत तेजतर्रार नेता हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने खुद को साबित किया है। वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं और उनकी पत्नी लोहरदगा नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं। भाजपा के लिए वह मुफीद हो सकते हैं। बरही के विधायक मनोज कुमार यादव भी कद्दावर नेता हैं। वह कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं। बरही से उन्होंने जीत का सिलसिला भी कमोवेश बनाए रखा है। वह दल में अपनी उपेक्षा से नाराज बताए जाते हैं। जरमुंडी के विधायक बादल की छवि साफ-सुथरी है। इसी बल पर उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव जीता था। तीनों विधायकों ने अगर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया, तो इससे बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल मचेगा और विधानसभा स्तर पर भी नए समीकरण तैयार होंगे। फिलहाल भाजपा के उच्चपदस्थ सूत्र इन विधायकों के संपर्क में बताए जाते हैं। उनकी हरी झंडी मिलते ही इस बाबत प्रक्रिया में तेजी आएगी।

लोकसभा चुनाव से पूर्व भी झारखंड में दलबदल का सिलसिला तेज हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया था। भाजपा ने उन्हें कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया और उन्हें जीत भी हासिल हुई। राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। मांडू के विधायक जय प्रकाश भाई पटेल ने भले ही सदस्यता जाने के भय से दल नहीं बदला, लेकिन उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों का खुलकर प्रचार किया। झामुमो ने उन्हें दल से निलंबित कर रखा है।

पलामू की राजनीति में भी उलटफेर : विधानसभा चुनाव के पूर्व पलामू प्रमंडल की राजनीति में भी उलटफेर हो सकता है। भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही इस बाबत खासे सक्रिय हैं। उनकी योजना अपने संगठन नवजवान संघर्ष मोर्चा के विस्तार की है। उन्होंने इस बाबत कुछ मौजूदा विधायकों से संपर्क भी साधा है। बताया जाता है कि पांकी के कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह और लातेहार के झाविमो विधायक प्रकाश राम उनके संपर्क में हैं। प्रकाश राम को फिलहाल झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) ने निलंबित कर रखा है।

न्यूज गैलरी

नया मोटर व्हीकल एक्ट मानने को तैयार नहीं ममता सरकार

कोलकाता : बंगाल की ममता सरकार नया मोटर व्हीकल एक्ट मानने को तैयार नहीं है। परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में यह स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को नए एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में जुर्माना राशि में की गई भारी बढ़ोतरी पर आपत्ति है। केंद्र सरकार एक सितंबर से इसे लागू करने जा रही है। नए कानून के मुताबिक तेज गति से गाड़ी चलाने पर अब 400 की जगह 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,000 के बदले 10,000 रुपये बतौर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। (जासं)

बंगाल भाजपा की उपाध्यक्ष बनीं भारती घोष

कोलकाता : बंगाल में पूर्व आइपीएस अधिकारी भारती घोष एवं लोकसभा चुनाव उम्मीदवार रहीं मफूजा खातून को प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंगलवार को यह घोषणा की। साथ ही रथिन बसु को प्रदेश भाजपा का महासचिव बनाया गया है। मफूजा खातून को प्रदेश कमेटी में स्थान देकर भाजपा ने अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश की है। मफूजा खातून ने इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जंगीपुर सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि, वह जीत नहीं पाईं, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी को अच्छी टक्कर दी थी। चुनावी लड़ाई में मफूजा के पराक्रम से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रभावित था। बताया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मफूजा को भाजपा उम्मीदवारी दे सकती है। मफूजा खातून माकपा की विधायक रह चुकी हैं। (जासं)

जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में बयान दर्ज

मुरादाबाद : रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा पर सपा सांसद डॉ. एसटी हसन की आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री निसार अहमद के बेटे मुस्तफा हुसैन ने मंगलवार को मुरादाबाद के कटघर थाने पहुंचकर बयान दर्ज कराए। कटघर स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में 30 जून को आयोजित कार्यक्रम में जयाप्रदा के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों व अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था। सांसद डॉ. एसटी हसन ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दो जुलाई को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में सांसद आजम खां, मुरादाबाद सांसद डॉ. एसटी हसन, स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम खां, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामपुर अजहर खां, सम्भल के सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खां व सैयद आरिफ हसन समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुरादाबाद सांसद पर सोशल मीडिया पर भाषण वायरल करने का भी आरोप है। बाद में मुकदमा रामपुर से मुरादाबाद ट्रांसफर होकर कटघर थाने आ गया। (जासं)

अब पेड़ चोरी के आरोप में फंसे सांसद आजम खां

बढ़ी मुश्किलें ▶ कत्थे के 2173 पेड़ काटने का लगा आरोप

वन विभाग ने कुलपति को जारी किया नोटिस

जागरण संवाददाता, रामपुर

सपा सांसद आजम खां की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले भू-माफिया, फिर किताब चोरी और अब पेड़ चोरी के आरोप में भी फंस गए हैं। उन पर जौहर यूनिवर्सिटी परिसर स्थित कोसी नदी क्षेत्र की जमीन पर लगे कत्थे के 2173 पेड़ काटने का आरोप है। वन विभाग ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है।

जौहर यूनिवर्सिटी में कोसी तट की पांच हेक्टेयर जमीन है। यह जमीन लीज पर ली गई है। आरोप है कि इस जमीन में कत्थे के 2173 पेड़ लगे थे, जो बिना अनुमति के चोरी से काट लिए गए। यह मामला एनजीटी तक पहुंचा। एनजीटी के आदेश पर टीम ने यहां आकर जांच की तो पाया कि पेड़ गायब हैं। इस पर वन विभाग ने यूनिवर्सिटी के कुलपति को नोटिस जारी किया है। जिला वन अधिकारी एके कश्यप का कहना है कि 2173 पेड़ लगाए गए थे। इसकी पुष्टि लीज पर देने संबंधी आदेश से भी होती है। इन पेड़ों के कटान के संबंध में वन विभाग में कोई रिकार्ड नहीं है। अगर अनुमति नहीं ली गई है तो पेड़ चोरी से काटे गए हैं। यूनिवर्सिटी के कुलपति को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि अगर पेड़ों की लकड़ी बेची गई तो उसके कागजात हैं या नहीं।

आजम खां फाइल

गौरतलब है कि आजम खां पर पिछले दो माह से तमाम आरोप लग रहे हैं। अब तक 50 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि 10 मुकदमे उनके खिलाफ पहले से ही दर्ज हैं। इनमें 30 मुकदमे तो जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के ही दर्ज कराए हैं। इसके बाद प्रशासन उन्हें भू-माफिया भी घोषित कर चुका है। पुलिस जौहर यूनिवर्सिटी पर छापा मारकर तीन हजार किताबें बरामद कर चुकी है। लाइब्रेरी के चार कर्मचारी करीब महीनेभर से जेल में बंद हैं। लाइब्रेरी भी तब से ही बंद है। किताब चोरी के मुकदमे में आजम का नाम भी शामिल कर लिया गया है।

29 मुकदमों में अग्रिम जमानत पर हुई सुनवाई : आजम खां के खिलाफ दर्ज 29 मामलों में अग्रिम जमानत पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई हुई। सांसद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने बहस की। हालांकि जमानत पर कोई फैसला नहीं हो सका। उनकी ओर से दाखिल जिन मामलों में अग्रिम जमानत पर मंगलवार को सुनवाई हुई, उनमें 28 जमीन पर कब्जे से जुड़े हैं। यह जमीन आलियागंज के किसानों की हैं। किसानों का आरोप है कि सपा शासनकाल में मंत्री रहते हुए आजम ने जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया। इसके अलावा एक मुकदमा मदरसा आलिया से किताबें चोरी का है।

सपा नेताओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

लूट के मुकदमों में आरोपित सपा नेताओं को अदालत से झटका लगा है। अदालत ने सपाइयों के 13 अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद उन्हें खारिज कर दिया है। जिन सपा नेताओं के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हुए हैं, उनमें पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, सांसद आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू और रानू खां शामिल हैं। इनके खिलाफ गंज कोतवाली में पिछले दिनों 10 मुकदमे दर्ज हुए थे। ये मुकदमे डूंगरपुर बस्ती के लोगों की ओर से कराए गए थे। आरोप है कि यहां रहने वाले लोगों के घरों को अवैध बताते हुए सपा शासनकाल में बुलडोजर से तुड़वा दिया गया था।

'हमला करें तो पुलिस और तृणमूल कार्यकर्ताओं को पीटें'

- भाजपा सांसद दिलीप घोष ने दिया विवादित बयान

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल भाजपा अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष अपनी आक्रामक टिप्पणियों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। घोष ने पूर्व मेदिनीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उन पर हमला होता है तो वे टीएमसी के लोगों और पुलिस की पिटाई कर दें। घोष ने इस मौके पर कहा, 'मैं उन्हें चेतावनी देता हूं, चाहे वे तृणमूल नेता हों या उनके चमचे पुलिस अधिकारी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मुझे साफ करने दें कि अगर आप पलटवार नहीं करते हैं तो आपको भाजपा कार्यकर्ता नहीं माना जाएगा। चाहे पुलिस हो या टीएमसी के लोग, उनकी पिटाई करो, जमीन पर पटको, मैं इससे निपट लूंगा ...ये मेरी जिम्मेदारी है।' बंगाल की तृणमूल सरकार पर हमला करते हुए घोष यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, पुलिस विपक्षी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लाद रही है। हम बंगाल में ऐसी सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ 28, 000 मामले दर्ज किए गए हैं। हम उनसे लड़ने के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस और टीएमसी काडर की यातना के कारण अपने घरों में नहीं जा पाते। सैकड़ों झूठे मामलों में जेल में बंद हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ भी हत्या का केस दर्ज किया। जिस दिन मैं लोगों को मारना शुरू करूंगा, हम उनकी पूरी पीढ़ी मिटा देंगे। हमने अभी तक किसी को नहीं मारा और हमें 18 सीटें मिलीं।

सीबीआइ ने केस न लौटाए तो पंजाब सरकार दायर करेगी अवमानना याचिका

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में सीबीआइ से केसों को वापस लेने के लिए पंजाब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार के पर्सनल विभाग को साफ तौर पर लिखने जा रहे हैं कि अगर सीबीआइ ने केस नहीं लौटाए तो सरकार सीबीआइ पर अदालत की अवमानना का केस दायर करेगी। उल्लेखनीय है कि सोमवार को सीबीआइ ने विशेष अदालत में कहा है कि वह फिर से केस की जांच करना चाहती है क्योंकि उसे कुछ नए सुबूत मिले हैं। वहीं, सरकार नहीं चाहती कि सीबीआइ अब केस की जांच करे।

बता दें कि इसी मामले में मोगा के पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा के केस में हाई कोर्ट ने विशेष जांच दल (एसआइटी) की जांच को सही बताया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआइ की जांच में कोई प्रगति नहीं हो रही है और जांच मुकम्मल करने के लिए सीबीआइ से केस वापस लेने का फैसला सही है। जनवरी 2019 में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, इसके बावजूद सीबीआइ ने केस नहीं लौटाए। सरकार ने सीबीआइ से केस लौटाने के लिए जो पत्र लिखा था उसके जवाब में केंद्र सरकार के पर्सनल विभाग ने मई में केवल इतना कहा कि यह मामला सीबीआइ डायरेक्टोरेट के साथ टेकअप किया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी प्रगति नहीं हुई।

सीबीआइ ने बीती 24 जुलाई को श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी। इसमें कहा गया कि इस केस की जांच में उसे कोई सुबूत नहीं मिला। पुलिस ने जो भी सुबूत जुटाए थे जांच में वे सही नहीं पाए गए। सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट लेने के लिए पंजाब सरकार भी अदालत में गई, लेकिन उसे कॉपी नहीं मिली।

गृह विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इतने बड़े मामले में जिस तरह सीबीआइ ने क्लोजर रिपोर्ट दी है उससे साफ लगता है कि मामले के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई गई है। सीबीआइ की कार्रवाई पर जिस तरह अंगुलियां उठी हैं उसको देखते हुए ही उसने फिर से जांच करने की बात अदालत में कही है। साथ ही कहा है कि क्लोजर रिपोर्ट पर फिलहाल रोक लगा दी जाए। विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सतीश चंद्रा ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पत्र लिखने संबंधी पूरी फाइल मुख्यमंत्री को भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआइ को बेअदबी मामले में दर्ज तीनों केसों से जुड़ी सभी फाइलें वापस देनी चाहिए ताकि विशेष जांच दल इन सभी केसों की जांच को सिरे चढ़ा सके।

कैप्टन अमरिंदर फाइल

- बेअदबी से जुड़े तीन केसों की फाइलें न लौटाने पर राज्य सरकार हुई सख्त
- मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर लिखेंगे केंद्र सरकार को पत्र

अब गुना सांसद ने महिला कलेक्टर के लिए बोले बिगड़े बोल

नईदुनिया, भोपाल : भाजपा नेताओं के बिगड़े बोल लगातार जारी हैं। भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा के बाद अब गुना से पार्टी के सांसद ने एक महिला कलेक्टर से लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। सांसद डॉ. केपी यादव के अशोकनगर की महिला कलेक्टर के बारे में किए गए भद्दे कमेंट वायरल हो रहे हैं।

दरअसल, सांसद केपी यादव ने ग्राम पंचायतों के परिसीमन के विवाद पर धरना दिया था। जब ज्ञापन लेने अशोकनगर कलेक्टर डॉ. मंजु शर्मा खुद नहीं आईं तो उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के चरण चुंबन के लिए कलेक्टर गांव-गांव पहुंच जाती थीं और उनके ही इशारे पर परिसीमन किया गया है। सारे काम सिंधिया के पीए के कहने पर हो रहे हैं। संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था चौपट हो गई है। यादव की इस बयानबाजी के बाद विवाद और गहरा गया है। हालांकि, अब तक सिंधिया की ओर से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है।

बंगाल में आर्थिक तंगी से जूझ रही माकपा, बेचनी पड़ रहीं गाड़ियां

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- खर्च कम करने पर जोर, लैंडलाइन का इस्तेमाल भी कम करने को कहा गया
- प्रत्येक जिला कमेटी को 12 लाख रुपये पार्टी फंड में जमा कराने का निर्देश

बंगाल में चुनाव-दर-चुनाव सियासी जमीन खो रही माकपा अब आर्थिक तंगी की भी चपेट में आ गई है। दैनिक खर्च चलाने को उसे अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ रही हैं। एक समय था, जब बंगाल माकपा देशभर में अपने संगठनों का खर्च वहन करती थी। वर्तमान में केरल को छोड़कर बाकी सभी जगह माकपा की आर्थिक स्थिति खराब है।

बंगाल में माकपा की आय आधी हो गई है। इसे देखते हुए राज्य पार्टी नेतृत्व ने प्रत्येक जिला कमेटी को अगले साल जनवरी तक 12 लाख रुपये संग्रह कर पार्टी फंड में जमा कराने को कहा है। इसके साथ ही पार्टी का खर्च कम करने का भी सख्त निर्देश दिया गया है। विभिन्न जिलों में गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने को कहा गया है। पार्टी के नाम से जो भी अतिरिक्त गाड़ियां हैं, उन्हें बेच देने को कहा गया है।

कैब का इस्तेमाल करें : माकपा के राज्य नेतृत्व की ओर से निर्देश जारी कर कहा गया है कि अब से सिर्फ पार्टी के जिला सचिव और वरिष्ठ नेताओं को ही गाड़ी का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। बहुत जरुरत पड़ने पर एप कैब का इस्तेमाल करने को कहा गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिलों में माकपा जिला कमेटी के नाम पर क्रमशः छह व चार गाड़ियां हैं। फोन का इस्तेमाल भी कम करने को कहा गया है। अंचल व शाखा कमेटी में टेलीफोन का कनेक्शन काटने को कहा गया है। पार्टी ने कहा है कि अभी सभी के पास मोबाइल है इसलिए लैंडलाइन का कम से कम इस्तेमाल किया जाए।

गैर आदिवासी घोषित किए जाने को कोर्ट में चुनौती देंगे अजीत जोगी

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्रों के लिए गठित हाई पावर कमेटी के फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जोगी को कमेटी ने आदिवासी नहीं माना है। उनका जाति प्रमाण पत्र रद करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से आहत जोगी मंगलवार को मीडिया के सामने आए और कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर नौ अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाषण और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान से मुझे इस तरह का फैसला आने का आभास पहले ही हो गया था। इसी वजह से हमने कोर्ट में रिट लगा रखी है। जोगी ने बताया कि अभी तक मुझे कमेटी के फैसले की कॉपी नहीं मिली है।

राजनीति में आते ही दी गई थी जाति को चुनौती : जोगी ने बताया कि वे जब तक आइएएस अफसर के रूप में नौकरी में थे, उनकी जाति पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। राजनीति में आते ही 1987 में इंदौर हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई। कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आया। इसके बाद दो बार जबलपुर, दो बार बिलासपुर हाई कोर्ट और एक बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन हर बार फैसला मेरे पक्ष में आया।

उन्होंने बताया कि अविभाजित मध्य प्रदेश की भूरिया सरकार और छत्तीसगढ़ की रमन सरकार इस मामले में पहले ही मुंह की खा चुकी है। जोगी ने कहा कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मुझे मरवाही का ही नहीं पूरे देश का मुखिया बनाया था, लेकिन भूपेश बघेल ने नहीं माना। मतलब इससे साफ है भूपेश इनसे सहमत नहीं हैं। गांधी परिवार ने मुझे आदिवासी मानते हुए एआइसीसी के आदिवासी विभाग का अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस छोड़ने तक मैं इस पद पर था।

अजीत जोगी फाइल

- जाति मामले की जांच कर रही कमेटी ने पूर्व सीएम को दिया झटका
- जोगी बोले- हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिट में करेंगे संशोधन

बड़ी उपलब्धि

उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने आइआइपी में प्रायोगिक संयंत्र का किया उद्घाटन, इससे तैयार होगा 850 लीटर डीजल

उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरे से तैयार होने लगा डीजल

राज्य ब्यूरो, देहरादून

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) के देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आइआइपी) ने सालभर के भीतर दूसरी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले वर्ष 27 अगस्त को इसी संस्थान में जेट्रोफा से तैयार बायोजेट फ्यूल से विमान ने देहरादून से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। इस बार इसी दिन मंगलवार को आइआइपी में प्लास्टिक कचरे से डीजल तैयार करने के प्रायोगिक संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक टन की क्षमता वाले इस संयंत्र से 1000 क्विंटल प्लास्टिक कचरे से 850 लीटर डीजल तैयार होगा। छह महीने के भीतर इसकी क्षमता 10 टन बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट को वेल्थ में बदलने वाले इस प्रयोग को बड़े स्तर पर दिल्ली में भी धरातल पर उतारा जाएगा।

आइआइपी परिसर में गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (गेल) के आर्थिक सहयोग से प्लास्टिक कचरे से डीजल तैयार करने का प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया गया है। संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संयंत्र के निरीक्षण के दौरान डीजल तैयार होने की प्रक्रिया को देखा और इसके बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि प्लास्टिक कचरे से मुक्ति की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इस संयंत्र से वेस्ट मटीरियल का डीजल के रूप में सदुपयोग हो सकेगा।

पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर दूसरे देशों पर कम होगी निर्भरता : पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि वर्षों के शोध के बाद आइआइपी अब प्लास्टिक कचरे से बड़े पैमाने पर डीजल के साथ ही अन्य पेट्रो उत्पादों का उत्पादन करने जा रहा है। इससे पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर देश की अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब पूरी दुनिया प्लास्टिक कचरे को लेकर चिंतित है। हमारे वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक वेस्ट को वेल्थ में तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से डीजल का निर्माण आर्थिक रूप से भी बेहतर है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक घरानों से भी वह अपील करेंगे कि प्लास्टिक वेस्ट को वेल्थ में बदलने के मद्देनजर वे आगे आएं और वैज्ञानिक प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लें। उन्होंने इस दिशा में गेल कंपनी के सहयोग की भी सराहना की।

उत्तराखंड के देहरादून में आइआइपी में स्थापित पहली प्रायोगिक यूनिट का उद्घाटन करते केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और आइआइपी के निदेशक अंजन रे। जागरण

अब महिलाओं को एक रुपये में मिलेगा सैनिटरी नैपकिन

- देशभर के 5,500 जन औषधि केंद्रों में होंगे उपलब्ध

नई दिल्ली, प्रेट्र : महिलाओं की हाइजीन समस्या को देखते हुए सरकार अब उन्हें सिर्फ एक रुपये में सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराएगी। इसके लिए सरकार ने मंगलवार से जन औषधि केंद्रों पर बिकने वाले सैनिटरी नैपकिन के मूल्य को घटाकर एक रुपया प्रति पैड कर दिया है। चार के पैक में बिकने वाले 'सुविधा' नाम के ये बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देश भर के 5,500 जन औषधि केंद्रों पर रियायती मूल्यों पर उपलब्ध हैं।

यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा, 'मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देशभर के गरीबों के लिए किए गए कामों में यह सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि 100 दिनों के भीतर देश की गरीब महिलाओं को एक रुपये में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। अब उनका यह आश्वासन हकीकत बन गया है।'

उधर, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार ने आज से एक रुपये में ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लांच कर दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण मोदी सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। मंडाविया ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान जन औषधि केंद्रों से 2.2 करोड़ सैनिटरी नैपकिन बेचे गए। इनकी कीमतों में कमी के चलते इनकी बिक्री कई गुना बढ़ने की उम्मीद है।

सरकार ने इन दुकानों में उपलब्ध जेनेरिक दवाओं के विवरण के साथ-साथ जन औषधि दुकानों का पता लगाने के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल एप लांच किया है। इस एप से लोग जन औषधि केंद्रों का पता लगाने के साथ ही जेनेरिक दवाओं के अधिकतम मूल्यों और ब्रांडेड दवाओं से उनकी तुलना का फायदा उठा सकते हैं।

75 फीसद की सब्सिडी मिलेगी जम्मू-कश्मीर में मेगा फूड पार्क की स्थापना पर सरकार की ओर से। खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि अब कंपनियां घाटी में बड़े खाद्य उद्योगों की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ेंगी।

बढ़ी बौखलाहट ▶ युद्ध का माहौल तैयार कर कश्मीर पर दुनिया का ध्यान खींचना चाहता है नापाक पड़ोसी, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश

पाक को सताई गुलाम कश्मीर की चिंता, तैनात किए कमांडो

सीमापार में बढ़ रही गतिविधियों को लेकर भारतीय सेना अलर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद भारत के साथ तल्ख हुए रिश्ते और कश्मीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ हर ओर से मिली हार ने पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ा दी है। इसी खिसियाहट में वह भारत से जंग शुरू करने का माहौल बना रहा है। वहीं, गुलाम कश्मीर को लेकर भी उसकी चिंता बढ़ गई है। इमरान खान की परमाणु हमले की धमकियों के बीच पाकिस्तान की सेना ने गुलाम कश्मीर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, गुलाम कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने अपने 100 से ज्यादा एसएसजी कमांडो को तैनात किया है। वहीं नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के लिए पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम (बैट) और आतंकी मिलकर भारतीय सेना के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहे हैं।

दरअसल, पाकिस्तान युद्ध का माहौल बनाकर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान कश्मीर पर केंद्रित करना चाहता है, ताकि दूसरे देश भारत-पाक के बीच मध्यस्थता का मार्ग तलाश सकें। यहां तक कि पाकिस्तान ने अपने सभी दूतावासों में एक कश्मीर डेस्क भी गठित किया है, जिससे जम्मू-कश्मीर पर भारत के फैसले के खिलाफ वो अपना राग अलाप सके। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गुलाम कश्मीर में जैश-ए-मुहम्मद के आतंकियों को एसएसजी कमांडो का पूरा समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तानी सेना जैश के आतंकियों का इस्तेमाल कर कश्मीर में बड़ी वारदातों को अंजाम देना चाहती है।

कश्मीर में अस्थिरता फैलाना चाहता है पाक : सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की फिराक में है। पाकिस्तान के सर-क्रीक इलाके में एसएसजी कमांडो की मौजूदगी भारत के शक को और गहरा कर रही है। जिसे लेकर भारतीय सेना और वायुसेना हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि, भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पर पनप रही इस स्थिति पर कुछ भी साफ कहने से बच रही है।

अफगानिस्तान से 100 आतंकी गुलाम कश्मीर भेजे : सूत्र बताते हैं कि हाल ही में अफगानिस्तान से 100 से ज्यादा आतंकियों को गुलाम कश्मीर भेजा जा चुका है। इसके अलावा जैश के करीब 15 आतंकी नियंत्रण रेखा के नजदीक पाकिस्तान की लिपा घाटी में रुककर घुसपैठ की फिराक में हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि घाटी में बर्फ गिरने से पहले पाकिस्तान आतंकियों को कश्मीर में दाखिल करवाना चाहता है।

सीमा पर मसूद का भाई सक्रिय : इसको लेकर मसूद अजहर का भाई इसका प्लान तैयार कर रहा है। जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती रऊफ असगर ने भी कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ के एजेंडे पर 19-20 अगस्त को बहावलपुर स्थित ठिकाने पर अपने टॉप गुर्गों से चर्चा की है। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने कहा कि नियंत्रण रेखा से लगे गुलाम कश्मीर के कोटली, रावलकोट, बाघ और मुजफ्फराबाद में आतंकी शिविर प्रत्यक्ष रूप से पाक सेना के सहयोग से दोबारा सक्रिय हो गए हैं।

भारत में बड़े हमले कराने की कोशिश में पाक

खुफिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन अगले कुछ हफ्तों में भारत के कई शहरों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी क्षमता कम है और क्षेत्र में सुरक्षाबलों द्वारा चलाए जा रहे आतंक रोधी अभियानों के चलते आतंकियों के पास नेतृत्व का भी अभाव है। जिसे देखते हुए भारतीय सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

पूरी तरह से हवाई मार्ग बंद करने पर विचार कर रहा पाक

▶ मंत्री ने कहा, जमीन से भारत-अफगान व्यापार मार्ग पर भी लगेगा प्रतिबंध

इस्लामाबाद, प्रेट्र : अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई मार्ग पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही वह अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए भूमि मार्ग के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। मंगलवार को एक वरिष्ठ मंत्री ने इसके संकेत दिए हैं।

दूसरी ओर पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने मंगलवार को चीन सेना के वरिष्ठ जनरल के साथ जम्मू-कश्मीर में स्थिति पर बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामाबाद की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने भी न्यूयार्क में महासभा की अध्यक्ष मारिया फेर्नांडा एस्पिनोसा से मुलाकात में जम्मू-कश्मीर में स्थिति पर चर्चा की।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भारत के साथ हवाई मार्ग पूरी तरह बंद करने और अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए पाकिस्तान के भूमि मार्ग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के बारे में फैसला लिया गया।

चौधरी ने ट्वीट किया है, 'प्रधानमंत्री भारत के लिए हवाई मार्ग पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में अफगानिस्तान के साथ कारोबार के लिए भारत को मिली भूमि मार्ग की सुविधा के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया गया। इन फैसलों के लिए कानूनी औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है।'

पाकिस्तान ने बालाकोट में जैश-ए-मुहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर भारतीय वायुसेना के हमले के बाद अपना हवाई मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया था। 27 मार्च को नई दिल्ली, बैंकाक और कुआलालंपुर को छोड़ सभी विमानों के लिए उसने अपना हवाई मार्ग खोल दिया था।

15 मई को पाकिस्तान ने हवाई मार्ग पर प्रतिबंध को 30 मई तक बढ़ा दिया था। 16 जुलाई को उसने सभी नागर विमानों के लिए हवाई मार्ग पूरी तरह खोल दिया। अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद से उसने भारत के साथ कारोबार निलंबित कर दिया है और ट्रेन एवं बस सेवा रोक दी है।

बिलावल ने कश्मीर पर विफलता के लिए इमरान की आलोचना की

पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री पूरी तरह विफल रहे। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान की नीति भारत से श्रीनगर कैसे लिया जाए थी, लेकिन अब चिंता इस बात की है कि गुलाम कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद को कैसे बचाया जाए। रावलपिंडी में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल ने मीडिया से कहा कि खान सरकार की अक्षमता के कारण पाकिस्तान ने कश्मीर खो दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जानते थे कि 370 खत्म करना भाजपा के एजेंडे में है लेकिन उन्होंने पहले ही कोई कदम नहीं उठाया।

कश्मीर में आज से खुलेंगे हाई स्कूल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बाद अब प्रशासन ने बुधवार से कश्मीर घाटी में हाई स्कूल खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा 27 और पुलिस थाना क्षेत्रों से दिन की प्रशासनिक पाबंदियां भी हटा ली जाएंगी। संचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अनंतनाग और बारामुला समेत 15 और टेलीफोन एक्सचेंज को बहाल कर दिया गया है।

एसएसपी श्रीनगर हसीब मुगल और स्कूल शिक्षा निदेशक मोहम्मद यूनिस मलिक की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सूचना निदेशक सहरीश असगर ने कहा कि वादी में स्थिति लगभग सामान्य हो चली है। विभिन्न इलाकों से दिन की पाबंदियों को हटाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा निदेशक मोहम्मद यूनिस मलिक ने कहा कि हमने पहले चरण में वादी में 3037 प्राइमरी स्कूल खोले। उसके बाद 774 मिडिल स्कूल भी खोले गए। अब बुधवार से हाई स्कूल भी खोल रहे हैं। यह स्कूल उन्हीं इलाकों में खुलेंगे, जहां दिन को कोई पाबंदियां नहीं हैं और स्थिति पूरी तरह शांत है। सूचना निदेशक सहरीश असगर ने बताया कि स्थिति में लगातार सुधार को देखते हुए पहले ही 69 पुलिस थाना क्षेत्रों से दिन की प्रशासनिक पाबंदियों को हटाया गया है। बुधवार को 27 और थाना क्षेत्रों से प्रशासनिक पाबंदियां हटाई जा रही हैं। इसके साथ ही वादी में दिन की पाबंदियों से मुक्त पुलिस थाना क्षेत्रों की संख्या 96 हो जाएगी। एसएसपी श्रीनगर डॉ. हसीब मुगल ने कहा कि सिर्फ हवल और टोटो ग्राउंड के इलाकों में पथराव की घटनाएं हुई हैं।

कश्मीर में पर्यटन की संभावनाएं तलाशने आएगी केंद्रीय टीम

जागरण संवाददाता, जम्मू

▶ केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री सितंबर के पहले हफ्ते में करेंगे दौरा

▶ पर्यटन मंत्रालय के दो अधिकारी पहले ही पहुंच चुके हैं जम्मू-कश्मीर

केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रह्लाद पटेल पर्यटन की संभावनाएं तलाशने के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे। वह दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल रहे जम्मू-कश्मीर के लिए पर्यटन योजना को अंतिम रूप देंगे। इसमें केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग-अलग योजनाएं होंगी।

पर्यटन मंत्रालय के दो अधिकारी इन योजनाओं की रूपरेखा तय करने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। एडवांस टीम के रूप में काम कर रहे यह दोनों अधिकारी प्रह्लाद पटेल को पर्यटन संभावनाओं की रिपोर्ट पेश करेंगे। नई दिल्ली में पटेल ने कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस दौरे पर नहीं गए तो सितंबर के पहले हफ्ते में टीम लेकर जम्मू कश्मीर जाएंगे। वह पहले लेह जाएंगे और फिर जम्मू-कश्मीर। इस दौरान चिह्नित पर्यटन स्थलों का दौरा करने के साथ ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संभावित कदमों की समीक्षा भी करेंगे। पटेल ने कहा कि टूरिस्ट गाइड को कौशल प्रशिक्षण देना जरूरी है। राज्य के युवाओं को विभिन्न भाषाओं में परिपूर्ण करने की जरूरत है। विभाग अगले दो महीने में इस कार्य को पूरा कर लेगा।

देश की 137 चोटियों को पर्यटकों के लिए खोला गया : प्रह्लाद पटेल ने कहा कि सरकार ने हाल ही में ई-वीजा शुरू करने के साथ देश की 137 चोटियों को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। इसमें से 15 चोटियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हैं, जहां विदेशी पर्यटकों के पहुंचने की काफी संभावनाएं हैं। जिन क्षेत्रों में होटलों की कमी है, वहां पर सरकार लोगों को पर्यटकों के लिए अपने घर खोलने की प्रेरणा देगी। उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण देगी।

लद्दाख के लिए बौद्ध देशों से पर्यटकों को आकर्षित करेगी सरकार : प्रह्लाद पटेल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनौतीपूर्ण खेलों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। लद्दाख के लिए सरकार बौद्ध देशों से पर्यटकों को आकर्षित करेगी। वहीं, किश्तवाड़ जैसे क्षेत्रों में सूफी परंपरा को प्रोत्साहित करने की योजना है। पटेल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर लोगों की राय बदलने की जरूरत है।

जम्मू-कश्मीर में विकास का रोडमैप तैयार करने पर मंथन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच संसाधनों व कर्मचारियों के बंटवारे पर चर्चा

▶ केंद्रीय गृहसचिव ने 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिवों के साथ की बैठक

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हालात सामान्य करना और राज्य के बंटवारे की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में है। इसके लिए केंद्रीय गृहसचिव एके भल्ला ने केंद्र के 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिवों के साथ लंबी बैठक की। इसमें विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू करने के साथ-साथ हालात को जल्द-से-जल्द सामान्य बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई।

गृहमंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार मंगलवार को हुई बैठक में राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं के साथ-साथ राज्य के बंटवारे के बाद केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच संसाधनों और कर्मचारियों के बंटवारे पर विस्तार से चर्चा हुई। गृह सचिव ने दोनों प्रदेशों में जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक बनाने का निर्देश दिया, ताकि ठंड के मौसम में किसी चीज की किल्लत का सामना न करना पड़े।

उनके अनुसार स्थानीय जरूरतों का आकलन करने के लिए केंद्र के विभिन्न विभागों के सचिव व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी राज्य का दौरा कर रहे हैं। बैठक में जम्मू-कश्मीर में 85 केंद्रीय विकास कार्यक्रमों को लागू करने में राज्य सरकार को मदद करने का फैसला किया गया, जिन्हें लागू करने की घोषणा हाल ही में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने की थी।

बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संसद से पारित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के तहत 31 अक्टूबर तक राज्य के बंटवारे और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का काम पूरा होना है। गृह सचिव ने सभी मंत्रालयों को युद्ध स्तर पर अपने-अपने हिस्से का काम पूरा करने को कहा। केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में रणवीर पिनल कोड के कानून समाप्त हो जाएंगे और आइपीसी व सीआरपीसी के कानून लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम पहुंचाने के लिए सभी नागरिकों को आधार कार्ड भी मुहैया कराना होगा। राज्य में नई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना होगा। सरकार का मानना है कि अभी तक विकास से वंचित रह गई कश्मीर की अधिकांश जनता तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाकर हालात को सामान्य बनाने में मदद मिलेगी।

सुधार का खाका खींचने पहुंची अल्पसंख्यक मामलों की टीम

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▶ जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम, बौद्ध और सिख समुदाय है अल्पसंख्यक

▶ राज्य में दो दिन रहेगी टीम, बैठकों का सिलसिला शुरू

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब केंद्र सरकार ने कश्मीर के आर्थिक और सामाजिक विकास का खाका तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की टीम दो दिवसीय कश्मीर दौरे पर पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, बौद्ध और सिख समुदाय शामिल हैं।

केंद्र की छह सदस्यीय यह टीम कश्मीर में नए स्कूल, कॉलेज और कौशल विकास केंद्र खोलने की संभावनाएं तलाशेगी। इसके लिए बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रशासन से केंद्र प्रायोजित योजनाओं को प्रभावी बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा की जा रही है। इस टीम ने श्रीनगर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात कर मंत्रालय द्वारा कश्मीर के विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सचिव शैलेश के नेतृत्व में आई इस टीम में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विकास और वित्त निगम की चेयरमैन निगर फातिमा, प्रबंध निदेशक शाहवाज अली और केंद्रीय वक्फ काउंसिल के सचिव एसएएस नकवी शामिल हैं।

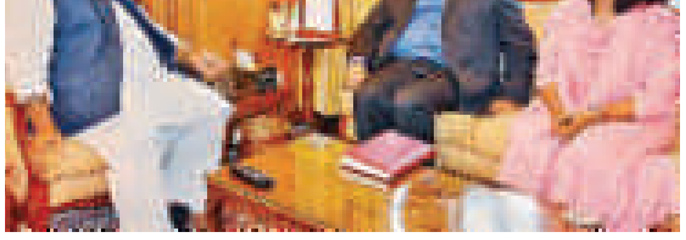

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सचिव शैलेश और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विकास व वित्त निगम की चेयरमैन निगार फातिमा ने मंगलवार को श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। प्रेट्र

विकास प्रोजेक्टों की पहचान होगी : वरिष्ठ अधिकारियों की यह टीम कश्मीर में विकास के प्रोजेक्टों की पहचान करने के साथ ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करेगी, जहां बदले हालात में केंद्र की योजनाओं को प्रभावी बनाया जा सकता है। कश्मीर के बाद यह टीम लद्दाख और जम्मू के दौरे पर भी जाएगी। यह अभियान अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की देखरेख में चलाया जा रहा है। मंत्रालय की पूरी कोशिश है कि कश्मीर के लोगों को हर लिहाज से सशक्त बनाया जाए।

अनु. 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं की आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बुधवार को कई याचिकाओं की सुनवाई करेगा।

इसके अलावा, सर्वोच्च अदालत राज्य में बाधित संचार व्यवस्ता को भी हटाने की मांग वाली याचिकाओं की भी सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में पत्रकारों को अपने दायित्वों का निर्वाह करने में परेशानी का उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में अधिवक्ता एमएल शर्मा, नेशनल कांफ्रेंस के सांसद मुहम्मद अकबर लोन और जस्टिस (सेवानिवृत्त) हस्नैन मसूदी शामिल हैं। इस क्रम में पूर्व आइएएस अफसर शाह फैजल और पूर्व जेएनयू छात्रा शहला रशीद जैसे हस्तियों ने केंद्र सरकार के कदम का विरोध किया है।

एक याचिका माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भी दायर की है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेता मुहम्मद तारीगामी की रिहाई की मांग की है, जिन्हें जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने हिरासत में ले रखा है। बुधवार को अनुच्छेद 370 से जुड़े इन सभी मामलों पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुनवाई होगी।

जम्मू-कश्मीर में दिखने लगा बदलाव

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से उपजे तनाव के बाद फिर से राज्य के हालत सामान्य हो गए हैं। यहां पर एक बार फिर से पर्यटकों का आवागमन बढ़ गया है। मंगलवार को गुलमर्ग में सैर करते पर्यटक। एएनआइ

कश्मीर में आतंकियों ने दो युवकों को मौत के घाट उतारा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर के त्राल में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने खानाबदोश गुज्जर-बक्करवाल समुदाय के दो युवकों को अगवा कर मौत के घाट उतार दिया। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर से पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर घाटी में यह इस तरह की पहली वारदात है।

त्राल के नागपायीन में इन दिनों खानाबदोश गुज्जर-बक्करवाल समुदाय के लोग अपने माल-मवेशियों के साथ डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि गत सोमवार की शाम स्वचालित हथियारों से लैस तीन से चार आतंकी वहां आए। आतंकियों ने पहले खाना खाया और उसके बाद उन्होंने दो युवकों अब्दुल कदीर कोहली और मंजूर अहमद को अगवा कर लिया। वहां मौजूद अन्य लोगों ने जब विरोध किया तो आतंकियों ने कहा कि वह इन दोनों को अपने साथ बतौर गाइड लेकर जा रहे हैं। जल्द ही वह इन्हें छोड़ देंगे, लेकिन आतंकियों ने दोनों को नहीं छोड़ा।

आतंकियों के जाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत निकटवर्ती सुरक्षा शिविर को सूचित किया। इसके बाद पुलिस और सेना के एक संयुक्त कार्यदल ने अभियान छेड़ा। राजौरी निवासी अब्दुल कदीर कोहली का गोलियों से छलनी शव बीती रात ही मिल गया था। वहीं, मंजूर का शव मंगलवार सुबह मिला। मंजूर खनमोह श्रीनगर का रहने वाला है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने त्राल में दो नागरिकों की हत्या की पुष्टि करते हुए बताया कि इसको जैश के आतंकियों ने अंजाम दिया है।

नाका पार्टी पर हमला कर भागा आतंकी गिरफ्तार : उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में श्रीनगर-मुजफ्फराबाद सड़क पर सोमवार रात राज्य पुलिस ने देलिना क्षेत्र के पास नाका लगाया हुआ था। पुलिसकर्मी वहां से गुजर रहे वाहनों को तलाशी ले रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक में सवार आतंकी ने नाका पार्टी पर फायर कर दिया। जवानों ने भी जवाबी फायर किया। इस पर आतंकी निकटवर्ती मोहल्ले की तरफ भागा। नाका पार्टी ने पीछा कर आतंकी को पकड़ लिया। आतंकी से एक असॉल्ट राइफल और एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। गिरफ्तार आतंकी की पहचान मोहम्मद इकबाल नायक उर्फ इबन खतीब के रूप में हुई है। वह बारामुला ओल्ड टाउन की न्यू कॉलोनी में रहने वाला है। इकबाल का संबंध जैश ए मोहम्मद से है। इकबाल इसी वर्ष 31 जुलाई को लापता हो गया था और बाद में आतंकी बन गया।

'देश के खिलाफ लोगों को उकसाने पर फैसल को हिरासत में लिया'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर कैडर के पूर्व आइएएस अधिकारी शाह फैसल की नजरबंदी को लेकर फैसल के मित्र हुसैन द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से श्रीनगर सीकेआर (सेंट्रल कश्मीर रेंज) के डीआइजी ने दिल्ली हाई कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर जवाब दिया है। इसमें कहा गया है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर देश की एकता और अखंडता के खिलाफ देश के लोगों को उकसाने के बाद शाह फैसल को हिरासत में लिया गया था। यही नहीं फैसल के पास कोई छात्र वीजा भी नहीं था, जबकि वह अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाने की बात कर रहे हैं।

शपथपत्र में सरकार ने कहा कि शाह फैसल के खिलाफ जेएंडके पुलिस द्वारा किए गए अनुरोध पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इसके तहत शाह फैसल को हिरासत में लिया गया था। श्रीनगर में शाह फैसल ने टर्मिनल पर लोगों को संबोधित किया था और उन्होंने इस दौरान लोगों को देश की एकता एवं अखंडता के खिलाफ उकसाया था। एयरपोर्ट अधिकारी और पुलिस इसकी गवाह है। यही नहीं फैसल द्वारा दिए जा रहे संबोधन से प्रभावित होकर लोग उग्र हो रहे थे।

आकर्षण

आमिर खान अभिनीत फिल्म की शूटिंग हुई थी यहां, रेंचो दीवार देखने आते हैं पर्यटक, स्कूल प्रबंधन नहीं चाहता है कि बॉलीवुड से जोड़ा जाए उसका नाम

पुरानी पहचान चाहता है 'थ्री इडियट' से मशहूर हुआ स्कूल

राज्य ब्यूरो, जम्मू

फिल्म थ्री इडियट के बाद रेंचो स्कूल के नाम से मशहूर हुआ लद्दाख का ड्रुक पदमा कारपो स्कूल बॉलीवुड से मिली 'पहचान' से पीछा छुड़ाना चाहता है। स्कूल प्रबंधन ही नहीं, अभिभावक और स्थानीय लोग भी चाहते हैं स्कूल को रेंचो स्कूल के नाम से न जाना जाए। स्कूल की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए इसे ड्रुक पदमा कारपो स्कूल नाम से ही जाना जाए। दरअसल, अभिनेता आमिर खान द्वारा अभिनीत फिल्म थ्री इडियट की शूटिंग इस स्कूल में हुई थी। इसके बाद से ही इससे रेंचो नाम जुड़ गया। यहां की रेंचो दीवार को देखने के लिए देखने के लिए देश ही नहीं विश्व भर के लोग पहुंचते हैं।

18 साल पुराने स्कूल का प्रबंधन चाहता है कि स्कूल को बॉलीवुड से नहीं जोड़ा जाए, बल्कि इसे अपनी असली पहचान और मूल्यों के लिए ही जाना जाए। स्कूल की प्रिंसिपल स्टैंजिन कुनजैंग कहती हैं कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि यहां बुद्धिस्ट परंपराओं, सिद्धांतों और विचारधारा को ध्यान रखकर शिक्षा दी जाती है। स्थानीय लोग अब भी स्कूल को ड्रुक पदमा कारपो स्कूल के नाम से ही पुकारते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्कूल बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख में बच्चों को विश्वस्तरीय उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। जनजातीय मूल्यों का भी ध्यान रखा जाता है। प्रिंसिपल की तरह अध्यापक और विद्यार्थी भी यही चाहते हैं कि स्कूल की पहचान ड्रुक पदमा कारपो स्कूल के रूप में ही हो, न कि रेंचो स्कूल से। प्रिंसिपल का कहना है कि हमें इस बात की खुशी है कि थ्री इडियट फिल्म की शूटिंग यहां पर हुई थी, लेकिन पर्यटकों की भारी भीड़ को संभालना मुश्किल था। वे फिल्म में रेंचो वाली दीवार को देखना चाहते थे। फोटो ले रहे थे। पर्यटकों ने हमारे लिए काफी मुश्किलें पैदा कर दी थीं। स्कूल में छात्राएं भी हैं और उनकी सुरक्षा का ख्याल भी रखना है। लोगों को यह समझना चाहिए कि यह स्कूल है।

लद्दाख के लेह जिले में स्थित ड्रुक पदमा कारपो स्कूल के परिसर में 'रेंचो वाल' की तरह बनाई गई दीवार के पास फोटो लेते पर्यटक। प्रेट्र

इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना है। इसलिए पर्यटकों के लिए स्कूल के दूसरी तरफ रेंचो वाल की तरह अन्य दीवार बना दी गई है। वहां पर लिख दिया गया है कि यह प्राइवेट गेट है। स्कूल के वाइस चेयरपर्सन सेरिंग मोटप ने कहा कि हमने पर्यटकों की सुविधाओं के लिए विजिटर सेंटर और रेंचो कैफे बनाया है।

स्कूल के नाम में रेंचो शब्द का जिक्र नहीं : स्कूल के कैंपस को बौद्ध मठ की तरह डिजाइन किया गया है। इसके मुख्य गेट पर रेंचो नाम का कोई शब्द नहीं है। गेट के साइड में लकड़ी के दो बड़े पैनलों पर ड्रुक पदमा कारपो स्कूल लिखा गया है। यह स्कूल बनने के समय ही लिखा गया था। स्कूल के वाइस चेयरपर्सन मोटप ने बताया कि पदमा कारपो मतलब सफेद कमल है। यह बौद्ध धर्म को आत्मसात करने को निरूपित करता है।

आतंकी नहीं अब पुलवामा में तैयार होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर

नवीन नवाज, पुलवामा

आतंकियों की नर्सरी के रूप में कुख्यात पुलवामा अब अपनी छवि बदल रहा है। वह कट्टरवादी आतंकी नहीं अब जान बचाने वाले विशेषज्ञ डाक्टरों की पौध तैयार करने के लिए तैयार हो रहा है। जिला अस्पताल पुलवामा राज्य का एकमात्र ऐसा जिला अस्पताल है, जहां डीएनबी (डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड)के तहत चिकित्सकों के लिए छह विशेषज्ञ स्नातकोत्तर (पीजी) पाठयक्रम शुरू किए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री डायलसिस कार्यक्रम और आयुष्मान योजना के लिए भी यह अस्पताल नजीर पेश कर रहा है।

यहां बता दें कि कश्मीर घाटी में इस समय करीब 280 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से 90 फीसद दक्षिण कश्मीर से ही हैं। दक्षिण कश्मीर से आने वाले आतंकियों में 80 फीसद इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं। बुरहान वानी और जाकिर मूसा जैसे कुख्यात आतंकी भी इसी जिले से थे। 14 फरवरी को पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार जैश-ए-मोहम्मद का आत्मघाती आतंकी आदिल डार भी पुलवामा का ही था। पर अब पुलवामा अपनी छवि बदलने की तैयारी में है।

डीएनबी के तहत छह विशेषज्ञ कोर्स होंगे: जिला अस्पताल पुलवामा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राशिद पारा ने बताया कि जिला अस्पताल पुलवामा में डीएनबी के तहत मेडिसिन, गायनकोलॉजी, सर्जरी, एनेस्थीसिया और पीडियाट्रिक्स समेत छह पीजी पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

अगले तीन सालों में यहां से 45 विशेषज्ञ डॉक्टर निकलेंगे। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला यह अस्पताल राज्य का पहला जिला अस्पताल है। डीएनबी के तहत पीजी कोर्स में दाखिला फीस 2.15 लाख रुपये रखी गई है। जिला अस्पताल पुलवामा फिलहाल 100 बिस्तरों वाला अस्पताल है। अब इसकी क्षमता बढ़ाकर 200 बिस्तर की जा रही है।

19.18 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) परीक्षा 2019 में। 13 दिनों तक देशभर के 337 केंद्रों में हुई परीक्षा। परीक्षा के लिए 38.58 लाख अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 28 अगस्त 2019

बड़ी चुनौती बन चुकी है प्लास्टिक

आज भारत समेत दुनिया के तमाम देश प्लास्टिक के कचरे से परेशान हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से प्लास्टिक के खिलाफ जन आंदोलन का आह्वान किया है। वर्ष 1950 से अबतक वैश्विक स्तर पर 8.3 से 9 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है, जो कचरे के चार से अधिक माउंट एवरेस्ट के बराबर है। अब तक निर्मित कुल प्लास्टिक का लगभग 44 फीसद वर्ष 2000 के बाद बनाया गया है। वहीं भारत में प्रतिदिन 9 हजार एशियाई हाथियों के वजन जितना 25,940 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। फिर भी, भारतीय दुनिया के सबसे कम प्लास्टिक उपभोक्ताओं में शामिल हैं। एक भारतीय एक वर्ष में औसतन 11 किग्रा प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है।

वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन (अरब टन में)

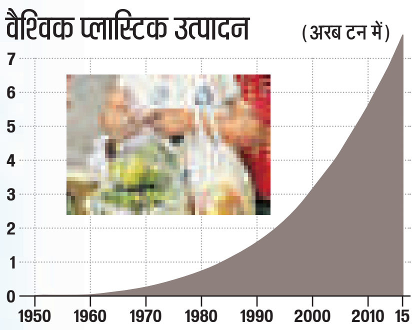

पर्यावरण में मौजूद प्लास्टिक

उत्पादित प्लास्टिक का लगभग 40 फीसद पैकेजिंग के इस्तेमाल में आता है, जिसे एक बार उपयोग किया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। 1950 के बाद से उत्पादित सभी प्लास्टिक का 79 फीसद पर्यावरण में अभी भी मौजूद है।

बेहद हानिकारक

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हर साल लगभग 5 ट्रिलियन प्लास्टिक की थैलियां दुनिया भर में उपयोग की जाती हैं। प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरण, समुद्र और धरती पर रहने वाले जीवों के लिए बेहद हानिकारक हैं। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश 2002 में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश था। कई अफ्रीकी देशों ने अपेक्षाकृत कम अपशिष्ट-संग्रह और रीसाइक्लिंग दरों के लिए जगह बनाई है। अमेरिका ने अभी तक प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, हालांकि उसके कुछ राज्यों ने स्वंय ही थैलियों पर प्रतिबंध लगा रखा है।

प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाले देश

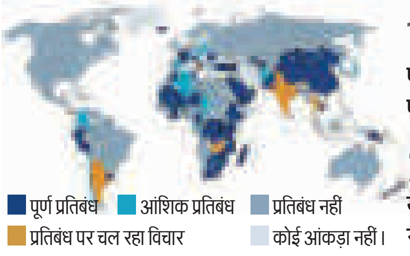

127 देशों ने प्लास्टिक की थैलियों पर लगा रखा है प्रतिबंध।

27 देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा रखा है प्रतिबंध

कचरा घर बना समुद्र

जॉर्जिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के मुताबिक 41 लाख टन से 1.27 करोड़ टन के बीच प्लास्टिक हर साल समुद्र में प्रवेश करता है, जो 2025 तक दोगुना होने की उम्मीद है।

भारत ने छेड़ी जंग

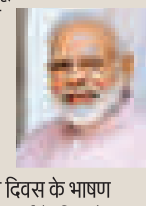

20 अगस्त को भारतीय संसद ने कहा कि वह परिसर में प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगी। 2 अक्टूबर से भारतीय रेलवे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। ये दोनों घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के कुछ दिनों बाद आई हैं, जिसमें उन्होंने नागरिकों से प्लास्टिक के उपयोग को छोड़ने का आग्रह किया था। प्लास्टिक के खिलाफ भारत ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है।

न्यूज गैलरी

वाजपेयी के बंगले में शिफ्ट हुए गृह मंत्री अमित शाह

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को अपने नए निवास में रहने चले गए। उनका नया निवास 6-ए कृष्ण मेनन मार्ग है। यह वही बंगला है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में सत्ता से हटने के बाद 14 साल तक रहे। इससे पहले शाह 11 अकबर रोड पर रहा करते थे। दरअसल, 2004 में एनडीए के सत्ता से हटने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी इस बंगले में रहने गए थे। वे अपने इस बंगले में करीब 14 साल तक रहे। पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद उनके परिवार ने नवंबर में बंगला खाली कर दिया था। बता दें कि जब वाजपेयी कृष्ण मेनन मार्ग के इस बंगले में रहने गए थे, तो इसका म्यूनिसिपल नंबर बदलकर 8 से 6-ए कर दिया गया था। (एएनआइ)

आठ लाख की इनामी महिला नक्सली डिप्टी कमांडर गिरफ्तार

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के कटेकल्याण एरिया में सक्रिय प्लाटून नंबर 26 की डिप्टी कमांडर कोवासी मंगली को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी डिस्ट्रिक रिजर्व गार्ड की महिला कमांडो की टीम ने की। उस पर लाख लाख रुपये का इनाम घोषित है। एसपी डॉ अभिषेक पल्लव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कटेकल्याण थाना टीम, सीआरपीएफ और डीआरजी की महिला कमांडोज ने सुबह ग्राम मेंडोली के पास घेराबंदी कर कोवासी मंगली(27) पुत्री भीमा को जिंदा पकड़ने में सफलता प्राप्त की। (नईदुनिया)

जन अदालत में नक्सलियों ने युवक को पीटकर मार डाला

कांकेर : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में जन अदालत लगाकर एक युवक को ग्रामीणों के सामने डंडे से पीट-पीटकर मार डाला। जानकारी के अनुसार कोयलीबेड़ा थाने के जूंगड़ा में सोमवार रात करीब 30 हथियारबंद नक्सली पहुंचे। नक्सलियों ने श्यामनाथ आंचला (28) को उसके घर से अगवा कर लिया। फिर ग्रामीणों को एकत्र कर जन अदालत लगाई। इस दौरान युवक पर बीएसएफ कैंप के अधिकारियों के पास जाकर मुखबिरी करने का आरोप लगाया। इसके बाद उसकी लाठी-डंडों से पिटाई शुरू की। तब तक पीटा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। (नईदुनिया)

बुलंदशहर हिंसा में छह और आरोपित जमानत पर छूटे

बुलंदशहर : बुलंदशहर में हुई हिंसा में जेल गए आरोपितों के जमानत पर छूटने का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार देर रात भी चार अन्य आरोपित जमानत पर जेल से छूट गए, जबकि एक आरोपित मंगलवार सुबह छूटा। जमानत पर छूटने वाले आरोपितों की संख्या अब 13 हो गई है। बीते वर्ष तीन दिसंबर को महाव गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के विरोध में चिंगरावठी पुलिस चौकी के पास बवाल हो गई थी, जिसमें स्याना कोतवाल सुबोध कुमार सिंह और चिंगरावठी गांव निवासी सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस व एसआइटी 44 आरोपितों को गिरफ्तार कर हिंसा व राजद्रोह की धाराओं में जेल भेज चुकी है। इस प्रकरण में जेल गए आरोपितों को हाईकोर्ट से हिंसा व राजद्रोह की धारा में जमानत मिलनी शुरू हो गई है। जीतू फौजी समेत अब तक 13 लोग जमानत पर छूट चुके हैं। पिछले दो दिनों में पांच लोग छूटे हैं। (जासं)

केरल में झूठी शान के लिए हत्या में 10 को उम्रकैद

फैसला ▶ प्रेम विवाह पर दलित ईसाई युवक की कर दी गई थी हत्या

सभी आरोपितों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

प्रतीकात्मक

कोट्टायम, प्रेट्र : केरल के बहुचर्चित दलित ईसाई युवक हत्याकांड में कोट्टायम की एक अदालत ने मंगलवार को 10 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने 22 अगस्त को कहा था कि केविन पी. जोसफ (23) की हत्या में उसकी पत्नी के रिश्तेदार संलिप्त थे। यह झूठी शान के लिए हत्या थी।

विशेष लोक अभियोजक सीएस अजयन ने यहां संवाददाताओं को बताया कि प्रधान सत्र अदालत के न्यायाधीश सी. जयचंद्रन ने सभी 10 आरोपितों को आइपीसी की धारा 302 (हत्या) व 364ए (फिरौती के लिए अपहरण) के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने सभी को 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये प्रमुख गवाह अनीश सेबस्टियन को तथा बाकी राशि केविन के पिता जोसफ व पत्नी नीनू चाक्को में बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई जुर्माना देने में नाकाम रहता है तो जब्त तीन बाइकों को नीलाम कर उसकी वसूली की जाए। छह आरोपितों को दो अन्य धाराओं में क्रमशः तीन व एक साल की अतिरिक्त सजा तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में कुल 14 आरोपित थे, लेकिन केविन के ससुर चाक्को समेत चार को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था। लोक अभियोजक ने बताया, केविन के साले स्यानू चाक्को समेत सभी 10 आरोपितों को दोहरी उम्रकैद हुई है। उम्रकैद का अर्थ है आखिरी सांस तक कैद या जब तक कि सरकार उन्हें माफ न कर दे। आइएएनएस के अनुसार, केविन के पिता ने अदालत के फैसले पर कहा कि वह कुछ लोगों के लिए मृत्युदंड की अपेक्षा कर रहे थे।

हालांकि, उन्हें संतोष है कि आरोपितों को वह सजा मिली, जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वे नीनू के पिता समेत अन्य चार आरोपितों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

केविन की पत्नी नीनू ने पिता के खिलाफ दी थी गवाही

केविन को उसके रिश्तेदार के साथ मन्नानम से अपहृत किया गया था। केविन का शव 28 मई 2018 को कोल्लम जिले के चालियक्कर नाले में मिला था। केविन के परिजन ने झूठी शान के लिए हत्या का आरोप लगाया था। कोर्ट में केविन की पत्नी नीनू ने बयान दिया था कि उसके पिता चाक्को ने उसकी शादी पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि केविन दलित था।

प्री-वेडिंग शूट में मंगेतर से रिश्वत लेते दिखा दारोगा, हुआ निलंबित

जागरण संवाददाता, जयपुर

▶ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का मामला, वीडियो वायरल

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक इंस्पेक्टर को प्री-वेडिंग शूट (शादी समारोह से पहले की जाने वाली वीडियो ग्राफी) में रिश्वत का दृश्य दर्शाना महंगा पड़ गया है। वीडियो वायरल होने पर अशोक गहलोत सरकार सख्त हो गई। सरकार और पुलिस विभाग का मानना है कि वर्दी में मंगेतर से रिश्वत लेने का दृश्य दिखाए जाने से पुलिस की छवि को धक्का लगा है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के निर्देश पर आरोपित इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों से अपील की है कि वह कोई भी ऐसा काम कभी भी नहीं करें, जिससे विभाग और वर्दी की छवि धूमिल होती हो। उधर, मंगलवार शाम को वीडियो सोशल साइट से हटा दिया गया।

चित्तौड़गढ़ जिले के मंडेतिया पुलिस थाने में तैनात इंस्पेक्टर धनपत ने अपनी मंगेतर किरन के साथ एक प्री-वेडिंग शूट किया। इस वीडियो को उसने सोशल साइट यू-ट्यूब पर अपलोड कर दिया। इसमें इंस्पेक्टर धनपत पुलिस की वर्दी में दिखाई पड़ता है। वीडियो में दिखाया गया है कि वह बिना हेलमेट पहने स्कूटी चलाने पर किरन को रोकते है, लेकिन किरन रिश्वत के तौर पर उनकी जेब में रुपये डाल देती है। लेकिन, जाते-जाते वह धनपत का पर्स निकाल लेती है। धनपत फिर किरन से मिलकर अपना पर्स मांगता है। इस मुलाकात में दोनों के बीच प्यार हो जाता है। इस पूरे वीडियो में हिंदी फिल्म का गाना भी बजता रहता है।

पुलिस महानिदेशक ने मांगी रिपोर्ट : इंस्पेक्टर धनपत ने जैसे ही यह वीडियो यू-ट्यूब में शेयर किया तो मामला सरकार तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव सहित अन्य आलाधिकारियों को बुलाकर बैठक बुलाई । पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में उदयपुर रेंज के महानिरीक्षक एवं चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है । सरकार को लगता है कि यह पुलिस की वर्दी का अपमान है। इसके साथ ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश सरकार एवं पुलिस की छवि को भी नुकसान हुआ है ।

वर्दी की मर्यादा का रखें ध्यान : पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) डॉ. हवा सिंह घुमरिया ने इंस्पेक्टर धनपत का वीडियो सामने आने के बाद सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि वह अपने मातहत पुलिसकर्मियों को वर्दी का गलत इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दें। अधिकारियों से कहा गया है कि वर्दी की मर्यादा बनी रहे, इस पर जरूर ध्यान दें ।

वायरल वीडियो से ली गई तस्वीर।

बिहार, मध्य प्रदेश या ओडिशा में बौद्ध मंदिर उड़ाने की थी साजिश

जागरण संवाददाता, कोलकाता : भारत में जमात उल मुजाहिदीन (जेएमबी) के मुखिया एजाज अहमद ने बिहार, मध्य प्रदेश व ओडिशा में किसी एक बौद्ध मंदिर को उड़ाने की साजिश रची थी। इसके लिए ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया गया था। ये राजफाश कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की पूछताछ में हुआ है। हालांकि कौन सा बौद्ध मंदिर निशाने पर, एसटीएफ ने यह जानकारी नहीं दी है।

उधर, एसटीएफ ने जेएमबी आतंकी को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि बंगाल बर्धमान के खागड़ागढ़ और बौद्ध गया (बिहार) विस्फोट मामले में फरार चल रहे जेएमबी आतंकी एजाज अहमद को एसटीएफ ने बिहार के गया से आइबी और स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था। आतंकी को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाकर पूछताछ की गई तो उसने कई सनसनीखेज राज उगले।

बिहार के गया में बैठकर ही बिहार और झारखंड में जेएमबी के आतंकी माड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी एजाज पर थी। गया के विभिन्न इलाकों में फेरी लगाकर वह जिहाद के नाम पर युवाओं को गुमराह कर आतंकी संगठन में शामिल करता था। वह म्यांमार में बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार किए जाने का हवाला देकर मुस्लिम युवाओं को बदला देने के लिए उकसाता था। सलाउद्दीन सालेहीन समेत संगठन के शीर्ष आतंकियों से संपर्क करने के लिए एजाज सेटेलाइट फोन का इस्तेमाल करता था। वह अपना परिचय कभी एजाज अहमद, डॉक्टर बाबू तो कभी मोहम्मद एजाज के नाम से देता था।

प्रधानमंत्री मोदी बोले, अरुण जी का अच्छा काम अजर-अमर रहेगा

▶ दिल्ली लौटते ही पीएम दिवंगत नेता जेटली के घर जाकर परिजनों से मिले

▶ 25 मिनट की मुलाकात में मित्र को दी श्रद्धांजलि, अमित शाह भी रहे मौजूद

नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 सम्मेलन से स्वदेश लौटते ही अपने मित्र और दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने जेटली के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करके अपने मित्र को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा, 'अरुण जी का अच्छा काम अजर-अमर रहेगा।'

मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री जेटली मोदी पेरिस से नई दिल्ली लौटते ही जेटली के कैलाश कालोनी स्थित आवास पर पहुंचे। वहां उनसे पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेटली के बेटे रोहन के साथ मौजूद थे। पीएम ने जेटली के सभी परिजनों से मुलाकात की और उनकी पत्नी और बच्चों से बात की। मोदी ने दिवंगत भाजपा नेता की फोटो पर फूल भी चढ़ाए। वह वहां करीब 20-25 मिनट रहे। सफेद रंग का कुर्ता पहने मोदी शोक संतृप्त परिवार के साथ कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। काफी देर तक उनके बीच मौन छाया रहा। इस चुप्पी को संक्षिप्त बातचीत से तोड़ा गया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और संगठन के महासचिव बीएल जोशी भी मौजूद रहे। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा, 'नियति ने बहुत जल्दी अरुण जी को हम सब से छीन लिया लेकिन भारत के लिए किया गया उनका अच्छा काम हमेशा अजर-अमर रहेगा।'

66 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का निधन विगत शनिवार को एम्स में इलाज के दौरान हो गया। तीन देशों की यात्रा पर गए मोदी उस समय बहरीन में थे। उन्होंने तत्काल फोन पर जेटली की पत्नी संगीता और बेटे रोहन से बात कर शोक संतृप्त परिवार को ढांढस बंधाया था। बहरीन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भावुक मोदी ने कहा था, 'मैं यह कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि मैं यहां इतनी दूर हूं और मेरा मित्र चला गया है। मैं कर्तव्य से बंधा होकर यहां खड़ा हूं, दूसरी ओर मित्रता की यादें हैं। मेरे दिल में अपार दुख है। हम हर क्षण साथ रहे, साथ संघर्ष किया, एक साथ सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए मिलकर काम किया।'

विदेश दौरे से लौटने के बाद मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के आवास पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। इस दौरान मोदी ने अरुण जेटली की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रेट्र

फिरोज शाह कोटला का नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम होगा

खेल संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने मंगलवार को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अपने पूर्व अध्यक्ष और देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया, जिनका पिछले सप्ताह निधन हो गया था। इस स्टेडियम को अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इसका नया नामकरण 12 सितंबर को एक समारोह में किया जाएगा। इसमें एक स्टैंड का नाम भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम पर भी रखा जाएगा।

डीडीसीए अध्यक्ष रजत शर्मा ने कहा कि जेटली का सहयोग और प्रोत्साहन ही था जिससे विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, आशीष नेहरा, रिषभ पंत और कई अन्य खिलाड़ियों ने भारत को गौरवान्वित किया। जेटली को इस स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने और दर्शक क्षमता बढ़ाने के साथ विश्वस्तरीय ड्रेसिंग रूम बनवाने का श्रेय जाता है।

यह समारोह जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू भी हिस्सा लेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जेटली राजनेता थे, जबकि फिरोज शाह हिन्दुस्तान के मशहूर बादशाह थे। ऐसे में बादशाह के नाम पर जिस इमारत या मैदान का नाम पड़ा है उसे बदलना सही नहीं है।

12 सितंबर को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा कार्यक्रम

मैं डीडीसीए की मैनेजिंग कमेटी के फैसले का स्वागत करता हूं। व्यक्तिगत तौर पर इस फैसले से मुझे खुशी हुई है क्योंकि अरुण जेटली को डीडीसीए प्रशासन में लाने का सौभाग्य मुझे ही मिला था। इस दौरान उनके साथ काफी सालों तक काम करने का मौका मिला।
-सीके खन्ना, कार्यवाहक अध्यक्ष, बीसीसीआइ

जेटली के निधन पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के अलावा वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन, इशांत शर्मा, वीवीएस लक्ष्मण सहित कई दिग्गज क्रिकेटरों और बीसीसीआइ ने पूर्व वित्त मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया था।

जेटली के निधन के बाद बीसीसीआइ ने डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष और बोर्ड उपाध्यक्ष की क्रिकेट प्रशासन में बदलाव लाने के लिए प्रशंसा की थी। बीसीसीआइ की तरफ से कहा गया था कि डीडीसीए के अध्यक्ष के रूप में लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्रिकेट ढांचे में काफी बदलाव किया। वह क्रिकेटरों के हमेशा करीबी मित्र रहे और हमेशा उनके साथ खड़े रहे, उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया और उनका समर्थन किया।

अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए डीडीसीए ने फैसला किया है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। हालांकि मैदान का नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ही रहेगा।
-रजत शर्मा, अध्यक्ष, डीडीसीए

डीडीसीए का यह फैसला जेटली जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने दिल्ली क्रिकेट के लिए काफी कुछ किया। अगर वह नहीं होते तो यह स्टेडियम नए रूप में भी नहीं होता।
-विनोद तिहारा, सचिव, डीडीसीए

अरुण जी नहीं रहे लेकिन हम उन्हें इस बहाने याद करते रहेंगे। उन्होंने दिल्ली क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके जैसे प्रशासक बहुत कम होते हैं।
-दिनेश शर्मा, पूर्व संयुक्त सचिव, डीडीसीए

मैं बहुत खुश हूं वह इसके हकदार थे। उन्होंने दिल्ली को एक विश्वस्तरीय स्टेडियम दिया। उनके नाम पर स्टेडियम का नाम होना अच्छा लेकिन अगर उनके जिंदा रहते ऐसा होता तो और भी अच्छा होता। यह उनको एक बहुत ही अनमोल तोहफा होता।
-गौतम गंभीर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

बोलीं प्रियंका

रेल कोच फैक्ट्री के निगमीकरण का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों के बीच पहुंचीं कांग्रेस महासचिव, यूनियन कर्मियों को सुनने के साथ ही खुद सरकार पर बरसीं

'उद्यमी मित्रों को सारी फैक्ट्रियां दे देगी सरकार'

जितेंद्र शर्मा, रायबरेली

लगातार मुद्दों की तलाश में नजर आ रहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने मंशा साफ कर दी है। वह अपने खानदानी सियासी क्षेत्र रायबरेली को ही सरकार के खिलाफ जंग का बड़ा मैदान बनाना चाहती हैं। यहां रेल कोच फैक्ट्री के निगमीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन में पहुंचीं प्रियंका ने केंद्र सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। दो टूक कहा कि सरकार एक-एक कर सभी फैक्ट्रियां और उपक्रम अपने उद्यमी मित्रों को सौंप देगी।

अपनी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में काफी समय से सक्रिय प्रियंका वाड्रा मंगलवार को यहां अपनेपन का भाव लिए 'बेटी' और 'हमदर्द' बनकर पहुंचीं। सुबह ठीक नौ बजे दिवंगत पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह के पैतृक गांव लालूपुर चौहान पहुंचकर उनकी बेटी विधायक अदिति सिंह व अन्य परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त किया। कुछ समय भुएमऊ गेस्ट हाउस में बिताने के बाद दोपहर तीन बजे लालगंज स्थित रेल कोच फैक्ट्री पहुंचीं। यहां फैक्ट्री के निगमीकरण के खिलाफ दो माह से आंदोलनरत कर्मियों के साथ ही क्षेत्रवासियों से 'खानदानी रिश्ता' मजबूत करने का भरपूर प्रयास किया। एक घंटे तक यूनियन कर्मियों को सुना। फिर खुद सरकार पर बरसीं। उन्होंने कहा कि मेरी मां का राजनीतिक संघर्ष आपको याद होगा। 2006 में इस्तीफा देकर फिर इसी क्षेत्र से सांसद बनीं। 2007 में रेल कोच फैक्ट्री की घोषणा हुई तो प्रदेश सरकार ने जमीन देने से मना कर दिया। आपके ही सहयोग से फैक्ट्री स्थापित कराई। तब उन्हें कितनी खुशी हुई। यह मैं उनकी बेटी होने के नाते जानती हूं। बोलीं कि मां को तब खुशी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हुई कि यहां की जनता को रोजगार मिला। इसके बाद सरकार को घेरते हुए बोलीं, अब यह भाजपा सरकार फायदे में चल रही फैक्ट्री का निगमीकरण कर रही है। फिर निजीकरण करेगी। सरकार की योजना है कि एक-एक कर ऐसी सभी फैक्ट्रियों और सरकारी उपक्रमों को अपने उद्यमी मित्रों को सौंप दिया जाए। सरकार देश में कंपनी राज लाना चाहती है।

चला रायबरेली का दांव : कांग्रेस महासचिव ने सरकार के खिलाफ एक और दांव चला। जनता की ओर सवाल उछाला कि सोचिए, निगमीकरण की शुरुआत रायबरेली से ही क्यों की जा रही है? सरकार के लिए आप नहीं, राजनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आश्वस्त किया कि आप जब भी बुलाएंगे, मैं आऊंगी।

बड़े आंदोलन की भूमिका : प्रियंका वाड्रा ने वादा किया कि इस आंदोलन में पंजाब, तमिलनाडु और बंगाल की रेल कोच फैक्ट्रियों के कर्मचारी भी आपके साथ आएंगे। पूरी कांग्रेस इसके लिए ताकत लगाएगी।

रायबरेली में मंगलवार को आधुनिक रेलकोच कारखाना के बाहर धरना दे रहे कर्मचारियों को संबोधित करतीं प्रियंका गांधी वाड्रा। जागरण

फर्रुखाबाद में बंदियों ने की हवालात में सेंध लगाने की कोशिश

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : पेशी पर न्यायालय आए एक बंदी ने साथी बंदियों के सहयोग से सेशन हवालात में सेंध लगाने की कोशिश की। आरोपित ने किसी नुकीली चीज से एक ईंट निकाल दी। इसी बीच हवालात प्रभारी जायजा लेने अंदर पहुंचे। ईंट निकली देख वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के होश उड़ गए। सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक व सीओ सिटी ने पड़ताल की। इसके बाद हवालात की मरम्मत कराई गई। मंगलवार को जिला जेल से 55 बंदी पेशी पर न्यायालय परिसर स्थित सेशन हवालात में लाए गए। शहर कोतवाली के श्याम नगर निवासी बंदी धर्मेंद्र उर्फ टर्रा ने किसी नुकीली वस्तु से हवालात में सेंध लगाने का प्रयास किया। कुछ बंदियों ने भी उसका सहयोग किया। इसी बीच हवालात प्रभारी मनोज यादव अंदर गए। ईंट निकली देखी तो मामला भांपते देर नहीं लगी। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन सिंह, सीओ सिटी मन्नीलाल गौड़, प्रतिसार निरीक्षक किश्वर अली व फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

ट्रक मालिक और चालक के दोस्त को सीबीआइ ने किया तलब

जागरण संवाददाता, फतेहपुर

उन्नाव के माखी गांव निवासी दुष्कर्म पीड़िता की कार दुर्घटना मामले में सीबीआइ ने ट्रक मालिक के साथ ही चालक के दोस्तों को बुधवार सुबह तलब किया है। फोन कर ट्रक मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मंगलवार को सीबीआइ टीम के जिले में आने की सुगबुगाहट थी, लेकिन वह नहीं आई। पांच अगस्त को सीबीआइ की तीन सदस्यीय टीम ने जेल में बंद ट्रक चालक आशीष पाल के पड़ोसियों से भी पूछताछ की थी। ट्रक मालिक देवेंद्र पाल और उसके भाई प्रसपा नेता नंदू पाल से भी सवाल-जवाब किया था। ट्रक मालिक देवेंद्र को लखनऊ बुलाकर जानकारी लेकर छोड़ दिया गया था, जबकि प्रसपा नेता से आधार कार्ड मंगवाया था। नंदू पाल ने बताया कि सीबीआइ के एक अधिकारी का फोन मंगलवार दोपहर आया था। उन्होंने देवेंद्र को बुलाया और कहा कि ट्रक चालक आशीष के अन्य चालक दोस्तों को लेकर बुधवार सुबह लखनऊ आएं।

उन्नाव दुष्कर्म कांड

पीड़िता की मां के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया हुई पूरी

जासं, नई दिल्ली : उन्नाव कांड से जुड़े दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को तीस हजारी अदालत में पीड़िता की मां के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। पीड़िता के एक चाचा के भी कुछ बयान दर्ज किए गए। बयान दर्ज करने की प्रक्रिया बुधवार को भी जारी रहेगी। इस मामले में विधायक कुलदीप सेंगर मुख्य आरोपित है और उन पर आरोप भी तय हो चुके हैं। इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में होती है और किसी भी गवाह की पहचान और उसका बयान लिखने पर अदालत ने रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्नाव कांड से जुड़े चार मामलों की सुनवाई दिल्ली की तीस हजारी अदालत में चल रही है।

87 पेमेंट एप को उस यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने होस्ट किया है जिसे 3 साल पहले भारतीय बैंकों को जोड़ने और डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया था।

व्यापम की शिकायतों की जांच के लिए तीन एसआइटी गठित

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के चर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले की पुरानी शिकायतों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की तीन एसआइटी का गठन किया गया है। ये एसआइटी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के एसपी एसटीएफ के नेतृत्व में काम करेंगी। इन्हें 60 शिकायतों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है।

विधानसभा में गृह मंत्री द्वारा व्यापम घोटाले की पुरानी शिकायतों की जांच कराने की घोषणा के बाद अब मप्र एसटीएफ द्वारा कार्रवाई शुरू की जा रही है। एसटीएफ के पास ऐसी करीब 197 शिकायतें हैं, जिनकी जांच न तो एसटीएफ कर रही थी और न ही सीबीआई। हालांकि, सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हीं मामलों की जांच कर रही है, जो उसे सौंपे गए हैं। इस कारण व्यापम की 197 शिकायतें कई साल से फाइलों में धूल खा रही थीं। सूत्रों के मुताबिक मालवा क्षेत्र संबंधी शिकायतों की जांच एसपी एसटीएफ इंदौर पद्म विलोचन शुक्ला करेंगे तो ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की शिकायतों पर एसपी एसटीएफ ग्वालियर अमित सिंह कार्रवाई करेंगे। भोपाल एसटीएफ एसपी राजेश सिंह भदौरिया भोपाल, जबलपुर और अन्य क्षेत्रों की शिकायतों की करेंगे।

मध्य प्रदेश एसटीएफ के विशेष महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि व्यापम की शिकायतों की जांच के लिए गठित एसआइटी ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार के शिकायतकर्ताओं को बुलाना शुरू कर दिया है। शिकायतकर्ताओं के नाम-पतों पर नोटिस भेजे जा रहे हैं।

शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत

दर्दनाक ▸ लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुई दुर्घटना

टेंपो को टक्कर मारने के बाद मैजिक पर पलटा ट्रक

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार और सड़क बनाने में तकनीकी दोष ने मंगलवार को 17 लोगों की जान ले ली। सुबह करीब दस बजे तेज रफ्तार ट्रक ने टेंपो को टक्कर मार दी। बेकाबू होकर ट्रक सामने से आ रहे मैजिक पर पलट गया। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि चार घायल हो गए। मरने वालों में तीन बच्चे व दो महिलाएं भी हैं। मंडलायुक्त व डीआइजी ने दुर्घटनास्थल का मुआयना किया।

सीतापुर की ओर से पान मसाला लेकर आ रहा ट्रक जमुका दोराहा के पास आगे चल रहे टेंपो में टकरा गया। इसके बाद बेकाबू होकर ट्रक सामने से आ रही मैजिक पर पलट गया। हादसे में टेंपो व मैजिक में सवार लोग घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने वाहनों में फंसे घायलों को निकाला। पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने 16 को मृत घोषित कर दिया। एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ट्रक चालक व हेल्पर का पता नहीं चल सका है।

शाहजहांपुर के रोजा में हादसे में बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रक हटवाती पुलिस। जागरण

हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी शाहजहांपुर को मृतकों के परिजनों को अनुमन्य धनराशि तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों का समुचित इलाज कराने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि टेंपो चालक ने बताया है कि ट्रक तेज रफ्तार में था।

एनएचएआइ के अधिकारियों को सड़क हादसे की जांच करने के निर्देश दिए हैं। प्रथम दृष्टया ट्रक चालक की गलती के साथ ही सड़क बनाने में तकनीकी दोष मुख्य कारण लग रहे हैं।

– रणवीर प्रसाद, मंडलायुक्त

तकनीकी खामी के कारण जमुका दोराहा मोड़ पर अक्सर हादसे होते हैं। सावन में भी कांवड़ियों की ट्राली पलट गई थी। इस मोड़ को सही कराया जाएगा।

–राजेश कुमार पांडेय, डीआइजी

जल जीवन मिशन में राज्यों ने मांगा ज्यादा पानी

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

▸ **केंद्र देना चाहता है हर व्यक्ति को रोजाना 55 लीटर, राज्यों ने मांगा 70 लीटर**

मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' के शुरू होने से पहले ही राज्यों ने अपनी मांगों की फेहरिस्त केंद्र के समक्ष रख दी है। उनकी प्रमुख मांग 'हर घर नल से जल' कार्यक्रम में हर व्यक्ति को रोजाना मिलने वाले पानी की मात्रा को बढ़ाने की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इसके तहत 55 एलपीसीडी (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) पानी देने का लक्ष्य रखा है जबकि राज्य इसे बढ़ाकर 70 एलपीसीडी करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कई राज्यों ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र से भारी भरकम धनराशि की मांग भी की है। खास बात यह है कि इन मुद्दों पर कांग्रेस और भाजपा शासित राज्यों की राय एक जैसी है।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में सोमवार को 'जल जीवन मिशन' पर राज्यों के मंत्रियों की बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने यह मांग उठाई। बैठक में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को 'जल जीवन मिशन' के तहत प्रस्तावित 55 एलपीसीडी के लक्ष्य को बढ़ाकर 70 एलपीसीडी कर देना चाहिए। इसी तरह राजस्थान की कांग्रेस सरकार के ऊर्जा एवं पीएचईडी मंत्री बीडी कल्ला ने भी जल उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को 55 एलपीसीडी की जगह 70 एलपीसीडी करने की मांग की। तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक सरकार में जलापूर्ति मंत्री एसपी वेलुमणि ने भी सभी परिवारों को पाइप से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 70 एलपीसीडी जलापूर्ति करने की मांग की।

सूत्रों ने कहा कि राज्यों ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए केंद्र से भारी भरकम धनराशि की मांग भी की। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने कहा कि उनके राज्य में 2024 तक सभी बस्तियों तक पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र से 1.20 लाख करोड़ रुपये की दरकार है। इसी तरह बिहार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने राज्य को तत्काल 8,000 करोड़ रुपये का अनुदान जारी करने की मांग की। मध्य प्रदेश के पीएचईडी मंत्री सुखदेव पांसे ने भी राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे पेयजल आपूर्ति के कार्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय योगदान के रूप 600 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की। तमिलनाडु ने भी कहा कि मौजूदा जल वितरण तंत्र को मजबूत करने और नई लाइनें बिछाने के लिए राज्य को लगभग 47,000 करोड़ रुपये की दरकार होगी। सूत्रों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 'जल जीवन मिशन' पर भारी भरकम 3,60,000 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 14 करोड़ से अधिक परिवारों को पानी का कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर जल की आपूर्ति की जाएगी।

स्वामी चिन्मयानंद पर छात्रा के अपहरण का मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री व मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद पर उन्हीं के कॉलेज की छात्रा के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते दिनों छात्रा ने एक वीडियो वायरल कर शारीरिक शोषण व दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। उसके बाद से वह लापता है।

मंगलवार देर शाम एसपी डॉ. एस चिनप्पा ने प्रेस कांफ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को स्वामी चिन्मयानंद के वाट्सएप नंबर पर मैसेज आया, जिसमें उनसे पांच करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। उस प्रकरण में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 24 अगस्त को एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक छात्रा स्वामी पर आरोप लगा रही है। रविवार को छात्रा के परिजनों ने चौक कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद ने उनकी बेटी को अगवा करा दिया है। स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

एसपी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो स्वामी से पूछताछ भी की जाएगी। पहले रंगदारी मांगे जाने की तहरीर आई थी, जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई। बताया कि छात्रा को सुरक्षित बरामद करने का प्रयास हो रहा है। छात्रा के पिता को सुरक्षा दे दी गई है। रिपोर्ट दर्ज करने में किसी तरह की लापरवाही या देरी नहीं की गई है। रंगदारी मांगने के मामले में भी जांच चल रही है। इस प्रकरण में एक को हिरासत में लिया गया है। युवक का कहना है कि उसके नाम से जारी नंबर से दोस्त ने मैसेज भेज रंगदारी मांगी थी।

न्यूज गैलरी

सजा से गुस्साए राइफलमैन ने अधिकारी की हत्या कर जान दी

चेन्नई : तमिलनाडु के पल्लवरम बैरक में एक राइफलमैन ने सैन्य अधिकारी की हत्या कर दी और बाद में खुद को भी गोली से उड़ा लिया। कथित तौर पर 'सुस्त रवैये' के लिए उसे सजा दी गई थी, जिससे वह गुस्से में था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वारदात मंगलवार को भोर में करीब तीन बजे हुई। अधिकारी की हत्या करने वाले राइफलमैन ने भी खुदकशी कर ली। उन्होंने बताया, 'हमें लगता है कि सुस्त रवैये के लिए हवलदार द्वारा दी गई सजा से राइफलमैन काफी भावुक हो गया था।' रक्षा सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। (प्रेट्र)

मानसरोवर यात्रा का सोलहवां दल भारत लौटा

पिथौरागढ़ : कैलास मानसरोवर यात्रा का 16वां दल मंगलवार को भारत लौट आया है। 57 सदस्यीय इस दल में 47 पुरुष और दस महिलाएं हैं। दल के लिपूलेख से होते हुए शाम तक गुंजी पहुंचेगा। वहीं, 17वां दल लिपूपास पार कर तिब्बत पहुंच गया है। उधर, 33 सदस्यीय 18वां दल नाबी से गुंजी पहुंचा। जहां पर आइटीबीपी के चिकित्सकों ने यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। अब तक 15 दल यात्रा पूरी कर चुके हैं। 18वें दल के तिब्बत में कैलास मानसरोवर की परिक्रमा पूरी कर लौटने के बाद वर्ष 2019 की कैलास मानसरोवर यात्रा का समापन हो जाएगा। (जासं)

आर्य समाज मंदिरों में विवाह पर नियम बनाने को मांगा समय

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आर्य समाज मंदिर में होने वाले विवाह के लिए नियम बनाने संबंधी दायर याचिका में शासन को जवाब प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। शासन की मांग पर कोर्ट ने समय दिया। दुर्ग निवासी दादु राम सोनकेर ने अधिवक्ता अनुराग झा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि आर्य समाज मंदिरों में विवाह के लिए आने वाले जोड़े के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं ली जाती है। यहां तक कि लड़की बालिग है या नहीं, युवक क्या करता है, उसके आय का क्या जरिया है, इनका वैवाहिक संबंध आगे चल सकता है या नहीं, इसका सत्यापन नहीं किया जाता। इसके अलावा युवक-युवती के परिवार या पुलिस को भी सूचना नहीं दी जाती है। शुल्क लेकर विवाह का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। मंगलवार को याचिका पर चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान शासन की ओर से समय देने की मांग की गई। (नईदुनिया)

देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी नहीं रहीं

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड और देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य का सोमवार देर रात निधन हो गया। पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने इसकी पुष्टि की है। वह लंबे समय से बीमार थीं। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। 1973 बैच की महिला आइपीएस अफसर कंचन चौधरी भट्टाचार्य ने 2004 में उस समय इतिहास रचा था, जब वह उत्तराखंड की पुलिस महानिदेशक बनीं। 31 अक्टूबर 2007 को वह पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुईं। इसके बाद वह 2014 के आम चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा। वह किरण बेदी के बाद देश की दूसरी महिला आइपीएस अधिकारी थीं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर दूरदर्शन पर सीरियल 'उड़ान' भी प्रसारित हो चुका है। 1997 में प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए उन्हें 'राष्ट्रपति पदक' भी मिला था।

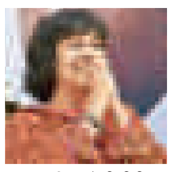

एक कार्यक्रम में डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। प्रेट्र

जापान के राजदूत ने की धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात

जापान के राजदूत केंजी हीरामात्सू ने मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और जापान के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। जागरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जापान के भारत में राजदूत केंजी हीरामात्सू ने मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और जापान के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। बैठक के बाद प्रधान ने कहा कि जापान के राजदूत केंजी हीरामात्सू के साथ उनकी मुलाकात फलदायी रही। उन्होंने एशिया के दो पुराने लोकतांत्रिक देशों के बीच ऊर्जा संबंध और प्रगाढ़ बनाने तथा भारत के स्टील सेक्टर में जापानी प्रौद्योगिकी और निवेश को बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा की। साथ ही दोनों देशों का सतत और समग्र विकास सुनिश्चित करने और पारस्परिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परंपरागत, गैर-परंपरागत और रिन्यूएबल ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के नये रास्ते तलाशने पर भी उन्होंने चर्चा की।

बच्चों के स्वास्थ्य सूचकांक के निचले पायदान पर झारखंड, मध्य प्रदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : खराब पोषाहार और जीवित बचने के न्यून दर ने झारखंड और मध्य प्रदेश को बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक के निचले पायदान पर ला खड़ा किया है। बच्चों का स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक स्वस्थ व्यक्तिगत विकास के तीन आयामों, सकारात्मक संबंध और सुरक्षा संदर्भ के माध्यम से तय किया जाता है। सूचकांक के अनुसार स्वास्थ्य, पोषाहार और शिक्षा सुविधाओं में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन से केरल शीर्ष स्थान पर आया है। मंगलवार को जारी बाल स्वास्थ्य सूचकांक को तीन आयामों स्वस्थ व्यक्तिगत विकास, सकारात्मक संबंध और सुरक्षा संदर्भ के जरिये मापा और पता लगाया गया है। यह सूचकांक एनजीओ वर्ल्ड विजन और आइएफएमआर एलईएडी ने विकसित किया है। तीन प्रमुख आयामों पर केंद्रित रहते हुए 24 सूचकांकों का चुनाव बच्चों के स्वास्थ्य सूचकांक की गणना विकसित करने के लिए किया गया है। सूचकांक में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को देखा जाता है। राज्यों में केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने सूचकांक के शीर्ष तीन स्थानों पर जगह बनाई है। मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश सबसे निचले पायदान पर हैं।

जगन्नाथ मंदिर के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक से इन्कार

▸ **ओडिशा सरकार के फैसले के खिलाफ दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज**

▸ **राज्य के एडवोकेट जनरल ने कहा, कानून के मुताबिक लिया फैसला**

नई दिल्ली, एएनआइ : पुरी में जगन्नाथ मंदिर के आसपास अनधिकृत निर्माण गिराने के ओडिशा सरकार के फैसले पर रोक की मांग संबंधी दो याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अरविंदलोचन और इंटर-कांटिनेंटल एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इनमें मेरिट नहीं है। ओडिशा के एडवोकेट जनरल अशोक पारिजा के बयान पर संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने ये याचिकाएं खारिज कीं। पारिजा का कहना था कि गैरकानूनी निर्माण गिराने का फैसला दास समिति की सिफारिशों के अनुपालन के साथ-साथ संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं के तहत लिया गया था। दास समिति ने जगन्नाथ मंदिर के आसपास 75 मीटर के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने की सिफारिश की थी।

जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने याचिकाएं खारिज करने के साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और न्यायमित्र रंजीत कुमार से जगन्नाथ मंदिर का दौरा करने और गैरकानूनी निर्माण हटाने के अभियान की स्थिति का जायजा लेने का निर्देश भी दिया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल और न्याय मित्र दोनों को रिपोर्ट दाखिल कर यह बताने का निर्देश भी दिया कि मंदिर के बेहतर विकास के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट फाइल

इससे पहले न्यायमित्र ने एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल की जिसमें जिला जज के सुझाव के आधार पर श्रीमंदिर में विभिन्न सुधारों की सिफारिश की गई है।

'जे. डे हत्याकांड में पूर्व पत्रकार को बरी करने का फैसला सही'

▸ **मिड डे के पत्रकार थे डे, गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ खबर लिखने पर मुंबई में कर दी गई थी हत्या**

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने पत्रकार जे. डे हत्याकांड में मंगलवार को वर्ष 2018 में सीबीआइ की विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा। विशेष अदालत ने हत्याकांड की आरोपित पूर्व पत्रकार जिग्ना वोरा को बरी कर दिया था। जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और एसके शिंदे की पीठ ने पाया कि वर्ष 2011 के इस हत्याकांड में सीबीआइ वोरा के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में सीबीआइ की विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन व अन्य आठ लोगों को सजा सुनाई थी, जबकि वोरा व पॉल्सन जोसफ को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। सीबीआइ ने वोरा व पॉल्सन को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

पीठ ने मंगलवार को कहा कि सीबीआइ ने कुछ फोन कॉल और चश्मदीद गवाहों के आधार पर वोरा व राजन आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि, कोई भी फोन कॉल यह साबित नहीं कर सका कि डे की हत्या वोरा के कहने पर की गई थी।

गौरतलब है कि सीबीआइ ने आरोप पत्र में दावा किया था कि वोरा ने पेशागत दुश्मनी के कारण मिड डे अखबार के पत्रकार जे. डे की शिकायत विदेश में रह रहे गैंगस्टर राजन से की थी। 11 जून 2011 को मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने जे. डे (56) की उपनगरीय पोवई इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभियोजन के अनुसार, गैंगस्टर राजन अपने गिरते स्वास्थ्य और अंडरवर्ल्ड में कमजोर होती पकड़ के संबंध में डे की रिपोर्टिंग को लेकर नाराज था, इसलिए उसने डे की हत्या करवा दी। इंडोनेशिया में गिरफ्तारी और अक्टूबर 2015 में भारत में प्रत्यर्पित किए जाने के बाद राजन इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

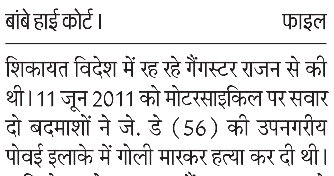

बांबे हाई कोर्ट। फाइल

अलीगढ़ में लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश

जागरण संवाददाता, अलीगढ़

▸ **धनीपुर हवाई पट्टी पर हादसा, छह लोगों की बची जान**

▸ **रनवे के ऊपर से गुजर रही बिजली की एचटी लाइन से टकराया, लगी आग**

अलीगढ़ में धनीपुर हवाई पट्टी पर मंगलवार सुबह दिल्ली से आ रहा जेट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। लैंडिंग के दौरान 33 केवी की लाइन से प्लेन का पिछला पहिया टकरा गया।

टकराकर प्लेन रनवे किनारे घास में करीब 500 मीटर तक घिसटता चला गया। कुछ देर बाद ही आग लग गई। गनीमत ये रही कि प्लेन में सवार दो पायलट व तकनीकी टीम के चार सदस्यों की जान बच गई। वे खिड़की खोलकर सुरक्षित बाहर निकल आए। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक प्लेन बुरी तरह जल चुका था।

एविएशन इंवेस्टीगेशन ब्यूरो (एआइबी) की छह सदस्यीय टीम ने जांच शुरू कर दी है। टीम यहां दो दिन रहेगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की टीम भी देर शाम पहुंच जाएगी। जांच पूरी होने तक पायलट प्रशिक्षण रोक दिया गया है। एयर चार्टर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के इस प्लेन ने दिल्ली से सुबह 8:15 बजे यहीं के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें कैप्टन किशोर व कैप्टन दीपक के साथ टेक्निकल टीम के रामप्रकाश गुप्ता, प्रभात त्रिवेदी, आनंद कुमार व कार्तिक सवार थे।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंगलवार को एक विमान लैंडिंग के दौरान बिजली के तारों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विमान में आग लग गई। जागरण

एआइबी ने शुरू की जांच : प्लेन क्रैश की जांच के लिए दिल्ली से एआइबी की छह सदस्यीय टीम पहुंची। टीम ने घटनास्थल का मुआयना करने के साथ ही पायलटों से पूछताछ की। हवाई पट्टी के एयर कंट्रोल सिस्टम से जुड़े स्टाफ से भी जानकारी की। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने भी जांच बैठा दी है। प्लेन क्रैश को सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि प्लेन उतरने की सूचना भी प्रशासन के पास नहीं थी।

दो कंपनियां देती हैं प्रशिक्षण : हवाई पट्टी पर प्लेन की मरम्मत का काम एयरक्राफ्ट सर्विस संभालती है। हवाई पट्टी पर दो कंपनियां पायनियर फ्लाइंग क्लब व एंबीशंस फ्लाइंग क्लब पायलट का प्रशिक्षण देती हैं। प्रशिक्षण के लिए दोनों कंपनियों के पास छह-छह प्लेन हैं।

बिहार के नवादा में महिला और युवक की पीटकर हत्या

जागरण संवाददाता, नवादा : बिहार के नवादा में एक महिला और युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह दोनों के शव मिले। डायन का आरोप लगाते हुए चिंता देवी की जान ली गई। राजेंद्र मांझी उर्फ लेंगड़ा की हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा। दोनों हत्याकांड में चार आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं।

नवादा के श्रवण गांव में कैलाश मांझी के 12 वर्षीय पुत्र मुन्ना मांझी की मौत सोमवार सुबह किसी बीमारी से हो गई थी। सुखदेव मांझी की 55 वर्षीया पत्नी चिंता देवी पर जादू-टोना कर बच्चे को मार डालने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने मंगलवार को लाठी-डंडे से उनकी जबरदस्त पिटाई की। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्या के आरोप में कैलाश मांझी और उसके पुत्र सोनू मांझी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

दूसरी वारदात नवादा के ही लालपुर मुसहरी की है। प्रेम प्रसंग में लाठी-डंडे से पीट-पीटकर बदमाशों ने 35 वर्षीय लेंगड़ा की जान ले ली। हालांकि पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश में हत्या हुई। लालपुर जंगल के किनारे चमैनियादह नदी से शव बरामद किया गया। हत्या के बाद शव को नदी में फेंक दिया गया था।

मिसाल

सोनी टीवी पर छह सितंबर की रात नौ बजे से होगा इस शो का प्रसारण, वर्तमान में एनडीआरएफ के डीजी हैं आइपीएस एसएन प्रधान

आइपीएस ने केबीसी में जीते 25 लाख, शहीदों के नाम किए

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड कैडर के 1988 बैच के आइपीएस अधिकारी एसएन प्रधान ने कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में 25 लाख रुपये जीते हैं। उन्होंने जीत की राशि शहीदों के आश्रितों के लिए बने खाता 'भारत के वीर' में जमा कर दिया है। इस शो का प्रसारण सोनी टीवी पर छह सितंबर की रात नौ बजे से होगा।

मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अधिकारी सत्य नारायण प्रधान वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) में महानिदेशक के पद पर पदस्थापित हैं। उन्होंने बताया कि कौन बनेगा करोड़पति ने उन्हें शो के लिए निमंत्रण दिया था। उन्होंने केबीसी से महानायक अमिताभ बच्चन के निमंत्रण को डीजी एनडीआरएफ के रूप में केवल इसी शर्त पर स्वीकार किया कि जीती हुई पूरी राशि वे शहीदों के आश्रितों के खाते में जमा करेंगे। केबीसी के हामी भरने के बाद एनडीआरएफ की टीम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुंबई गई थी। उन्होंने कहा कि शो के दौरान हुई बातचीत और अपने अनुभवों को साझा नहीं कर सकते, क्योंकि शो का प्रसारण होने से पहले इसके लिए मना किया गया है।

अमिताभ के साथ केबीसी के हॉट सीट पर बैठना कभी न भुलने वाला पल : एनडीआरएफ के महानिदेशक (डीजी) एसएन प्रधान ने कहा कि 'कौन बनेगा करोड़पति' के हॉट सीट पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ बैठना अपने आप में अद्भुत अनुभव रहा। अब तक टेलीविजन पर ही यह शो देखा था। अमिताभ बच्चन को सामने से देखा। उनके प्रश्न पूछने का अंदाज व शो का संचालन अद्भुत था। मेरे लिए वह पल रोमांच से भरा हुआ था, जब मैं केबीसी के हॉट सीट पर बैठकर महानायक के प्रश्नों का जवाब दे रहा था। उन्होंने केबीसी के हॉट सीट पर बैठने को कभी न भुलने वाला पल बताया।

आइपीएस एसएन प्रधान की प्रोफाइल

- 1988 बैच के आइपीएस अधिकारी एसएन प्रधान 22 जनवरी 2019 को एनडीआरएफ के महानिदेशक बने।
- इससे पहले अगस्त 2016 से जनवरी 2019 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे हैं।
- उन्हें 2006 में राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक व 2012 में राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक मिला है।
- वर्ष 2008 में यूके सरकार ने पुलिसिंग पर इनोवेशन के लिए उन्हें 'क्विंस अवार्ड' दिया था।

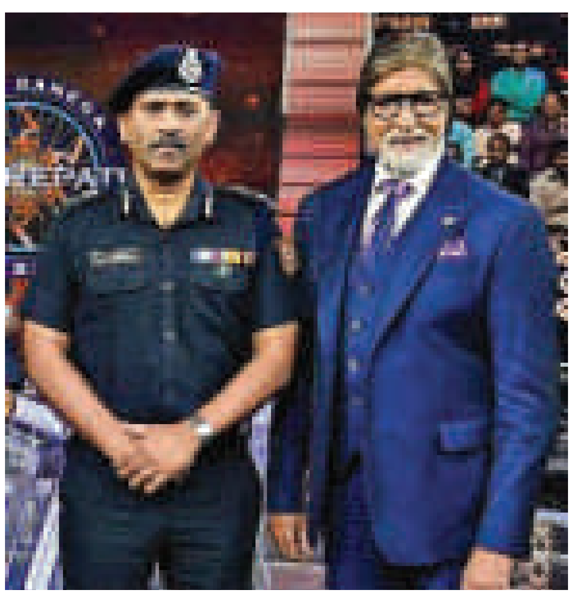

झारखंड कैडर के आइपीएस एसएन प्रधान (एनडीआरएफ के डीजी) केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन के साथ। जागरण

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की पैरोल की एक और कोशिश नाकाम

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़

जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत की पैरोल लेने की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। उसकी पत्नी हरजीत कौर द्वारा पैरोल के लिए दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा कि पैरोल देना राज्य व कोर्ट की दया पर निर्भर है, यह याची का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही याचिका वापस लेने की छूट देते हुए उसे खारिज कर दिया।

गुरमीत की पत्नी ने हाई कोर्ट में दायर याचिका का आधार गुरमीत की मां (अपनी सास) नसीब कौर की बीमारी को बनाया था। याचिका में कहा गया था कि नसीब कौर बीमार हैं। उनकी आयु 85 साल है। पिछले दिनों नसीब कौर को हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन वह अपना इलाज नहीं करवा रही हैं। उनकी इच्छा है कि गुरमीत सिंह उसके पास हो। जब तक उनका बेटा उसके पास नहीं आएगा, वह इलाज नहीं कराएगी। इसी वजह से उन्होंने रोहतक जेल के जेल अधीक्षक को 29 जुलाई को पार्थना पत्र देकर गुरमीत को पैरोल देने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य ने उनको पैरोल देने से इन्कार कर दिया। गौरतलब है कि गुरमीत दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहा है। डेरे में अस्पताल, मां का वहीं इलाज कराएं

पीठ ने कहा कि जब आपके डेरे में अस्पताल है तो आपने डेरा प्रमुख की माता को प्राइवेट अस्पताल में क्यों दाखिल करा रखा है। उनकी एंजीयोग्राफी भी हो चुकी है। गुरमीत को छोड़ उनका पूरा परिवार जब उनके साथ है तो गुरमीत को पैरोल की क्या जरूरत है। बता दें कि इससे पहले भी गुरमीत ने अपनी दत्तक बेटी की शादी में जाने के लिए पैरोल की मांग को लेकर हाई कोर्ट से याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था। उसके बाद खेती के लिए जेल अधीक्षक से पैरोल मांगी, लेकिन वह अर्जी भी बाद में वापस ले ली गई थी। याचिका पर सुनवाई प्रारंभ होते ही पीठ ने डेरा प्रमुख की पत्नी द्वारा याचिका दायर करने पर ही सवाल उठा दिया। पीठ ने कहा कि आप का किस अधिकार से यह याचिका दायर कर रही हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 28 अगस्त 2019

दैनिक जागरण
जीवन की दशा बदलनी है तो कर्म की दिशा बदलिए

सही समय पर उचित फैसला

केंद्र सरकार को करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के रिजर्व बैंक बोर्ड के फैसले को लेकर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से जैसा शोर मचाया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि कोई अनर्थ होने जा रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि कुछ अर्थशास्त्री भी रिजर्व बैंक के फैसले को सही संदर्भ में देखने से इन्कार कर रहे हैं। इससे इन्कार नहीं कि रिजर्व बैंक एक बड़ी धनराशि सरकार को हस्तांतरित करने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह काम पहली बार हो रहा है। रिजर्व बैंक की ओर से पहले भी ऐसा किया जाता रहा है। अंतर बस इतना है कि पहले उसकी ओर से सरकार को हस्तांतरित की जाने वाली राशि इतनी अधिक नहीं होती थी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को कितनी राशि दी जा सकती है, इसकी सिफारिश बकायदा एक समिति ने की है और उसके प्रमुख इसी बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल कुमार जालान हैं। इसी के साथ यह भी ध्यान रखा जाए तो बेहतर कि रिजर्व बैंक ने जालान समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि उसने यह पाया कि उसकी वित्तीय स्थिति बेहतर है। जिन्हें भी रिजर्व बैंक का यह फैसला रास नहीं आ रहा है उन्हें इस पर गौर करना चाहिए कि भारत सरकार को जो धन मिलने जा रहा है वह देश का पैसा है। आखिर इसमें क्या हर्ज है कि देश का पैसा देश के काम आए? निःसंदेह ऐसा भी नहीं है कि रिजर्व बैंक ने अपना सारा खजाना खाली करने का फैसला किया हो।

चूंकि फिलहाल अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है और मंदी का अंदेशा उभर आया है इसलिए रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय रूप से सरकार के हाथ मजबूत करने की पहल को उपयुक्त समय पर उठाया गया कदम ही कहा जाएगा। यदि अर्थव्यवस्था की सुस्ती और गहराने के बाद रिजर्व बैंक की ओर से सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का फैसला किया जाता तो शायद अनुकूल नतीजे हासिल करने में मुश्किल होती। रिजर्व बैंक के फैसले के बाद कारोबार जगत के साथ आम जनता के बीच तो एक अच्छा संदेश जाएगा ही, वैश्विक निवेशकों को भी इसका अहसास होगा कि भारत ने आर्थिक सुस्ती को दूर भगाने के लिए कमर कस ली है। रिजर्व बैंक से उम्मीद से अधिक राशि मिलने से केंद्र सरकार को केवल खर्च बढ़ाने में ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि चालू वित्त वर्ष के शेष समय में बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक में खर्च बढ़ाकर मांग को बल देने में सहायता मिलेगी।

सेहत पर सवाल

उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमे की सेहत नासाज है। तमाम कोशिशों के बाद भी यहां व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पा रही हैं। राज्य गठन के वक्त से इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। उन्नीस साल बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं खोजा जा सका। अभी तक की सरकारों ने अपने-अपने नजरिये से नित नए फार्मूले लागू किए, पर समस्या जस की तस बनी हुई है। हालात इस कदर खराब हैं कि अधिकांश पर्वतीय जिलों में सरकारी अस्पताल रेफरल सेंटर बन कर रह गए हैं। बेस अस्पतालों की स्थिति भी कमोबेश यही है। सच तो यह कि स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर लाने के नाम पर अभी तक केवल प्रयोग ही हुए हैं। इच्छाशक्ति और प्रभावी नीति न होना इसकी वजह सामने आ रही है। ये सही है कि उत्तराखंड में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है, लेकिन जो उपलब्ध भी हैं उनके इस्तेमाल की सही योजना विभाग के पास नहीं दिखती। पर्वतीय अंचलों में डॉक्टर कदम रखने को तैयार नहीं हैं, इसके उलट शहरी इलाकों के अस्पतालों में जुगाड़बाजी से तैनाती पाने की होड़ लगातार बढ़ रही है। कोई शक नहीं कि इस स्थिति के लिए सरकारें ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि किसी भी सरकार ने कभी भी इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं किया कि पर्वतीय इलाकों में किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है। ट्रांसफर-पोस्टिंग में राजनीतिक दखल और चहेतों को एडजस्ट करने की प्रवृत्ति ने इस समस्या को और गहरा किया है। सवाल यह कि क्यों नहीं राज्य की एक सम्यक स्वास्थ्य नीति तैयार कर ली जाती। इसमें यह स्पष्ट हो कि पर्वतीय क्षेत्र में एक नियत अवधि तक सेवा देने के बाद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शहरी में तैनाती पाने का स्वतः हकदार होंगे। कई मौकों पर सरकारें इस तरह की बातें कहती सुनाई दीं, मगर इसे कार्य व्यवहार में लाने से मुंह चुराती दिखीं। इसी का नतीजा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कभी स्टाफ की कमी तो कभी डॉक्टरों के पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार न होना बताकर सरकार अपना बचाव कर रही है, पर सवाल अपनी जगह खड़ा है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। अब कुछ अस्पतालों को पीपीपी मोड पर देने की बात कही जा रही है, लेकिन शायद सरकार इस बात को भूल रही है यह प्रयोग उसका असफल हो चुका है। पूर्व में जिन अस्पतालों में यह प्रयोग किया गया था, वहां स्थिति सुधरने के बजाय खराब हुई है, तो क्या गारंटी अब परिणाम आशातीत मिलेंगे। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

बहुत खलेगा इस अरुण का अस्त होना

प्रशांत मिश्र

वाजपेयी के बाद जेटली भाजपा के संभवत: अकेले ऐसे नेता माने जा सकते हैं जिनके दोस्त हर दल में थे। विचारधारा से परे उनके बीच लंबी बातचीत हो सकती थी

रैना बीती जाए... आरडी बर्मन का यह गाना अरुण जेटली जी को बहुत प्रिय था। सुना है हाल के दिनों में वह कई बार इस गाने को सुनते रहे थे। यह सच है कि तीन-चार महीने पहले तक बीमारी को हराकर जीवन के मैदान में फिर से उतरने को लेकर विश्वस्त अरुण जी को हाल के दिनों में आभास होने लगा था कि अब जीवन की डोर छोटी हो रही है। और इसीलिए अपनों से, खास दोस्तों से मिलते तो भविष्य के लिए कुछ-कुछ संदेश जरूर देते थे। दोस्तों को यही बोलकर गए थे कि मित्र मंडली चलती रहनी चाहिए। जितना संभव हो एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन अगर कोई यह समझ बैठे कि वह हार गए थे या भयभीत थे तो बिल्कुल गलत होगा। दरअसल जितना मैं समझ पाया वह न तो किसी भी परिस्थिति से डरने वाले थे और न ही धैर्य खोने वाले। वह तो डटकर मुकाबला करने वाले थे। छात्र राजनीति से लेकर केंद्र सरकार में मंत्री बनने तक उन्होंने कभी अधीरता नहीं दिखाई। जो जिम्मेदारी मिलती गई उसमें खुद को साबित करते गए। बीमारी के बाद मौत ने उन्हें जरूर हर किसी से ओझल कर दिया है, लेकिन जीवन और राजनीति को लेकर उनकी सोच और प्रासंगिकता हमेशा बरकरार रहेगी।

अरुण जी को जानने-पहचानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी और इस नाते उनके हर पहलू पर काफी बातें होती रही हैं। मैं तो इतना कह सकता हूं कि एक इंसान के रूप में उनका जाना समाज के लिए बहुत बड़ी रिक्तता पैदा कर गया है। कहा जाता है कि अच्छे इंसान की पहचान इससे हो सकती है कि उनके घरेलू सहायक कितने लंबे वक्त से टिके हैं। सभी जानते हैं कि उनके घर का न तो कभी कोई सेवक बदला, और न ही दोस्त, बल्कि संख्या बढ़ती ही चली गई। उनका यही गुण उन्हें राजनीति में भी अलग खड़ा करता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वह भाजपा के संभवतः अकेले ऐसे नेता माने जा सकते हैं जिनके दोस्त हर दल में थे। विचारधारा से परे हटकर उनके बीच लंबी बातचीत हो सकती थी। एक दूसरे के हमराज बन सकते थे। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सभी जानते हैं कि बिहार में भाजपा और जदयू के बीच जितना लंबा गठबंधन रहा है उतने ही दोनों दलों के बीच तनाव के पल भी रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अरुण जेटली के संबंधों में इस कारण कोई बाधा नहीं आई। मगर उतना ही ध्यान इसका भी रहा कि राजनीतिक विचारधारा और सांगठनिक कर्तव्य की राह में संबंध आड़े न आएं। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम ऊपर रखने की बात आई तो नीतीश के साथ अच्छे संबंधों ने उन्हें नहीं जकड़ा। भाजपा और जदयू अलग-अलग हो गए तब भी संबंध नहीं बिगड़े। कर्तव्यपरायणता की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी।

अवधेश राजपूत

मुझे याद आता है कि नोटबंदी के बाद मीडिया के एक मित्र ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अरुण जी से बहुत तीखे सवाल किए थे। बाद में पत्रकार की पत्नी के अलावा भी कई साथियों ने जब कहा कि सवाल बहुत तीखे थे तो वह पत्रकार अरुण जी के पास पहुंचे। उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए थे तो उन्होंने तपाक से कहा-अरे भाई, तुम्हें यही पूछना चाहिए था। दोस्ती की जगह दूसरी है और काम की जगह दूसरी। यही उनकी बड़ी खूबी थी। उनकी दोस्ती सामने वाले को बांधती नहीं थी, बल्कि उन्मुक्त करती थी। उनका बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कद भी कभी किसी को छोटा महसूस नहीं करने देता था, बल्कि ऊपर उठने को प्रेरित करता था।

दरअसल उनके आसपास हमेशा ऐसा माहौल होता था कि कभी भी आपसी मनभेद न पैदा हो सके। मुझे याद है कि भाजपा संगठन के एक बड़े नेता के बारे में एक खबर छपी थी जिसमें यह लिखा गया था कि वह अमेरिका में घूम रहे हैं। किसी कारणवश उस पर खूब चर्चा हुई थी। खबर लिखने वाले जेटली के भी मित्र थे और उक्त पदाधिकारी के भी। जाहिर तौर पदाधिकारी का शक जेटली के ऊपर गया था। उन्होंने तत्काल आमना-सामना कर यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। मौजूदा दौर के नेताओं से उन्हें एक और बात जुदा करती थी और वह था धैर्य। बात 1999 की है। मीडिया के एक मित्र की शादी थी। तब जेटली सूचना प्रसारण विभाग में राज्यमंत्री बनाए गए थे। मैंने जब उनसे कहा कि वाजपेयी जी ने उन्हें क्षमता से कम दिया है तो वह कंधे पर धौल लगाते हुए बोले-सब ठीक है। इसमें कोई बात नहीं है और न ही मुझे आकांक्षा है। उनकी क्षमता को पहचानते हुए ही वाजपेयी जी ने बाद में उन्हें बड़े-बड़े मंत्रालय दिए थे। एक ऐसे इंसान का जाना समाज में रिक्तता पैदा कर गया है।

रही बात भाजपा की तो लंबे अरसे तक उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। उन्हें संकटमोचक के रूप में ही जाना जाता रहा है। टेबल पर गेम जीतना उन्हें अच्छी तरह आता था और यही कारण है कि गुजरात में लोकप्रिय और अजेय रहे नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ही लगातार गुजरात का प्रभारी बनाए रखना चाहा। उनकी आलोचना करने वाले यह कहते हैं कि वह खुद कभी नहीं जीत पाए। लेकिन पार्टी के अंदर इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जीतने का मंत्र उनके पास था। वह अर्जुन नहीं बन पाए लेकिन द्रोणाचार्य के गुण थे। 2019 लोकसभा चुनाव अभियान में भी प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। नेतृत्व और निर्णय क्षमता को केंद्रित कर चुनाव लड़ने के प्रबल समर्थक रहे जेटली ने 2014 से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन यानी राष्ट्रपति शैली वाले चुनाव की बात शुरू कर दी थी। बीमारी के कारण वह शुरुआती कुछ दिनों के बाद कार्यालय आने में भी असमर्थ थे, लेकिन कर्मठता इतनी थी कि वह अस्पताल या घर बुलाकर भी प्रवक्ताओं को भाजपा का पक्ष रखने का मंत्र दिया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी उनकी समझ पर इतना भरोसा था कि जब 2014 में महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेना था तो शाह ने घोषणा करने से पहले जेटली से सलाह ली थी। उस वक्त भी जेटली अस्पताल में भर्ती थे।

संगठन बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसे बड़ा बनाने में व्यक्तियों का हाथ होता है। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, दोबारा बहुमत के साथ सरकार में आने का रिकार्ड है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शाह को जाता है। लेकिन इससे पहले भाजपा को खासकर बुद्धिजीवियों के बीच स्वीकार्य बनाने वालों में एक नाम जेटली भी थे। उनकी कमी भाजपा को भी खलेगी और समाज में अच्छी बाते करने वाले, अच्छी सोच को बढ़ाने वाले लोगों को भी खलेगी।

(लेखक दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक हैं)

response@jagran.com

दोहरी रणनीति से गायब होगी मंदी

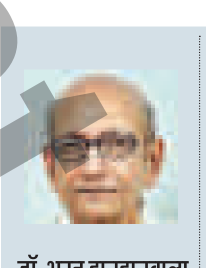

डॉ. भरत झुनझुनवाला

यदि छोटे उद्यमियों को संरक्षण देने के साथ ही विनिर्माण के बजाय सेवा क्षेत्र पर जोर दें तो मंदी को मात दी जा सकती है

देश के प्रमुख आर्थिक सलाहकार यानी सीईए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भारतीय उद्यमियों का आह्वान किया है कि वे निवेश बढ़ाएं। चूंकि निवेश ही आर्थिक विकास का अहम पैमाना है, लिहाजा हमें निवेश और खपत के संबंध को समझना होगा। यह कहानी अंडे और मुर्गी जैसी है। यदि हम मानें कि पहले निवेश होता है। जैसे किसी उद्यमी ने कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में निवेश किया तो उस निवेश से कुछ श्रमिकों को वेतन मिलता है। उस वेतन से वे खपत करते हैं। उनके द्वारा खपत किए जाने से बाजार में तमाम वस्तुओं की मांग बढ़ती है। इस मांग की पूर्ति के लिए उद्यमी पुनः निवेश करते हैं। ऐसा मानें तो आर्थिक विकास का बुनियादी कारक निवेश है। यह हुआ कि अंडा पहले आता है। अब इसी चक्र को हम खपत से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे यदि देश की जनता ने कपड़े की खपत बढ़ाई तो कपड़े के दाम बढ़े। कपड़े की मांग और दाम बढ़े तो उद्यमी ने कपड़े की फैक्ट्री में निवेश किया। निवेश किया तो उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ा तो उसमें श्रमिकों को वेतन मिला जिससे पुनः खपत में वृद्धि हुई। यह हुआ कि मुर्गी पहले आती है।

स्पष्ट है कि यह एक गोल चक्र है जिसे हम किसी भी छोर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन खपत और निवेश को साथ-साथ चलना होता है जैसे आपस में बंधी हुई दो गाड़ियां। मान लीजिए खपत अधिक हुई और निवेश कम हुआ। लोगों ने कपड़े ज्यादा खरीदे और उद्यमी ने कपड़े बनाने की फैक्ट्री कम लगाई। ऐसे में बाजार में कपड़े के दाम बढ़ेंगे जिसके कारण खपत कम हो जाएगी। निवेश के अभाव में खपत नहीं बढ़ सकती है। खपत की गाड़ी अकेले आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि पीछे बंधी निवेश की गाड़ी रुकी हुई है। इसी प्रकार यदि हम मानकर चलें कि निवेश में वृद्धि हुई और खपत में कटौती हो गई तो निवेश में वृद्धि से उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो माल के दाम घटेंगे। माल के दाम घटेंगे तो निवेशक को घाटा होगा और पुनः निवेश बंद हो जाएगा। निवेश की गाड़ी भी अकेले आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि पीछे बंधी खपत की गाड़ी रुकी हुई है। अतः खपत और निवेश को साथ-साथ चलना ही होता है।

खपत और निवेश के साथ-साथ चलने में भी एक विशेष अनुपात होता है। इसे इस तरह समझें कि यदि हम बैल से खेती करते हैं तो निवेश कम होता है और खपत ज्यादा होती है, क्योंकि बैल की देखरेख के लिए ज्यादा श्रमिक चाहिए होते हैं जबकि बैल का दाम तुलना में कम होता है। यदि हम ट्रैक्टर से खेती करें तो ट्रैक्टर में निवेश अधिक और श्रमिक द्वारा खपत कम होती है। इसलिए खपत का हिस्सा कम और निवेश का हिस्सा ज्यादा होता है। इस प्रकार खपत और निवेश का अनुपात तकनीकों से निर्धारित हो जाता है। इस अनुपात में दोनों को साथ-साथ चलना होता है। फिर भी खपत और निवेश में ज्यादा प्रभावी खपत ही दिखती है। जैसे फिलहाल बाजार में माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। निवेश हो चुका है और उत्पादन हो रहा है, लेकिन खपत न होने के कारण मंदी छाई हुई है। खपत के प्रभावी होने का प्रमाण धर्मस्थल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मैसुरु के अध्ययन से मिलता है। इसके अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में जो परिवर्तन होते हैं उसके प्रमुख कारकों में 26 प्रतिशत हिस्सा खपत का है और चार प्रतिशत निवेश का है। यानी देश की आय में उतार-चढ़ाव खपत के कारण होता है।

सीईए सुब्रमण्यम के अनुसार उन देशों में विकास का कारक खपत होती है जहां पर आय 10,000 डॉलर प्रति व्यक्ति से अधिक है। यह बात अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर खरी नहीं उतरती है। अमीरों द्वारा यदि एक रुपये की आय होती है तो उसमें से केवल 10 पैसे की खपत की जाती है और 90 पैसा निवेश किया जाता है। इसकी तुलना में यदि गरीबों को एक रुपये की आय होती है तो उसमें 90 पैसे की खपत की जाती है और 10 पैसे का निवेश किया जाता है। अतः उन देशों में खपत ज्यादा बढ़ती है और विकास तेज होता है जहां गरीबों की आय में वृद्धि होती है। अन्य अर्थशास्त्रियों के आकलन से भी सुब्रमण्यम की बात मेल नहीं खाती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जोसेफ स्टिगलिट्स के अनुसार मौजूदा वैश्विक मंदी का मुख्य कारण असमानता है। अमीरों की आय अधिक है और गरीबों की कम। इस कारण बाजार में मांग सुस्त है। संभव है कि सुब्रमण्यम ने यह बात सिर्फ इसलिए कही हो कि भारतीय उद्यमी निवेश करने को उन्मुख हों।

नीति आयोग के पूर्व प्रमुख अरविंद पानगड़िया ने इस संदर्भ में कहा है कि आर्थिक विकास को वापस पटरी पर लाने के लिए उद्योगों को टैक्स आदि में छूट देने के स्थान पर आर्थिक सुधारों को लागू करना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं कि उद्योगों को टैक्स आदि में रियायतें देने से बात नहीं बनेगी। यदि कार का दाम पांच लाख से घटकर चार लाख हो जाए तब भी जनता के पास उसे खरीदने की क्षमता नहीं है। इसीलिए उद्योगों को दी गई छूट प्रभावी नहीं होगी। बहरहाल पानगड़िया द्वारा आर्थिक सुधारों में गति के सुझाव में कुछ पेंच फंसे हुए हैं। यहां प्रश्न है कि कौन सा सुधार? अभी तक का अनुभव यह है कि आर्थिक सुधारों के कारण ही मंदी आई है। जीएसटी जैसा सुधार लागू करने के कारण छोटे उद्योग दबाव में आ गए। इस दबाव से उनमें रोजगार के अवसर कम सृजित हुए। श्रमिकों के वेतन में कटौती हुई और मंदी पैठ कर गई। इसलिए यदि हम जीएसटी जैसे सुधारों को और मुस्तैदी से लागू करेंगे तो मंदी बढ़ेगी, न कि घटेगी।

मंदी को तोड़ने के लिए दो कार्य करने होंगे। पहला यह कि छोटे उद्यमियों को संरक्षण देना होगा। छोटे उद्यमी रोजगार के अधिक अवसर सृजित करते हैं। उनके द्वारा किए उत्पादन में वेतन का हिस्सा अधिक होता है जिससे खपत बढ़ती है। खपत बढ़ने से खपत और निवेश का सुचक्र स्थापित हो जाता है। दूसरा हमें विदेशों को आपूर्ति करने के लिए विनिर्माण के बजाय सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना होगा। सेवाओं का वैश्विक बाजार लगातार बढ़ रहा है। इसलिए हमें 'मेक इन इंडिया' के स्थान पर 'सर्व्ड फ्रॉम इंडिया' को अपनाना होगा। तभी हम रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे। इससे खपत बढ़ेगी और निवेश भी होगा। इन दो तरीकों से हम मंदी को मात दे सकते हैं।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम, बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

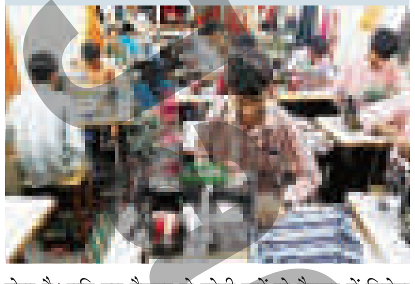

ऊर्जा

ज्ञान की सार्थकता

लोगों को शिक्षा की प्रेरणा देने के लिए सरकारें अभियान चला रही हैं। इसके लिए हर स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। यह मान लिया गया है कि शिक्षित समाज मानव सभ्यता के विकास का मानदंड तय करता है। आज शिक्षा की सफलता रोजगार पाने में है। बड़े से बड़े संस्थान बाकायदा आंकड़े जारी करते हैं कि उनके संस्थान के कितने छात्रों को रोजगार मिला। यह शिक्षा रोजगार तो दिला सकती है, किंतु ज्ञानवान भी बनाती है इसमें संदेह है।

ज्ञान का संबंध आत्मिक चेतना से है जो मनुष्य के चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाती है। ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क को नहीं आत्मा को जगाता है जिससे मन में यह जानने की जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं कौन हूं? मनुष्य जब तक स्वयं को नहीं जानेगा कि वह कौन है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग क्या है तब तक वह यह कैसे निश्चित करेगा कि उसे जीवन को किस मार्ग पर ले चलना है? अपने मूल की खोज करना ही पूरे ब्रह्मांड को जान लेना है। स्वयं को जान लेना अपने अंदर में बसने वाले परमात्मा को पा लेना है। परमात्मा यदि कण-कण में है तो मनुष्य के अंदर भी है। उसे पा लेना ही तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है।

मानव समाज का विकास बड़े उद्योगों, आलीशान इमारतों, चौड़ी सड़कों, पुलों और भौतिकता की चकाचौंध में नहीं है। एक समय था कि रावण ने सोने की लंका बनाई थी। नगर सोने का था, किंतु उसमें रहने वालों के मन कलुषित और सत विहीन थे। इसीलिए उन्हें दैत्य कहा गया। सारे दैत्य भी मारे गए और सोने की लंका भी नष्ट हो गई थी। आज ज्ञान के अभाव में जैसा स्वरूप मानव समाज का बन रहा है उसमें हिंसा, घृणा और अनैतिकता का ही बोलबाला दिखता है। क्या हम एक और लंका दहन की ओर बढ़ रहे हैं। इससे बचना है तो ज्ञानवान मनुष्य तैयार करने होंगे। समाज को ज्ञान से जोड़ना होगा। शिक्षा का अपना महत्व है, किंतु ज्ञान के बिना वह अंततः निराश करने वाली है।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

कमजोर होता सामाजिक ताना-बाना

मंजूषा

परिवारों के टूटने की बढ़ती संख्या केवल एक आंकड़ा भर नहीं है, यह हमारे बिखरते सामाजिक ताने-बाने का आईना है

हाल में ही आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड्स वूमेन 2019-2020 : फैमिलीज इन ए चेंजिंग वर्ल्ड के मुताबिक भारत में परिवारों के टूटने के मामले बढ़ रहे हैं। बीते दो दशकों के दौरान तलाक के मामले दोगुने हो गए हैं। अभी भारत में लगभग 14 लाख लोग तलाकशुदा हैं। भारत जैसे सुदृढ़ सामाजिक-पारिवारिक ढांचे वाले देश में टूटते परिवारों के बढ़ते आंकड़े वाकई विचारणीय हैं। दरअसल परिवारों में आज भी पुरुष वर्चस्व कायम है, जबकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और उच्च शिक्षित युवतियां परिवार से जुड़े फैसलों में भागीदारी चाहती हैं। अधिकतर परिवारों में महिलाएं खुलकर अपनी सोच जाहिर नहीं कर सकतीं। नतीजतन रोजमर्रा की जिंदगी में या तो तनाव और टकराव बढ़ रहा है या संवादहीनता की स्थितियां आ रही हैं। दोनों ही परिस्थितियों में पति-पत्नी के बीच मतभेद बढ़ते हैं जो अक्सर तलाक का कारण बनते हैं। बीते दो दशकों के दौरान महिलाओं के अधिकार बढ़े हैं, पर परिवारों में मानवाधिकार उल्लंघन और लैंगिक असमानता के मामले जस के तस हैं। ऐसे हालातों में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की भी चिंतनीय स्थितियां बनी हुई हैं।

बीते कुछ वर्षों में हमारे यहां परिवार और समाज का पूरा ढांचा ही बदल गया है। निःसंदेह इन बरसों में आए सभी बदलाव सकारात्मक नहीं हैं। जीवनशैली से लेकर विचार और व्यवहार तक जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा जुड़ गया है, जो घर-परिवार में बिखराव ला रहा है। उन्मुक्त जीवनशैली, संवाद की कमी, असंवेदशील सोच, असहिष्णुता और विवाहेत्तर संबंध जैसे कई कारण वैवाहिक रिश्तों के टूटने का कारण बन रहे हैं। साथ ही सहनशीलता और सकारात्मक सोच में कमी के चलते छोटी-छोटी वजहों से भी शादीशुदा जीवन बिखर रहा है। यहां तक कि स्मार्ट उपकरणों ने भी रिश्तों में सेंध लगाई है। उम्रभर के साथ वाले रिश्ते में भी लोग एक-दूसरे के लिए समय निकलने के बजाय आभासी दुनिया में वक्त बिता रहे हैं।

विवाह विच्छेद के अधिकतर मामले बड़े शहरों से ही सामने आ रहे हैं। पिछले पांच साल में मुंबई जैसे शहरों में शादीशुदा जीवन में अलगाव के मामले 200 प्रतिशत तक बढ़े हैं। युवा और कामकाजी जोड़ों की बड़ी जनसंख्या वाले शहर बेंगलुरु में तलाक के बढ़ते मामलों के कारण 2013 में तीन नए फैमिली कोर्ट खोलने पड़े थे। ये आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम पति-पत्नी एक दूसरे की बात न सुनना जरूरी समझते हैं और न ही समझना, जबकि यह एक कटु सच है कि सह-अस्तित्व और एक दूसरे से तालमेल बैठना के भाव के बिना कोई परिवार नहीं चल सकता। रीत रहे भरोसे के इस दौर में वैवाहिक रिश्तों में संदेह और गलतफहमियां भी बहुत जल्दी जगह बना लेती हैं। यही वजह है कि मामूली मनमुटाव भी अब तलाक का कारण बन रहा है। कारण कई हैं, लेकिन वैवाहिक रिश्तों के न निभ पाने की प्रमुख वजह हमारे सामाजिक-पारिवारिक ढांचे का बिखराव ही है, जो हर हाल में चिंतनीय है।

(लेखिका शिक्षिका हैं)

इतिहास से सबक लेने की जरूरत

ताशकंद और शिमला समझौते के सबक शीर्षक से युक्त अपने लेख में सुरेंद्र किशोर ने भारत-पाकिस्तान के साथ हुए 1965 और 1971 के युद्ध के बाद होने वाले द्विपक्षीय समझौते के हश्र से सबक लेने की जो बात की है, वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एकदम सटीक है। क्योंकि मोदी सरकार ने अनुच्छेद-370 और 35-ए पर निर्णायक कदम उठाते हुए, जिस तरह से जम्मू-कश्मीर के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है, उससे पाकिस्तान बौखला गया है। भारत के इस कठोर फैसले से पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब पीओके के साथ कश्मीर को मिलाने की उसकी साजिश नाकामयाब हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान की किसी भी गैरजिम्मेदाराना हरकत के प्रति भारत को न केवल सचेत रहने की जरूरत है, अपितु सीमा पार से होने वाली गोलीबारी और घुसपैठ का करारा जवाब देकर पाकिस्तान को यह संदेश भी देना है कि अब भारत उसकी किसी भी बेजा हरकत को पहले की तरह बर्दाश्त नहीं करेगा। वस्तुतः अभी तक भारत ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान के प्रति जैसी उदारता बरती है उसके बदले में उसे प्रतिघात ही मिले हैं। ताशकंद और शिमला समझौते में भारत ने उदारतापूर्वक अपने द्वारा जीती गई पाकिस्तानी जमीन और उसके आत्मसमर्पित बंदी सैनिकों को सकुशल वापस कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने इस समझौते के विपरीत आतंकवाद के जरिये भारत के साथ छद्म-युद्ध छेड़ दिया। बावजूद इसके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस सेवा शुरू करते हुए स्वयं पाकिस्तान जाकर मैत्री का संदेश दिया था। लेकिन बेशर्म पाकिस्तान ने बदले में कारगिल युद्ध का आघात दिया। भला ऐसे दगाबाज पाकिस्तान पर भारत कैसे भरोसा करे? यद्यपि मोदी शासित भारत बहुत ही सतर्क निगाहों से पाकिस्तान की छोटी से छोटी हरकत को भी देख रहा है। इसके बाद भी भारत को इतिहास से सबक लेते हुए अविश्वसनीय और गैरजिम्मेदार पाकिस्तान के प्रति विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

डॉ. वीपी पाण्डेय

मेलबाक्स

दोषियों को मिले सख्त सजा

शासन-प्रशासन की गलतियों के कारण ही आज सभी स्कूलों में दिए जा रहे मिड-डे मील की गुणवत्ता में कमी देखी जा रही है। यह केवल शामली, अमरोहा और मिर्जापुर के ही विद्यालयों की बात नहीं है, कमोबेश पूरे देश में यही हाल है। घूसखोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम न लगने के कारण मिड-डे मील में बच्चों के भोजन के साथ लापरवाही बरती जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मिर्जापुर में एक विद्यालय में बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए देना शर्मिंदगी की बात है। एक तरफ हम मंगलयान पर सवार हो मंगल ग्रह की यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चे नमक रोटी खाने को मजबूर हैं। नमक रोटी खाने के लिए एक बच्चे का बाध्य होना यह दर्शाता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार कितनी तेजी से पांव पसार रहा है। सरकार कुछ भी करने की कोशिश करती है तो अधिकारी-कर्मचारी मिलकर इसको पूरा नहीं होने देते। बीच में ही उन पैसों का बंदरबांट हो जाता है। इसलिए मिड-डे मील की गुणवत्ता को गिराने में जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

ट्रंप को मोदी का संदेश

27 अगस्त को प्रकाशित संपादकीय ट्रंप से खरी बात पढ़ा। फ्रांस के बायरिट्ज शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने खरी-खरी बात कह दी कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और भारत पाकिस्तान के मसले द्विपक्षीय हैं, इसमें हम किसी तीसरे राष्ट्र को तकलीफ नहीं देना चाहते। इस खरी टिप्पणी से डोनाल्ड ट्रंप को भी ये संदेश पहुंच गया होगा कि आज के भारत को झुकाया नहीं जा सकता। इससे पहले चीन को भी ये कड़ा संदेश दे दिया गया है कि वह भारत के अंदरुनी मामले में हस्तक्षेप न करे। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। अनुच्छेद 370 हटाने से पाकिस्तान से और चीन की लगती सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत ने सभी जरूरी मंचों पर भी यही आवाज उठाया कि वह कश्मीर पर मध्यस्थ का राग इसलिए सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये उसका आंतरिक मामला है। पाकिस्तान से भी अगर किसी मामले पर बात होगी तो वह पाक अधिकृत कश्मीर पर ही होगी।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

15000 से अधिक बड़ी दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता है हर साल कोलकाता की हुबली नदी में। अनुमान है कि विसर्जित होने वाली प्रतिमाओं में से अधिकांश 15 से 50 फुट ऊंची होती हैं।

आजकल

एक सामाजिक व्याधि है रैगिंग

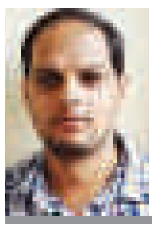
अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

सैफई स्थित उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूपीयूएमएस) में 20 अगस्त को हुई घटना से साफ है कि रैगिंग के मामले में न तो कानून अपना काम कर पा रहा है और न ही संस्थान अपने यहां होने वाली ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था बना पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि रैगिंग की मानसिकता समझकर उसके निदान के बारे में सोचा जाए। अब रैगिंग को एक सामाजिक व्याधि मानकर उसका उपचार करने की जरूरत है

अदालतों ने शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के निर्देश दे रखे हैं, सरकारें भी ऐसी घटनाओं को लेकर संजीदा हैं, पर दाखिलों के बाद देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के नाम पर क्या-क्या होता है सैफई स्थित उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूपीयूएमएस) में 20 अगस्त, 2019 को हुई घटना इसका स्पष्ट उदाहरण है। कहने को राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश पर सत्यान्वेषी समिति (फैक्ट फाइंडिंग कमेटी) ने जांच शुरू कर दी है, इसे 28 अगस्त को रिपोर्ट भी सौंपनी है, लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं, उनसे प्रतीत हो रहा है कि घटना में दोषी पाए गए सात छात्रों को राहत मिल सकती है। उन पर दर्ज एफआइआर के फैसले पर दोबारा विचार हो सकता है। यूं पहली बार यह मामला प्रकाश में आने पर दावा किया गया था कि सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों से भारतीय संस्कारों के तहत एक प्रक्रिया करवाई थी, लेकिन इस घटना का वीडियो सामने आया तो पता चला कि सीनियर छात्रों ने यूनिवर्सिटी के करीब डेढ़ सौ जूनियर छात्रों का जबरन मुंडन करवा दिया था और हॉस्टल के सामने इन सभी छात्रों की परेड करवाई गई थी। इनसे फिल्मी अंदाज में 'हुजूर तोहफा कबूल है' के नारे भी लगवाए गए थे। घटना की संजीदगी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि नाराज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने मेडिकल यूनिवर्सिटी की मान्यता रद करने तक की चेतावनी दी। साथ ही रैगिंग में शामिल हर एक छात्र पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने को भी कहा था। इसके अलावा जिला प्रशासन की रिपोर्ट में भी विश्वविद्यालय प्रशासन को रैगिंग छिपाने का दोषी पाया गया।

कितनी कारगर है एंटी रैगिंग यूनिट

ऐसी कोई भी रैगिंग अंततः किस नतीजे पर पहुंचती है, इसकी एक मिसाल कुछ ही महीने पहले मुंबई के नायर अस्पताल से जुड़े टोपीवाला मेडिकल कॉलेज से एमडी कर रहीं डॉ. पायल तड़वी की आत्महत्या के रूप में सामने आई थी। डॉ. तड़वी ने रैगिंग की प्रताड़ना के दबाव में 22 मई, 2019 को आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पूरे देश में इस प्रकरण को लेकर हंगामा मचा था। इस मामले में गंभीर बात यह थी कि डॉ. तड़वी ने रैगिंग की शिकायत कॉलेज प्रशासन से की थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। आत्महत्या के बाद इस कॉलेज की तीन महिला डॉक्टरों को रैगिंग और प्रताड़ना के आरोप में महाराष्ट्र के रेजीडेंट डॉक्टर संघ ने निलंबित अवश्य किया, लेकिन इससे समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। रैगिंग की कोई दर्दनाक घटना हो चुकने के बाद कानून कितने भी उपाय कर ले, लेकिन इससे प्रताड़ित होने वाले छात्र को शायद ही कोई राहत मिलती हो। समस्या यह है कि रैगिंग की ऐसी तमाम घटनाएं उन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होती रहती हैं, जहां एंटी रैगिंग यूनिटें पहले ही बनाई जा चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यादातर शिक्षण संस्थानों में एंटी रैगिंग यूनिटें सिर्फ खानापूर्ति के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि वे वहां पढ़ने आ रहे नए छात्रों को रैगिंग से बचाने में पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो रही हैं। यहां तक कि आइआइटी जैसे संस्थानों में रैगिंग की जा रही है, जबकि वहां एंटी रैगिंग सेल और यूनिटें मौजूद हैं।

मेलजोल के नाम पर मनमानी

पहचान और मेलजोल बढ़ाने के नाम पर शिक्षण संस्थानों में बदस्तूर जारी रैगिंग का सबसे खराब पहलू इसमें दबंग जातियों का हावी होना और समाज में कायम सामंतवाद का झलकना है। इस सामंती रोग के कारण नए छात्रों को दबा-कुचला और शोषित महसूस कराया जाता है और विरोध करने वाले छात्रों को जातिसूचक शब्दों से प्रताड़ित करने के अलावा इस तरह तंग किया जाता है कि कई बार उन्हें आत्महत्या में ही इससे छुटकारे का रास्ता नजर आने लगता है। वर्ष 2019 के डॉ. तड़वी के हादसे से चार साल पहले 2015 में ऐसी ही एक घटना चेन्नई के एक इंजीनिरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे 19 साल के एक हैदराबादी युवक के साथ हुई थी। तब बीटेक के दूसरे साल के छात्र वी. कृष्ण चैतन्य ने रैगिंग से परेशान होकर हैदराबाद स्थित अपने घर में फांसी लगा ली थी। आत्महत्या के अपने नोट में उसने साफ लिखा है कि वह कॉलेज के एक सीनियर छात्र द्वारा प्रताड़ित करने के कारण यह कदम उठा रहा है। यह सीनियर छात्र उससे अपना जेब खर्च लेता था और उसकी पिटाई भी करता था।

कॉलेजों और हॉस्टलों की चारदीवारी के भीतर युवा छात्रों (लड़के और लड़कियों) के साथ क्या-क्या होता है-इसका कुछ खुलासा तभी हो पाता है, जब आत्महत्या जैसी कोई बड़ी घटना हो जाती है। इधर पिछले कुछ वर्षों में कानूनन कुछ सख्ती तो हुई है, पर यह सख्ती लगता है कि जैसे कागजों में ही सिमट कर रह गई है। कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश के हर उच्च शिक्षण संस्थान में रैगिंग के खिलाफ एक समिति बनाने से लेकर संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर संस्थान की मान्यता रद करने तक का निर्देश दिया हुआ है। कानूनी तौर पर रैगिंग पर पाबंदी है और इस संबंध में लगभग सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को सख्त निर्देश है कि अगर ऐसी घटना हुई तो इसकी जवाबदेही उन्हें भी लेनी होगी, लेकिन देखने में आया है कि ये सारे प्रबंध कागजी ही साबित हुए हैं। न तो कॉलेजों में परिचय या मेलजोल बढ़ाने के नाम पर की जाने वाली रैगिंग रुकी है और न ही इसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत या उदाहरण मिले हैं। ऐसे मामलों में ज्यादातर संस्थान घटनाओं को मामूली कहासुनी या दो गुटों में सामान्य मारपीट दिखाकर उन्हें रफादफा करने की कोशिश करते हैं। उनके ऐसे कदम ही उद्दंड छात्रों को रैगिंग के नाम पर मनमानी करने की प्रेरणा देते हैं।

असल में अब रैगिंग को एक सामाजिक व्याधि मानकर उसका उपचार करने की जरूरत है। रैगिंग क्यों नहीं रुक पा रही है-इसके कारणों को भी अब समझना होगा। वास्तविकता यह है कि ज्यादातर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बहुत सारे युवा रैगिंग को कथित तौर पर परिचय की संस्कृति मानते हैं, लेकिन परिचय बढ़ाने के नाम पर कई बार उद्दंड किस्म के छात्र सारी हदें पार कर जाते हैं। मेलजोल बढ़ाने के नाम पर दाखिला लेने वाले नए छात्रों के साथ वे ऐसा बर्ताव करते हैं, जिससे कि या तो उस छात्र की समूची जिंदगी बर्बाद हो जाती है या फिर वह बचाव का कोई रास्ता नहीं देखकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। साफ हो रहा है कि रैगिंग के मामले में न तो कानून अपना काम कर पा रहा है और न ही संस्थान अपने यहां होने वाली घटनाओं की रोकथाम की कोई मुकम्मल व्यवस्था बना पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि रैगिंग की मानसिकता समझकर उसके निदान के बारे में सोचा जाए।

खुद को श्रेष्ठ समझने की विकृत सोच

देखने में आया है कि रैगिंग करने में प्रायः वे छात्र आगे होते हैं जो या तो फिल्मों से प्रेरित किसी विकृत मानसिकता के शिकार होते हैं या फिर वे अपने भीतर किसी छद्म श्रेष्ठता अथवा सामंतवादी भाव से प्रेरित होते हैं। इसी कारण वे संस्थान में आने वाले नए छात्रों को निरीह एवं कमजोर समझकर उनसे अपनी कही हर बात-आदेश मानने को कहते हैं। चूंकि नए छात्रों में इतना साहस नहीं होता कि वे वरिष्ठ छात्रों की शिकायत कर पाएं, इसका फायदा रौब जमाने वाले सीनियर छात्रों को होता है। वे नए छात्रों को हर मामले में कमजोर साबित करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उनका अहं तुष्ट होता है। कभी-कभी तो वे नए छात्रों से अपनी यौन पिपासा भी शांत करना चाहते हैं या फिर अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का जरिया बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि नए छात्र शर्म और भय की वजह से किसी भी मंच पर उनकी शिकायत नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे अपना मनमाना शोषण जारी रखते हैं। यह सही है कि ऐसे असंख्य मामलों में नए छात्र शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर पाते होंगे, लेकिन कुछ छात्र सीनियर छात्रों की धौंस एवं शोषण से घबराकर आत्महत्या जैसा रास्ता चुन लेते हैं, जिससे रैगिंग की घटनाएं प्रकाश में आ जाती हैं।

रोकथाम के लिए चले अभियान

रैगिंग के बारे में अब नए नजरिये से सोचने की जरूरत है, तभी इसकी कुछ रोकथाम संभव है। पहले तो यह मानना होगा कि यह सिर्फ दाखिले के वक्त पेश आने वाली समस्या नहीं है। सामंतवादी सोच रखने वाले युवा-सीनियर छात्रों की दबंगई पूरे साल चलती रह सकती है-इस तथ्य को अब स्वीकार कर लेना होगा। कानून ने तो रैगिंग के खिलाफ ऐसे बंदोबस्त कर रखे हैं कि दबंग से दबंग छात्र रैगिंग करने से पहले सौ बार सोचे, लेकिन ये प्रबंध सिर्फ कागजी यानी दिखावा हैं-यह तो रैगिंग की लगातार जारी घटनाओं से साबित हो ही रहा है। दबंग छात्र और कॉलेज एवं प्रशिक्षण संस्थान लचर कानूनी और शासन व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं, अन्यथा उन पर रैगिंग रोकने का भारी दबाव होता।

समझना होगा कि कानूनी सख्ती और शिक्षण संस्थान की सजगता के साथ-साथ उनमें पहले से पढ़ रहे छात्रों को रैगिंग के नुकसान के बारे में और नए छात्रों को इसकी शिकायत हर हाल में दर्ज कराने को प्रेरित करने की जरूरत है। छात्रों में मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह समझ बनानी होगी कि रैगिंग असल में एक तरह का सामंतवाद है, जो भारत जैसे समतावादी एवं लोकतांत्रिक देश में कायम नहीं रह सकता।

सामंती सोच का अवशेष

यह अजीब विडंबना है कि जिन शिक्षण संस्थानों में छात्र अपने दिमागी जाले साफ करने जाते हैं, वहां एक-दो वर्ष बिता देने के बाद उनके दिमाग में विकृत सोच की गंदगी की मात्रा और बढ़ जाती है। ऐसी एक नहीं, कई घटनाएं हैं जो इसके सुबूत देती हैं। जैसे दो साल पहले 2017 में आइआइटी कानपुर में हुई एक घटना काफी चर्चा में रही थी। इस संस्थान के सेकंड ईयर के छात्रों ने अगस्त 2017 माह में नए छात्रों के कपड़े उतरवा उन्हें घंटों अश्लील हरकत करने को मजबूर किया था। छात्रों की शिकायत के बाद बनी जांच कमेटी ने 22 सीनियरों को रैगिंग के मामले में संदेह के दायरे में रखकर जांच की थी। संस्थान की सर्वोच्च एकेडमिक बॉडी सीनेट ने दोषियों को अपना पक्ष रखने के लिए एक मौका भी दिया था। जांच पूरी होने पर 22 दोषी छात्रों को 3 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। दावा किया गया कि इस नामी संस्थान में ऐसी रैगिंग वर्षों से जारी थी। वहां हर साल सैकड़ों छात्र अपने जूनियर्स को तंग करते रहे हैं।

ऐसी ही एक घटना तीन वर्ष पूर्व 2016 की है। इस हादसे में केरल के मलप्पुरम जिला स्थित एक मेडिकल कॉलेज में फ्रेश बैच के छात्रों को रैगिंग के तहत टॉयलट साफ करने और गंदा पानी पीने को मजबूर किया गया था। करीब 40 छात्रों की शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन सक्रिय हुआ और 21 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया था।

खरी-खरी

बालाकोट! और बड़ा बालाकोट...

बीएल आच्छा

बेहद पुराने किले में घूमते हुए मैंने गाइड से पूछा-रात को इस खंडहर हुए परकोटे वाले किले में कोई आता है? वह बोला-नहीं बाबू जी, रात के सन्नटे में कौन आएगा? हां, यह डर भी है कि कोई प्रेतात्मा चक्कर लगाती है। मैंने कहा-इसका कोई सुबूत? वह बोला-बाबूजी, लोगों का विश्वास है। डर भी बैठा हुआ है। कोई किंवदंती भी है अतृप्त आत्मा की। मगर बिना सुबूत कैसे माना जाए? सुबूत तो जरूरी है। भारत में लोकतंत्र है। सुबूतों की जमीन पर खड़ा लोकतंत्र। बिन सुबूतों के कोई लोकतंत्र पारदर्शी कैसे बने?

सरहद पर रोजमर्रा की गोलीबारी ने जानें लीं। बदले में सर्जिकल हुआ। पाकिस्तान मुंहअंधेरे ही चीं बोल गया। पर सुबह होते ही मुंह धोकर साफ कर लिया। सरकार ने सर्जिकल की दुंदुभि बजाई। पर सवाल सुबूतों का था। लाख सेना कहे। लोकतंत्र सुबूतों के बिना पारदर्शी नहीं होता। बहस-मुबाहिसे। टीवी के वाक्युद्ध। पार्टियों की गोलंदाजी। यों 'उरी' बनी। मगर फिल्म कोई सुबूत नहीं। वायरल होते वीडियो! मगर वीडियो और सुबूत अलग-अलग चीजें हैं।

पुलवामा गुस्सैल उड़ान भरकर बालाकोट हो गया। मिनटों में आतंकी अड्डा बारूदी आग में स्वाहा हो गया। गोले गिरे, लाशें बिछीं। मगर सुबूत? एफ-16 गिराया। मगर सुबूत? विपक्ष का फर्ज है सुबूत मांगना। पाकिस्तान ने भी महीने भर तक देसी-विदेशी खबरीले परिंदों को पर नहीं मारने दिया बालाकोट में। पूरा चुनाव बालाकोट की शोहरत और सुबूतों की मांग में सिमट गया।

पर पिछले दिनों पुराने किले की प्रेतात्मा बालाकोट का सच कहने को मजबूर कर गई। यों सच का डर प्रेतात्मा की तरह झनझनाता है। राजधानी छोड़कर अपने देश की आजादी का जलसा मनाने वजीर-ए-आला पीओके पहुंच गए। क्रिकेट के पुराने हाथ, मगर राजनीति का बल्ला नया-नया। छक्का लगाने की स्ट्रेटेजी में बोल गए-मुझे पक्की खबर है, इंडिया चुप नहीं बैठेगा। अब इंडिया बड़ा बालाकोट करने की साजिश रच रहा है। मतलब छोटा बालाकोट तो हो ही गया था।

जो पहले मार खाकर भी रोया नहीं, वही महा-डर से घबराकर वजीर-ए-आला की जुबां से निकल गया। मार खाए देश ने ही बालाकोट की पर्ची सुबूत के रूप में पकड़ा दी। सुबूत भी और भविष्य के बालाकोट का खौफ भी।

ट्वीट-ट्वीट

सरकार और विपक्षी दलों को आपसी मतभेद भुलाकर कश्मीर पर कोई हल निकालने का संकल्प लेना चाहिए ताकि कश्मीर में हालात सामान्य हो सकें। पहले इंसानियत को देखा जाए। बाकी बातें बाद आती हैं।
सुधींद्र कुलकर्णी@SudheenKulkarni

सरकारी दबाव में आरबीआइ ने अपना जो सरप्लस सरकार को दिया है उससे तीन बातें स्पष्ट हैं। एक यही कि यह सरकार के वित्तीय दिवालियेपन का सूचक है। दूसरा-सरकार द्वारा रिजर्व बैंक जैसी स्वायत्त संस्था पर हमला है और तीसरा यही कि जनता की जो कमाई आरबीआइ ने बचाई वह सरकार ने उड़ाई। जयवीर शेरगिल@JaiveerShergill

सरकार की आलोचना करने वाले ध्यान दें कि अव्वल तो रिजर्व बैंक ने यह कदम जालान समिति की सिफारिश के बाद उठाया है और दूसरा अरविंद सुब्रमण्यम जैसे लोगों के चार लाख करोड़ रुपये के अनुमान के उलट रिजर्व बैंक ने इस मद में 53,000 करोड़ रुपये ही जारी किए हैं।
सुनील जैन@thesuniljain

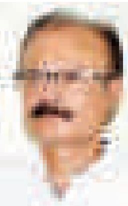
आलोक मिश्रा
राज्य संपादक, नईदुनिया, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ डायरी

बरसात के मौसम में बजी चुनावी घंटी

भाजपा और कांग्रेस के बीच चित-पट का खेल इस साल तो बंद नहीं होने वाला। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा... अब आगे एक विधानसभा का उपचुनाव... और उसके बाद निकाय चुनाव। पिछले साल नवंबर से शुरू हुआ यह दौर अभी जारी है और कुछ महीने जारी ही रहेगा। भादो के इस पखवाड़े छत्तीसगढ़ का मौसम सरकारी उठा-पठक के बीच उपचुनाव की घंटी बजते ही कुछ-कुछ राजनीतिक हो चला है। और बात जब राजनीति की हो तो अपना दांव चलने से भला कौन चूकने वाला। इधर शह-मात के खेल में बारी-बारी से बाजी मारने वाले दोनों दलों ने सियासी मिजाज दिखाना शुरू कर दिया है।

विधायक भीमा मंडावी की शहादत से खाली पड़ी दंतेवाड़ा सीट पर अगले महीने चुनाव घोषित हो चुके हैं। दोनों के लिए ही यह सीट मायने रखती है। 12 विधानसभा सीटों में से पूरे बस्तर संभाग में भाजपा के पास यही एक सीट है। लोकसभा में भाजपा की पौबारह रही, लेकिन राज्य की 11 में नौ पर कब्जा जमाने के बाद भी बस्तर उसके हाथ से फिसला। इस उपचुनाव में यह सीट वह कतई नहीं गंवाना चाहेगी। जबकि विधानसभा में भारी जीत के बाद लोकसभा में औंधे मुंह गिरी कांग्रेस बस्तर में अपना वजूद बचाने में कामयाब रही थी। इसलिए कांग्रेस चाहेगी कि वह दंतेवाड़ा में 21 सौ वोटों का गड्ढा पाटकर 'बस्तर हमारा है' का संदेश दे दे। लोकसभा चुनाव के बाद मोदीमय हुए माहौल में यह जीत मनोबल बढ़ाने वाली होगी। हालांकि इधर आदिवासियों में कांग्रेस थोड़ी कमजोर भी पड़ी है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी दिवस को सरकार स्तर पर मनाया और उस दिन सार्वजनिक अवकाश तक घोषित कर दिया। अब दंतेवाड़ा सीट कांग्रेस की पुरानी लोकप्रियता को तो कसौटी पर कसेगी ही वहीं सरकार के आठ महीनों का मूल्यांकन भी करेगी। इसलिए दोनों ही दल आजमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दंतेवाड़ा के साथ ही विधायक दीपक बैज के बस्तर से सांसद बन जाने से चित्रकोट भी खाली है। कांग्रेस को लग रहा था कि अगल-बगल की इन दोनों सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे तो यह उसके पक्ष में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर कांग्रेस आपत्ति भी जता रही है कि एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे। चित्रकोट को भी समय से जनप्रतिनिधि मिल जाए तो वहां का विकास कार्य गति से होता रहे, लेकिन कांग्रेस का यह अलाप बेअसर ही दिखाई दे रहा है।

इन दिनों सरकार 'तबादला इच्छुकों' से भी खूब परेशान है। नई सरकार बनने के बाद अब जब तबादलों पर से रोक हटी तो हर तरफ कतारें लग गईं। मंत्रियों के बंगले तक भीड़ जुटने लगी। जिसका हुआ वह खुश, जिसका नहीं उसका मुंह सूजा। शिक्षा विभाग तो खासा चर्चा में रहा। तीस हजार से ज्यादा मास्साबों की अर्जियां लगीं। दलाल सक्रिय हो गए। पहली सूची जारी होते ही बवाल शुरू हो गया। कांग्रेसी विधायकों का दल मंत्री के ठौर पहुंच गया। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया तक बात गई। अब मुख्यमंत्री ने ठोस पहल का आश्वासन दिया है और सूची अपने यहां से जारी करवाने की बात कही है, लेकिन चाहे जितना भी पारदर्शी इसे बनाया जाए, कुछ न कुछ अपेक्षाएं तो टूटेंगी ही, और जब टूटेंगी तो खिलाफ ही होंगी। इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी जब से कार्यभार संभाला है, खासी सक्रिय हैं। लगातार भेंट मुलाकातों का दौर जारी है और निर्बलों को न्याय दिलाने की बात वह लगातार दोहरा रही हैं। इसी बीच एक पत्र सामने आ गया। यह उनके पूर्व पद के लेटर हेड पर था। इस पत्र में कांग्रेसी विधायकों को तोड़कर भाजपा में लाने की बात लिखी थी। पत्र फर्जी करार दिया गया। करार देने के बाद वह वाकई फर्जी हो भी गया। बाद में इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं चली।

अंत में : जोगी की जाति-पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति प्रदेश में खासी चर्चा में है। वे कहते हैं कि वे आदिवासी हैं, लेकिन जाति की छानबीन को बनीं एक नहीं दो समितियों ने उसे नकार दिया है। पहले भाजपा सरकार में बनी समिति ने जब उनके खिलाफ रिपोर्ट दी तो जोगी यह कहते हाईकोर्ट चले गए थे कि कमेटी कोरम पूरी नहीं करती। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब भूपेश सरकार ने जो कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट भी जोगी के खिलाफ है। जोगी का आरोप है कि इस कमेटी ने हस्ताक्षर करके सादे कागज भूपेश को दे दिए थे। वे अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या देश में प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण पर रोक लगा दी जानी चाहिए?

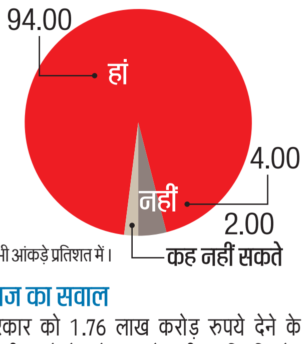

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने के आरबीआइ के फैसले पर कांग्रेस की आपत्ति उचित है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

भाषा पाकिस्तान की रहें बोलते आप,
जनता देती जायगी रोज आपको शाप।
रोज आपको शाप सदा भोगोगे दुर्गति,
यदि ना सके सुधार बंधुवर तुम अपनी मति।
हम भारत के लोग रखें क्या उनसे आशा,
बहुत भा रही आज पाक को जिनकी भाषा!
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

प्रदूषण का कारण न बनें पर्व

पंकज चतुर्वेदी
पर्यावरण मामलों के जानकार

पर्व आपसी सौहार्द बढ़ाने, स्नेह एवं उमंग का संचार करने और बदलते मौसम में स्फूर्ति के संचार के वाहक होते हैं। आज इन्हें अपने मूल स्वरूप में अक्षुण्ण रखने की चुनौती है

भारत में पर्व केवल सामाजिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि वे प्रकृति के संरक्षण का संकल्प और कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर भी होते हैं। भारत के सभी त्योहार सूर्य, चंद्रमा, धरती, जल संसाधनों, पशु-पक्षी आदि की आराधना पर केंद्रित हैं। बीते कुछ वर्षों में भारतीय आध्यात्म को बाजारवाद की ऐसी नजर लगी कि अब पर्व पर्यावरण को दूषित करने का माध्यम बनते जा रहे हैं। हर साल सितंबर महीने के साथ ही बारिश के बादल अपने घरों को लौटने को तैयार हो जाते हैं। सुबह सूरज कुछ देर से दिखता है और जल्दी अंधेरा छाने लगता है। मौसम के इस बदलते मिजाज के साथ पर्व-त्योहारों का दौर भी शुरू हो जाता है। सनातन मान्यताओं की तरह प्रत्येक शुभ कार्य के पहले गजानन गणपति की आराधना अनिवार्य है और इसीलिए उत्सवों का प्रारंभ गणेश चतुर्थी से ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में अगस्त-2016 में अपील कर चुके हैं कि देव प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की नहीं बनाएं, मिट्टी की ही बनाएं, लेकिन देश के दूरस्थ अंचलों की छोड़ दें, राजधानी दिल्ली में भी इस पर अमल नहीं दिखता है। गणपति स्थापना तो प्रारंभ होता है, इसके बाद दुर्गा पूजा या नवरात्रि, दीपावली से ले कर होली तक एक के बाद एक आने वाले त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक हैं। विडंबना है कि जिन त्योहरों के रीति रिवाज, खानपान कभी समाज और प्रकृति के अनुरूप हुआ करते थे, आज पर्व के मायने हैं पर्यावरण, समाज और संस्कृति, सभी का क्षरण।

गत एक दशक के दौरान विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं, राज्यों के प्रदूषण बोर्ड आदि ने गंगा, यमुना, गोमती, चंबल जैसी नदियों की जल गुणवत्ता का गणपति या देवी प्रतिमा विसर्जन से पूर्व एवं पश्चात अध्ययन किया और पाया कि आस्था का यह ज्वार नदियों के जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसी कई रिपोर्ट लाल बस्तों में बंधी पड़ी हैं और आस्था के मामले में दखल से अपना वोट-बैंक खिसकने के डर से शासन धरती के अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहा है। महाराष्ट्र, उससे सटे गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलगांना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल में पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला गणेशोत्सव अब देश में हर गांव-कस्बे तक फैल गया है। दिल्ली में ही हजार से ज्यादा छोटी-बड़ी मूर्तियां स्थापित होती हैं। पारंपरिक तौर पर मूर्ति मिट्टी की बनती थी, जिसे प्राकृतिक रंगों, कपड़ों आदि से सजाया जाता था। आज प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बन रही हैं, जिन्हें रासायनिक रंगों से पोता जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को जब्त करने की चेतावनी भी दी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और पूरा बाजार रासायनिक रंगों से पुती प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं से पटा हुआ है।

गणेशोत्सव का समापन होता ही है कि नवरात्रि में दुर्गा पूजा शुरू हो जाती है। यह पर्व भी लगभग पूरे भारत में मनाया जाने लगा है। हर गांव-कस्बे में एक से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक पूजा पंडाल बनने लगे हैं। बीच में विश्वकर्मा पूजा भी आ जाती है। एक अनुमान है कि हर साल देश में इन तीन महीनों के दौरान कई लाख प्रतिमाएं बनती हैं और इनमें से 90 फीसद प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं। इस तरह देश के ताल-तलैया, नदियों-समुद्र में नब्बे दिनों में कई सौ टन प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक रंग, पूजा सामग्री मिल जाती हैं। पीओपी ऐसा पदार्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता है। चूंकि ज्यादातर मूर्तियां पानी में न घुलने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती हैं, जिन्हें विषैले एवं पानी में न घुलने वाले रंगों में रंगा जाता है, इसलिए हर साल इन मूर्तियों के विसर्जन के बाद पानी में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से घट जाती है जो जलीय जीवों के लिए जानलेवा साबित होती है। कुछ वर्ष पहले मुंबई से वह विचलित करने वाला समाचार मिला था जब मूर्तियों के धूमधाम से विसर्जन के बाद लाखों की तादाद में जुहू किनारे मरी मछलियां पाई गई थीं।

पहले शहरों में कुछ ही स्थानों पर सार्वजनिक पंडाल में विशाल प्रतिमाएं रखी जाती थीं, लेकिन अब अंदाजा है कि अकेले मुंबई में कोई डेढ़ लाख गणपति प्रतिमाएं हर साल समुद्र में विसर्जित की जाती हैं। इसी तरह से कोलकाता की हुबली नदी में ही 15000 से अधिक बड़ी दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। अनुमान है कि विसर्जित होने वाली प्रतिमाओं में से अधिकांश 15 से 50 फुट ऊंची होती हैं। बंगाल में तो वसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा के लिए कोई एक करोड़ प्रतिमाएं स्थापित करने और उनको विसर्जित करने का भी रिवाज है। चूंकि ये पर्व बरसात समाप्त होते ही आ जाते हैं, जुलाई महीने में मछलियों के भी अंडे एवं बच्चों का मौसम होता है। ऐसे में दुर्गा प्रतिमाओं का सिंदूर, सिंथेटिक रंग आदि पानी में घुलकर उसमें निवास करने वाले जलचरों को भी जहरीला करते हैं। बाद में ऐसी ही जहरीली मछलियां खाने पर कई गंभीर रोग इंसान के शरीर में घर कर जाते हैं। इसके साथ ही ये धीरे-धीरे भोजन श्रृंखला का हिस्सा बन अनेक बीमारियों का भी कारण बनते हैं।

सवाल खड़ा होता है कि तो क्या पर्व-त्योहारों का विस्तार गलत है? इन्हें मनाना बंद कर देना चाहिए? एक तो हमें प्रत्येक त्योहर की मूल आत्मा को समझना होगा, जरूरी तो नहीं कि बड़ी प्रतिमा बनाने से ही भगवान ज्यादा खुश होंगे! क्या छोटी प्रतिमा बनाकर उसका विसर्जन जल-निधियों की जगह अन्य किसी तरीके से करके अपनी आस्था और परंपरा को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता? प्रतिमाओं को बनाने में पर्यावरण मित्र सामग्री का इस्तेमाल करने जैसे प्रयोग तो किए ही जा सकते हैं। पूजा सामग्री में प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित करना, फूल-ज्वारे आदि को स्थानीय बगीचे में जमीन में दबाकर उसका खाद बनाना, चढ़ावे के फल, अन्य सामग्री को जरूरतमंदों में बांटना, बिजली की जगह मिट्टी के दीयों का प्रयोग ज्यादा करना, तेज ध्वनि बजाने से बचना जैसे साधारण से प्रयोग हैं जो पर्वों से उत्पन्न प्रदूषण एवं उससे उपजने वाली बीमारियों पर काफी हद तक रोक लगा सकते हैं।

1997 में हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से गांव में किसान के घर जन्मे नीरज चोपड़ा 1958 में मिल्खा सिंह के बाद किसी भी खेल में एक ही वर्ष (2018) में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 28 अगस्त 2019

'भगीरथ' प्रयास से गंगा का जल चंगा

उम्मीद ▸ उत्तर प्रदेश में गंगा जल की गुणवत्ता पर दिखा असर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दावा और सुधरेंगे हालात

आंकड़े भले ही पूर्णरूप से संतोषजनक नहीं हैं, लेकिन निर्मल गंगा की दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं कदम

रूमा सिन्हा, लखनऊ

नमामि गंगे का असर उत्तर प्रदेश के कानपुर सहित कई शहरों में देखने को मिल रहा है। फाइल

नमामि गंगे का असर उत्तर प्रदेश में गंगाजल की गुणवत्ता पर साफ दिखने लगा है। बीते तीन वर्ष के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से पुष्टि हुई है कि गंगा सफाई की कोशिशों से जहां सीवेज प्रदूषण में कमी आई है, वहीं औद्योगिक प्रदूषण पर भी कुछ हद तक लगाम लगी है। यद्यपि आंकड़ों के अनुसार गंगा की गुणवत्ता अब भी असंतोषजनक श्रेणी में हैं, लेकिन निर्मल गंगा के लिए जारी सरकारी प्रयासों के लिए प्रदूषण स्तर में आई गिरावट को एक अच्छा संकेत माना जा रहा है।

सीवेज जनित प्रदूषकों का स्तर गिरा : राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी विगत तीन वर्ष 2017, 2018 व 2019 के जून माह के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि सीवेज जनित प्रदूषकों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी), टोटल कॉलीफॉर्म, फीकल कॉलीफॉर्म जीवाणुओं के स्तर में जून 2017 के मुकाबले जून 2019 में काफी कमी आई है। बताते चलें कि यूं तो बोर्ड प्रत्येक माह के रिवर क्वालिटी आंकड़े जारी करता है, लेकिन जून माह के आंकड़े इसलिए लिए गए हैं क्योंकि इस समय भीषण गर्मी व नदी में प्रवाह कम होने से नदी प्रदूषण की स्थिति सबसे खराब होती है।

यहां देखा गया सुधार : आंकड़ों पर नजर डालें तो सभी प्रमुख स्थानों कानपुर, जाजमऊ, प्रयागराज, वाराणसी में बीओडी के स्तर में कमी आई है। वहीं, सीवेज जनित हानिकारक जीवाणुओं (टोटल व फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया) की तादाद में भारी कमी आई है। फीकल कॉलीफार्म मल जनित जीवाणु होते हैं। कानपुर डाउनस्ट्रीम पर इनकी संख्या में सर्वाधिक कमी आई है। यहां टोटल कॉलीफॉर्म एक लाख 20 हजार से घटकर 33 हजार व फीकल कॉलीफॉर्म 47 हजार से घटकर 21 हजार ही रह गए हैं। वहीं, प्रयागराज व वाराणसी में भी इनकी संख्या में 40 से 60 फीसद तक की कमी आई है जो गंगा सफाई अभियान के लिए एक अच्छा संकेत है। उल्लेखनीय है कि नमामि गंगे योजना के तहत बड़े पैमाने पर नालों को रोककर सीवेज डायवर्जन व शोधन का काम किया जा रहा है।

जून माह में प्रदूषण की स्थिति

मॉनीटरिंग स्थल	बी.ओ.डी.			टोटल कॉलीफार्म			फीकल कॉलीफार्म		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
कानपुर अपस्ट्रीम	3.7	3.8	3.6	7000	4600	4300	38000	2500	2600
जाजमऊ (स्नानघाट)	_	5.6	4.8	-	11000	9400	-	7000	4900
कानपुर डाउनस्ट्रीम	5.8	7.6	5.4	120000	84000	33000	47000	27000	21000
प्रयागराज अपस्ट्रीम	3.8	3.8	2.9	39000	27000	20000	17000	13000	11000
प्रयागराज डाउनस्ट्रीम	4.1	3.6	3.0	41000	26000	22000	22000	13000	11000
वाराणसी डाउनस्ट्रीम	6.0	5.6	3.5	70000	63000	27000	49000	43000	17000

चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ सीवेज प्रदूषण, तो दूसरी और औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए भी चाकचौबंद प्रबंध किए गए हैं। इंडस्ट्री की वेब कैमरे से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। टेनरी के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। केवल नदियां ही नहीं सहायक नदियों व सभी नालों की नियमित निगरानी की जा रही है। गंगा के प्रवाह पर भी काम किया गया है। यही वजह है कि गंगा में सुधार दिखाई देने लगा है। आने वाले समय में स्थितियां और बेहतर होंगी।

– आशीष तिवारी, सदस्य सचिव, उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

खास मोबाइल एप के जरिये कहीं से भी बच्चों की क्लास पर रख सकेंगे नजर

प्रमोद चौधरी, जामताड़ा

डिजिटल इंडिया के जमाने में अभी सिर्फ स्कूल संचालक ही सीसीटीवी पर क्लास रूम की गतिविधियों को देख पाते थे, लेकिन अब अभिभावक भी अपने घर, दफ्तर या कहीं से भी स्कूल में अपने बच्चों पर नजर रख सकेंगे। बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहने वाले अभिभावकों को भी इससे मदद मिलेगी। यह संभव हुआ है बिहार के अरवल के रहने वाले साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ व कंप्यूटर इंजीनियर दीपक कुमार के प्रयास से। हाल ही में झारखंड के जामताड़ा पहुंचे दीपक ने बताया कि उन्होंने ट्रांसपेरेंट एजुकेशन एप बनाया है जो बच्चों की कक्षा की गतिविधियों को अभिभावकों के मोबाइल तक पहुंचाएगा। इस तकनीक से बच्चों की पढ़ाई में भी सुधार होगा।

ऐसे काम करेगा एप : दीपक ने बताया कि यह एप थ्रीडी तकनीक पर आधारित है। अभिभावकों को अपने मोबाइल फोन में एजुकेशन एप को डाउनलोड करना होगा। एप के माध्यम से मोबाइल में क्लास, बच्चे का रोल नंबर व पहचान से जुड़े आधार का नंबर डालना पड़ेगा। स्कूलों की कक्षाओं में लगे सीसीटीवी से क्लास की गतिविधि मोबाइल पर दिखेगी। क्लास रूम की आवाज भी मोबाइल पर सुनी जा सकेगी।

इतना आएगा खर्च : स्कूल प्रबंधन को इस सेवा को देने के लिए हर कक्षा में 40-50 हजार रुपये खर्च करने होंगे। इस राशि से सीसीटीवी, डाटा बेस मॉनिटर व अन्य उपकरण लगेंगे। इसे इंटरनेट के सहारे मोबाइल एप का प्रयोग कर अभिभावकों से जोड़ दिया जाएगा। दीपक ने बताया कि सितंबर में इस एप को लांच कर दिया जाएगा।

ऐसे मिली प्रेरणा : दीपक ने बताया कि वर्ष 2004 में स्मार्ट क्लास की तकनीक बोकारो के कुछ स्कूलों में शुरू कराई थी। तब मन में यह विचार आया कि सीसीटीवी से कक्षा की स्थिति केवल स्कूल के प्राचार्य देख पाते हैं। अभिभावकों को भी इसमें शामिल किया जाए तो और भी अच्छा होगा। तब कोशिश शुरू की। अंततः काफी मशक्कत के बाद यह एप तैयार कर लिया।

तलाशी राह

▸ **बिहार के कंप्यूटर इंजीनियर को खास मोबाइल एप विकसित करने में मिली सफलता, अगले माह होगा लांच**

दीपक कुमार, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ। जागरण

दिल्ली व लखनऊ के डीएवी स्कूल से होगी शुरुआत

इस सुविधा को देश में पहली बार दिल्ली व लखनऊ का डीएवी स्कूल प्रबंधन शुरू करेगा। दीपक कुमार से इस मामले में प्रबंधन की बात हुई है।

एजुकेशन एप बन चुका है। दिल्ली व लखनऊ के डीएवी स्कूल की कक्षाओं को इससे जोड़ दिया जाएगा। यह तकनीक अभिभावकों के लिए लाभदायक होगी। बच्चों की सुरक्षा भी हो सकेगी। स्कूलों में निगरानी से बच्चों के शैक्षणिक स्तर में भी सुधार हो सकेगा।

– दीपक कुमार, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट

जिम कॉर्बेट पार्क में शेर, चीता और गैंडा लाने की तैयारी

त्रिलोक रावत, रामनगर (नैनीताल)

योजना परवान चढ़ी तो जिम कॉर्बेट पार्क के जंगल में बाघों के अलावा अब शेर, चीता व गैंडा भी घूमते हुए मिलेंगे। दरअसल, बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट में अब इन वन्य जीवों को लाने पर भी विचार किया जा रहा है। देहरादून में होने वाली बैठक में वनाधिकारियों की मौजूदगी में इस पर चर्चा हो सकती है।

कॉर्बेट पार्क देश-विदेश में मुख्य रूप से बाघों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हाथी, गुलदार, भालू, सांभर, चीतल, घड़ियाल, मगरमच्छ, पक्षियों की विभिन्न प्रजाति समेत अनेक सरीसृप प्रजातियां मौजूद हैं। इन सबके बीच जंगल की सुंदरता यहां चार चांद लगाती है। इन्हें देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलता है।

ऐसे में अब यहां वन्य जीवों की प्रजातियों को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें शेर, चीता व गैंडा को कॉर्बेट में लगाने की पहल हो सकती है। इस संबंध में 30 अगस्त को देहरादून में होने वाली स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा। बैठक में इन वन्य जीवों को यहां लाने व उसमें आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों पर भी मंथन किया जाएगा।

बाघों के लिए मशहूर जिम कॉर्बेट में अब चीते भी दिखाई देंगे। फाइल फोटो

...तो विदेश से लाया जाएगा चीता

कॉर्बेट में जिन प्रजातियों को लाने पर विचार हो रहा है, उन्हें लाने के लिए समय भी लग सकता है। इसकी वजह यह है कि जिस चके को कॉर्बेट में लाने की बात हो रही है, वह देश से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में जाहिर है कि उसे विदेश से ही यहां लाया जाएगा। इसके अलावा गुजरात से शेर तथा गैंडे को लाया जाएगा। कॉर्बेट के निदेशक राहुल के अनुसार, शेर, चीता व गैंडा को कॉर्बेट में लाने पर विचार किया जा रहा है। स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड की बैठक में इस पर फैसला होगा।

डाटागीरी

छोटे राज्यों में छात्र और शिक्षक का अनुपात सबसे अच्छा

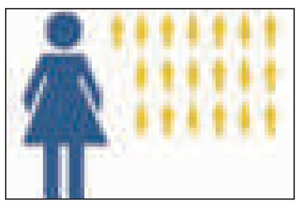

प्रतीकात्मक

देश में बड़े राज्यों की तुलना में छोटे राज्यों में छात्र और शिक्षक का अनुपात सबसे अच्छा है। बीते दिनों संसद में सरकार द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत के राज्यों में पीटीआर की स्थिति क्या है और शिक्षा के अधिकार का कितना पालन हो रहा है।

2017-18 में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन (यूडीआइएसई) द्वारा संकलित रिपोर्ट के अनुसार, त्रिपुरा, सिक्किम और नगालैंड में छात्र और शिक्षक का अनुपात (पीटीआर) सबसे अच्छा है।

यह मापदंड तय किए हैं सरकार ने : सरकार ने देश में छात्र-शिक्षक अनुपात का मापदंड तय किया गया है। इसके तहत प्राथमिक विद्यालय में यह 30:1 यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक में यह 35:1 होना चाहिए। यूडीआइएसई की रिपोर्ट में पाया गया कि अभी देश में प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात औसतन 23:1 तो उच्च प्राथमिक के लिए 24:1 है।

बिहार जैसे बड़े राज्यों की स्थितियां खराब

रिपोर्ट में बिहार जैसे बड़े राज्य में स्थितियां खराब पाई गई हैं। यहां 67.94 फीसद प्राथमिक विद्यालय और 77.86 फीसद उच्च प्राथमिक विद्यालय मानक के अनुरूप नहीं हैं। यहां छात्र-शिक्षक औसत सबसे निचले स्तर पर है। जहां प्राथमिक स्तर पर 38:1 और उच्च प्राथमिक में 39:1 का औसत है। उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी छात्र और शिक्षक का अनुपात अच्छा नहीं है। केरल जैसा बड़ा राज्य जहां शिक्षा के अधिकार का सबसे ज्यादा अनुपालन किया गया है, वहां भी छात्र और शिक्षक का अनुपात मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है।

छात्र-शिक्षक अनुपात

सबसे अच्छे पांच राज्य

राज्य	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
सिक्किम	4	6
नगालैंड	7	8
मणिपुर	8	9
अंडमान एंड निकोबार द्वीप	10	9
त्रिपुरा	10	10

सबसे खराब पांच राज्य

राज्य	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
बिहार	38	39
दिल्ली	35	34
उत्तर प्रदेश	31	30
दमन एंड दिउ	29	23
झारखंड	25	30

आंकड़े अनुपात में

किस राज्य में कितने फीसद स्कूल मानकों पर खरे नहीं उतरे

सबसे अच्छे पांच राज्य

राज्य	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
त्रिपुरा	0.72	2.85
सिक्किम	1.26	0.27
अंडमान एंड निकोबार द्वीप	2.20	1.96
पुडुचेरी	2.99	1.11
नगालैंड	2.21	0.85

सबसे खराब पांच राज्य

राज्य	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
बिहार	67.94	77.86
झारखंड	50.28	64.24
उत्तर प्रदेश	41.30	42.06
आंध्र प्रदेश	43.13	14.68
राजस्थान	38.85	16.62

सभी आंकड़े फीसद में

ईशान के निशाने ने सीनियर खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे

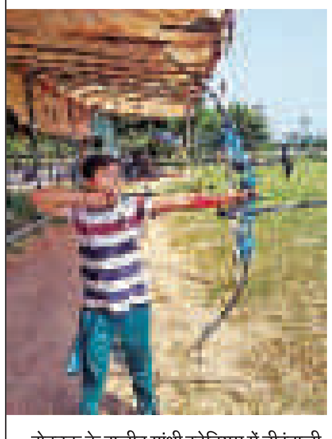
रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में तीरंदाजी का अभ्यास करता ईशान हुड्डा। जागरण

सफलता की कोई उम्र नहीं होती। अगर लगन पक्की हो तो किसी भी क्षेत्र में ज्यादा अनुभवी व्यक्ति को भी पछाड़ा जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हरियाणा के रोहतक जिले के 14 वर्षीय ईशान हुड्डा ने। इस युवा तीरंदाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीनियर खिलाड़ियों को पछाड़ नेशनल कैंप में अपनी जगह बनाई है...

उभरता सितारा

रतन चंदेल, रोहतक

अगर इरादा पक्का हो तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी भेदा जा सकता है। ऐसे ही मजबूत इरादों की बानगी पेश कर रहा है हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला 14 वर्षीय ईशान, जो तीरंदाजी के क्षेत्र में तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। प्रदेश स्तर के साथ-साथ कई नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल कर चुके ईशान का निशाना इतना शानदार है कि बीते दिनों उसने अपनी उम्र से अधिक अनुभव वाले खिलाड़ियों को पछाड़कर सीनियर नेशनल कैंप में अपनी जगह बनाई है। ईशान के कोच संजय सुहाग का दावा है कि ईशान भारतीय तीरंदाजी इतिहास में इतनी कम उम्र में सीनियर खिलाड़ियों को पीछे छोड़ सीनियर नेशनल कैंप में जगह बनाने वाला पहला खिलाड़ी है।

इस तरह शुरू हुआ सफर : ईशान ने बताया कि चार साल पहले उसने स्कूल में बच्चों को तीरंदाजी करते देखा। उसने भी संकल्प लिया कि वह भी तीरंदाजी करेगा। परिवार में कोई भी इस खेल से जुड़ा नहीं था, लेकिन संकल्प का विकल्प नहीं होता। उसने अभ्यास शुरू किया और जब कुछ अच्छा प्रदर्शन करने लगा तो स्कूल की टीम में शामिल कर लिया गया। परिवार वालों ने भी प्रोत्साहित किया और अब वह रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में रोजाना सात घंटे अभ्यास करता है।

ये हैं उपलब्धियां

- **2018-19 में आंध्र प्रदेश में हुए नेशनल खेलों में पांच व एक कांस्य पदक जीता**
- **2017 में मणिपुर में नेशनल खेलों में दो स्वर्ण पदक हासिल किए। प्रदेश स्तर पर भी कई मेडल अपने नाम किए**

ईशान में सीखने की ललक है। उसकी एकाग्रता काबिल-ए-तारीफ है। पिछले छह साल में मेरे पास पहला ऐसा बाल खिलाड़ी है, जिसकी एकाग्रता का स्तर अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजों जैसा है।

– संजय सुहाग, कोच

ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य : ईशान का लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। ईशान प्रदेश से लेकर नेशनल तक कई मेडल जीत चुका है। नेशनल कैंप के लिए उनके समक्ष ऐसे तीरंदाज थे, जिनमें से अनेक का अनुभव ईशान से ज्यादा था, लेकिन गंभीर व शांत स्वभाव के ईशान ने शानदार प्रदर्शन किया और अनुभवी खिलाड़ियों पर भारी पड़ते हुए भारतीय टीम के कैंप में स्थान बनाया।

पढ़ाई में भी रहता है अव्वल : रोहतक के एमडीएन स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाला ईशान हमेशा प्रथम श्रेणी में पास होता है। ईशान के पिता जितेश कुमार हरियाणा पुलिस में सिपाही हैं, जबकि मां सविता प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हैं।

फोटो न्यूज

तेजी से बढ़ रहा ड्राइवरलेस वाहनों का बाजार

विश्व की पहली ऑन डिमांड ड्राइवरलेस बस सर्विस

ड्राइवरलेस वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। चीन सहित कई देशों में ड्राइवरलेस बस सर्विस शुरू हो चुकी है। अब सिंगापुर ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए नई पहल की है। दरअसल, बीते दिनों सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड रिजॉर्ट में ऑन डिमांड ड्राइवरलेस बस सर्विस लांच की गई। फिलहाल इसका ट्रायल रन किया गया, लेकिन जल्द ही यह आम लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। इस तरह सिंगापुर दुनिया का पहला देश होगा, जहां ऑन डिमांड ड्राइवरलेस बस सर्विस उपलब्ध होगी।

एप से होगी बुकिंग

इस सर्विस के लिए लोग अपने मोबाइल पर एप के जरिये बुकिंग करा सकेंगे। सिंगापुर के परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, अगले कुछ महीनों में पूरे शहर में कई अन्य ड्राइवरलेस व्हीकल सर्विस शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। (फोटो एएफपी)

ट्रायल रन के दौरान रहा ड्राइवर

बीते दिनों जब इस बस का ट्रायल रन किया गया तब ड्राइवर सीट पर एहतियात के तौर पर चालक को बैठाया गया था। हालांकि, ट्रायल के दौरान उसके बस संभालने की नौबत नहीं आई, लेकिन उसके होने से बस में बैठे यात्रियों ने राहत की सांस ली थी। परिवहन मंत्रालय का कहना है कि लोगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है।

अलीबाबा की ड्राइवरलेस डिलीवरी सेवा

कुछ माह पहले ही चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने सामान की डिलीवरी के लिए ड्राइवरलेस वाहन की सर्विस शुरू की थी। इसकी शुरुआत चीन के शियोनगान से की गई। यह वाहन एक बार में 200 छोटे पार्सल की डिलीवरी कर सकता है। कंपनी की योजना धीरे-धीरे चीन के अन्य शहरों में भी यह सेवा शुरू करने की है। बता दें कि अलीबाबा ड्रोन के जरिये भी सामान की डिलीवरी कर चुका है।

हवा में जहर घोल रही है अमेजन आग

धरती का फेफड़ा कहे जाने वाले अमेजन के जंगल धधक रहे हैं। पूरे दुनिया के पर्यावरणविद् चिंतित हैं। इस आग की गर्मी फ्रांस में सोमवार को संपन्न हुए जी-7 सम्मेलन में भी महसूस की गई। आग को बुझाने के लिए धरती पर युद्धस्तर पर प्रयास जारी हैं तो आसमान में एक ऐसी आंख है जो टकटकी लगाएं इससे प्रदूषित हो रहे वायुमंडल का आकलन कर रही है। नासा का एक्वा सेटेलाइट अमेजन के जंगलों में लगी आग से वायुमंडल में बढ़ते कार्बन मोनोआक्साइड की मात्रा का आकलन कर रहा है।

गैस का गुण

हवा के साथ कार्बन मोनोआक्साइड गैस लंबी दूरी तय कर सकती है। यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की वायु को प्रभावित करने में सक्षम है। वायुमंडल में करीब एक महीने तक मौजूद रह सकती है। इसके बाद ही इसका असर खत्म होता है।

अच्छी बात

वैज्ञानिकों के अनुसार अच्छी बात यह है कि गैस बहुत ऊंचाई पर है। लिहाजा जिस वायु को हम सांस के साथ अंदर लेते हैं वह इससे अछूती है, लेकिन अगर तेज हवा इसके प्रदूषक तत्वों को धरती की तरफ धकेल देंगी तो दुनिया के अधिकांश हिस्से की वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

धरती का फेफड़ा

अमेजन के जंगल धरती पर ऑक्सीजन तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यहां धरती की कुल ऑक्सीजन का 20 फीसद हिस्सा तैयार होता है। लिहाजा इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। वैश्विक समुदाय इसीलिए चिंतित है क्योंकि इससे वायु गुणवत्ता के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने का खतरा है। अमेजन बेसिन तीस लाख पौधों और जीवों की प्रजातियों का घर है। दस लाख जनजातियां यहां रहती हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में इस क्षेत्र का बड़ा योगदान है। इसके जंगल लाखों टन उत्सर्जित कार्बन को हर साल सोखते हैं। लेकिन लगातार आग की घटनाओं से पेड़ों में जमा कार्बन फिर से वायुमंडल में पहुंच रहा है।

कैम्स का आकलन

अमेजन के जंगलों में लगी आग से उठ रहे धुएं का गुबार अमेजन और उसके आसपास के इलाकों में छाया हुआ है। यूरोपीय संघ के अर्थ आब्जर्वेशन प्रोग्राम के तहत भेजे गए सेटेलाइट कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मानीटरिंग सर्विस (कैम्स) के अनुसार यह धुंआ अटलांटिक तट तक फैल गया है। यहां से 3200 किमी दूर साओ पाउलो का आसमान भी धुएं से भर चुका है। आग से बड़ी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड गैस निकल रही है। इस साल आग से 228 मेगाटन कार्बन डाईऑक्साइड निकलने का अनुमान है। गैस की यह मात्रा 2010 के बाद सर्वाधिक है। इस घटना में कार्बन मोनोआक्साइड भी उत्सर्जित हो रही है।

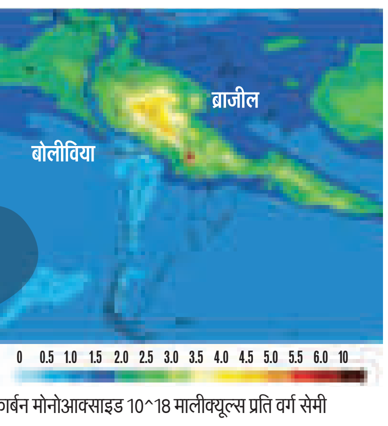

कार्बन मोनोआक्साइड 10^18 मालीक्यूल्स प्रति वर्ग सेमी

भयावह स्थिति

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एटमास्फेरिक इंफ्रारेड साउंडर (एयर्स) सेटेलाइट पिछले तीन दिनों से अमेजन के जंगलों में लगी आग से निकल रही जहरीली गैस कार्बन मोनोआक्साइड का आकलन कर रहा है। ये गैस 18 हजार फीट की ऊंचाई पर एकत्र हो रही है। यह ऊंचाई नेपाल के माउंट काला पत्थर और तंजानिया के किलिमंजारो के बराबर है। मैप में जिस तरह से रंग हरे से पीले और फिर लाल में तब्दील हो रहा है, वह बताता है कि कार्बन मोनोआक्साइड का सांद्रता (पीपीएम) में तेजी से वृद्धि हो रही है।

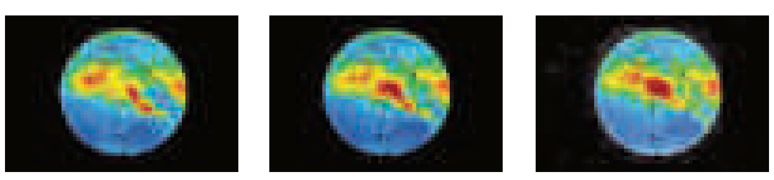

8 लाख मस्जिदें हैं इंडोनेशिया में। मस्जिदों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। यहां करीब तीन लाख मस्जिदें हैं। वहीं, करीब ढाई लाख मस्जिदों के साथ बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है।

मिंटी के युद्ध कौशल ने भारतीय नारी शक्ति को दिया नया आयाम

जागरण विशेष ▶ 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक और अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना के जवाबी हमले को नाकाम करने में निभाई अहम भूमिका

दीपक बहल, अंबाला

▶ **युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने जा रहीं भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल**

बीती 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने सीमापार एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। इस अभियान में बतौर पाथ फाइंडर और फाइटर कंट्रोलर बेहद अहम भूमिका निभाने वालीं भारतीय वायुसेना की युवा स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को आठ अक्टूबर को वायुसेना दिवस पर युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया जाएगा। यह गौरव हासिल करने वाली वह देश की पहली महिला बनने जा रही हैं। वायुसेना के सौजन्य से आयोजित विशेष साक्षात्कार में मिंटी ने कहा- दुश्मन विमानों को सीमा पर आते देख मुझे लगा मानो इसी क्षण के लिए मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की है और देश के लिए मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है।

26 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 27 को पाकिस्तानी वायुसेना को मुंहतोड़ पटखनी देने वाले गौरवशाली क्षणों के बारे में मिंटी और उनके परिजनों से हमने विशेष बातचीत की। मिंटी का परिवार हरियाणा के अंबाला शहर में रहता है। पिता रिटा. ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर रवींद्र अग्रवाल, बड़े भाई अरविंद अग्रवाल और पति राहुल गुप्ता सहित मिंटी की सासु, भाभी और हर रिश्तेदार, हर नागरिक उनके इस पराक्रम पर गर्व का अनुभव कर रहा है। पिता रवींद्र कहते हैं, 'बिटिया ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया है...।' भाई अरविंद और पति राहुल भी मिंटी की सूझबूझ और मानसिक दृढ़ता की तारीफ करते नहीं थकते। कहते हैं मिंटी ने सभी को गर्व से भर दिया है। अरविंद के हवाले से मिंटी ने कहा, मैं अपनी सासु मां और भाभी को भी श्रेय देना चाहूंगी, जिनके प्रोत्साहन और सहयोग से मैं देश के लिए अपने दायित्व की सफलतापूर्वक पूर्ति कर सकी। मेरी मां आज जीवित होतीं तो वे भी बहुत खुश होतीं...।

इस तरह लड़ा युद्ध... : मिंटी ने बताया कि फाइटर कंट्रोल यूनिट वायुसेना की अग्रिम पंक्ति है। देश की हवाई सीमा की निगरानी यही करती है। न केवल निगरानी बल्कि हवाई लड़ाई की स्थिति में रडार स्क्रीन पर एक-एक विमान की पॉजिशन और गतिविधि के अनुरूप त्वरित रणनीति तैयार कर अपने युद्धक विमानों को दिशानिर्देश देना बेहद जिम्मेदारी भरा काम है। 26 और 27 को मैं इस यूनिट की उत्तरी कमांड का नेतृत्व कर रही थी। 26 को एयर स्ट्राइक के बाद हम पूरी तरह सजग थे कि यदि पाकिस्तान की ओर से पलटवार किया गया तो उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। हुआ भी यही। 27 की सुबह मैं अपने निगरानी कक्ष में तैनात थी। रडार स्क्रीन पर मैंने जल्द ही भांप लिया कि करीब 25 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमारी ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही पलों में मैं आश्वस्त हो चुकी थी कि इनका रुख श्रीनगर की ओर है और हम पर हवाई हमला होने जा रहा है। मैंने तुरंत अलार्म दे दिया। सबसे पहले श्रीनगर में तैनात तीन युद्धक विमानों को दुश्मन विमानों की लोकेशन बताते हुए उनका रास्ता रोका गया। अन्य जगहों पर भी हमारे लड़ाकू विमान अलर्ट मोड में थे। उन्हें भी पाकिस्तानी विमानों की लोकेशन बताते हुए सहायक दिशानिर्देश दिए। कुछ ही पलों में दुश्मन विमानों और हमारे विमानों के बीच हवाई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हम उन पर भारी पड़े। हमारे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी विमानों को बम गिराने का मौका न देते हुए खदेड़ना शुरू कर दिया।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

वायुसेना की फाइटर कंट्रोलर स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल। सौजन्य से – अरविंद अग्रवाल

मैंने अभिनंदन से कहा– टारगेट लॉक... हिट... और दुश्मन का विमान तबाह

मिंटी ने बताया, 'मेरा काम दो स्तर पर था। एक, अपने पायलटों को दुश्मन विमानों की सटीक लोकेशन मुहैया कराना और समन्वित रणनीति तैयार करना, ताकि दुश्मन पर जल्द काबू पाया जा सके। दूसरा, इससे पहले कि हमें दुश्मन कोई नुकसान पहुंचाए, उसे ढेर कर देना। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने मिग–21 बायसन लड़ाकू विमान से दुश्मन के दो एफ–16 विमानों का पीछा कर रहे थे। मैं उन्हें दुश्मन विमानों की सटीक लोकेशन दे रही थी। जल्द ही वह क्षण आया जब मैंने कहा– टारगेट लॉक... हिट...। अभिनंदन ने मिसाइल दाग दी और पल भर में दुश्मन का विमान आग के शोलों में तब्दील हो गया। इसके बाद दूसरे विमान को निशाने पर लिया गया, लेकिन इस बीच अभिनंदन का विमान सीमा के पार जा पहुंचा। मैंने उन्हें वापस मुड़ने का संकेत दिया, पर ठीक उसी समय वे सीमा पार उस रेंज में प्रवेश कर गए, जहां जैमर लगे होने के कारण तकनीकी संपर्क टूट गया। कुल मिलाकर आधे घंटे से भी कम समय में हमने दुश्मन को खदेड़ दिया था, वह भी अपने इलाके में बिना कोई बड़ा नुकसान उठाए...।'

मानो इसी एक क्षण की मुझे प्रतीक्षा थी...

सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण कौन सा था, इस पर मिंटी ने कहा, 'जब मैंने रडार स्क्रीन पर मिल रहे संकेतों से यह भांपा कि अनेक दुश्मन विमान हम पर हमला करने को बढ़ रहे हैं। बिना चिंतित हुए दृढ़ संकल्प लिया कि अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगी। यही वह वक्त है जिसके लिए मैं एयरफोर्स में भर्ती हुई हूं...। और जब दुश्मन विमान पर टारगेट लॉक करने के बाद उसे हिट करने (विध्वंस) का संकेत दिया। ऐसा लगा मानो इसी एक क्षण की मुझे प्रतीक्षा थी। किसी भी क्षण चुनौती जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि एयरफोर्स में शामिल होने के बाद मैं ऐसी किसी भी चुनौती के लिए हर पल तैयार थी।'

राजौरी की शमीम का डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा

जम्मू–कश्मीर के राजौरी जिले की इरमीम शमीम ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की प्रवेश पाने में सफलता हासिल की। शमीम का मुंह मीठा कराते उनके परिजन। प्रेट्र

जागरण संवाददाता, राजौरी

▶ **जम्मू–कश्मीर के राजौरी की गुज्जर जनजाति से ताल्लुक रखने वाली जिले की पहली छात्रा को एम्स में मिला दाखिला**

▶ **दस किलोमीटर पैदल स्कूल में पढ़ने जाती थीं शमीम**

जम्मू-कश्मीर के युवा राज्य ही नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अब राजौरी जिले की एक गुज्जर समुदाय की छात्रा इरमिम शमीम की मेहनत रंग लाई है। उसने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में दाखिला पाया है। एम्स में दाखिला लेने वाली वह जिले की पहली गुज्जर छात्रा है। अब उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। सीमावर्ती जिले के धनोर गांव की रहने वाली छात्रा पढ़ने के लिए दस किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। छात्रा के इस मुकाम से राजौरी जिले के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद एक तरफ केंद्र सरकार जहां विकास में तेजी लाने के सभी संभव प्रयास कर रही है, वहीं राज्य के युवा भी कामयाबी का परचम लहरा विकास की राह पर बढ़ने को तैयार हैं। कुछ समय पहले तक राज्य में मुश्किल हालात और आतंकवाद के चलते यहां के लोगों, खासकर युवाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब नए माहौल के बीच राजौरी जिले की बेटी इरमिम शमीम ने एम्स में दाखिला पाया है।

सीमावर्ती जिले के धनोर गांव की रहने वाली शमीम की राह काफी मुश्किल भरी थी। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसे स्कूल जाने के लिए हर दिन दस किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती थी। गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। शहर तक आने के लिए इतने वाहन नहीं थे। यही नहीं, पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखने वाली शमीम काफी गरीब परिवार से आती हैं, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से न सिर्फ उसने तमाम बाधाओं से पार पा लिया, बल्कि एम्स जैसे प्रमुख संस्थान में प्रवेश भी पा लिया।

लड़कर ही चुनौतियों से मिलती है सफलता

शमीम ने कहा कि हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या होती है। आपको चुनौतियों से लड़ना होगा। लड़कर ही सफलता मिलती है। शमीम के मुताबिक, उसके इस मुकाम से परिवार काफी खुश है।

विलुप्तप्राय गोडावण पक्षी की प्रजाति को बचाने का प्रयास रहा सफल

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर

▶ **राजस्थान की हैचरी में सात में से छह अंडों से निकले चूजे**

▶ **विदेश से मंगाए गए उपकरण में सहेजकर रखे गए**

▶ **सोन चिरैया के नाम से भी है प्रसिद्ध**

विलुप्तप्राय गोडावण पक्षी की फाइल फोटो।

विलुप्तप्राय गोडावण पक्षी की प्रजाति को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर जिले के समीप स्थापित हैचरी (चूजा पालन केंद्र) में सहेजकर रखे गए सात में से छह अंडों से चूजे बाहर निकल आए हैं। गोडावण के ये सभी छह चूजे एकदम स्वस्थ हैं। सातवें अंडे से चूजा बाहर निकलने का इंतजार किया जा रहा है। सोन चिरैया के नाम से भी प्रसिद्ध गोडावण अब देश में महज 150 ही बचे हैं। ऐसे में यहां जन्मे चूजों ने उम्मीद बंधाई है कि राजस्थान का राज्य पक्षी अब लुप्त नहीं होगा।

प्रदेश के वनमंत्री सुखराम विश्नोई का कहना है कि गोडवाण को बचाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के वन विभाग ने कुछ माह पूर्व गोडावण को बचाने के लिए एक योजना तैयार की थी। जैसलमेर जिले में एक सेंटर स्थापित किया गया। इस सेंटर में गोडावण के अंडों को सहेजने की योजना बनाई गई। विशेषज्ञों को इस सेंटर में विशेष रूप से नियुक्त किया गया। जून माह में गोडावण के अंडे देने के समय वन विभाग ने डेजर्ट नेशनल पार्क से सात अंडों को अलग-अलग समय एकत्र किया। इन अंडों को अबुधाबी से मंगाए गए विशेष तरह के एक्यूबेटर (उपकरण) में रख कर सहेजा गया। इन अंडों को करीब 25 दिन सहेज कर रखना पड़ता है। काफी बड़े आकार के इन अंडों में से पहला चूजा करीब एक माह पहले निकला। इसके बाद वहां तैनात टीम पूरे उत्साह के साथ बाकी छह अंडों को सहेजने में जुट गई। इन सभी चूजों को विदेश से मंगाया गया विशेष आहार दिया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में उपलब्ध इनका प्राकृतिक आहार भी दिया जा रहा है।

इन सभी चूजों को जैसलमेल जिले सम इलाके के सेंटर में ही रख कर बड़ा किया जाएगा। तीन वर्ष में गोडावण व्यस्क होता है और प्रजनन के लिए तैयार होता है। तीन वर्ष तक इन्हें यहां रख कर इनसे अंडे लिए जाएंगे। वहीं, अगले वर्ष इसी तर्ज पर गोडावण के अंडे एकत्र कर इनको इसी तर्ज पर सहेजा जाएगा। इनकी संख्या 25 से अधिक होने पर इन्हें डेजर्ट नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए राजस्थान के वन विभाग के साथ ही देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय के अलावा इस मामले में विशेषज्ञता रखने वाले अबुधाबी के एक संस्थान का सहयोग लिया जा रहा है।

गोडावण को बोलचाल में सोन चिड़िया, हुकना व गुरायिन जैसे नाम से भी बुलाया जाता है। एक मीटर से अधिक ऊंचा यह पक्षी उड़ने वाले सभी पक्षियों में सबसे अधिक वजनी माना जाता है। यह भारत व पाकिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। पहले यह देश के कई राज्यों में पाया जाता था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश में सिर्फ सात व गुजरात में इसकी संख्या महज दो रह गई हैं। दोनों मादा हैं। समूचे देश में इनकी संख्या करीब 150 होगी। इसकी घटती संख्या के कारण इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी की श्रेणी में रखा गया है।

महाभारत के 11 नारी चरित्रों को निभाएंगे ट्रांसजेंडर

जागरण संवाददाता, कोलकाता : महाभारत के 11 नारी चरित्रों को ट्रांसजेंडर निभाते नजर आएंगे। सातवें 'ऋतु उत्सव' के तहत आगामी तीन सितंबर को कोलकाता के आइसीसीआर स्थित सत्यजीत रे ऑडिटोरियम में 'महामानबी' नामक इस नृत्य नाटिका का मंचन होगा। महाभारत के जिन नारी चरित्रों को नृत्य नाटिका में दर्शाया जाएगा, उनमें गंगा, सत्यवती, कुंती, द्रौपदी, अंबा, माद्री, गांधारी, चित्रांगदा, शुभद्रा, उत्तरा और शिखंडी शामिल हैं। नृत्य नाटिका में 'रुद्रपलाश' के कलाकार परफार्म करेंगे।

गौरतलब है कि रुद्रपलाश ट्रांसजेंडर कलाकारों की नाटक मंडली है। रुद्रपलाश की प्रमुख मेघ सायंतनी घोष ने कहा, 'बंगाल के प्रख्यात फिल्मकार ऋतुपर्णो घोष को श्रद्धांजलि स्वरूप हम ऋतु उत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। इसी के तहत इस बार हम नृत्य नाटिका 'महामानबी' का मंचन करेंगे। देश में पहली बार इस तरह की किसी नृत्य नाटिका का आयोजन होगा। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर समुदाय की सांस्कृतिक प्रतिभा दिखाने के साथ-साथ यह संदेश भी देना चाहते हैं कि हमें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है और समाज के हरेक क्षेत्र में समान अधिकार दिया जाना चाहिए।'

नृत्य नाटिका की निर्देशक मेघ सायंती घोष ही हैं जबकि पटकथा भाशवती दत्ता ने लिखी है। कलाकार फिलहाल पूरे उत्साह से फाइनल रिहर्सल में जुटे हुए हैं। नृत्य नाटिका के बाद 11 ट्रांसमेन और ट्रांसवूमेन को 'पड़ा-प्रकृति सम्मान' से नवाजा जाएगा।

सोनागाछी के 'अंधकार' को दूर करने में जुटीं महाश्वेता

▶ **कोलकाता के रेडलाइट इलाके में दो दशक से जारी है सेक्स वर्कर्स के हक की लड़ाई**

▶ **मानव तस्करी के खिलाफ छेड़ रखी है मुहिम**

▶ **यौनकर्मियों के बच्चों का भविष्य भी संवार रही हैं 52 वर्षीय महाश्वेता मुखर्जी**

बंगाल के कोलकाता में दुर्बार महिला समन्वय कमेटी के सोनागाछी स्थित कार्यालय में सेक्स वर्करों से बातचीत करतीं महाश्वेता मुखर्जी (बाएं से तीसरी)। बिमल कर्मकार

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

नारी सशक्तीकरण

कोलकाता स्थित एशिया के सबसे बड़े रेडलाइट एरिया सोनागाछी को उन्होंने बेहद करीब से देखा है। 52 वर्षीय महाश्वेता मुखर्जी पिछले दो दशकों से यहां यौनकर्मी महिलाओं के हित के लिए सक्रिय हैं। समाज की ये घोर उपेक्षित महिलाएं अपने दुख-दर्द उनसे साझा करती हैं। मानव तस्करी के खिलाफ भी उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। महाश्वेता सेक्स वर्कर्स के संगठन दुर्बार महिला समन्वय कमेटी की एडवोकेसी ऑफिसर हैं। सेक्स वर्कर्स को यौन संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूक करना, उनका एचआइवी टेस्ट कराना, संक्रमित पाए जाने पर इलाज की व्यवस्था करना, यौनसुरक्षा के उपाय बताना और उपलब्ध कराना, मानसिक रूप से परेशान महिलाओं को मनोचिकित्सा और परामर्श मुहैया कराना, उनके लिए आर्थिक मदद जुटाना यह सभी काम वह पूरी शिद्दत से करती आ रही हैं। यही नहीं, वे सेक्स वर्कर्स के बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार मुहैया कराकर उनका भी भविष्य संवार रही हैं। किसी को जबरन इस धंधे में न धकेला जाए, इसका भी वे खास ध्यान रखती हैं। संगठन अब तक ऐसी डेढ़ हजार से अधिक किशोरियों व महिलाओं का उद्धार कर उन्हें उनके घर भेज चुका है, जिन्हें जबरन इस धंधे में उतारा जा रहा था।

महाश्वेता बंगाल के 60 रेडलाइट एरिया में नियमित अंतराल में जाकर वहां की सेक्स वर्कर्स के लिए भी काम कर रही हैं। प्रत्येक रेडलाइट एरिया की समस्याओं के लिए स्वयंसेवी समूहों के गठन में भी उनकी अहम भूमिका रही है। ऐसे समूहों में संबंधित इलाके के प्रबुद्ध लोग और सेक्स वर्कर्स भी शामिल हैं। महाश्वेता बंगाल के सांसदों के जरिये मानव तस्करी से जुड़े मसलों को संसद में उठाने को भी तत्पर रहती हैं। जब भी लोकसभा व राज्यसभा का सत्र चलता है, महाश्वेता दिल्ली में होती हैं। उनका संगठन दिल्ली स्थित नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स के साथ मिलकर देशभर में काम कर रहा है।

1999 से जुटी हैं मिशन में : हावड़ा के बाली इलाके के निश्चिंदा की रहने वालीं महाश्वेता 1999 में बतौर फील्ड को-आर्डिनेटर दुर्बार से जुड़ी थीं। उन्हें हावड़ा के तीन क्षेत्रों उलबेरिया, राजगंज और डोमजूड़ में सेक्स वर्करों के लिए खोले गए क्लीनिक के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। महाश्वेता वहां के रेडलाइट एरिया में घूम-घूमकर सेक्स वर्कर्स को यौन संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूक करती थीं और पीड़ितों को क्लीनिक लाकर उनका इलाज कराती थीं। वे डॉक्टर नहीं हैं, फिर भी इलाके में सब उन्हें डॉक्टर दीदी कहकर बुलाते थे। महाश्वेता को इस काम में परिवार का पूरा साथ मिला। ससुराल में पति व सास-ससुर ने समर्थन किया तो मायके में मां ने भी सराहा, हालांकि संकोच के कारण महाश्वेता पिता को इस बारे में नही बता पाई थी। एक दिन टीवी पर दुर्बार के एक सामाजिक कार्यक्रम में पिता ने अपनी बेटी को देखा तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है और उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी।

कोलकाता के सोनागाछी स्थित कार्यालय में महाश्वेता मुखर्जी। जागरण

उनमें और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं

राजनीतिक विज्ञान से स्नातक महाश्वेता ने कहा, 'बचपन में सोनागाछी के बारे में बहुत खराब बातें सुनती थी, लेकिन जब यहां सेक्स वर्कर्स के बीच आई, उनसे मिली, बातें कीं, तो उन्हें समझा। दरअसल, उनमें और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं है। वे आसमान से नहीं टपकी हैं, बल्कि इसी समाज का हिस्सा हैं। उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, तभी ये काम कर रही हैं। सोनागाछी में करीब 10 हजार सेक्स वर्कर्स हैं। इनमें से सात हजार यहीं रहकर पेशा करती हैं। बाकी विभिन्न इलाकों से रोजाना यहां आती हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

जागरण पड़ताल

2014 में सामने आया था झारखंड के सिमडेगा में पहला मामला, अब भी सक्रिय है विषाणु, पूरे भारत में सर्वाधिक मामले यहां हुए दर्ज, अब तक 232 मरीजों में मिले लक्षण, 88 में हुई पुष्टि, 11 की हो चुकी है मौत

भारी पड़ सकती है सिमडेगा में सिर छुपाए एंथ्रेक्स की अनदेखी

उत्तम नाथ पाठक, रांची

11 लोगों की जान ले चुकी है एंथ्रेक्स बीमारी। प्रतीकात्मक

सुनकर चौंक गए होंगे आप, लेकिन यह सच है। कभी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण यूरोप में होने वाली खतरनाक बीमारी एंथ्रेक्स ने झारखंड में भी अपने पांव जमा लिए हैं। वह भी आज से नहीं पांच वर्ष पहले से। 2014 में सबसे पहले एंथ्रेक्स ने झारखंड के सिमडेगा में दस्तक दी थी। अब तक 232 मरीजों में इसके लक्षण मिले, जिनमें 88 में इसकी पुष्टि हो चुकी है। वहीं इस बीमारी से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है।

एंथ्रेक्स के कुछ मामले ओडिशा और बंगाल में सामने आ चुके हैं। लेकिन पूरे भारत में सिमडेगा जितनी संख्या में मरीज मिलने का कोई मामला सामने नहीं आया है। एंथ्रेक्स को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की आशंका हमेशा से जताई जाती रही है। इसके जीवाणु मिट्टी में काफी समय तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं और यह किसी भी केमिकल के संपर्क में आने के बाद सक्रिय हो जाते हैं।

सिमडेगा में एंथ्रेक्स का विषाणु खत्म न होने की जगह साल दर साल फैलता जा रहा है। रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) के माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि पहली बार यह बीमारी बानो में 2014 में सामने आई थी। कुरुचडेगा में कई लोगों में एंथ्रेक्स के लक्षण पाए गए थे। उस समय लोग इसे समझ नहीं सके और पांच लोगों की मौत हो गई थी। तभी मेरे पास पहली बार यह मामला आया था। इसके बाद धीरे-धीरे एंथ्रेक्स के विषाणु ने पूरे जिले को अपनी चपेट में ले लिया और सिमडेगा में यह महामारी बन गया।

जानकारी के अनुसार कोलेबिरा प्रखंड के बंदरचुआ में दो, ठेठईटांगर के बसारटोली, चिमटीटोली, हुरदा के कोहिपाट और किनबिरा बसाटोली में एक-एक मौत 2014 से अब तक हो चुकी है। डॉ. शरण के अनुसार, एंथ्रेक्स को लेकर यहां काफी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सर्विलांस टीम लोगों को जागरूक करती है। जागरूकता ही सबसे पहले बचाव का उपाय है।

बीमारी से मरे हुए मवेशी को दफन करने की जगह खा जाते हैं लोग : सिमडेगा के जिला महामारी रोग विशेषज्ञ डॉ. अध्ययन शरण का कहना है कि यह काफी पिछड़ा क्षेत्र है। लोगों में जागरूकता की कमी थी। कम पढ़े लिखे लोग होने के कारण लोग यहां मृत पशुओं के मर जाने के बाद उसे दफन नहीं करते हैं। बल्कि उसे काटकर उसका मांस खा जाते हैं। बीमारी से मरे पशु में कई तरह के खतरनाक विषाणु होते हैं। वहीं एक वजह यह भी है कि जो लोग मृत जानवर का चमड़ा निकालते हैं, उनके शरीर में भी संक्रमण हो सकता है। आध पका या कच्चा मांस खाने से भी इसका खतरा रहता है।

वर्षवार अब तक हुई मौतों का आंकड़ा

वर्ष	मौत
2014	05
2015	03
2016	02
2017	01

पशुओं में लक्षण

एंथ्रेक्स पीड़ित मवेशी खाना पीना छोड़ देता है और सुस्त पड़ जाता है। शरीर के छिद्रों से खून रिसता है। जानवर की मौत के काफी समय बाद भी उसके शरीर में अकड़न नहीं होती है।

मनुष्य में लक्षण

पीड़ित व्यक्ति के हाथ या पैर पर घाव हो जाता है। शरीर या अंग फूल जाता है। बुखार। सांस लेने में परेशानी और बेचैनी। सीने में दर्द होगा। खून की उल्टी।

उत्तर प्रदेश के नैनी में बनेगा डिजिटल कुंभ म्यूजियम

अमरदीप भट्ट, प्रयागराज

पूरी दुनिया को अपनी आभा से आश्चर्यचकित कर चुके दिव्य और भव्य कुंभ-2019 का अब एक और स्वरूप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही देखने को मिलेगा। इसके लिए 'डिजिटल कुंभ म्यूजियम' की रूपरेखा बनाई गई है। इस म्यूजियम में कुंभ को डिजिटल माध्यम से देखा जा सकेगा। खास यह कि म्यूजियम की इमारत कुंभ कलश के आकार की होगी। इसमें महापुरुषों की मोम की प्रतिमाएं होंगी। नैनी में यमुना नदी किनारे बनने वाले इस म्यूजियम के लिए पर्यटन विभाग ने 285 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है।

प्रयाग की पावन धरती पर कुंभ का आयोजन देख देश-दुनिया ने इसकी दिव्यता को सराहा था। साधु संतों व विभिन्न अखाड़ों ने भी अपने शिविरों को अभूतपूर्व स्वरूप देकर करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। इस कुंभ की यादें ताजा करने के लिए अब पर्यटन विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। योजना है कि गऊघाट से पुराने यमुना पुल को पार करते ही बंधे के दूसरी ओर नैनी की तरफ यमुना नदी के किनारे डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाया जाएगा।

कुंभ म्यूजियम में करीब 285 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने और बजट प्राप्त होते ही निर्माण शुरू कराया जाएगा।

– दिनेश कुमार, उप निदेशक पर्यटन

तीन मंजिला होगी इमारत : म्यूजियम के लिए कुंभ कलश के आकार की तीन मंजिला इमारत का निर्माण कराया जाएगा। इसमें कुंभ से संबंधित चित्रों व अन्य चीजों को कंप्यूटर के जरिये डिजिटल रूप में दिखाया जाएगा। इमारत के निचले तल पर महापुरुषों की मोम की प्रतिमाएं भी लगवाई जाएंगी, ताकि म्यूजियम देखने आने वाले लोग इनके दर्शन कर सकें।

इरडा ने स्थापित किया सिंगल विंडो

नई दिल्ली : इरडा ने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इनीशिएटिव कार्यक्रम में सिंगल विंडो स्थापित की है। इसके माध्यम से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर के विकास के लिए नए प्रयोगों की अनुमति ले सकेंगी। इरडा ने हाल ही में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कार्यक्रम के तहत 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। गौरतलब है कि सैंडबॉक्स कार्यक्रम का उद्देश्य बीमा सेक्टर में इनोवेशन द्वारा विकास व पॉलिसी होल्डर के हितों का संरक्षण करना है। (प्रेट्र)

अमेजन के हाथों शेयर बिक्री केवल पूंजी जुटाने के लिए नहीं की गई है। इस सौदे का मकसद वर्तमान इको-सिस्टम का हिस्सा होना है। इससे दोनों कंपनियों का डिजिटल पेमेंट पोर्टफोलियो मजबूत होगा।

— किशोर बियानी
फाउंडर, फ्यूचर ग्रुप

संसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
37,641.27	11,105.35	₹ 39,670	₹ 46,740	₹ 71.48	$ 58.66
▲ 147.15	▲ 47.50		▲ ₹190	▼ ₹0.54	

राहत ▸ भ्रामक विज्ञापनों के मामले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सेलिब्रिटी को माना गया है कम जिम्मेदार

सेलिब्रिटी पर कम, कंपनी पर होगी ज्यादा कठोर कार्रवाई

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

भ्रामक विज्ञापनों में शामिल होने के बावजूद नामी-गिरामी हस्तियों यानी सेलिब्रिटीज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। उनके खिलाफ अधिकतम केवल एक साल किसी प्रचार में हिस्सा लेने की पाबंदी लगाई जा सकती है। संसद से पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की नियमावली बनाने के लिए बुलाई बैठक में केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा 'भ्रामक प्रचार कराने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें ब्रांड अंबेसडर की भूमिका तो केवल लिखित मैटर के बोलने की होती है। इसलिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।'

पासवान ने कहा कि उत्पाद बनाने वाली कंपनियां जो कुछ लिखकर भ्रामक प्रचार कराती हैं, उसकी सच्चाई की तस्दीक कराना बहुत आसान नहीं है। इसलिए ब्रांड अंबेस्डर या प्रचार में हिस्सा लेने वाली नामचीन हस्तियों की जगह उत्पाद बनाने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में इस आशय का प्रावधान किया गया है। जबकि पहले की जारी गाइडलाइन में भ्रामक प्रचार में शामिल सेलिब्रिटी के खिलाफ भारी जुर्माना और जेल की सजा तक का प्रावधान था।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सेलिब्रिटी का काम सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना है, संबंधित कंपनियां ज्यादा जिम्मेदार हैं। प्रेट्र

आमतौर पर बाजार में कई उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं, जिसमें ब्रांड अंबेसडर के खिलाफ कार्रवाई की बात होती रही है। उपभोक्ताओं को ठगने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इनमें लोगों के निशाने पर सबसे ज्यादा नामचीन हस्तियां ही रही हैं। उस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई की बातें भी उठती रहीं। लेकिन नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में उन्हें राहत मिल गई है। उनके खिलाफ अब अधिकतम कार्रवाई एक साल की पाबंदी होगी। यानी उन्हें एक साल तक किसी उत्पाद के विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी।

उपभोक्ता संरक्षण की बहुत ज्यादा शिकायतें हेल्थकेयर से जुड़ी ही होती हैं। इसके बावजूद नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में हेल्थकेयर सेक्टर में होने वाली धांधली और अनियमितता पर बहुत कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। इस बारे में उपभोक्ता मामलों के मंत्री पासवान ने कहा कि इसे लेकर कानून में बहुत स्पष्टता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि हेल्थकेयर सेक्टर के लिए पहले वाले कानून ही लागू रहेंगे।

ई-कॉमर्स की गाइडलाइंस होंगी अनिवार्य : पासवान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- उपभोक्ता संरक्षण कानून में किए गए सख्त प्रावधान, कसेगा शिकंजा
- नये कानून के लिए दिसंबर तक बन जाएगी नियमावली

उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य से ई-कॉमर्स के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देश नये कानून के पारित होने के बाद कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कानून की अवहेलना करने वाली ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संसद से पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए इस वर्ष के अंत तक नियमावली बन जाएगी। इसके लिए हर किसी को 15 सितंबर तक अपना सुझाव देने की छूट दी गई है। ई-कॉमर्स के बाबत मंत्रालय ने जारी गाइडलाइन पर भी सबसे सुझाव मांगे हैं। तैयार की गई गाइडलाइन नए कानून की नियमावली का हिस्सा हो जाएगी, जिसे लागू करना अनिवार्य बना दिया जाएगा। नियमावली बनाने से पूर्व सांसदों से चर्चा करने के बाद पासवान मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मंगलवार की बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 14 सांसदों ने हिस्सा लिया।

प्रतीकात्मक

बैठक में सांसदों ने विभिन्न पक्षों पर अपनी राय रखी। भाजपा के सांसद विजय गोयल ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण और उपभोक्ता संरक्षण आयोग के बीच के विरोधाभास पर अपनी बात रखते हुए नियमों में सुधार की जरूरत बताई। जबकि अन्य सांसदों ने प्रस्तावित नियमावली में ई-कॉमर्स की गाइडलाइंस को अनिवार्य बनाए जाने पर जोर दिया। बैठक में शामिल उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारियों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की। पासवान ने जोर देकर कहा कि बाजार के बदलते मिजाज को देखते हुए ऐसा करना बेहद जरूरी है।

ये हैं प्रस्तावित गाइडलाइन : उपभोक्ता सचिव अविनाश के. श्रीवास्तव ने बताया कि प्रस्तावित गाइडलाइंस में ई-कॉमर्स कंपनियों को सेल्फ डिक्लेरेशन देने होंगे। ऐसी कंपनियों को हर हाल में 14 दिनों के भीतर रिफंड करने होंगे। सभी उत्पादों की पैकिंग पर गाइडलाइन के मुताबिक शर्तें और शिकायत करने वाला पता भी लिखना होगा। सेंट्रल ट्रिब्यूनल ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कानून के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई कर सकता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी गड़बड़ी करने वाली कंपनियों पर तत्काल कार्रवाई करेगी। उपभोक्ता आयोग शिकायत मिलने वाली मुआवजा दिलाने का काम करेगा। अथॉरिटी भ्रामक प्रचार करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कस सकती है, जांच के बाद उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने में सक्षम होगी।

एसबीआइ के पास पर्याप्त पूंजी, फंड की जरूरत नहीं

मुंबई, प्रेट्र : एसबीआइ ने कहा है कि उसके पास पर्याप्त पूंजी है, उसे इस वर्ष सरकार की ओर से फंड की जरूरत नहीं है। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एसबीआइ के मैनेजिंग डाइरेक्टर अरिजीत बसु ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त फंड है। उन्होंने कहा कि एसबीआइ शेयर बाजार से पूंजी जुटाने में सक्षम है और हमने अपने टियर-1, टियर-2 बांड प्रोग्राम की घोषणा भी कर दी है। बसु ने कहा कि फंड की जरूरत उन बैंकों को है जो बाजार से फंड जुटाने में सक्षम नहीं हैं।

बसु ने कहा कि एसबीआइ फंड जुटाने के लिए नॉन-कोर असेट में अपनी हिस्सेदारी बेचने के बारे में भी सोच रहा है। इससे पहले एसबीआइ के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा था कि बैंक चौथी तिमाही में एसबीआइ कार्ड के लिए आइपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। कुमार ने कहा था कि बैंक जनरल इंश्योरेंस में अपने शेयर बेचने में थोड़ा समय ले सकता है। बसु ने कहा कि सरकार इंडस्ट्री के हित में कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये डालने की बात कही थी।

कई बैंकों ने बाजार में लांच की रेपो रेट आधारित लोन स्कीम

नई दिल्ली, प्रेट्र : अग्रणी सरकारी बैंकों पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और इलाहाबाद बैंक ने आरबीआइ की रेपो रेट पर आधारित रिटेल लोन स्कीम लांच की है। पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी एडवांटेज नाम से रिटेल लोन स्कीम लांच की है। स्कीम के तहत लिए गए लोन पर 0.25 परसेंट की दर से ब्याज देय होगा। यह ब्याज दर पूर्व में लागू एमसीएलआर पर आधारित ब्याज दर से कम होगी। पीएनबी की ओर से बताया गया कि हाउसिंग लोन के लिए नया रेट 8.25 परसेंट से 8.35 परसेंट तक तथा कार लोन के लिए 8.65 परसेंट होगी। पहले लिए गए लोन को बहुत कम शुल्क पर स्कीम से लिंक किया जा सकेगा।

इलाहाबाद बैंक ने कहा है कि वह 75 लाख रुपये तक के लोन को रेपो रेट से लिंक करेगा। बैंक रेपो रेट के साथ ब्याज दरों को जोड़ने के लिए अपने हाउसिंग लोन को 75 लाख रुपये तक रखेगा और मुद्रा लोन को आगामी पहली सितंबर से इस स्कीम के तहत ले आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते शुक्रवार कों कहा था कि रिटेल लोन सस्ता करने के लिए बैंक रेपो रेट पर आधारित लोन स्कीम लांच करेंगे।

केंद्र ने उठाए कदम, अब मैन्यूफैक्चरिंग सुधारने के लिए राज्य आगे आएं : भार्गव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मारुति सुजुकी के चेयरमैन ने कहा- राज्यों के रेवेन्यू में ऑटो इंडस्ट्री का बड़ा योगदान

इकोनॉमी में सुस्ती को रोकने के लिए केंद्र की तरफ से उपायों की घोषणा के बाद अब ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों की नजरें राज्य सरकारों की तरफ मुड़ गई हैं। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है कि राज्यों को इकोनॉमी में अपनी भूमिका को समझते हुए मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। राज्य अपनी भूमिका समझेंगे, तभी देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

भार्गव ने मारुति सुजुकी इंडिया की सालाना आमसभा में शेयरहोल्डर्स को संबोधित करते हुए कहा कि देश में मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़े। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर राज्य सरकारों की भूमिका अहम हो सकती है। सियाम के मुताबिक ऑटोमोबाइल सेक्टर का मैन्यूफैक्चरिंग की जीडीपी में योगदान 45 परसेंट से अधिक है।

राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका : राज्यों की भूमिका का महत्व बताते हुए भार्गव ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की राज्यों के रेवेन्यू में हिस्सेदारी काफी अहम है। अधिकांश राज्यों में टैक्स की दरें काफी ऊंची हैं। इसके लिए उन्होंने पेट्रोल-डीजल पर राज्यों में लगने वाले टैक्स की दरों का हवाला दिया। भार्गव ने कहा कि यह राज्य सरकारों पर ही निर्भर करता है कि वे कार रखने को कितना किफायती बनाते हैं। राज्य सरकारों का यही रुख ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ को तय करता है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें अपनी इस भूमिका को नहीं समझेंगी और देश के विकास में भागीदारी नहीं करेंगी तो पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य को पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इकोनॉमी की रफ्तार को तेज करने संबंधी उपायों की घोषणा पर भार्गव ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम को वित्त मंत्री ने निर्देशित कर दिया है। अब इंडस्ट्री को इसमें बदलाव दिख रहा है। खासतौर पर ऑटो कंपनियों की फाइनेंसिंग कॉस्ट नीचे आ रही है। इसके लिए उन्होंने वित्त मंत्री का आभार भी जताया।

गौरतलब है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की मंदी को लेकर पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री लगातार आवाज उठा रही थी। मांग घटने से वाहनों की बिक्री में तेज गिरावट देखी गई और ऑटोमोबाइल सेक्टर में नौकरियां जाने की खबरें भी आईं। इसके बाद सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए बीते शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्ती को दूर करने संबंधी कई उपायों की घोषणा की थी।

बजाज का नजरिया अलग : हालांकि ऑटो सेक्टर में मंदी की खबरों पर बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज का नजरिया पूरी इंडस्ट्री से एकदम अलग रहा। उन्होंने बीते सप्ताह एक इंटरव्यू में स्पष्ट कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को बिक्री में कमी के लिए खुद अपने गिरेबां में झांककर देखना चाहिए। उन्होंने दोपहिया वाहनों की बिक्री में पांच-सात परसेंट की गिरावट को संकट मानने से इन्कार किया।

गुजरात में फ्लाइंग कार प्लांट लगने की संभावना

जासं, अहमदाबाद : दुनिया के लिए अब तक अजूबा बनी उड़ने वाली कार का एक प्लांट गुजरात में लगने की संभावना है। देश के विविध राज्यों में प्लांट के लिए जगह देखने के बाद डच कंपनी पाल-5 के सह संस्थापक व सीईओ रॉबर्ट डिंजेमेंस के नेतृत्व में कंपनी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री विजय रुपाणी से मुलाकात की।

गुजरात सरकार ने डच कंपनी को राज्य में प्लांट लगाने के लिए जमीन, पानी, बिजली व हर संभव सुविधाएं देनेका भरोसा दिलाया है साथ ही अन्य इनसेंटिव भी देने की बात कही है। गत दिनों कंपनी के अधिकारियों के साथ भारत में डच एंबेसडर और दूतावास के अधिकारी भी मुख्यमंत्री से मिले। कंपनी के अधिकारियों ने इस मुलाकात के बाद बताया कि वे भारत के अन्य राज्यों में भी प्लांट के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं। कंपनी के अधिकारी एशिया में प्लांट के लिए गुजरात में निवेश की संभावना व जगह की तलाश के लिए आए थे। कंपनी का मानना है कि वर्ष 2040 तक दुनिया में उड़ती कार का बाजार डेढ ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। दो पैसेंजर की क्षमता वाली इस कार का वजन 910 किलोग्राम होगा। इसकी ऑन रोड स्पीड 160 किमी प्रति घंटा होगी।

नियमों से खिलवाड़ बंद करें म्यूचुअल फंड कंपनियां : सेबी

मुंबई, प्रेट्र : सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने रिटर्न आधारित म्यूचुअल फंड कंपनियों को दिए गए एक कड़े संदेश में कहा है कि इंडस्ट्री ने अधिक रिटर्न के लिए जोखिम वाले निवेश किए हैं। त्यागी ने कहा कि इंडस्ट्री की खामियां अब सामने आ चुकी हैं, अब समय है कि वे नियमों के आधार पर काम करें और सुरक्षा से खिलवाड़ बंद करें।

- निवेशकों की सुरक्षा है सेबी की प्राथमिकता, अधिक रिटर्न के लिए रिस्की निवेश नहीं करें म्यूचुअल फंड

त्यागी ने म्यूचुअल फंड की टैगलाइन 'सही है' पर बात करते हुए कहा कि निवेशकों ने इन फंड पर बहुत भरोसा दिखाया है। इंडस्ट्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि भरोसा बनने में वर्षों का समय लगा है और यह एक झटके में टूट सकता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए त्यागी ने कहा कि इंडस्ट्री को चाहिए कि सुरक्षा के उपायों को खुद से अपनाएं, जिससे संभावित क्रेडिट डिफॉल्ट के बाद सामने आई समस्याओं से निपटा जा सके।

त्यागी ने कहा कि इंडस्ट्री को उधारी और निवेश के बीच अंतर को ध्यान रखना चाहिए और म्यूचुअल फंड में रिटर्न के साथ सुरक्षा को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड में ट्रस्टी को परोक्ष भागीदार नहीं बनाए रखना चाहिए, वह पहले स्तर पर गेटकीपर की तरह काम करते हैं। त्यागी ने कहा कि ट्रस्टी को तुरंत सुरक्षा उपाय करने चाहिए और सेबी को सूचना देनी चाहिए।

त्यागी के मुताबिक सेबी का पहला उद्देश्य निवेशक के हितों की रक्षा करना है। सेबी समय-समय पर बनाए गए नियमों के मुताबिक अपने काम को अंजाम देता है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए। त्यागी ने कहा कि बीते साल तक म्युचुअल फंड इंडस्ट्री की गिनती भारत में कैपिटल मार्केट की सक्सेस स्टोरी में होती थी, लेकिन बीते साल आइएल एंड एफएस और डीएचएफएल ग्रुप जैसे डिफॉल्टर के सामने आने के बाद इंडस्ट्री को नुकसान का सामना करना पड़ा। त्यागी ने घरेलू निवेशकों की इंडस्ट्री तक पहुंच बढ़ाने के मुद्दे पर कहा कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आधार-आधारित केवाईसी सिस्टम लागू करने के लिए सेबी काम कर रहा है।

लगातार तीसरे सत्र में शेयर बाजार मजबूत

मुंबई, प्रेट्र : शेयर बाजारों में पिछले लगातार दो कारोबारी सत्रों की बढ़त मंगलवार को भी जारी रही। इस सप्ताह शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू इकोनॉमी को जो बूस्टर डोज दिया था, उसका असर सोमवार के बाद मंगलवार को दिखाई दिया। दिन के कारोबार के दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 147.15 अंकों यानी 0.39 परसेंट की बढ़त के साथ 37,641.27 पर बंद हुआ। एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 47.50 अंकों यानी 0.43 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई। दिन के कारोबार के आखिर में निफ्टी 11,105.35 पर बंद हुआ।

मंगलवार को मिलाकर लगातार तीन कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 1,168 अंकों का उछाल ले चुका है। निफ्टी भी इस दौरान 364 अंकों की बढ़त ले चुका है। दिन के कारोबार में ऑटो, मेटल और फाइनेंस सेक्टर के शेयरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सेंसेक्स इंट्रा-डे में 37,731.51 अंक के उच्च स्तर पर जा पहुंचा। इस दौरान इसका निम्न स्तर 37,449.69 अंक रहा। निफ्टी भी इंट्रा-डे में 11,141.75 अंक के स्तर तक गया। सेंसेक्स के कारोबार में टाटा मोटर्स ने 8.87 परसेंट की वृद्धि के साथ सबसे ज्यादा उछाल दर्ज किया। इसके अलावा टाटा स्टील, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, वेदांता और एमएंडएम के शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया।

- आरबीआइ द्वारा सरकार को करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा पर बाजारों में रौनक
- टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के अलावा ऑयल व गैस शेयरों में दिखी बड़ी बढ़त

दूसरी ओर भारती एयरटेल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, कोटक बैंक, सन फर्मा, एचयूएल और एक्सिस बैंक के शेयरों में 3.58 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई। जानकारों के मुताबिक आरबीआइ द्वारा केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए जाने की खबर ने निवेशकों में उत्साह का संचार किया, जिसका सकारात्मक असर बाजार पर दिखा। इसके अलावा इकोनॉमी को गति देने के सरकारी प्रयासों के कारण भी निवेशकों का उत्साह बना हुआ है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन के साथ बातचीत करने की घोषणा का असर भारत सहित एशिया और यूरोप के बाजारों पर पड़ा। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, हैंग सेंग, कॉस्पी और निक्केई बढ़त के साथ बंद हुए, वहीं यूरोप के मार्केट ने भी अपने पहले सत्र में अच्छा प्रदर्शन किया ।दिन के कारोबार के बारे में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हैड विनोद नायर ने कहा कि पिछले सप्ताह आरबीआइ ने सुधार के जिन कदमों की घोषणा की, उससे चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बाजारों में सुधार की उम्मीद बहुत बढ़ी है। इससे निकट भविष्य में बाजारों को फायदा मिलेगा। लेकिन टैक्स कलेक्शन में किसी भी तरह की कमी हुई, तो सरकार के लिए आरबीआइ से मिलने वाली रकम का समुचित उपयोग कर पाने में दिक्कत होगी।

सोना 40 हजार से पहले ठिठका, चांदी सुधरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोने में लगातार पांच कारोबारी सत्रों के उछाल का सिलसिला मंगलवार को थम गया और यह 40 हजार रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर बंद नहीं हो पाया। हालांकि सोमवार को दिन के कारोबार में एक बार यह 40 हजार के ऊपर गया था। लेकिन उस दिन भी बाजार बंद होते समय यह थोड़ा गिरकर 39,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। मंगलवार को भी सोने का बंद भाव यही रहा। दूसरी तरफ, चांदी में 190 रुपये का उछाल दर्ज किया गया और कारोबार के आखिर में यह 46,740 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

एचडीएफसी सिक्युरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) तपन पटेल ने कहा कि हाल ही में चीन और अमेरिका ने ट्रेड वार पर वार्तालाप दोबारा शुरू करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये में भी मजबूती आई, जिसने निवेशकों को सोने में निवेश से रोक दिया। हालांकि चांदी पर औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं जैसे निवेशक मेहरबान रहे।

न्यूयॉर्क में सोने का भाव जबर्दस्त उछाल के साथ 1,531.40 डॉलर, जबकि चांदी का भाव 17.78 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर पहुंच गया। नई दिल्ली में 99.9 फीसद खरा सोना 39,670 रुपये, जबकि 99.5 फीसद खरा सोना 39,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। आठ ग्राम सोने की गिन्नी का भाव भी 29,500 रुपये के पुराने भाव पर बरकरार रहा। चांदी हाजिर 190 रुपये चढ़कर 46,740 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

चांदी के सिक्कों का भाव प्रति सैकड़ा फिर 2,000 रुपये चढ़कर 96,000 रुपये खरीद और 97,000 रुपये बिक्री के स्तर जा पहुंचा।

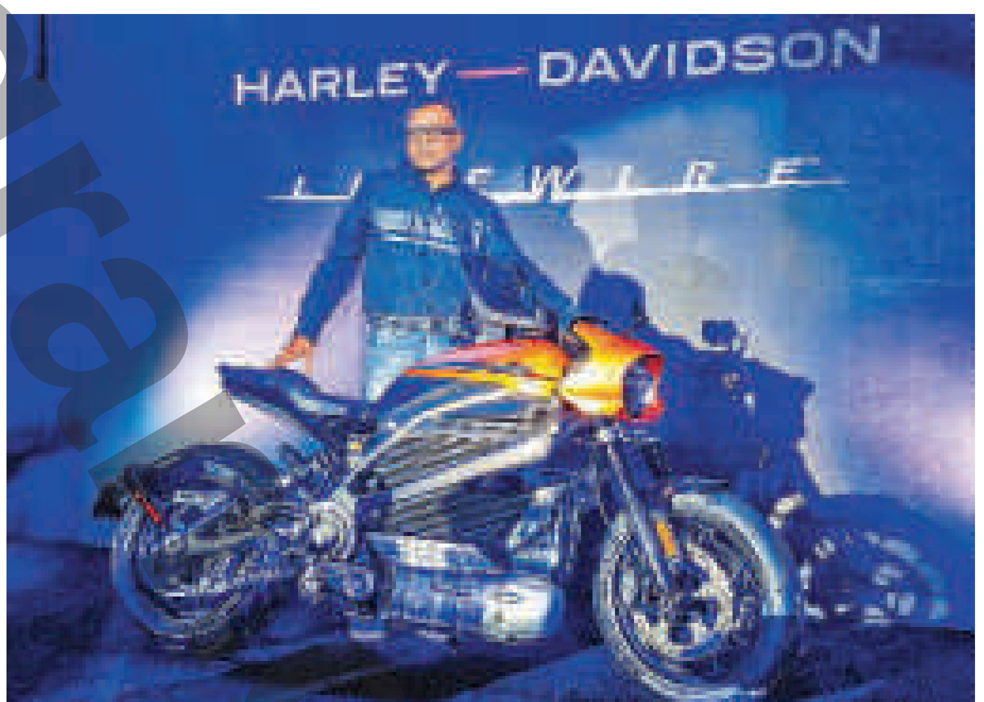

इलेक्ट्रिक बाइक लाएगी हार्ले डेविडसन

अमेरिका की दिग्गज बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने मंगलवार को नई दिल्ली में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 'लाइव वायर' का प्रदर्शन किया। इस मौके पर कंपनी ने बीएस-6 मानक वाली स्ट्रीट-750 भी लांच की, जिसकी कीमत 5 .47 लाख रुपये रखी गई है। प्रेट्र

आकलन

इन्फ्रास्ट्रक्चर और बैंक रिकैपिटलाइजेशन पर खर्च का अनुमान, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दिखने लगेगा सकारात्मक असर

आरबीआइ से मिला फंड इकोनॉमी को देगा रफ्तार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पिछले सप्ताह सरकार द्वारा की गई बड़ी घोषणाओं के बाद अब रिजर्व बैंक से मिले रिकॉर्ड सरप्लस से स्पष्ट हो गया है कि आने वाला समय कुछ बदलाव लाएगा। इकोनॉमी में मंदी की चर्चाओं के बीच इन घटनाओं का सकारात्मक असर चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में दिख सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस रकम का कहां इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार आरबीआइ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर खासकर बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन, हाउसिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर करेगी। ऐसा होने पर इकोनॉमी के अलग-अलग क्षेत्रों में सुस्ती को दूर करने में मदद मिल सकती है। असल में कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च बढ़ाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वित्त वर्ष 2019-20 में अब तक इसकी रफ्तार धीमी रही है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (सीजीए) के अनुसार सरकार ने चालू वित्त वर्ष में करीब 3.36 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य रखा है। लेकिन अप्रैल-जून तिमाही में इसमें से मात्र 63 हजार करोड़ रूपये ही खर्च किए गए हैं, जो बजट के लक्ष्य का मात्र 18.9 परसेंट है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में 86,988 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो उस वर्ष के आम बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लक्ष्य का 29 परसेंट था। इस तरह पहली तिमाही में कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि के बजाय लगभग 30 परसेंट की कमी आई है।

प्रतीकात्मक

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री समीर नारंग का कहना है कि आरबीआइ के ट्रांसफर से सरकार को 2019-20 के लिए तय किए गए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। ब्रोकरेज फर्म एमके की एक रिसर्च रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सरकार अगर आरबीआइ से मिली धनराशि का इस्तेमाल खर्च बढ़ाने के लिए करती है तो यह खर्च कंजंप्शन के बजाय इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होगा। इससे अल्पावधि में बाजार को मदद मिलनी चाहिए। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ग्लोबल की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सरकार इस धनराशि का इस्तेमाल बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये के रिकैपिटलाइजेशनके लिए करेगी। ऐसा होने पर ब्याज दरों में कमी आएगी।

डेढ़ वर्ष की कवायद का फल : उल्लेखनीय है कि पिछले एक डेढ़ साल से रिजर्व बैंक से सरप्लस राशि लेने की कवायद हो रही थी। इसे लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के बीच काफी तनाव भी बना रहा। रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल और डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने सरकार को सरप्लस में से फंड ट्रांसफर करने के विचार का विरोध भी किया था। इसके बाद आचार्य ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने जालान समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक के बोर्ड ने सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का निर्णय किया है। इसमें 1,23,414 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सरप्लस के रूप में हैं, जबकि 52,637 करोड़ रुपये संशोधित इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत अतिरिक्त प्रावधान के हैं।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आरबीआइ से लगभग एक लाख करोड़ रुपये सरप्लस मिलने की उम्मीद जताई थी। वैसे, चालू वित्त वर्ष में सरकार को यह राशि मिलने से अपना फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी क्योंकि पीएम किसान जैसे सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों पर भारी भरकम खर्च होने राजस्व में अपेक्षित वृद्धि न होने के कारण सरकार को फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण था।

बिजनेस सेंटीमेंट को बढ़ाएंगे केंद्र सरकार के उपाय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुस्त होती इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने के वित्त मंत्रालय की तरफ से घोषित उपायों को अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सेंटीमेंट बढ़ाने वाला बताया है। एजेंसी का कहना है कि ये उपाय निवेशकों और बिजनेस समुदाय का उत्साह बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर घरेलू और वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां पूरे साल विपरीत बनी रहीं तो जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4 परसेंट तक भी गिर सकता है।

- मूडीज ने कहा - विपरीत परिस्थितियों में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4 परसेंट भी रह सकता है

प्रतीकात्मक

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अगर जीडीपी ग्रोथ रेट में और गिरावट आती है, तो इसके 6.8 परसेंट तक पहुंचने की गुंजाइश अगले वित्त वर्ष में बनेगी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट विलियम फोस्टर का कहना है, 'हमें उम्मीद है कि सरकार ने जो उपाय किए हैं वे निवेशकों और बिजनेस का उत्साहवर्धन करेंगे। सरकारी बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये की राशि डालने के काम में तेजी आने से कर्ज देने के काम में तेजी आएगी और सुधार के कदमों को जमीन पर उतारा जा सकेगा।' मूडीज ने साल 2019 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.8 से घटाकर 6.2 परसेंट कर दिया था। हालांकि यस बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदा राव का मानना है कि वह वित्त वर्ष 2019-20 में 6.7 परसेंट के जीडीपी के अपने पूर्वानुमान पर कायम हैं। उनके मुताबिक सरकार की तरफ से जिन उपायों की घोषणा की गई है उनसे सुस्ती के अंदेशे को दूर भगाने में मदद मिलेगी।

2015 में संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थाई सदस्य देशों व जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान को अपने नाभिकीय कार्यक्रम में कटौती करनी थी, लेकिन 2018 में अमेरिका ने खुद को इस समझौते से अलग कर लिया।

चीन में जासूसी के आरोप में ऑस्ट्रेलियाई लेखक गिरफ्तार

मेलबर्न, प्रेट्र : चीन में गत जनवरी से हिरासत में रखे गए ऑस्ट्रेलियाई लेखक और राजनीतिक समीक्षक यांग हेंगजुन को गत 23 अगस्त को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के अनुसार, 54 वर्षीय यांग को चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के मामले में जांच के दायरे में रखा गया था। अब उन्हें जासूसी के अपराध के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरिस पेने ने मंगलवार को कहा, 'चीन में जासूसी के संदेह में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक व लेखक यांग हेंगजुन की गिरफ्तारी की खबर से सरकार बेहद चिंतित और निराश है। इस मुश्किल घड़ी में हम यांग और उनके परिवार के साथ हैं।

यांग को बिना किसी आरोप के सात महीने तक बीजिंग में हिरासत में रखा गया। तब से चीन ने ना तो उन्हें हिरासत में रखने का कोई कारण बताया और ना ही उनके वकीलों या पारिवारिक सदस्यों को मिलने की इजाजत दी। मैं अपने पूर्व के आग्रह को दोहराती हूं कि यांग को अगर उनके सियासी मत के आधार

पत्नी और बच्चे के साथ गत जनवरी में चीन गए थे यांग हेंगजुन

मृत्युदंड की हो सकती है सजा। प्रतीकात्मक

पर पकड़ा गया है तो उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए।' यांग अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क में रहते थे। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गत जनवरी में चीन के गुआंगझोउ शहर की यात्रा पर गए थे। तभी उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। बाद में चीन के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के संदेह में यांग को पकड़ने की पुष्टि की थी।

चीन के कानून के तहत जासूसी के आरोप में तीन साल की जेल से लेकर मृत्युदंड तक की सजा सुनाई जा सकती है।

ताइवान के पास एक माह में तीसरा सैन्य अभ्यास कर रहा चीन

बीजिंग, एएफपी : चीन फिर पड़ोसी ताइवान के पास पूर्वी चीन सागर में सैन्य अभ्यास कर रहा है। महीने भर के भीतर ताइवान से सटे समुद्री इलाके में यह चीन का तीसरा सैन्य अभ्यास है। चीन की सेना ने इससे पहले जुलाई में ताइवान स्ट्रेट में दो युद्धाभ्यास किए थे। ताइवान और अमेरिका के बीच बड़ा रक्षा सौदा तय होने के बाद इसे चीन की तरफ से दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। चीन से तनातनी के बीच ताइवान ने अमेरिका से एफ-16 लड़ाकू विमानों की खरीद पक्की कर ली है।

चीन के झेजियांग समुद्री सुरक्षा प्रशासन ने सोमवार को कहा कि अगले दो दिनों तक सैन्य अभ्यास के कारण पूर्वी चीन सागर में जहाजों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस सैन्य अभ्यास को 'लाइव-फायर ड्रिल' बताया है। वर्ष 1949 में गृहयुद्ध के बाद से ताइवान की शासन व्यवस्था चीन से अलग रही है। लेकिन चीन, ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और देश के विरुद्ध जाने पर ताइवान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी भी देता है। दबाव बनाए रखने के लिए वह ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां करता रहता है।

जॉनसन एंड जॉनसन पर 4100 करोड़ का जुर्माना

अमेरिकी जज ने कहा, कंपनी ने अपने फायदे के लिए ओपॉयड के खतरे को किया नजरअंदाज

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : अमेरिका के ओकलाहोमा राज्य के एक जज ने नशीली दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े ओपॉयड संकट मामले में दिग्गज अमेरिकी हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर 57.2 करोड़ डॉलर (करीब 4,100 करोड़ रुपये) का जुर्माना ठोका है। जज ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने जानबूझकर ओपॉयड के खतरे को नजरअंदाज किया और अपने फायदे के लिए डॉक्टरों को नशीली दर्दनिवारक दवाएं लिखने के लिए मनाया। जज ने हालांकि राज्य सरकार की ओर से ओपॉयड पीड़ितों के उपचार के लिए मांगी गई राशि के मुकाबले जॉनसन एंड जॉनसन को काफी कम भुगतान करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने 17 अरब डॉलर (करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये) की मांग की थी।

ओकलाहोमा की क्लेवलैंड काउंटी की जिला अदालत के जज थाड बाल्कमैन ने अपने फैसले में गंभीर टिप्पणी करते हुए

प्रतीकात्मक

कहा, जॉनसन एंड जॉनसन ने राज्य के कानून का उल्लंघन किया। कंपनी की गलत, भ्रामक और खतरनाक मार्केटिंग के कारण तेजी से नशे की लत बढ़ी और ओवरडोज से मौत के मामले सामने आए। राज्य के प्रमुख अटार्नी ब्राड बैकवर्थ ने कहा, 'हमने यह साबित किया कि इस ओपॉयड संकट का मूल कारण जॉनसन एंड जॉनसन है। इसने 20 साल के दौरान इससे अरबों डॉलर की कमाई की।'

फैसले के खिलाफ अपील करेगी कंपनी : फैसले पर जॉनसन एंड जॉनसन की वकील सबरीना स्ट्रांग ने कहा, 'हमारे पास अपील करने का मजबूत आधार है और हम पूरे जोश के साथ इसे चुनौती देंगे।' जबकि कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष माइकल उल्लमन ने कहा, 'ओकलाहोमा में जानसेन के कारण ओपॉयड संकट खड़ा नहीं हुआ। हमने यह पाया है कि ओपॉयड संकट सार्वजनिक स्वास्थ्य का जटिल मामला है। इससे प्रभावित हर किसी के साथ हमारी गहरी सहानुभूति है।'

60 फीसद मादक पदार्थों की करती थी आपूर्ति : तस्मानिया में अफीम की खेती करने वाले लोगों से करार करने वाली जॉनसन एंड जॉनसन करीब 60 फीसद मादक पदार्थों की आपूर्ति करती थी। इसके उपयोग से दवा बनाने वाली कंपनियां ऑक्सीकोडोन जैसी ओपॉयड दवाएं बनाती थीं। जॉनसन एंड जॉनसन की सहयोगी कंपनी जानसेन फार्मास्यूटिकल्स अपनी खुद की ओपॉयड दवा बनाने लगी थी। इस गोली का अधिकार साल 2015 में बेच दिया गया था।

क्या है ओपॉयड : अफीम से बनने वाली दर्द निवारक दवाओं को ओपॉयड कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसका नशे के लिए प्रयोग करते हैं। अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी के अनुसार, देश में ओपॉयड के चलते साल 1999 से 2017 के दौरान करीब चार लाख लोगों की मौत हुई।

कंपनियों पर ढाई हजार मुकदमे

जज के फैसले पर ओपॉयड दवा बनाने वाली करीब दो दर्जन कंपनियों की नजर थी क्योंकि इन दवाओं को बनाने वाली कंपनियों, वितरकों और विक्रेताओं पर अमेरिका में इसी तरह के करीब ढाई हजार मुकदमे चल रहे हैं।

दो कंपनियों ने किया समझौता

जॉनसन एंड जॉनसन मामले में ही आरोपित दो अन्य दवा कंपनियां अमेरिका की पर्ड्यू फार्मा और इजरायल की टेवा ओकलाहोमा के साथ पहले ही समझौता कर चुकी हैं। पर्ड्यू 27 करोड़ डॉलर (करीब 1,900 करोड़ रुपये) और टेवा 8.5 करोड़ डॉलर (करीब 600 करोड़ रुपये) का भुगतान करने पर सहमत हुईं।

ईरान ने कहा, प्रतिबंधों को खत्म कर अमेरिका बढ़ाए पहला कदम

नरमी के संकेत ▶ जी-7 की बैठक में ट्रंप ने कहा था, रूहानी से बातचीत के लिए तैयार

पिछले साल परमाणु समझौते से अलग होकर ट्रंप ने ईरान पर लगा दिए थे प्रतिबंध

तेहरान, एएफपी : अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी में मामूली कमी आने के संकेत मिले हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के एक दिन बाद ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने मंगलवार को कहा कि प्रतिबंध खत्म कर अमेरिका पहला कदम बढ़ाए। फ्रांस के बायरिट्स शहर में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वह अपने ईरानी समकक्ष के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं।

अमेरिका समेत दुनिया के ताकतवर देशों और ईरान के बीच 2015 में परमाणु समझौता हुआ था। लेकिन पिछले साल मई में ट्रंप ने एकतरफा फैसला करते हुए अमेरिका को समझौते से अलग कर लिया था। इसके बाद ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। प्रतिबंधों के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई है।

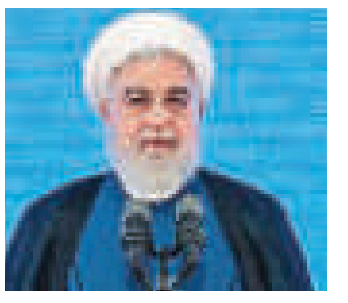

ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। एएफपी

ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में रूहानी ने कहा कि अमेरिका सबसे पहले ईरान के खिलाफ लगाए गए सभी गैरकानूनी, अनुचित और गलत प्रतिबंधों को वापस लेने का कदम उठाए। रूहानी ने कहा,' सकारात्मक बदलाव की कुंजी अमेरिका के हाथों में है।' ईरान ने तो अमेरिका के सबसे बड़ी आशंका को पहले ही खारिज कर दिया है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर अमेरिका की चिंता परमाणु बम को लेकर है तो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खुमैनी द्वारा जारी फतवा के जरिए उसे पहले ही दूर किया जा चुका है। खुमैनी ने 2003 में फतवा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि ईरान परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं रखता, उसकी सैन्य नीति पारंपरिक हथियारों पर आधारित है।

रूहानी ने कहा, 'पहला कदम बढ़ाइए। बिना इस कदम के, गतिरोध दूर नहीं होगा।' बता दें कि बायरिट्ज में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में ट्रंप और रूहानी की बैठक का माहौल सघन कूटनीतिक और बातचीत के बाद तैयार हो पाया है। जी-7 सम्मेलन के आखिर में प्रेस कांफ्रेंस में ट्रंप ने कहा था कि वह रूहानी के साथ बातचीत के लिए तैयार है। मैक्रों ने बैठक के लिए समय प्रस्तावित किया है उम्मीद है रूहानी भी उसके लिए तैयार होंगे। दोनों नेताओं की बैठक को लेकर अभी कोई तारीख तो सामने नहीं आई है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए सितंबर के आखिर में ट्रंप और रूहानी दोनों न्यूयॉर्क में होंगे। उस दौरान ही दोनों के बीच बातचीत का अवसर बन सकता है।

इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में ईरान ने दो को जेल भेजा

तेहरान, एएफपी : ईरान ने इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में दो लोगों को 10 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। दोनों में से एक ब्रिटेन की दोहरी नागरिक है। गैरकानूनी भुगतान हासिल करने के लिए दोनों को और दो साल जेल में बंद रहना होगा। मंगलवार को न्यायपालिका ने यह घोषणा की। अनौयुशेह अशौरी नाम की महिला ब्रिटेन और ईरान की नागरिक है। इजरायल के मोसाद गुप्तचर संस्था को सूचना देने के लिए उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। न्यायपालिका के प्रवक्ता गुलामहुसैन इस्माइल ने यह जानकारी दी है। महिला को इजरायल से गैरकानूनी कोष हासिल करने के लिए दो साल की सजा और जुर्माने के तौर पर उतनी राशि जमा कराने का आदेश दिया गया है।

भारत-अमेरिका के बीच समुद्री सुरक्षा की मजबूती पर हुई बात

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय बैठक में द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूती देने के उपायों पर विचार किया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 23 अगस्त को भारत-अमेरिका समुद्री सुरक्षा संवाद के चौथे दौर की बैठक में इस पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि दोनों पक्षों के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर विचारों का आदान-प्रदान भी हुआ। बैठक में पहले के तीन दौर की बैठकों में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई। इस मुद्दे पर दोनों के बीच सहयोग बढ़ा है।

अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बड़ी भूमिका पर बल दे रहा है। दूसरे देश इसे इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख समुद्री मार्ग को किसी तरह के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए नवंबर, 2017 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने बहुप्रतीक्षित नई रणनीति 'क्वाड' को भी आकार दिया था। यह समुद्री सुरक्षा को लेकर एक साझा गठबंधन है। मंत्रालय के मुताबिक भारत-अमेरिका समुद्री सुरक्षा संवाद के अगले दौर की बैठक भारत में होगी। अमेरिका में हुई चौथे दौर की बातचीत के विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव इंद्र मणि पांडे के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल गया था।

'कश्मीर पर अलग-थलग पड़ना पाक विदेश नीति की नाकामी'

वॉयस ऑफ कराची के अध्यक्ष ने कहा, इमरान खान ने स्वीकार की विफलता

वाशिंगटन, एएनआइ : कश्मीर मसले पर दुनिया में कोई तवज्जो नहीं मिलने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की खूब फजीहत हो रही है। वॉयस ऑफ कराची के अध्यक्ष नदीम नुसरत ने सोमवार को कहा कि इमरान खान ने यह स्वीकार कर लिया है कि कश्मीर मसले पर उनके मुल्क की कूटनीति विफल हो गई है।

अमेरिका स्थित यह हिमायती समूह पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की दशा के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है। इस समूह के अध्यक्ष ने एक बयान में कहा, 'इमरान खान पाकिस्तान की सेना क कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। वह जीएचक्यू (पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर) की ओर से बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह मान लिया है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग पड़ गया है। अगर कुछ मुस्लिम देश आज हमारे साथ नहीं हैं, तो इसकी वजह आर्थिक और दूसरे कारण हैं। वे आने वाले समय में हमारे साथ होंगे।'

नुसरत ने बताया कि कश्मीर का मसला शुरू से ही पाकिस्तान की विदेश नीति का सबसे अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान की सेना और इसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी आइएसआइ राष्ट्रीय खजाने से अरबों रुपये आतंकी संगठनों को खड़ा करने के अलावा अपने दूतावासों में कश्मीर समितियां और कश्मीर डेस्क बनाने पर खर्च करती है। यह सब कुछ कश्मीर की आजादी के लिए संघर्ष के नाम पर किया जाता है। सेना की अगुआई वाले

नदीम नुसरत। फाइल

पाकिस्तान की घरेलू और विदेश नीतियों की विफलता से मुल्क में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो गई है।'

मौलिक अधिकारों से वंचित किए गए मुहाजिर : मुहाजिर नेता नुसरत ने पाकिस्तान में बलूच, पश्तून, मुहाजिर और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की बदहाल दशा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन अल्पसंख्यक लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। सैकड़ों मुहाजिर, बलूच, पश्तून और दूसरे अल्पसंख्यक सुरक्षा बलों के हाथों लगभग नरसंहार का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कराची और मुहाजिरों को बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। मुहाजिर शब्द का इस्तेमाल उर्दू बोलने वाले उन लोगों के लिए किया जाता है, जो 1947 में भारत से पाकिस्तान चले गए थे।

ट्रंप का पूर्व साझीदार चोरी में गिरफ्तार

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारतीय मूल के होटल कारोबारी दिनेश चावला को अमेरिका के एक एयरपोर्ट से लगेज चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चावला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होटल कारोबार में साझीदार भी रह चुका है। चावला ने पूछताछ में कहा, मैं जानता हूं कि लगेज चोरी करना गलत है, लेकिन मैं रोमांच के लिए ऐसा करता था।

न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के अनुसार, चावला होटल्स के सीईओ दिनेश चावला को पिछले हफ्ते मेंफिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगेज ले जाते देखा गया था। पुलिस का कहना है कि चावला ने चोरी किया एक सूटकेस अपनी कार में रखा और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट वापस आ गए। एयरपोर्ट पुलिस के अनुसार, कार की जांच करने पर सूटकेस के अलावा एक अन्य लगेज बरामद किया गया। चावला को दो लगेज की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन लगेज में रखे सामान की कीमत चार हजार डॉलर (करीब दो लाख 80 हजार रुपये) बताई गई है। चावला ने लंबे समय से लगेज चोरी करने का जुर्म स्वीकार किया है। चावला और उनके भाई सुरेश चावला डेल्टा और क्लीवलैंड में लक्जरी होटल और मोटेल संचालित करते हैं। गत फरवरी तक उनका ट्रंप आर्गेनाइजेशन के साथ करार था।

अमेजन पर जी-7 की मदद सशर्त स्वीकार करने को तैयार ब्राजील

ब्राजीलिया, एएफपी : अमेजन के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए जी-7 देशों की सहायता राशि पर ब्राजील असमंजस में है। पहले सहायता राशि का स्वागत करने और फिर ठुकराने के बाद अब ब्राजील ने सहायता को सशर्त स्वीकार करने की बता कही है। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने कहा है कि अगर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपनी अपमानजनक टिप्पणी वापस लें, तो ब्राजील मदद स्वीकारने को तैयार है।

धरती का फेफड़ा कहे जाने वाले अमेजन के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए जी-7 देशों ने दो करोड़ डॉलर (करीब 142 करोड़ रुपये) की मदद देने की पेशकश की है। हालांकि मैक्रों और बोल्सोनारो के बीच तनातनी के चलते ब्राजील ने मदद लेने से इन्कार कर दिया। बोल्सोनारो के चीफ ऑफ स्टाफ ओनिक्स लोरेनजोनी ने कहा था, 'हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन इस धनराशि को यूरोप में जंगलों के विस्तार में खर्च करना ज्यादा उपयुक्त हो सकता है।' अब बोल्सोनारो ने कहा है कि अगर मैक्रों अपने अपमानजनक शब्द वापस लें, तो ब्राजील सहायता स्वीकार करने को तैयार है। मैक्रों और बोल्सोनारो के बीच जुबानी जंग चल रही है। बोल्सोनारो ने मैक्रों की पत्नी को लेकर मजाक किया था। इस

ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कहा, पहले अपने अपमानजनक शब्द वापस लें इमैनुअल मैक्रों

अमेजन के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए 142 करोड़ रुपये देने को तैयार है जी-7

पर मैक्रों ने काफी कड़े शब्दों में उनकी निंदा की थी। फिर पलटवार करते हुए बोल्सोनारो ने मैक्रों को उपनिवेशवादी सोच वाला बताया। उन्होंने कहा कि मैक्रों ब्राजील को अपना कोई उपनिवेश समझते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दो दिन 1,659 नए स्थानों पर आग लगी। आग से निपटने के लिए ब्राजील सेना की मदद ले रहा है। ब्राजील के रक्षा मंत्री फर्नांडो अजेवेडो ने स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही है। अमेजन के जंगलों का करीब 60 फीसद हिस्सा ब्राजील में है।

ट्रंप ने की बोल्सोनारो की तारीफ : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आग से निपटने की दिशा में बोल्सोनारो के प्रयासों की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा, 'अमेजन की आग से निपटने के लिए बोल्सोनारो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, साथ ही ब्राजील के लोगों के हित में अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें और उनके देश को अमेरिका का पूरा समर्थन है।'

भारत-पाक तनाव भी था जी-7 सम्मेलन का मुद्दा

वाशिंगटन, प्रेट्र : व्हाइट हाउस ने सोमवार को दावा किया कि हाल ही में संपन्न हुए जी-7 शिखर सम्मेलन में उठाए गए पांच प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद करना था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका प्रयास किया था।

फ्रांस के दक्षिणपश्चिमी बायरिट्ज शहर में 24-26 अगस्त तक आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने भी शिरकत की थी। व्हाइट हाउस ने कहा, ' जी-7 में उठाए गए पांच बड़े मुद्दे थे- एकता का संदेश देना, एक अरब डॉलर के व्यापार सौदे की सुरक्षा, अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) को आगे बढ़ाना, यूरोप के साथ मजबूत व्यापार संबंध विकसित करना और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करना।' व्हाइट हाउस ने यह भी कहा, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की जरूरत पर जोर दिया और हमारे देशों के बीच महान आर्थिक संबंध बनाने की बात भी की।'

व्हाइट हाउस का दावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने तनाव कम करने में मदद का किया प्रयास

बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति ने की थी मध्यस्थता की पेशकश

मोदी और ट्रंप की मुलाकात जी-7 सम्मेलन में सबसे चर्चित रही। फाइल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुंजाइश को सिरे से खारिज करते हुए सोमवार को कहा था कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और 'हम किसी तीसरे देश को परेशान नहीं करना चाहते।' ट्रंप ने तत्काल इसका समर्थन किया था।

हाल ही में ट्रंप मध्यस्थता की पेशकश की थी। बाद में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और मोदी ने बीती रात कश्मीर के बारे में 'काफी विस्तार' से बात की और उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान खुद ही इसका समाधान कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने एक ट्वीट में कहा कि मोदी के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को स्वीकार किया। व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर मोदी और ट्रंप की तस्वीरें भी साझा की थी, जिसमें दोनों नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं।

बांग्लादेश में शादी के प्रमाणपत्र से कुमारी शब्द हटाने का आदेश

ढाका, एएफपी : बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि मुस्लिम शादी प्रमाणपत्र से कुमारी शब्द हटा देना चाहिए। इस दक्षिण एशियाई देश के मुस्लिम विवाह कानून के तहत दूल्हन को प्रमाणपत्र के तीन विकल्पों कुमारी, विधवा या तलाकशुदा में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। शादी के प्रमाणपत्र में इस शब्द का उपयोग 1961 से किया जा रहा है।

डिप्टी अटार्नी जनरल अमित तालुकदार ने बताया कि अदालत ने रविवार को अपने संक्षिप्त फैसले में सरकार को इस शब्द को हटाने और उसकी जगह अविवाहित शब्द का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। अदालत का विस्तृत फैसला अक्टूबर तक प्रकाशित होने की उम्मीद है। तब तक शादी के प्रमाणपत्र में यह बदलाव भी दिख सकता है। प्रमाणपत्र में कुमारी शब्द के इस्तेमाल को 2014 में चुनौती देने वाले समूहों की वकील आयनुन नाहर सिद्दीकी ने कहा, 'यह ऐतिहासिक फैसला है।' बांग्लादेश के कई अधिकार समूह लंबे समय से शादी के प्रमाणपत्र में कुमारी शब्द के इस्तेमाल की आलोचना कर रहे थे। उनका कहना था कि यह अपमानजनक और भेदभावपूर्ण है।

बिगड़ते हालात

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के टकराव के दौरान खींची गई तस्वीर, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने के लिए चीन की सरकार ने थ्येनआनमन चौक पर जुटे लोगों पर चलवा दिए थे सेना के टैंक

हांगकांग की एक तस्वीर ने ताजा कीं टैंकमैन की यादें

न्यूयॉर्क टाइम्स से

हांगकांग : 30 साल पहले सफेद शर्ट, काली पैंट पहने और दोनों हाथों में शॉपिंग बैग लिए टैंक के सामने खड़े व्यक्ति की तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने के लिए चीन की सरकार ने थ्येनआनमन चौक पर जुटे प्रदर्शनकारियों पर सेना के टैंक चलवा दिए थे। उसी दौरान एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के फोटोग्राफर जेफ विडनर ने वह तस्वीर खींची थी। तस्वीर सामने आने के बाद उस व्यक्ति को टैंकमैन और अज्ञात विद्रोही जैसे नाम दिए गए थे।

अब हांगकांग की एक तस्वीर ने उस याद को ताजा कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटोग्राफर लाम यिक फी द्वारा खींची गई इस तस्वीर में एक व्यक्ति हाथ में छाता थामे एक पुलिसकर्मी के सामने खड़ा है। पुलिसकर्मी ने उसकी तरफ बंदूक तानी हुई है। हांगकांग में इन दिनों हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की शुरुआत एक विवादास्पद

न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटोग्राफर लाम यिक फी द्वारा हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन के दौरान खींची गई तस्वीर।

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के फोटोग्राफर जेफ विडनर द्वारा चीन के थ्येनआनमन चौक पर 1989 में खींची गई 'टैंकमैन' की तस्वीर।

प्रत्यर्पण विधेयक से हुई थी। इसमें हांगकांग के आरोपितों को मुकदमे के लिए चीन प्रत्यर्पित करने का प्रस्ताव था। व्यापक विरोध के बाद हांगकांग की चीन समर्थक मानी जाने वाली प्रमुख कैरी लाम ने विधेयक को स्थगित कर दिया था। लेकिन अब प्रदर्शनकारी इस विधेयक को पूरी तरह निरस्त करने और लाम के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। विरोध प्रदर्शनों ने लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का रूप ले लिया है। लगातार 12 हफ्तों से जारी आंदोलन चीन सरकार के लिए हांगकांग में बीते 22 सालों की सबसे बड़ी चुनौती है। यह पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश 1997 में चीन के पास आया था। उसके बाद से कई बार लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन ताजा आंदोलन सबसे ज्यादा समय से जारी है। कई जगह आंदोलन ने हिंसक रूप भी ले लिया है। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस रबर बुलेट, लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का इस्तेमाल कर रही है।

हांगकांग पर विकसित देशों के प्रस्ताव पर भड़का चीन

बीजिंग, प्रेट्र : फ्रांस में विकसित देशों के समूह जी-7 के सम्मेलन में हांगकांग को लेकर आए प्रस्ताव पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। हांगकांग के हालात को देखते हुए जी-7 देशों ने चीन को 1984 में हुए ब्रिटेन-चीन समझौते की जिम्मेदारियों की याद दिलाई है। सोमवार को संपन्न हुए सम्मेलन में हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव लाया गया।

जी-7 के प्रस्ताव में कहा गया, 'जी-7 1984 में चीन-ब्रिटेन के बीच हांगकांग को लेकर हुए समझौते के महत्व को मानता है और हिंसा से बचने की अपील करता है।' समूह के सातों देशों ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका ने प्रस्ताव को समर्थन दिया। इस प्रस्ताव को हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ा अंतरराष्ट्रीय समर्थन माना जा रहा है।

जी-7 देशों का यह प्रस्ताव चीन को रास नहीं आया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने इसे चीन के आंतरिक मामलों में जी-7 का दखल करार दिया। प्रवक्ता ने कहा, 'हांगकांग के मामले में जी-7 देशों के बयान पर सख्त आपत्ति जताते हुए हम इसका विरोध करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सामान्य नियमों के अनुसार किसी भी देश को चीन-ब्रिटेन संयुक्त घोषणापत्र के तहत हांगकांग के मामले में दखल का अधिकार नहीं है।'

जी-7 सम्मेलन में हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों के पक्ष में आया है प्रस्ताव

चीन ने कहा, इस मामले में दखल का किसी देश को अधिकार नहीं

क्या है चीन-ब्रिटेन का संयुक्त घोषणापत्र? : 1984 के चीन-ब्रिटेन घोषणापत्र के तहत हांगकांग में एक देश, दो प्रशासन की व्यवस्था पर सहमति बनी थी। इसके तहत विदेश एवं रक्षा मामलों के अतिरिक्त हांगकांग को पर्याप्त स्वायत्तता देने की बात थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन (एचकेएसएआर) के मूलभूत कानूनों में 50 साल तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मंगलवार को डॉन ब्रेडमैन को उनकी 111वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि दी।
– सचिन तेंदुलकर

मेरठ की पारुल ने उप्र को दिलाया पहला स्वर्ण

जागरण संवाददाता, लखनऊ : 59वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स मीट में पहले दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश (उप्र) की महिला एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया। मेरठ की पारुल चौधरी ने 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीतकर उप्र को पहला स्वर्ण दिलाया। उन्होने 17 .51 .38 मिनट का समय निकालकर शीर्ष स्थान हासिल किया। हालांकि इसके बावजूद पारुल थोड़ा निराश दिखीं, क्योंकि वह इतने अच्छे प्रदर्शन पर भी विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकीं।

विश्व क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच टक्कर : एंजेलो मैथ्यूज

दिग्गज बल्लेबाज, महेला जयवर्धने, कुमरा संगकारा, तिलकरत्ने दिलशान के संन्यास के बाद श्रीलंका की क्रिकेट टीम कमजोर पड़ गई थी। यह टीम फिर से एक बार खड़ी हो रही है और इस टीम को खड़ा करने का जिम्मा पूर्व कप्तान और बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज के ऊपर है। वह उन तीनों अनुभवी बल्लेबाजों के साथ खेले हैं और अब इस युवा टीम के साथ भी खेल रहे हैं। श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट जीता तो वनडे विश्व कप 2019 में टीम नॉकआउट में नहीं पहुंच पाई और छठे स्थान पर रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में श्रीलंकाई टीम ने पहला टेस्ट जीता लेकिन दूसरा टेस्ट हारने के कारण उसे सीरीज के ड्रॉ होने से ही संतोष करना पड़ा। उनका मानना है कि इस समय विश्व क्रिकेट में भारत और श्रीलंका की टीमें अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। श्रीलंका के प्रदर्शन व अन्य मुद्दों को लेकर **अभिषेक त्रिपाठी** ने पूर्व कप्तान **एंजेलो मैथ्यूज** से खास बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश :

साक्षात्कार

● **श्रीलंका के टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? श्रीलंका का क्रिकेट किस ओर जा रहा है?**

-इसमें कोई शक नहीं है कि टेस्ट चैंपियनशिप से क्रिकेट के इस प्रारूप में एक जोश आ गया है। मुझे लगता है कि श्रीलंकाई टीम के सभी खिलाड़ी पिछले कुछ समय में शीर्ष टीमों के खिलाफ खेले हैं। इस चैंपियनशिप में लंबा सफर बचा है। हमने पहले टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड की टीम शानदार क्रिकेट खेलती है और उनके खिलाफ खेलना में दबाव तो रहता ही है। पहले टेस्ट की चौथी पारी में दिमुथ और थिरिमाने की साझेदारी ने लक्ष्य को आसान बना दिया। चौथी पारी में ऐसी साझेदारी रास्ता आसान कर देती है। मुझे लगता है कि सभी खिलाड़ियों ने अच्छा किया और अपना-अपना योगदान दिया। यह सीरीज हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। अगर हम उसे जीतते तो बेहतर रहता।

● **न्यूजीलैंड सीमित प्रारूपों में एक अच्छी टीम है। क्या आपको लगता है कि यह टीम टेस्ट में कुछ अलग है?**

-मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई भी प्रारूप हो, न्यूजीलैंड की टीम ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को बेहतर तरीके से तैयार किया है। टेस्ट, वनडे और टी-20 अलग-अलग प्रारूप हैं और इसमें घर या बाहर के मैदानों पर बहुत कुछ मैच के रिजल्ट निर्भर होते हैं। न्यूजीलैंड ने घर और घर से बाहर अच्छा क्रिकेट खेला है। उन्होंने तीनों प्रारूप में एक टीम के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। वे विश्व कप के उपविजेता हैं और वे यह भी जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलना है।

● **जयसूर्या, जयवर्धने, संगकारा, दिलशान के संन्यास के जाने के बाद श्रीलंकाई टीम में पहले जैसी बात नहीं रही है। उनकी जगह क्यों नहीं भर पाई? कहां कमी रह गई?**

-निश्चित तौर पर बड़े खिलाड़ियों के संन्यास से फर्क तो पड़ता है। जयसूर्या ने पहले संन्यास लिया। उसके बाद जयवर्धने, संगकारा और दिलशान ने क्रिकेट से विदा ली। इन तीनों ने कई साल तक टीम के साथ समय बिताया और खेले। सीनियर खिलाड़ी होने के नाते अब टीम को खड़ा करने की मेरी जिम्मेदारी बनती है। उन तीनों की जगह को भरना आसान नहीं है। हमें जो भी मौके मिलेंगे तो हमारी कोशिश अच्छा करने की रहेगी। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा करने में सफल होंगे।

● **दिमुथ करुणारत्ने की कप्तानी में खेलना कैसा लग रहा है और आपका क्या अनुभव रहा?**

-शानदार, मुझे लगता है कि अभी सब अच्छा चल रहा है। हमने दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज फिर वनडे विश्व कप और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज उनके नेतृत्व में खेली। वह हर खिलाड़ी को आजादी के साथ खेलने देते हैं और हर खिलाड़ी का हौसला भी बढ़ाते हैं इससे खिलाड़ियों को अपना शानदार प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। टीम में हर कोई उनका सम्मान करता है। मुझे लगता है कि वह अपना काम बखूबी निभा रहा है। उनका भविष्य अच्छा है और हर कोई उसकी मदद करता है। उन्होंने टीम को अच्छे से एकजुट किया है।

● **अब आपने गेंदबाजी करना लगभग छोड़ दिया है, इसके पीछे क्या कारण है?**

- मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई मुख्य कारण नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में मुझे चोटें लगती रही और फिर चयनकर्ताओं ने मुझसे कहा कि टीम को मेरी बल्लेबाजी की जरूरत है इसलिए तुम एक बल्लेबाज के तौर पर खेलो लेकिन मैं फिर से गेंदबाजी करने की कोशिश करूंगा और टी-20 से शुरुआत करने के बारे में सोच रहा हूं। मैं अपनी गेंदबाजी को बहुत याद करता हूं और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी टीम में एक ऑलराउंडर के तौर पर योगदान देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि वनडे में भी गेंदबाजी करूंगा।

● **आप दो या तीन कप्तानों के साथ खेले हैं, आपका पसंदीदा कौन है?**

-किसी एक के बारे में कहना मुश्किल है। महेला, दिलशान, संगकारा सभी अच्छे कप्तान रहे हैं। वे सभी अच्छे इंसान हैं। वे सभी अपने करियर में सफल हुए हैं। तो आप किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोल सकते।

● **विश्व क्रिकेट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अच्छा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम संतुलित है?**

-मैं किसी एक टीम के बारे में नहीं कह सकता। भारत और इंग्लैंड पिछले दो साल से अच्छा करते आ रहे हैं। उन टीमों के बीच अच्छी टक्कर चल रही है लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आप उस दिन या टेस्ट में पांच दिन कैसा खेलते हैं। यह उस दिन के प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है। वे पिछले कई साल से अच्छा कर रहे हैं।

● **आपको क्या लगता है तेज गेंदबाज होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। क्या लंबाई महत्वपूर्ण है। आप खुद छह फुट के हैं?**

-मुझे लगता है कि लंबाई ठीक होनी चाहिए लेकिन इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि लाहिरू कुमारा 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकता है लेकिन वह इतना लंबा नहीं है। आपको अपनी गेंदबाजी में तेजी, समय और लय लानी होती है। अगर ये चीजें होंगी तोलंबाई ज्यादा महत्व नहीं रखती। मुझे नहीं लगता कि आपको गेंद तेजी से फेंकने के लिए लंबाई को कोई कारण मानना चाहिए।

● **हाल ही में एशेज सीरीज में जोफ्रा आर्चर ने स्टीव स्मिथ को चोटिल किया था। आपको क्या लगता है कि आजकल क्रिकेट बहुत खतरनाक हो गया है?**

-हो सकता है। 95 प्रतिशत गेंदबाज यह कभी नहीं सोचता कि उसे बल्लेबाज को चोटिल करना है। बल्लेबाज को आउट करने के लिए गेंदबाज रणनीति बनाते हैं। यह घटना कभी-कभी मैच में हो जाती है। हर कोई किसी को चोटिल करना नहीं चाहता है। मुझे लगता है कि यह खेल का हिस्सा है। हर टीम में ज्यादातर गेंदबाज 145 या 150 किमी की रफ्तार से गेंद फेंक रहे हैं।

फेडरर से लड़कर हारे झज्जर के सुमित नागल

सुमित ने 20 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता के खिलाफ जीता पहला सेट दो घंटे 25 मिनट तक चले मुकाबले को 6-4, 1-6, 2-6, 4-6 से गंवाया

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : भारतीय युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने जज्बा और जुझारूपन दिखाकर ग्रैंडस्लैम में अपने पदार्पण की स्वप्निल शुरुआत करते हुए दिग्गज रोजर फेडरर के खिलाफ पहला सेट जीता, लेकिन इसके बाद लगातार तीन सेट हारकर उन्हें पहले दौर के मुकाबले में ही हारकर बाहर होना पड़ा।

मंगलवार की सुबह हुए इस बहुचर्चित मैच में झज्जर के 22 वर्षीय नागल ने न्यूयॉर्क के आर्थर ऐस स्टेडियम में अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई। वह भले ही 20 ग्रैंडस्लैम जीतने वाले पूर्व विश्व नंबर वन पुरुष खिलाड़ी रोजर फेडरर से यह मुकाबला 6-4, 1-6, 2-6, 4-6 से हार गए हों, लेकिन पूरा भारत उनका मुरीद हो गया। दो घंटे 25 मिनट तक चले मुकाबले के शुरुआती 38 मिनट में उन्होंने फेडरर की सांसें फुला दीं तो यहां भारतीय दर्शक की भी धड़कनें तेज हो गईं। भारतीय प्रशंसकों को एक बार लगने लगा था कि हरियाणा का यह छोरा अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर ना कर दे, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। नागल पिछले 20 वर्षों में ग्रैंडस्लैम के पुरुष सिंगल्स मुख्य ड्रॉ में एक सेट जीतने वाले केवल चौथे भारतीय हैं। यह सेट उन्होंने विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी के खिलाफ जीता। पिछले दो दशक में नागल से पहले ग्रैंडस्लैम में भारत की ओर से सोमदेव, युकी भांबरी और मायनेनी ही एक सेट जीत सके हैं।

ऐसा था पहला सेट

मैच में फेडरर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। क्वालीफाइंग के जरिये यूएस ओपन के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाले नागल ने पहले सेट के तीसरे गेम में फेडरर के डबल फॉल्ट का फायदा उठाकर ब्रेक प्वाइंट लिया। फेडरर जब एटीपी रैंकिंग में 190वें नंबर के खिलाड़ी को समझने की कोशिश कर रहे थे तब नागल ने अपने रिटर्न और फोरहैंड से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अभी फेडरर और दर्शक कुछ समझ पाते कि नागल ने दूसरी बार उनकी सर्विस तोड़ दी। इसके बाद उन्होंने 0-30 से पिछड़ने के बाद अपनी सर्विस बचाई। नागल ने अपने करारे शॉट से फेडरर को नेट पर आने का मौका नहीं दिया। इस बीच, फेडरर अपनी गलतियों पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

दूसरे, तीसरे और चौथे सेट में छाए फेडरर

इसके बाद उम्मीदें बढ़ गईं, लेकिन फेडरर ने खुद को संभाला और फिर नागल को अपना असली खेल दिखाया। उन्होंने पहले से बेहतर सर्विस करनी शुरू की और नेट पर आकर अंक बनाने शुरू कर दिए। दूसरे सेट में जल्द ही वह 5-0 से आगे हो गए और सातवें गेम में उन्होंने यह सेट जीतकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। नागल ने छह सेट प्वाइंट बचाए और दो बार उनके पास ब्रेक प्वाइंट का मौका भी आया। नागल अब भी चुनौती दे रहे थे, लेकिन फेडरर अपने रंग में लौट आए थे। तीसरे और चौथे सेट में भी कहानी वैसे ही आगे बढ़ी। नागल ने कुछ अंक जुटाए, लेकिन मुकाबला अब एकतरफा दिखने लगा था। 20 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन ने मैच के लिए सर्विस की तो नागल ने कुछ अच्छे रिटर्न से 0-40 का स्कोर कर दिया। फेडरर ने पांच ब्रेक प्वाइंट बचाकर आखिर में मैच अपने नाम किया। नागल दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। वह ऑटोग्राफ देकर तालियों के बीच स्टेडियम से बाहर गए।

"मेरा मानना है कि वह जानता है कि क्या कर सकता है। आपको निरंतरता बनाए रखनी होती है। उसने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। उसने जिस तरह से इस क्षण को नियंत्रित किया वह अच्छा था। कोर्ट पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी आसान नहीं होता। आप इसके लिए जीते हो, आप इसका सपना देखते हो, बड़े मंच पर खेलते हो। उसने यह सब अच्छी तरह से किया। यह मेरे लिए मुश्किल सेट था। उसने बहुत अच्छा खेल दिखाया और उसे श्रेय जाता है। मैं गलतियों में कमी करने पर ध्यान दे रहा था। उम्मीद है कि आगे मैं बेहतर प्रदर्शन करूंगा। **रोजर फेडरर**

नागल का यूएस ओपन में सफर

बनाम	स्कोर	नतीजा
क्वालीफाइंग दौर		
तत्सूमो इटो	7-6, 6-2	जीत
पीटर पोलांस्की	7-5, 7-6	जीत
जोआओ मेनेजीस	5-7, 6-4, 6-3	जीत
मुख्य दौर		
रोजर फेडरर	6-4, 1-6, 2-6, 4-6	हार

"मैं सिर्फ मैच का आनंद लेना चाहता था। इसके अलावा मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। मैं फेडरर के खिलाफ खेलना चाहता था। मैं जीत और हार के बारे में नहीं सोच रहा था। यह एक अच्छा अनुभव है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि टीवी पर मेरे बारे में क्या कहा जा रहा था। आप फेडरर की कॉपी नहीं कर सकते। वह शानदार हैं। **सुमित नागल**, भारतीय टेनिस खिलाड़ी

सुमित ने कम उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। महेश भूपति ने उसका ट्रायल लिया था। उसने कई मुश्किलों का सामना किया। हम सुमित का समर्थन करने के लिए पूरी दिल्ली में घूमे। मैं बहुत खुश हूं कि उसने फेडरर के खिलाफ मैच खेला। उसे कुछ चोटें आई थीं, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। **कृष्णा**, सुमित नागल की मां"

रोजर फेडरर vs सुमित नागल

रोजर फेडरर		सुमित नागल
12	ऐस	00
07	डबल फॉल्ट	04
61	विनर्स	17
57	अनफोर्स्ड एरर	32
10	ब्रेक प्वाइंट सेव	06
22	कुल गेम जीते	13

"नागल ने विश्व के महान खिलाड़ी के खिलाफ गजब का धैर्य दिखाया और टिके रहे। इस साल नागल ने जो सुधार किया है, उस पर उसे और उसकी कोचिंग टीम को गर्व होना चाहिए। **महेश भूपति**, पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी

2018 में नागल ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन और विंबलडन के क्वालीफाइंग दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे

2015 में नागल ने वियतनाम के लाइ होंग नाम के साथ मिलकर विंबलडन में लड़कों के डबल्स वर्ग का खिताब जीता था

58000 डॉलर (करीब 41 लाख रुपये) नागल को मिलेंगे यूएस ओपन के पहले दौर का मुकाबला खेलने पर

तेंदुलकर, लक्ष्मण व सौरव को क्यों नहीं मिला बोर्ड का वकील

नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रशासकों की समिति (सीओए) ने फैसला किया है कि वह हितों के टकराव के मामले में राहुल द्रविड़ का केस लड़ेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के एक अधिकारी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर सीओए द्रविड़ का केस लड़ सकती है तो इसी तरह के मामले में उसने सचिन तेंदलुकर, सौरव गांगुली और लक्ष्मण का केस क्यों नहीं लड़ा?

बीसीसीआइ के लोकपाल डीके जैन ने हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के मुखिया नियुक्त किए गए द्रविड़ को हितों के टकराव के मामले में नोटिस भेजा है और उन्हें 26 सितंबर को अपने पास बुलाया है। बीसीसीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीओए ने हितों के टकराव मामले में जिस तरह का रुख द्रविड़ के लिए अपनाया है वैसा ही रुख उसे सौरभ, सचिन और लक्ष्मण के मामले में अपनाना चाहिए था। अधिकारी ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो सीओए का मनमाना रवैया समझ में नहीं आता। बीसीसीआइ की नजरों में सभी पूर्व खिलाड़ी समान होने चाहिए। अगर अब सीओए ने फैसला किया है कि वह द्रविड़ के मामले में अपना वकील नियुक्त करेगी तो यही सोच सचिन, सौरव और लक्ष्मण के मामले में क्यों नहीं अपनाई गई? क्या यह इसलिए था कि वह मानद भूमिका में थे और प्रत्यक्ष तौर पर बीसीसीआइ के कर्मचारी नहीं थे। यह साफ तौर पर गलत है। एक अन्य अधिकारी ने इसी तरह के एक और वाकये को उठाया जहां एमवी श्रीधर को महानिदेशक (क्रिकेट संचालन) के पद से हितों के टकराव के मामले के कारण हटना पड़ा था, लेकिन बोर्ड द्वारा वकील मुहैया नहीं कराया गया था। अधिकारी ने कहा कि हमें इसके लिए भी डीआरएस चाहिए। अगर आप कुछ साल पहले जाते हैं तो श्रीधर को हितों के टकराव के मामले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें किसी भी तरह का वकील या किसी भी तरह की मदद मुहैया नहीं कराई गई थी। इस तरह का व्यवहार उस इंसान के साथ किया गया था जिसने भारतीय क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ दे दिया था जिनकी कुछ दिनों पहले ही हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई और यह बात अभी तक हमें परेशान करती है।

फिर चर्चा में भारतीय टेनिस

फेडरर के खिलाफ भारतीय

खिलाड़ी	फेडरर की जीत	वर्ष	टूर्नामेंट
रोहन बोपन्ना	7-6, 6-2	2006	हाले ओपन
सोमदेव	6-3, 6-3	2011	दुबई चैंपियनशिप
सोमदेव	6-2, 6-1, 6-1	2013	फ्रेंच ओपन
सुमित नागल	4-6, 6-1, 6-2, 6-4	2019	यूएस ओपन

दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शुमार रोजर फेडरर से यूएस ओपन में एक सेट जीतने वाले सुमित नागल के इस प्रदर्शन ने भारतीय टेनिस को सुर्खियों में ला दिया और अब इसकी दशा और दिशा पर बहस हो रही है।

भारत के इकलौते ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा और भारत के पूर्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देवबर्मन ने ट्विटर पर इस पर अपनी राय व्यक्त की है। बिंद्रा ने कहा कि नागल ने दिखा दिया है कि भारत भविष्य में ग्रैंडस्लैम चैंपियन पैदा कर सकता है। वहीं सोमदेव ने सवाल दागा कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते क्या चैंपियन निकल सकेंगे। जर्मनी में अभ्यास करने वाले नागल ने अप्रैल से जून तक चैलेंजर सर्किट में आठ टूर्नामेंट खेलकर पांच के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

मेदवेदेव को टक्कर देने में सफल रहा : प्रजनेश

न्यूयॉर्क : भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहा कि उन्होंने यूएस ओपन के पहले दौर के मुकाबले में विश्व रैंकिंग में पांचवें स्थान पर काबिज डेनिल मेदवेदेव को कड़ी टक्कर दी, लेकिन टखना मुड़ने के कारण वह आक्रामक खेल को जारी नहीं रख पाए। लगातार चौथे ग्रैंडस्लैम के मुख्य ड्रॉ में खेल रहे प्रजनेश को सोमवार को रूस के खिलाड़ी से 4-6 1-6, 2-6 से शिकस्त मिली। प्रजनेश ने कहा, 'वह निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। वह ज्यादा गलतियां नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है मैंने अपने खेल से उन्हें टक्कर दी। मेरा टखना मुड़ गया, जिसके बाद मेरे लिए स्थिति मुश्किल हो गई।

जोकोविक दूसरे दौर में पहुंचे

न्यूयॉर्क, एएफपी : पिछले पांच में से चार ग्रैंडस्लैम जीतने वाले सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविक ने यहां यूएस ओपन में अपने पहले दौर के मुकाबले में स्पेन के 76वीं रैंकिंग के रोबर्टो कारबालेस बेइना को 6-4, 6-1, 6-4 से पराजित किया। जोकोविक का अगला मुकाबला अर्जेंटीना के 56वीं रैंकिंग के जुआन इग्नेसियो लोंडेरो से होगा।

जोकोविक ने कहा, 'मैं अपने प्रदर्शन से काफी खुश हूं और अब मेरी निगाह अगले मैच पर है। यह टूर्नामेंट ऐसे समय होता है जब विजेता के बारे में अनुमान लगाना सबसे मुश्किल है।' जोकोविक, फेडरर और राफेल नडाल बिग थ्री के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों खिलाड़ियों ने पिछले 65 ग्रैंडस्लैम मुकाबले में 54 में जीत दर्ज की है। जोकोविक ने कहा, 'हां, यह साल का आखिरी ग्रैंडस्लैम है। ऐसे में कुछ खिलाड़ी ज्यादा थके होंगे क्योंकि यह लंबा सत्र है और आपको अलग-अलग कोर्ट पर खेलना होता है जिसके लिए बदलाव करने होते हैं और इससे आपके शरीर पर असर पड़ता है। शायद इसीलिए इस टूर्नामेंट में 'बिग थ्री' के अलावा दूसरे खिलाड़ियों ने भी खिताब जीते है।' वहीं, अन्य मुकाबलों में जापान के सातवीं वरीयता प्राप्त केई निशिकोरी जब मार्को ट्रंगेटिली के खिलाफ 6-1, 4-1 से आगे चल रहे थे तो तब अर्जेंटीनी क्वालीफायर ने पीठ दर्द के कारण हटने का फैसला किया।

सेरेना ने शारापोवा को हराया

न्यूयॉर्क, एएफपी : अपने 24वें ग्रैंडस्लैम की कवायद में लगीं अमेरिकी दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने यहां मारिया शारापोवा को करारी शिकस्त देकर यूएस ओपन में शानदार शुरुआत की। सेरेना ने शारापोवा को 6-1, 6-1 से हराया। छह बार की यूएस ओपन चैंपियन ने इस जीत के केवल 59 मिनट का समय लिया। यह शारापोवा पर उनकी लगातार 19वीं जीत है। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक जो 22 मैच खेले गए हैं उनमें से 20 सेरेना ने जीते हैं। सेरेना ने मैच के बाद कहा, 'मैं जब भी उसके खिलाफ खेलती हूं तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हूं। जब आप उसके खिलाफ खेलते हो तो आपको एकाग्रता बनाए रखनी होती है।' सेरेना का अगला मुकाबला विश्व में 121वें नंबर की कैटी मैकनैली से होगा। अन्य मुकाबलों में फ्रेंच ओपन चैंपियन एश्ले बार्टी और तीसरी वरीयता प्राप्त कैरोलिना प्लिस्कोवा भी संघर्षपूर्ण जीत दर्ज करके आगे बढ़ने में सफल रहीं। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी वरीयता प्राप्त बार्टी ने बेहद खराब शुरुआत से उबरकर कजाखिस्तान की 80वीं रैंकिंग की जरीना दीयास को 1-6, 6-3, 6-2 से पराजित किया, जबकि प्लिस्कोवा ने हमवतन चेक गणराज्य की टेरेजा मार्टिनकोवा को 7-6, 7-6 से हराया। महिला वर्ग में पांचवीं वरीयता प्राप्त इलिना स्वितोलिना ने व्हीटनी ओसुगवे को 6-1, 7-5 से हराया।

खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आइओए के सीजीएफ से बात करने के बाद खेल मंत्रालय लेगा निर्णय

सरकार करेगी कॉमनवेल्थ गेम्स बॉयकॉट पर फैसला

अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली

2022 में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ से निशानेबाजी को बाहर किए जाने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) उन खेलों का बहिष्कार करना चाहता है लेकिन खेल मंत्री ने आइओए के प्रतिनिधियों को कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (सीजीएफ) के अध्यक्ष से मिलने की सलाह दी है। दैनिक जागरण ने जब उनसे पूछा कि आइओए लगातार इन खेलों के बहिष्कार की धमकी दे रहा है, इसको लेकर खेल मंत्रालय की राय क्या है? रिजिजू ने कहा कि अभी हमने उन्हें सीजीएफ के मुखिया से बात करके अपील करने को कहा है। समय आने पर इस पर फैसला लिया जाएगा। इस पर आखिरी फैसला सरकार ही करेगी।

जब उनसे पूछा गया कि क्या बॉयकॉट करना ही सही रास्ता है तो उन्होंने कहा कि देखिये खेल सभी के लिए है। जितने भी खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक के लिए लड़ते हैं, उन सभी के लिए यह खेल महत्वपूर्ण है। कॉमनवेल्थ आयोजन समिति ने यह फैसला किया है कि बर्मिंघम में निशानेबाजी नहीं होनी चाहिए। आइओए और भारतीय निशानेबाजी संघ के प्रतिनिधि मेरे पास आए थे। उन्होंने भविष्य की संभावनाओं पर मुझसे बात की और मुझसे पूछा कि क्या इसमें क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि कहा कि बॉयकॉट करना है या नहीं करना है, इसका फैसला अभी लेने का समय नही है। यह एक बड़ा फैसला है।

भारतीय खेल मंत्री किरण रिजिजू। प्रेट्र

किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल को बॉयकॉट करना बहुत बड़ा फैसला होता है। हम जोश में कोई फैसला नहीं कर सकते लेकिन यह बात सही है कि कॉमनवेल्थ गेम्स समिति को भी समझना होगा कि भारत इन खेलों का सबसे बड़ा देश है और कोई भी बड़ा फैसला लेते समय भारत के पक्ष को सुनना चाहिए। आइओए से कॉमनवेल्थ आयोजन समिति को पूछना चाहिए या सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने निशानेबाजी को बाहर रखने के फैसले को लेकर आइओए से कोई वार्तालाप नहीं किया है। मैंने आइओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा को कहा कि आप सरकार के पास आ गए हैं, हम विचार करेंगे लेकिन हम कुछ फैसला करें, उससे पहले आप कॉमनवेल्थ गेम्स समिति के सामने भारत का पक्ष रखें कि हमें यह फैसला मंजूर नहीं है। इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। जब उनसे कहा कि इस फैसले पर वोटिंग भी हो चुकी है और उन्होंने फैसला ले लिया है कि निशानेबाजी वापस नहीं आएगी? ऐसे में उनसे बात करने से क्या फायदा? रिजिजू ने कहा कि आइओए ने मुझे बताया कि फैसला हो चुका है लेकिन हमें अपील तो करना ही पड़ेगी। इसमें दो बातें हैं, एक है राष्ट्रीय रुचि।

निशानेबाजी से हमको सबसे ज्यादा पदक मिलते हैं। वह खेल ही नहीं होगा तो हमें क्या फैसला लेना चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो फैसला लिया जाए उससे बाकी खेलों और भारत की उम्मीदों को नुकसान नहीं हो। हम सही समय पर संतुलित फैसला लेंगे।

पेरिस और लॉस एंजिल्स ओलंपिक पर नजर

नई दिल्ली : खेल मंत्री से जब अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ 10 महीने बचे हैं और ऐसे में हमें मौजूदा प्रतिभा के साथ जाना होगा। 10 महीने में हम नई प्रतिभा को तैयार नहीं कर सकते। हम पिछले ओलिंपिक से बेहतर नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी दीर्घकालिक तैयारी 2024 में पेरिस और 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए है। बड़े खेलों की मेजबानी पर उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं।

रहाणे का नया अध्याय शुरू

वीवीएस लक्ष्मण
वेरी-वेरी स्पेशल

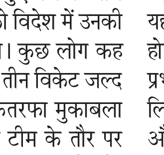

एंटीगा में हुए पहले टेस्ट में भारतीय टीम जीत की दावेदार थी, लेकिन वेस्टइंडीज ने खराब खेल दिखाते हुए मैच के चौथे दिन ही भारतीय टीम को विदेश में उनकी सबसे बड़ी जीत दे दी। कुछ लोग कह सकते हैं कि पहले दिन तीन विकेट जल्द गंवाने के बाद यह एकतरफा मुकाबला था, लेकिन नंबर एक टीम के तौर पर भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की। जब आप एक ही प्रारूप में खेल रहे होते हैं तो खुद को लंबे प्रारूप में ढालना आसान नहीं होता है।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण चेतेश्वर पुजारा हैं। इससे अजिंक्य रहाणे पर दबाव बढ़ा और उन्होंने जरूर थोड़ा दबाव महसूस किया होगा क्योंकि पिछले दो वर्ष से उन्होंने कोई शतक नहीं लगाया था। इसके बावजूद चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन ने उन पर भरोसा जताया। उपकप्तान रहाणे इसके बाद अपने आप को साबित करने में कामयाब रहे और रविवार को शतक लगाकर दिखाया कि यह पारी उनके लिए मायने रखती है।

रहाणे अपनी काबिलियत के साथ न्याय नहीं कर पाए थे। मुझे उम्मीद है कि यहां से उनके करियर का नया अध्याय होगा। मैं हनुमा विहारी के प्रदर्शन से प्रभावित हुआ। उन्होंने बिना कोई दबाव लिए स्वतंत्रता के साथ बल्लेबाजी की और लगा कि वह टेस्ट क्रिकेट के लिए बने हैं।

वहीं केएल राहुल खुद से बेहद निराश होंगे, क्योंकि अच्छी शुरुआत के बाद भी उन्होंने दोनों पारियों में अपना विकेट गंवाया। भारतीय तेज गेंदबाज एक बार दोबारा अच्छी लय में थे। इशांत ने पूरे मैच में शानदार गेंदबाजी की लेकिन जिन्होंने सभी को प्रभावित किया वह जसप्रीत बुमराह थे।

बुमराह शीर्ष-10 में, कोहली नंबर-एक

टेस्ट रैंकिंग ▸ गेंदबाजों की सूची में तेज गेंदबाज जसप्रीत सातवें स्थान पर पहुंचे

बल्लेबाजी में स्टोक्स व रहाणे को भी हुआ फायदा

नई दिल्ली, प्रेट्र : वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगा टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पहली बार आइसीसी टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष-10 गेंदबाजों में जगह बनाई है, जबकि विराट कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर बरकरार हैं। बुमराह ने विंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की अंतिम पारी में पांच विकेट लिए थे। यह टेस्ट करियर में चौथा मौका था जब उन्होंने पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लिए थे।

बुमराह के प्रदर्शन के दम पर भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जीत के साथ शुरुआत की। बुमराह नौ स्थान की छलांग लगाते हुए 774 अंकों के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस हालांकि अब भी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। वह 908 अंकों के साथ नंबर एक पर काबिज हैं। वहीं, दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबादा 851 अंकों के साथ दूसरे और जेम्स एंडरसन 814 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड के बायें हाथ तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने एक बार फिर शीर्ष पांच में जगह बनाई है। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में अविश्वसनीय पारी खेलकर इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोमांचक जीत दिलाने वाले ऑलराउंडर बेन स्टोक्स टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडरों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर स्टोक्स और जैक लीच ने आखिरी विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी कर ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत छीनी, बल्कि इंग्लैंड को एशेज सीरीज में बनाए रखा। स्टोक्स ने इस मैच में 135 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली। स्टोक्स दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इससे पहले वह सितंबर 2017 में तीसरे नंबर पर थे। स्टोक्स को 44 अंक मिले, जिससे अब उनके 411 अंक हो गए हैं और अब वह वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर से 22 अंक ही पीछे हैं।

बल्लेबाजों में वेस्टइंडीज के खिलाफ नॉर्थ साउंड में हुए पहले टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाने वाले भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे एक स्थान के फायदे के साथ 10वें पायदान पर पहुंच गए हैं। रहाणे ने एंटीगा में अपने करियर का 10वां टेस्ट शतक लगाया था। वहीं स्टोक्स ने बल्लेबाजों की सूची में भी 13 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है और अब वह करियर की सर्वश्रेष्ठ 13वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। रहाणे 21वें नंबर से 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। कप्तान विराट कोहली 910 अंक के साथ शीर्ष पर हैं।

टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पांच बल्लेबाज

बल्लेबाज	देश	अंक
विराट कोहली	भारत	910
स्टीव स्मिथ	ऑस्ट्रेलिया	904
केन विलियमसन	न्यूजीलैंड	878
चेतेश्वर पुजारा	भारत	856
हेनरी निकोल्स	न्यूजीलैंड	749

टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पांच गेंदबाज

गेंदबाज	देश	अंक
पैट कमिंस	ऑस्ट्रेलिया	908
कैगिसो रबादा	द. अफ्रीका	851
जेम्स एंडरसन	इंग्लैंड	814
वर्नोन फिलेंडर	द. अफ्रीका	813
ट्रेंट बोल्ट	न्यूजीलैंड	793

रिकॉर्ड जीत के बाद कोहली एंड कंपनी ने अनुष्का के साथ की क्रूज की सैर

कैरेबियाई डायरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में रिकॉर्ड जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम के सदस्य क्रूज पर कैरेबियन द्वीप की सैर करने निकले। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा किया, जिसमें वह कप्तान विराट कोहली, मयंक अग्रवाल और रविचंद्रन अश्विन के साथ क्रूज पर नजर आ रहे हैं। कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा भी इस तस्वीर में हैं। यह सब क्रूज पर मस्ती करते हुए देखे गए। इस बीच चाइनामैन कुलदीप यादव ने भी इंस्टाग्राम एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के साथ जेट स्की पर मस्ती करते दिखे।

भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य व विराट कोहली की पत्नी अनुष्का। ट्विटर

पंत की जगह रिद्धिमान खेलें दूसरा टेस्ट : किरमानी

कोलकाता, प्रेट्र : भारत के महानतम विकेटकीपरों में से एक सैयद किरमानी का मानना है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में रिषभ पंत की जगह रिद्धिमान साहा को मौका दिया जाना चाहिए। भारत के लिए 88 टेस्ट खेल चुके किरमानी का मानना है कि साहा चोटिल थे और उन्हें पंत के समान मौके मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि पंत अभी युवा हैं, लेकिन काफी प्रतिभाशाली हैं। उन्हें हालांकि काफी कुछ सीखना है। उन्होंने कहा मैदान पर यह सबसे कठिन स्थिति होती है। हर कोई दस्ताने पहनकर विकेटकीपर नहीं बन सकता।

फिटनेस को लेकर सोशल मीडिया पर हुई शास्त्री की खिंचाई

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ गए। इस बार शास्त्री को फिटनेस को लेकर बातें सुननी पड़ीं। भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में 318 रनों से मात दी थी। इसके बाद टीम ने कुछ दिन की छुट्टियां बिताने का मन बनाया। शास्त्री ने सोमवार को एंटीगा के कोको बे से एक फोटो ट्विटर पर पोस्ट की और लिखा कि हॉट, हॉट, हॉट। समय है कुछ जूस पीने का। कोको बे बेहतरीन खूबसूरत जगह है। शास्त्री को यह फोटो पोस्ट करना उन्हें महंगा पड़ा क्योंकि इसके बाद वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। एक यूजर ने ट्वीट किया कि आप अपनी फिटनेस और साथ ही पेट पर ध्यान दें। आप भारतीय टीम के कोच हैं ना कि किसी गली की क्रिकेट टीम के। एक अन्य यूजर ने लिखा कि आपको बीयर की जरूरत है, जूस की नहीं। कृपया अगली फोटो साइड से लेना, मैं देखना चाहता हूं कि आपका पेट कितना बड़ा है। एक और शख्स ने लिखा कि कृपया अपने कपड़े पहनने का तरीका सुधारें। आप काफी अजीब लग रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि आपको जूस की जगह बीयर पीनी चाहिए, जो आपको पसंद भी है। भारतीय टीम मंगलवार को एंटीगा में क्रूज पर संमदर का लुत्फ ले रही थी।

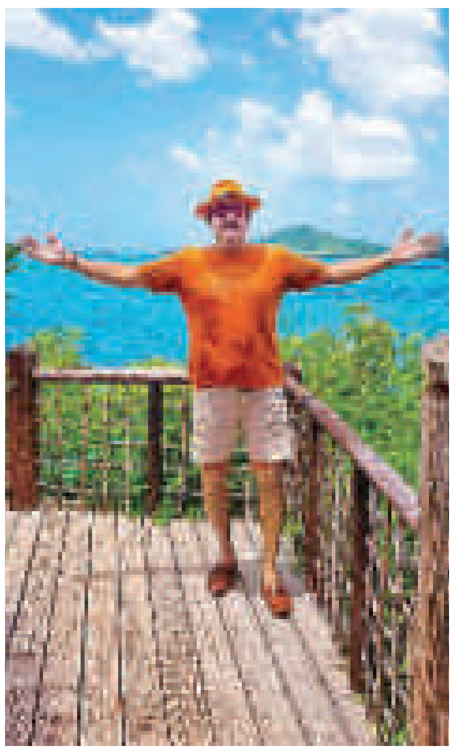

क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री। ट्विटर

रोहित ने लिया बुमराह और रहाणे का इंटरव्यू

एंटीगा, आइएएनएस : वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में रोहित शर्मा को अंतिम-11 में मौका नहीं मिला, लेकिन वनडे टीम का उप कप्तान टेस्ट मैच खत्म होने के बाद एक नई भूमिका में नजर आया। रोहित ने पहले टेस्ट में भारत की जीत के हीरो रहे जसप्रीत बुमराह और अंजिक्य रहाणे पर सवालों के बाउंसर फेंकने का काम किया। रहाणे ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 102 और पहली पारी में 81 रन बनाए थे। बुमराह ने दूसरी पारी में सात रन देकर पांच विकेट अपने नाम किए थे। इस जीत के बाद रोहित ने बीसीसीआइ डॉट टीवी पर रहाणे और बुमराह का इंटरव्यू लिया। रोहित ने बुमराह से पूछा कि आप बल्लेबाजों को आउट स्विंग करा रहे थे जो आपकी स्वाभिवक गेंद नहीं है।

आप आमतौर पर क्रीज के कोने का उपयोग कर गेंद को अंदर लाते हैं, लेकिन (सोमवार को) आप बल्लेबाजों को ऑफ स्टंप के बाहर से बीट करा रहे थे। आपने इस पर काम किया या फिर आप हवा का फायदा उठा कर गेंद को हिला रहे थे। बुमराह ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा आउट स्विंगर गेंद का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं, लेकिन सोमवार को यह कुछ ज्यादा किया और इसका कारण हवा रही। मैंने इंग्लैंड में भी आउट स्विंग का इस्तेमाल किया था। इससे मुझे आत्मविश्वास मिला। रोहित ने रहाणे से सवाल पूछा कि कई लोग कह रहे थे कि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं।

लोग क्या कहते हैं, क्या आप उस बारे में सोचते हैं? रहाणे ने कहा कि मैं आलोचना को दिल पर नहीं लेता। यह ऐसी नागवार चीज है जिस पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। टेस्ट टीम के उप कप्तान ने कहा कि जब आप शतक जमाते हैं तो निजी तौर पर काफी खुश महसूस करते हैं। मेरे लिए यह पारी काफी संतोषजनक थी जिसमें मैंने काफी मेहनत की।

भारत लौटने पर सिंधू का जोरदार स्वागत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

शानदार

▸ **कोच गोपीचंद के साथ सोमवार रात लौटीं पीवी, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री से की मुलाकात**

भारत की पहली विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधू का स्वदेश लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने भी वादा किया कि वह ज्यादा से ज्यादा पदक जीतने के लिए आगे और कड़ी मेहनत करेंगी।

ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधू ने स्विट्जरलैंड के बासेल में रविवार को जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-7, 21-7 से हराकर खिताब जीता। इसके साथ ही वह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थीं। इससे पहले सिंधू इस टूर्नामेंट के पिछले संस्करणों में दो रजत और दो कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। वह जब सोमवार रात को राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के साथ यहां इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंची तो लोगों ने उन्हें घेर लिया।

कड़ी मेहनत करूंगी : व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद सिंधू ने सहनशीलता दिखाई। इस 24 वर्षीय खिलाड़ी के चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने एयरपोर्ट पर मौजूद समर्थकों और मीडिया को पूरी तवज्जो दी। सिंधू से एक साथ कई सवाल पूछे गए, उन्होंने कहा, 'मैं वास्तव में खुश हूं। मुझे अपने देश पर बहुत गर्व है। इस जीत का लंबे समय से इंतजार था और मैं इससे बहुत खुश हूं।' सिंधू से पूछा गया कि अब ओलंपिक में एक साल से भी कम समय रह गया है तब उनकी क्या योजनाएं हैं, तो उन्होंने कहा, 'मैं कड़ी मेहनत करूंगी और अधिक से अधिक पदक जीतने की कोशिश करूंगी।'

भावनाएं हो गई थीं हावी : सिंधू ने पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान भावुक पलों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि जब राष्ट्रगान बज रहा था तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए थे। उन्होंने कहा, 'मेरे आंसू निकल आए और भावनाएं मुझ पर हावी थीं। यह मेरे लिए शानदार क्षण था। मेरे सभी प्रशंसकों का आभार। आपकी दुआओं से ही यह संभव हो पाया। मैं अपने कोच गोपी सर और किम (जी ह्यून) का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। उन्होंने काफी प्रयास किए और मेरे खेल में कुछ बदलाव किए।'

जताया आभार : दक्षिण कोरिया की पूर्व अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी किम इस साल के शुरू में गोपीचंद की सिफारिश पर कोचिंग स्टाफ में जुड़ी थीं। सिंधू ने सहयोग के लिए सरकारी एजेंसियों और भारतीय बैडमिंटन संघ (बाई) का भी आभार जताया। उन्होंने कहा, 'वाकई में बहुत अच्छा स्वागत किया गया। मैं भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), खेल मंत्रालय और सरकार को भी धन्यवाद देती हूं। उनका बहुत सहयोग रहा।'

पदक के साथ पीवी सिंधू। प्रेट्र

मोदी ने बताया सिंधू को भारत का गौरव

नई दिल्ली : पीवी सिंधू ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें भारत का गौरव बताया। मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट किया, 'भारत की गौरव, एक चैंपियन जो एक स्वर्ण और ढेर सारा सम्मान लेकर घर लौटीं, आपसे मिलकर खुशी हुई पीवी सिंधू। आपको बधाई और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।'

खेल मंत्री ने सिंधू को दिया 10 लाख का चेक

नई दिल्ली : विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत हासिल करने पर पीवी सिंधू को मंगलवार को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पुरस्कार स्वरूप 10 लाख रुपये का चेक दिया। ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधू ने यहां पहुंचने पर खेल मंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर भारतीय बैडमिंटन संघ (बाई) के अध्यक्ष हिमांता बिस्वा सरमा, कोच पुलेला गोपीचंद और किम जी ह्यून एवं सिंधू के पिता व 1986 एशियन गेम्स में वॉलीबॉल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य पीवी रमाना भी शामिल थे। यह मुलाकात एक घंटे से ज्यादा समय तक चली। खेल मंत्री ने बी साई प्रणीत को भी शुभकामनाएं दीं और विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर चार लाख रुपये का चेक दिया। 1983 में प्रकाश पादुकोण के विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में पदक जीतने के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले प्रणीत पहले भारतीय हैं।

सिंधू का हर पदक खास : गोपी

नई दिल्ली : गोपीचंद ने कहा कि सिंधू का स्वर्ण खास था, लेकिन इस बड़ी स्पर्धा में उनके पिछले पदकों को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने फाइनल में सिंधू के दबदबे वाले खेल का जिक्र करते हुए कहा, 'यह अभूतपूर्व है। इसका लंबे समय से इंतजार था, लेकिन उन्होंने जो भी पदक जीते हैं, सभी खास हैं। हम कांस्य और रजत (पिछले संस्करणों में) भी जीत चुके हैं। स्वर्ण पर सवाल था। ओलंपिक में जाने से पहले इसे जीतना अभूतपूर्व है। जिस तरह से उन्होंने ऐसा किया, वह वाकई में खुशी देने वाला था।'

विविध

चीन विवादित क्षेत्र में 100 बार घुसा है तो हम 200 बार : जीओसी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: सेना के उप प्रमुख मनोनीत लेफ्टिनेंट जनरल एम एम नरवाने ने कहा कि अगर चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर 'विवादित क्षेत्र' में 100 बार अतिक्रमण किया है तो भारतीय सेना ने 200 बार ऐसा किया है। उन्होंने दावा किया कि चीन ने डोकलाम गतिरोध के समय 'क्षेत्रीय दबंग' की तरह काम किया। फिलहाल पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (जीओसी) नरवाने ने कहा कि चीन को समझना चाहिए कि भारतीय सेना वैसी नहीं रही जैसी 1962 में चीन-भारत युद्ध के समय थी।

कोलकाता में भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स में 'डिफेंडिंग आवर बॉर्डर्स' पर संवाद के दौरान उन्होंने कहा, 'डोकलाम गतिरोध से स्पष्ट संकेत मिला था कि भारतीय सशस्त्र बल कमजोर नहीं पड़े।' पूर्व वायु सेना प्रमुख और चेंबर की रक्षा उप समिति के सदस्य अरूप राहा ने 1962 के युद्ध से मिले सबक और उसके बाद समस्याओं से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा, तो नरवाने ने कहा, 'हम अब 1962 वाली सेना नहीं हैं। चीन कहता है कि इतिहास मत भूलो तो हमें भी उन्हें यही बात कहनी है।' कहा कि भारत 1962 से बहुत आगे निकल आया है और 2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान चीन की कोई तैयारी नहीं दिख रही थी।

कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

यशलोक सिंह, गुरुग्राम

▸ **एनुअल टेक्नोलॉजी कांफ्रेंस के दौरान कृषि क्षेत्र में एआइ के महत्व पर किया गया मंथन**

वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की ओर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि गुरुग्राम में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नेस्कॉम) की दो दिवसीय एनुअल टेक्नोलॉजी कांफ्रेंस के दौरान कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के महत्व पर मंथन किया गया। टेक्नोलॉजी क्षेत्र के दिग्गजों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के कल्याण को लेकर लगातार नए-नए कदम उठाए जा रहे हैं। 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर अब खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए देश के किसानों की तकदीर और कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने को लेकर काफी कुछ हो रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक किसानों के लिए मुनाफे की खेती साबित हो सकती है। इससे फसल की लागत घटेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक फसलों को कीट से होने वाले नुकसान से बचाने में मददगार साबित होगी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए मौसम की सटीक भविष्यवाणी हो सकेगी, जिसका फायदा किसान उठा सकते हैं। बीज, मिट्टी, उर्वरक, कीटनाशकों एवं सिंचाई के बारे में किसानों को पूर्व में ही सूचना प्राप्त हो जाएगी। एआइ के जरिये दो माह का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हमारे रोजाना के जीवन में एआइ और रोबोटिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एचपी के मैनेजिंग डायरेक्टर सोम सतसंगी का कहना है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहा है। आर्थिक तौर से भी यह जीवन में दिन प्रतिदिन सुधार लाने का काम कर रही है।

आइबीएम रिसर्च की डायरेक्टर गार्गी दासगुप्ता ने कहा कि कृषि क्षेत्र में किसानों के हित में सुधार की दिशा में एआइ बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। आज 80 फीसद उद्यम एआइ डाटा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

क्या है आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस : जॉन मैकार्थी ने 1955 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) शब्द का इस्तेमाल किया था। इन्हें इसका जनक भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किए जाते हैं, जो उन्हीं तर्कों के आधार पर चलता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी मनुष्यों की तरह सोचना व व्यवहार करना है। तथ्यों को समझ कर तर्क एवं विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया देना।

आइटी एक्सपर्ट रजत श्रीवास्तव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विशेष भूमिका निभा रहा है। आज कृषि क्षेत्र में इसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र के लिए भी किया जा रहा है। किसानों की आमदनी, कृषि पैदावार व फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने में यह मील का पत्थर साबित होगी।

टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ अमित सेठी ने कहा कि यह समय टेक्नोलॉजी का है। इसका योगदान सिर्फ उद्योगों की शुरुआत तक ही सीमित नहीं है बल्कि कारोबार के विस्तार की दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। हर क्षेत्र की प्रगति के लिए इसकी जरूरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को लेकर नेस्कॉम के एनुअल टेक्नोलॉजी कांफ्रेंस में काफी बातें हुईं।

हिमाचल एमएमएस मामले में पति-पत्नी और वो गिरफ्तार

जासं, कुल्लू : हिमाचल प्रदेश स्थित बंजार से संबंधित जुलाई में वायरल एमएमएस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एमएमएस बनाने और उसको वायरल करने के मामले में तीनों के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है। आरोपितों में पति-पत्नी और शिकायतकर्ता शामिल हैं।

एमएमएस बाथरूम में नहाते वक्त दोनों ने सहमति बनाया था। लगभग 12 मिनट 35 सेकेंड के इस वीडियो में दिखने वाले दोनों नेता और नेत्री प्रदेश की बड़ी पार्टी से संबंधित थे। एमएमएस वायरल होने के बाद दोनों को पदों से हटा दिया था। दोनों के संबंधों के बारे में नेता की पत्नी को मालूम और वह परेशान भी थी। ऐसे में उसने पति के मोबाइल से निकालकर इस एमएमएस को वायरल कर दिया था। एमएमएस वायरल होने के अगले दिन नेता की पत्नी और वीडियो में मौजूद नेत्री का लगभग 13 मिनट का ऑडियो भी सार्वजनिक हुआ था। इसमें दोनों बहस करती सुनाई दे रही थीं। इस दौरान दोनों एमएमएस के वायरल करने की बात भी कर रही थीं। उक्त एमएमएस फरवरी में सरकारी गेस्ट हाउस या किसी होटल में बनाया गया था। एमएमएस वायरल होने के बाद बंजार थाने में पीड़िता ने 27 जुलाई को शिकायत दर्ज करवाई थी।

चार जोन में तब्दील होगा ग्रेनो का एक्सपो मार्ट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

▸ **नौ सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की है संभावना, 197 देशों के राजनयिक होंगे शामिल**

▸ **नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में होगा आयोजन**

▸ **31 अगस्त से जिले में आने शुरू हो जाएंगे पुलिसकर्मी**

मिट्टी (मृदा) की गिरती गुणवत्ता एवं बढ़ते मरुस्थलीकरण को लेकर दो सितंबर से ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में होने वाले कॉप 14 (कांफ्रेंस ऑफ द पार्टीज) में 197 देशों के राजनयिक आएंगे। इसके लिए एक सितंबर से ही एक्सपो मार्ट में पुलिसकर्मी सुरक्षा संभालेंगे। एक्सपो मार्ट इस दौरान चार जोन में तब्दील होगा। विदेशी राजनयिक की सुरक्षा में एक्सपो मार्ट के आसपास एक हजार पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा नौ सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान पैरामिलेट्री के जवान भी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। कॉप 14 में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए पुलिस-प्रशासन की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एसपी देहात रणविजय सिंह व सीओ प्रथम तनु उपाध्याय ने एक्सपो मार्ट के कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बैठाना शुरू कर दिया है। कॉप 14 के मद्देनजर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी मामले में निगाह बनाए हुए हैं।

दरअसल, कॉप 14 में दुनिया भर के 197 देशों के राजनयिक व पर्यावरण एवं जलवायु क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ व संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम एक सितंबर से 13 सितंबर तक होगा। इसमें शामिल होने वाले मेहमानों के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने, उनके ठहरने, सुरक्षा आदि को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। इसी के तहत मेरठ जोन के एक हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 13 दिन के लिए एक्सपोमार्ट में लगाई गई है। इस बार कॉप 14 कांफ्रेंस ऑफ द पार्टीज की मेजबानी भारत कर रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल देशों के प्रतिनिधि मृदा की गिरती गुणवत्ता को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों को साझा करेंगे एवं भविष्य के लिए रणनीति तैयार करेंगे।

इतने पुलिसकर्मियों की लगेगी ड्यूटी

एएसपी चार, सीओ 20, महिला सिपाही 80, महिला दारोगा 20, छह थाना प्रभारी, 290 पुरुष दारोगा और 600 पुरुष सिपाही

> कॉप 14 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान एक्सपो मार्ट छावनी में तब्दील रहेगा। जल्द ही पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग कर उनको उनकी ड्यूटी के बारे में बताया जाएगा।
>
> **-वैभव कृष्ण, एसएसपी, गौतमबुद्ध नगर**

सफर में मिलेगा सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का संदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ **महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को यादगार बनाने में जुटा रेल प्रशासन**

भारतीय रेल बापू की 150वीं जयंती को यादगार बनाएगा और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। ट्रेन के कोच से लेकर रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के किनारों पर इसकी झलक दिखेगी। उनके सत्य व अहिंसा के संदेश को प्रचारित किया जाएगा। साथ ही स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर भी काम होगा।

रेलवे ट्रैक के किनारे खाली भूमि पर पौधारोपण के साथ ही नर्सरी विकसित की जाएंगी। पूरे देश में 150 नर्सरी बनाने का फैसला किया गया है, इसमें से चार दिल्ली-एनसीआर के रेलवे स्टेशनों के आसपास बनेंगी। दिल्ली मंडल में शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन के नजदीक रामपुरा में, तुगलकाबाद यार्ड में, फरीदाबाद रेलवे स्टेशन और सोनीपत रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे का यांत्रिक विभाग नर्सरी विकसित करेगा। इसके साथ ही उत्तर रेलवे में पांच लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं।

यात्रियों को ट्रेन में महात्मा गांधी के दर्शन व संघर्ष की जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए ट्रेन के कोच को विशेष तौर पर सजाने की तैयारी है। कई ट्रेनों में इस समय पर्यटन स्थलों से संबंधित पेंटिंग लगाए गए है। अमूमन ट्रेन जिस राज्य से होकर गुजरती है वहां के पर्यटन स्थलों से जुड़ी हुई पेंटिंग लगाई जाती हैं। जिसे बदलकर महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित पेंटिंग लगेगी। कई ट्रेनों में कोच के प्रवेश द्वार पर अभी स्वच्छ भारत मिशन का लोगो (बापू का चश्मा) लगा हुआ मिल जाता है। इसे बदलकर महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती लिखा हुआ नया लोगो लगाया जाएगा।

अब तीन घंटे पहले गंतव्य तक पहुंचेगी गोरखपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर

▸ **गोरखपुर से सुबह 6.35 बजे रवाना होकर तीसरे दिन 6.45 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी**

▸ **कम होगा ठहराव, बढ़ेगी लंबी दूरी की ट्रेनों की रफ्तार**

राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह अब लंबी दूरी की ट्रेनें भी फर्राटा भरती नजर आएंगी। मंत्रालय की पहल पर रेलवे बोर्ड ने मिशन स्पीड पर काम आरंभ कर दिया है। कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी हो चुकी है। इसमें पूर्वोत्तर रेलवे की 15015 गोरखपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस की स्पीड बढ़ाने को बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। अब यह ट्रेन निर्धारित समय से तीन घंटे पहले ही गंतव्य तक पहुंच जाएगी।

गोरखपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस गोरखपुर से रोज 6.35 बजे से रवाना होकर गोंडा, बादशाहनगर, ऐशबाग, उन्नाव, कानपुर सेंट्रल, भोपाल, इटारसी, नागपुर, सिकंराबाद के रास्ते तीसरे दिन सुबह 9.45 बजे यशवंतपुर (निकट बेंगलुरु) पहुंचती है। अब इसके पहुंचने का समय तीन घंटे कम होगा और ट्रेन सुबह 6.45 बजे पहुंचेगी। दरअसल, लंबी दूरी की गाड़ियां गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय ले रही हैं। ऐसे में लंबी दूरी की ट्रेनों को चिह्नित कर रफ्तार बढ़ाकर, अनावश्यक ठहराव कम कर समय की बचत की तैयारी है। इसमें पूर्वोत्तर रेलवे सहित भारतीय रेल की महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल हैं। इसके लिए क्षेत्रीय रेलों के परिचालन अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे में तेज रफ्तार लायक रेल लाइनें तैयार की जा रही हैं। इस पर 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। इसके लिए बाराबंकी से छपरा (425 किमी) मुख्य मार्ग पर रेल लाइनों को बदलकर क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू है। 52 की जगह 60 किग्रा वजन की मेटलाइज्ड पटरियां बिछाई जाएंगी। स्टेशनों के बीच रेल लाइनों के बीच कोई गैप नहीं होगा। यार्ड में डिस्टेंट सिग्नल के आगे डबल डिस्टेंट सिग्नल लगाने की तैयारी है। इससे रफ्तार 19 फीसद बढ़ जाएगी।

> बोर्ड और जोन स्तर पर मंथन चल रहा है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जा रही है। वाराणसी-इलाहाबाद रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है।
>
> **-पंकज कुमार सिंह, सीपीआरओ, एनई रेलवे**

मौसम विशेष

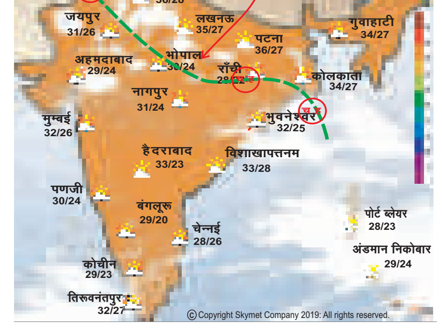

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश का मौसम गर्म रहेगा। इन राज्यों में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा जारी रहेगी। राजस्थान में अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में मौसम मुख्यतः आंशिक बादलों के साथ शुष्क और गर्म बना रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/26/व	अहमदाबाद	34/26/व
कोलकाता	35/28/व	बड़ौदा	32/25/आंबा
चेन्नई	36/28/व	नागपुर	30/23/व
हैदराबाद	33/24/व	इन्दौर	27/22/आंबा
बंगलूरू	28/20/व	रांची	33/25/आंबा
त्रिवेन्द्रम	31/27/व	पटना	32/26/व
गुवाहाटी	34/28/व	जमशेदपुर	32/25/आंबा
गंगटोक	19/12/व	पुणे	23/22/व

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

बुधवार 28 अगस्त 2019

16

www.jagran.com

मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ऐतिहासिक भाषण दिया

1963 में आज ही वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल पर दो लाख लोगों के सामने मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस भाषण को 20वीं सदी का सबसे मशहूर भाषण कहा जाता है। इसमें रंगभेद को मिटाने का आह्वान किया गया था।

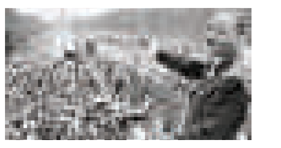

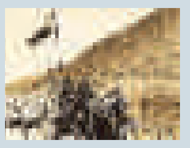

हाजी पीर पोस्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा किया

1965 में आज ही भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने हाजी पीर पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। यह बहुत बड़ी सफलता थी। इस युद्ध में भारतीय फौज ने 19 सौ वर्ग किमी का पाकिस्तानी इलाका जीता था। जबकि पाकिस्तान ने भारत के 540 वर्ग किमी के इलाके पर कब्जा कर लिया था।

आज भी दिलों पर राज करते हैं फिराक गोरखपुरी

उर्दू के अजीम शायर फिराक गोरखपुरी का जन्म 1896 में आज ही यूपी के गोरखपुर में हुआ था। उनका असली नाम रघुपति सहाय था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। उन्हें उर्दू और अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी और फारसी भाषा की अच्छी समझ थी। 1970 में उर्दू काव्य गुले नग्मा के लिए ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। अपने जीवनकाल में कई गजल, शेर, कविताएं और कहानियां लिखीं। 1968 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। 3 मार्च 1982 को देहांत हो गया।

इधर-उधर की

131 रुपये की लॉटरी से जीते करोड़ों

ओटावा, एजेंसी : एक कहावत है ऊपर वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। ये कहावत कनाडा की रहने वाली एक महिला पर बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल, विक्की मिशेल ने 131 रुपये में एक लॉटरी खरीदी थी और उससे उसने 31 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि जीत ली है। अब विक्की की खुशी का ठिकाना नहीं है। बतौर विक्की वो हमेशा लॉटरी के टिकट खरीदती रहती थीं। इससे पहले उन्होंने करीब 878 रुपये जीते थे। इस जीते हुए पैसों से उन्होंने फिर से लॉटरी की टिकट खरीदी, लेकिन उससे सिर्फ वो करीब 439 रुपये ही जीत पाईं। उसके बाद इन पैसों से उन्होंने और भी लॉटरी के टिकट खरीदे थे। 19 अगस्त को मिशेल के अकाउंट में सिर्फ 131 रुपये ही बचे थे और उससे उन्होंने फिर से लॉटरी की टिकट खरीद ली। इस बार उनके भाग्य ने उनका साथ दिया और वो 31 करोड़ 55 लाख रुपये जीतने में कामयाब रहीं। यह राशि उन्हें किश्तों में 30 साल तक हर महीने आठ लाख 80 हजार रुपय में मिलेगी।

अब युद्ध कौशल सिखाएगा वीआर

तकनीक ▶ वर्चुअल रियलिटी के जरिये नई दुनिया में प्रवेश करेंगे सैनिक

इजरायल अपने सैनिकों को नई तकनीक की मदद से कर रहा प्रशिक्षित

नई तकनीक से सैनिकों को कुशल बनाने की हो रही कवायद। प्रतीकात्मक

पेटाह टिकवाह (इजरायल), एएफपी : आतंकी हमले के धमाके की आवाज के बाद एक सैनिक अचानक एक संकरी सुरंग में घुसता है और नुकीली चट्टानों के बीच पहुंच जाता है। उसके बाद वह वहां से उतर कर उफनती नदी और दलदल को पार करते हुए दुश्मन तक पहुंचता है और उसे मार देता है, लेकिन तभी उसे अन्य आतंकी घेर लेते हैं... चिंता न करें ये हजबुल्ला के आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि यह वर्चुअल रियलिटी (वीआर) का कमाल है, जिसके जरिये इजरायल के सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

दरअसल, तकनीकि युग में सैनिकों को परंपरागत तरीके से प्रशिक्षित करने के तरीके अब गुजरे जमाने की बात हो चुके हैं। नए दौर में सैनिकों को आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के जरिये प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो नई दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। इजरायल ने अपने सैनिकों को वीआर के जरिये प्रशिक्षित करना भी शुरू कर दिया है। यहां एक छोटे से कंप्यूटर कक्ष में बैठकर सेना की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के सदस्य नई दुनिया की चुनौतियों से निपटने गुर सीख रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी के कमैरों को अपनी आंखों पर बांधे ये सैनिक कभी तेजी से अपने सिर को नीचे करते हैं तो कभी अचानक ऊपर और कभी हाथों के सहारे दीवारों को टलोलते हैं। सुरक्षा कारणों से अपना नाम नहीं बताते हुए एक सैनिक ने कहा 'हम बैठे-बैठे यहां सब कुछ देख सकते हैं और चुनौतियों से निपटना सीख रहे हैं। वीआर के सेटों को पहनने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि मैं वास्तविकता में मौके पर मौजूद हूं।'

उन्होंने कहा 'वीआर के जरिये सुरंग में जाने के बाद मुझे लगा में वास्तविकता में सुरंग में पहुंच गया है और वहां जो कुछ भी हुआ, वह ठीक वैसा ही था जैसा अक्सर आतंकियों की हमलों में होता है। हमें एक निश्चित समय के बाद अपने टारगेट को खत्म कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होता है। यह वाकई बेहद चुनौतीपूर्ण है।'

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आज के दौर में कई बार आतंकी भी वैज्ञानिक तकनीकों को प्रयोग कर सुरक्षाकर्मियों को चकमा दे जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सुरक्षाकर्मियों को भी तकनीकि रूप से कुशल बनाया जाए और हर परिस्थिति से पार पाना सिखाया जाए।

क्या है वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर : तकनीक के इस दौर में वर्चुअल रियलिटी का बोलबोला धीरे-धीरे बढ़ रहा है। वर्चुअल रियलिटी के सेट आपको एक जगह बैठे ही दुनिया की सैर करा सकते हैं। इस डिवाइस के माध्यम से आपको गेमिंग और एप्लीकेशन में एक अलग अहसास होगा।

कैसे करता है काम : वर्चुअल हेडसेट का लोग दो तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। एक तो सीधे वीआर हेडसेट का उपयोग करने के लिए आप गेमिंग कंसोल से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद आप किसी कार्यक्रम को लाइव देख पाते हैं। वहीं दूसरी ओर अब उपभोक्ता इसका उपयोग स्मार्टफोन के माध्यम से भी कर रहे हैं। इसे आसानी से स्मार्टफोन के साथ भी फिट किया जा सकता है।

आइआइटी की 'मुट्ठी' में होगी आकाशगंगा

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कानपुर अब आकाशगंगा का निकट से अध्ययन कर सकेगा। ग्रहों की गति के साथ तारामंडल का पाठ पढ़ाने वाली संस्थान की वेधशाला (ऑब्जर्वेट्री) को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। 'ऑब्जर्वेट्री फॉर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर' में लगे टेलीस्कोप, गाइड स्कोप, चार्ज कपल्ड डिवाइस (सीसीडी) आटोमेटिक होने से कैंपस में कहीं भी बैठकर गतिमान ग्रहों की फोटो ली जा सकेगी। अभी इन डिवाइस के संचालन के लिए सेंटर पर जाना पड़ता है। वेधशाला प्रमुख प्रो. पंकज जैन ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है।

छात्रों ने बनाया यू ट्यूब चैनल : आइआइटी की वेधशाला से जुड़े छात्रों ने एक यू ट्यूब चैनल बनाया है। छात्र इसमें कार्यक्रमों की झलकियां व उसके वीडियो अपलोड करते हैं। प्रो. पंकज जैन ने बताया कि स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को आकाशगंगा के बारे में बताने के लिए आधुनिक उपकरणों से ग्रहों की कई फोटो ली गई है। समय-समय पर यह फोटो यू ट्यूब में अपलोड की जाती हैं। आने वाले दिनों में खगोलीय पिंडों की अधिक से अधिक फोटो यू ट्यूब के साथ गूगल में भी देखी जा सकेंगी। इसके बाद तारों की दुनिया उन स्कूली बच्चों के लिए रहस्यमय नहीं रह जाएगी जो उसके बारे में जानना चाहते हैं।

तारा मंडल देखेंगे नन्हें वैज्ञानिक : संस्थान में पहली बार 'नासा इंटरनेशनल ऑब्जर्व द मून नाइट' मनाया जाएगा। 30 सितंबर से चार अक्टूबर तक वेधशाला में स्कूली छात्र तारामंडल के नजारे ले सकेंगे। वेधशाला समन्वयक तारिश सेन ने बताया कि इस वर्ष नासा इंटरनेशनल ऑब्जर्व द मून नाइट पांच अक्टूबर को होगी। पांच दिन तक छात्र-छात्राएं न केवल चांद व सितारों को देख सकेंगे बल्कि आधुनिक उपकरणों से भी परिचित होंगे।

स्पेक्ट्रम

खास बातें

- वेधशाला में स्थापित है पॉवर टेलीस्कोप
- खगोलीय पिंडों का बारीकी से किया जा सकता है अध्ययन
- टेलीस्कोप, गाइड स्कोप व सीसीडी से फोटो लेने में लगता है एक घंटे का समय
- हाइपस्टार लेंस के इस्तेमाल से कम समय में ली जा सकेगी फोटो

प्रयोगशाला में विकसित किया मांस

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला के भीतर मांस (मीट) को विकसित करने में सफलता पाई है, जो पौष्टिक होने के साथ-साथ जानवरों की हत्या को कम करने में मदद कर सकता है।

आइआइटी गुवाहाटी के डॉक्टर बिमन बी मंडल ने कहा कि प्रयोगशाला में विकसित किया गया मांस एक सुरक्षित विकल्प है। इससे न सिर्फ जानवरों की हत्या को रोका जा सकता है बल्कि पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आइआइटी की बायोमैटेरियल एंड टिश्यू इंजीनियरिंग प्रयोगशाला में शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक से पूरी तरह से प्राकृतिक मांस विकसित किया है। मंडल ने कहा कि इसका स्वाद कच्चे मांस के जैसा ही है लेकिन उपभोक्ताओं की जरूरत के लिहाज से इसकी पौष्टिकता को और बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण मांस उद्योग इस समय जबरदस्त दबाव का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या संभावनाओं की भविष्यवाणी का हवाला देते हुए मंडल ने कहा कि वर्तमान मांस उद्योग 2050 तक वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि एक किलो चिकन के मांस का उत्पादन करने के लिए लगभग 4,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और एक किलो मटन का उत्पादन करने के लिए 8,000 लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण विश्व गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में कृत्रिम मांस उत्पादन की नई विधियां कारगर सिद्ध हो सकती है।मंडल ने कहा कि कृत्रिम मांस उत्पादन के लिए शोधकर्ताओं ने जानवरों की बायोप्सी के टुकड़ों को प्रयोगशाला में विकसित कर मांस के बड़े टुकड़े विकसित किए हैं।

शोध अनुसंधान

दुबले लोगों में फैटी लिवर होने का कारण पता चला

वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने में कामयाबी हासिल की है कि पतले लोगों में फैटी लिवर डिजीज का कारण क्या है? इस बीमारी में लिवर में वसा का जमाव होने लगता है। गंभीर होने पर यह बीमारी लिवर खराब होने का कारण भी बन सकती है। आमतौर पर मोटापे को इसकी वजह माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में पतले लोगों में भी यह बीमारी देखी गई है। पतले लोगों में यह बीमारी अन्य से ज्यादा घातक सिद्ध होती है। शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने फैटी लिवर की परेशानी से जूझ रहे पतले और मोटे लोगों के मेटाबॉलिज्म, पेट के बैक्टीरिया एवं जीन संबंधी कारकों का अध्ययन किया। इससे पतले लोगों में बीमारी के कारणों को समझने में मदद मिली। वैज्ञानिकों का कहना है कि बीमारी का कारण बनने वाले कुछ जीन व प्रोटीन की ही मदद से पतले लोगों में इस बीमारी का इलाज खोजना भी संभव हो सकता है। - आइएएनएस

कैंसर के खतरे को कम कर सकता है समुद्री घोंघा

वैज्ञानिकों ने समुद्री घोंघे से पाए जाने वाले एक तत्व को कैंसर के खिलाफ कारगर पाया है। घोंघे की मोलस्क ग्रंथि से मिलने वाले एक विशेष रसायन पर करीब एक दशक तक शोध के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह तत्व आंतों के कैंसर से बचाने में कारगर है। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता कैथरीन एबॉट ने कहा, 'हम इन नतीजों से बहुत उत्साहित हैं। हमें उम्मीद है कि इससे आंतों के कैंसर की नई दवा ईजाद करने का रास्ता खुल सकता है।' घोंघे से मिलने वाला यह खास तत्व आंतों में कैंसर की गांठ को बनने से रोकता है। यह कैंसर दुनियाभर में कैंसर के कारण होने वाली मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। वैज्ञानिकों ने कहा कि समुद्री जीवों एवं पौधों से मिलने वाले कई तत्व भविष्य में चिकित्सा जगत के लिए अहम हो सकते हैं। - आइएएनएस

जानलेवा काला ज्वर के इलाज में अब गोली भी होगी असरदार

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

- आइआइटी हैदराबाद ने विकसित की ओरल टैबलेट
- क्लीनिकल टेस्ट के बाद आएगी बाजार में, सुई से मिलेगी निजात

काला ज्वर (बुखार) जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आइआइटी हैदराबाद ने एक ऐसी ओरल टैबलेट (गोली) विकसित की है, जो शरीर में नियंत्रित तरीके से घुलती है। यह शरीर को बगैर नुकसान पहुंचाए 10 दिनों के भीतर पीड़ित को बीमारी से पूरी तरह से निजात दिलाने में सक्षम है। क्लीनिकल ट्रायल के बाद जल्द ही इसे बाजार में उतारा जाएगा। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि अब तक इस बीमारी से निपटने के लिए कोई गोली उपलब्ध नहीं है। पीड़ितों को इलाज के लिए कम से कम 45 दिनों तक लगातार इंजेक्शन (सुई) लेना पड़ता है, जो महंगा और तकलीफदेह साबित होता है।

यह बीमारी सबसे ज्यादा उन्हीं इलाकों में होती है, जहां गरीबी अधिक है। फिलहाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल इस बीमारी से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक, काला ज्वर से निपटने के लिए दवा तो उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ सुई के रूप में। इसके बावजूद समय रहते पीड़ितों पर उसका असर नहीं हो पाता है।

अक्सर सुई के माध्यम से दवा पीड़ित व्यक्ति के शरीर में संतुलित मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। नतीजतन, वह जहर बनकर फैल जाती है। ऐसे में लोगों की इलाज के दौरान ही मौत भी हो जाती है। सुई के जरिये इलाज काफी महंगा भी पड़ता है।

आइआइटी हैदराबाद के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. चंद्रशेखर शर्मा के मुताबिक, काला ज्वर में फंगल इंफेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। अनुसंधान के दौरान यह पाया गया कि इस बीमारी में एक ऐसी गोली ही ज्यादा कारगर होगी, जो नियंत्रित तरीके से शरीर के भीतर दवा की मात्रा को पहुंचाए। इसके बाद दवा निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इसमें नैनोफाइबर तकनीक का इस्तेमाल किया गया। डॉ. शर्मा के मुताबिक, नैनोफाइबर तकनीक अत्याधुनिक है। इसका इस्तेमाल अभी दुनिया भर में कम ही दवाओं के निर्माण में किया जा रहा है।

फेडोर को लेकर गया रूसी यान दूसरे प्रयास में आइएसएस पर उतरा

मॉस्को, एएफपी : मानव सरीखे रोबोट फेडोर को लेकर अंतरिक्ष में गया रूसी यान सोयूज मंगलवार को अपने दूसरे प्रयास में सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस) पर उतर गया। नासा टीवी ने इसकी पुष्टि की है। वैज्ञानिक उपकरण और अन्य साजोसामान के साथ फेडोर को लेकर सोयूज एमएस-14 अंतरिक्ष यान गुरुवार को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमोस के कजाखस्तान स्थित प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ था। वह शनिवार को आइएसएस के करीब पहुंच गया था। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उससे जुड़ नहीं पाया था।

आइएसएस में इस समय फेडोर के अलावा छह अंतरिक्ष यात्री हैं। फेडोर मानव की तरह चलने-फिरने में सक्षम है। इसे जोखिम भरे काम करने के उद्देश्य को लेकर बनाया गया है। आइएसएस पर पहुंचते ही फेडोर ने ट्वीट किया, 'देरी के लिए माफी। ट्रैफिक में फंस गया था। अब काम करने के लिए तैयार हूं।' आइएसएस में फेडोर को 'अब चलें..अब चलें' कहते हुए भी सुना गया।

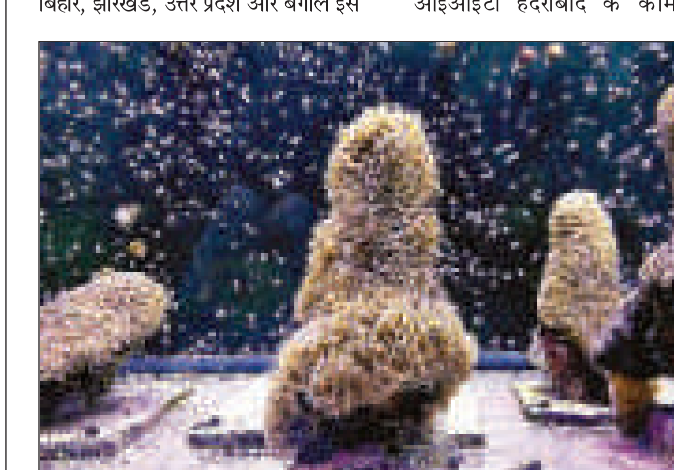

वैज्ञानिकों ने पहली बार तैयार किया कोरल

अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में स्थित द फ्लोरिडा एक्वेरियम कंजरवेशन सेंटर के लैब में बने वाटर टैंक में पिलर कोरल। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने पहली बार कोरल (प्रवाल) तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। इसे अमेरिका की ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पिलर कोरल अटलांटिक महासागर में मिलने वाले यह एक हार्ड कोरल होता है। बता दें कि कोरल रीफ समुद्री जीवों के रहने के लिए सबसे मुफीद माना जाता है। एएफपी

अमेरिकी स्टोर की चीन में ऐसी ओपनिंग कि हो गई सड़क जाम

अमेरिका और चीन के बीच भले ही ट्रेड वार चल रहा हो, ग्राहकों को इससे बहुत लेना-देना नहीं दिख रहा है। इसका ताजातरीन उदाहरण शंघाई के मिन्हैंग जिले में देखने को मिला, जहां अमेरिकी हाइपरमार्केट स्टोर चेन कॉस्टको की पहली स्टोर ओपनिंग पर इतने ग्राहक जुटे कि स्टोर को थोड़ी ही देर में बंद करना पड़ा। इस स्टोर में ग्राहकों की जुटी भीड़ के चलते मिन्हैंग में घंटों जाम लगा रहा। आलम यह था कि गाड़ी पार्क करने के लिए तीन घंटे की वेटिंग थी और स्कूल के बच्चे कई घंटे बाद घर वापस लौट सके। (पीटीआइ)

स्क्रीन शॉट

...इस तरह अपने माता-पिता का सपना पूरा करेंगी विद्या !

आम तौर पर विज्ञान और गणित विषय छात्रों को सबसे ज्यादा डराते हैं, लेकिन बॉलीवुड की 'बेगम जान' यानी विद्या बालन इन दोनों विषयों को एक साल के अंदर सीखने की बात कह रही हैं। उनका कहना है कि इस तरह वह अपने माता-पिता का सपना पूरा करेंगी। साल 2013 में लांच किए गए मंगलयान पर मिनी वेद ने किताब 'दोज मैग्नीफिसेंट वुमेन ऐंड देयर फ्लाइंग मशीन' लिखी है। मंगलवार को इस किताब के लॉन्च के मौके पर विद्या ने कहा कि साल भर में वह विज्ञान और गणित दोनों सीख लेंगी। दरअसल, हालिया रिलीज फिल्म 'मिशन मंगल' में विद्या वैज्ञानिक की भूमिका में नजर आईं। इसके बाद वह इंसानी कंप्यूटर कही जाने वाली महिला गणितज्ञ शकुंतला देवी की बायोपिक कर रही हैं। यानी सिल्वर स्क्रीन पर एक ही साल में वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों की भूमिकाओं में नजर आएंगी। विद्या ने कहा, 'ज्यादातर दक्षिण भारतीय माता-पिता चाहते हैं कि उनकी औलाद गणित या विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करें, लेकिन मुझे न तो विज्ञान आता है, न ही गणित। मैं दसवीं क्लास में ही साइंस स्ट्रीम छोड़कर आर्ट की तरफ मुड़ गई। इसके बाद विज्ञान से वास्ता ही नहीं पड़ा। अब एक ही साल में गणितज्ञ और वैज्ञानिक दोनों बनकर मैं अपने माता-पिता का सपना पूरा कर रही हूं।'

क्या अब शाह रुख के साथ फिल्म बनाएंगे संजय लीला भंसाली?

सलमान खान और आलिया भट्ट को एक साथ स्क्रीन पर देखने की ख्वाहिश रखने वाले प्रशसंकों की हसरतें अधूरी रह गई हैं। सलमान खान ने रविवार को खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी कि संजय लीला भंसाली के साथ उनकी फिल्म 'इंशाअल्लाह' फिलहाल रुक गई है, लेकिन वह ईद पर जरूर आएंगे। भंसाली के स्टूडियो ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल वह इस फिल्म के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे की घोषणा जल्द की जाएगी। ऐसे में सभी की नजरें शाह रुख खान की और घूम गई हैं। कहीं वह घोषणा संजय शाह रुख खान को लेकर तो नहीं करने वाले हैं। सुनने में आया है कि भंसाली के साथ 'देवदास' फिल्म कर चुके शाह रुख के साथ फिल्म 'इजहार' को लेकर बातचीत चल रही है। अब शाह रुख के साथ संजय फिल्म बनाएंगे या नहीं, इसकी घोषणा के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि वर्ष 2020 की ईद पर सलमान खान जरूर आएंगे। दरअसल, जब सलमान ने ट्वीट में बताया कि 'इंशाअल्लाह' ईद पर नहीं आ रही हैं, तब अक्षय कुमार ने उस छुट्टी का फायदा उठा लिया। उनकी फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' अगले साल ईद पर रिलीज होगी। 'लक्ष्मी बॉम्ब' की रिलीज की घोषणा के बाद सलमान खान ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने 'किक' का डायलॉग लिखकर इशारा कर दिया कि वह 'किक 2' के साथ ईद पर आएंगे। सलमान ने लिखा, 'इतना मत सोचना मेरे बारे में दिल में आता हूं...और ईद पर भी।' यानी ईद पर सलमान और अक्षय फिर आमने-सामने होंगे। बहरहाल, 'इंशाअल्लाह' के बंद होने के बारे में कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर सलमान खान फिल्म के क्लाइमेक्स में थोड़ा बदलाव चाहते थे। संजय भंसाली इसे रोमांटिक फिल्म बनाना चाहते थे, जबकि सलमान रोमांस को फिल्म का केवल हिस्सा रखना चाहते थे। भंसाली को कहानी में सलमान की दखलअंदाजी नहीं पसंद आई और उन्होंने फिल्म को बंद करने का निर्णय ले लिया।

बड़े पर्दे पर दिखाई देगा अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन

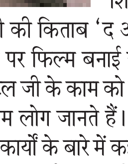

देश के महानतम नेताओं पर फिल्में बनाने का सिलसिला जारी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित फिल्म भी अब बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। अमाश फिल्म्स के शिवा शर्मा और जीशान अहमद ने लेखक उल्लेख एनपी की किताब 'द अनटोल्ड वाजपेयी' के राइट्स प्राप्त कर लिए हैं, जिस पर फिल्म बनाई जाएगी। शिवा शर्मा ने फिल्म के बारे में बताया, 'अटल जी के काम को तो सभी जानते हैं, पर उनके असल जीवन के बारे में कम लोग जानते हैं। इस किताब में बतौर प्रधानमंत्री उनके व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में कई ऐसी प्रेरक बातें हैं, जिन्हें कम लोग जानते होंगे। इसीलिए हमने उन पर फिल्म बनाने का इरादा किया।' जीशान अहमद के अनुसार, 'स्क्रिप्ट का काम शुरू हो चुका है। पूरी होने के बाद हम निर्देशक व कलाकारों का चयन कर लेंगे।'

'83 में बमन ईरानी निभाएंगे फारुख इंजीनियर का किरदार

कबीर खान निर्देशित फिल्म '83 में बमन ईरानी पूर्व क्रिकेटर-कमेंटेटर फारुख इंजीनियर का किरदार निभाते नजर आएंगे। रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा की है, जिसमें कबीर खान के साथ बमन ईरानी भी हैं। रणवीर ने लिखा है कि 'सभी स्टार आ गए हैं। जिन उल्लेखनीय लोगों से मैं मिला हूं, उनमें से एक, सबसे बेहतरीन कलाकारों में शुमार। वह लाखों में एक हैं।'

रहें सतर्क

दवाओं के अनावश्यक इस्तेमाल से बढ़ रहा दिल, किडनी और दिमागी बीमारी का खतरा, शोधकर्ताओं ने रक्तचाप कम करने वाली दवाओं के बारे में पुनर्विचार करने की बताई जरूरत

तेजी से धड़कता है भारतीयों का दिल

- इंडियन हार्ट स्टडी में शोधकर्ताओं ने किया दावा
- एक मिनट में 80 बार धड़कता है हृदय
- औसतन एक मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय

सुबह के मुकाबले शाम को ज्यादा रहता है भारतीयों का रक्तचाप। प्रतीकात्मक

कोलकाता, प्रेट्र : आमतौर पर लोगों का हृदय एक मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है, लेकिन इंडियन हार्ट स्टडी (आइएचएस) में शोधकर्ताओं ने दावा किया गया है कि भारतीयों के हृदय की गति औसत से ज्यादा है। उनका हृदय एक मिनट में 80 बार धड़कता है। साथ ही इस अध्ययन में यह भी कहा गया है कि अन्य देशों के लोगों की तुलना में भारतीयों का ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप सुबह के मुकाबले शाम को ज्यादा रहता है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने देश के 15 राज्यों के 355 शहरों में रह रहे 18,918 लोगों को शामिल किया। इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थीं। यह अध्ययन वर्ष 2018 में अप्रैल के बाद अगले वर्ष जनवरी के बीच किया गया। यह काम 19 डॉक्टरों की एक टीम ने अंजाम दिया। साथ ही उन्होंने रक्तचाप कम करने वाली दवाओं के बारे में पुनर्विचार करने की भी जरूरत बताई।

खतरनाक है मास्क्ड हाइपरटेंशन : आइएचएस समन्वयक और विवेकानंद चिकित्सा विज्ञान संस्थान में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. सौमित्र कुमार ने कहा कि यह अध्ययन में हमें भारतीयों के हृदय गति की उच्च दर को कम करने के साथ-साथ व्हाइट कोड हाइपरटेंशन और मास्क्ड हाइपरटेंशन को कम करने में मदद कर सकता है। मास्क्ड हाइपरटेंशन उस स्थिति को कहते हैं जब मरीज डॉक्टर के पास जाकर रक्तचाप की जांच कराता है तो वह सामान्य रहता है, लेकिन घर पर जांच करने पर वह हमेशा उच्च रहता है, जबकि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में परीक्षण के दौरान रक्तचाप सामान्य से कुछ ज्यादा रहता है।

बढ़ते हैं किडनी और हृदय संबंधी रोगों के जोखिम : आइएचएस के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि भारतीयों में मास्क्ड हाइपरटेंशन और व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के 42 फीसद मामले देखने को मिले। पश्चिम बंगाल में 22.50 फीसद लोगों में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और 17.30 फीसद लोगों में मास्कड हाइपरटेंशन के मामले देखने को मिले। शोधकर्ताओं ने कहा कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में कई बार जांच में सही आंकड़े न मिल पाने के कारण मरीज अनावश्यक दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। इससे उन्हें और ज्यादा नुकसान होता है, जबकि मास्क्ड हाइपरटेंशन में का निदान करना आसान नहीं होता। अनावश्यक दवाओं के चलते हृदय, मस्तिष्क और किडनी की बीमारियों के जोखिम बढ़ जाते हैं और लोगों की मौत तक हो जाती है।

लगातार बढ़ रहे हैं मामले : डॉक्टर कुमार ने कहा कि उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी रोगों के बीच निकट संबंध होता है और यह भारत में लगातार बढ़ रहा है। इसलिए हमें समय रहते इसके खतरों को भांपते हुए कदम उठाने की जरूरत है।